Machine Translated by Google

ग्राउंड जीरो

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 6 मई, 2024 को जंगल में आग लगने की घटना। नवंबर 2023 से, जब जंगल में आग लगनी शुरू हुई, तब से राज्य में 1,038 घटनाएं हो चुकी हैं। शशि शेखर कश्यप

उत्तराखंड की जलती पहाड़ियाँ

उत्तराखंड में पिछले नवंबर से चल रहे वन क्षेत्र में आग लगने से मई में पांच लोगों की मौत हो गई। वन विभाग ने इस आग के लिए पलायन, हाई-टेंशन तारों और चीड़ के पेड़ों की बहुतायत को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आग पूरी तरह से मानव निर्मित है। इशिता मिश्रा पूरे राज्य में यात्रा करती हैं और पाती हैं कि ग्रामीण, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, आग बुझाने में मदद कर रही हैं।

बसंती ने राल इकट्ठा करने के लिए उत्तराखंड के सुंदर अल-मोरा जिले के सुनरा-कोट गांव की पहाड़ियों पर चढ़ाई की। 2 मई को ज्ञानू चालौने और उनकी पत्नी जंगल में चीड़ के पेड़ों से। यह जोड़ा पिछले साल ही अपने तीन बच्चों की बेहतर ज़िंदगी और शिक्षा के लिए नेपाल से उत्तराखंड आया था। उस सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। वे रमेश बाकुनी नामक एक ठेकेदार के लिए राल निकालने का काम करते थे, जिसे पहाड़ों में लीसा कहा जाता है। अगर वे छह महीने तक रोज़ाना 10 घंटे काम करते तो उन्हें 50,000-60,000 रुपये मिलते।

जब वे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो दंपत्ति ने चीख सुनी। उन्होंने देखा कि एक आदमी पहाड़ी की चोटी पर भाग रहा था, जो अपने ऊपर लगे आग को हिलाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें डर के मारे एहसास हुआ कि वह दीपक पुजारा था, जो उनका दोस्त था। चालीस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और पुजारा की पत्नी तारा को ज़मीन पर पड़ा पाया, जो आधी जली हुई थी। जल्दी से, उन्होंने पास के पेड़ की एक हरी शाखा तोड़ी और पुजारा को मारना शुरू कर दिया, जबकि उनके कपड़े भी जल गए। इससे पहले कि कोई उनकी मदद कर पाता, चारों पीड़ित बुरी तरह जल चुके थे। अस्पताल में सभी ने दम तोड़ दिया।

बकुनी के पास कई दिनों तक चैलौने के बच्चों को यह खबर बताने की हिम्मत नहीं थी। बकुनी कहते हैं, "वे महीनों से मेरे बगीचे में खेल रहे हैं। मेरे पास उन्हें यह बताने का साहस नहीं था कि क्या हुआ था," उन्हें चिंता है कि लोग अब उनके लिए काम नहीं करेंगे। बच्चे अब नेपाल के बझांग जिले में अपने चाचा की देखरेख में हैं, जहाँ से वे आए थे।

इस साल उत्तराखंड में वन्य क्षेत्रों में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में 38,000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 71.05% है। नवंबर 2023 से, जब वन्य क्षेत्र में आग लगनी शुरू हुई, 10 मई तक 1,038 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1,385.5 हेक्टेयर (हेक्टेयर) वन भूमि जलकर खाक हो गई है। जबकि अधिकारियों ने इन्हें पहाड़ों में होने वाली "वार्षिक आग" के रूप में खारिज कर दिया है, इन आगजनी की कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ी है जिनका जीवन पहाड़ों पर निर्भर है।

उत्तराखंड वन विभाग की वेबसाइट पर एक पुस्तिका में कहा गया है कि यहां से अन्य राज्यों में लोगों का बढ़ता पलायन, जिससे पहाड़ बंजर हो गए हैं; हाई-टेंशन तार; और चीड़ के पेड़ों की बहुतायत, जो प्रकृति में अत्यधिक अपूरणीय हैं, वनों के विनाश के मुख्य कारण हैं।

पुस्तिका में कहा गया है कि युवा वर्ग को यह नहीं पता कि वनों के संरक्षण का कैसे सामना किया जाए, क्योंकि वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम उन्हें पर्यावरण के बारे में शिक्षित नहीं करता है, तथा पुरानी पीढ़ी, जो मुख्य रूप से पहाड़ों पर रहती है, संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने में असमर्थ है।

इसमें आगे कहा गया है, "पहाड़ों में लोगों को अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के तहत खाना पकाने की गैस मिल रही है और इसलिए, ग्रामीणों ने खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों के जंगलों में जाना बंद कर दिया है, जो वनों के संरक्षण में वृद्धि का एक कारण भी है।"

उत्तराखंड में वन बल के प्रमुख के पद पर कार्यरत धनंजय मोहन कहते हैं कि इस साल अत्यधिक सूखे और सामान्य से कम बर्फबारी के कारण सतहें शुष्क हो गई हैं। इससे चीड़ के पेड़ों से भरे जंगलों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। वन विभाग के अनुसार,

> पहले से ही जंगलों के अनुकूल वातावरण में, जब ग्रामीण खेतों में पराली जलाते हैं तो जंगलों में आग तेजी से फैलती है।
>
> धनंजय मोहन
> प्रभारी, प्रमुख वन बल में उत्तराखंड

वन विभाग की वेबसाइट के अनुसार, उत्तराखंड में 3,94,383.84 हेक्टेयर चीड़ के जंगल हैं। राज्य में 13 किस्म के पेड़ों में से 15% चीड़ के पेड़ हैं।

वे कहते हैं, "पहले से ही जंगलों के अनुकूल इस माहौल में, जब ग्रामीण खेतों में पराली जलाते हैं, तो जंगलों में आग तेज़ी से फैलती है। राज्य में गांव और जंगल एक दूसरे से सटे हुए हैं। जंगल में आग तब भी लगती है, जब लोग जंगल में जली हुई सिगरेट छोड़ देते हैं या जंगल में आग लगा देते हैं, ताकि ज़मीन साफ हो जाए, इस विश्वास के साथ कि इससे चारे की पैदावार बढ़ेगी।"

आज 6 मई है। कुमाऊं हिमालय में समुद्र तल से 1,900 मीटर ऊपर स्थित अल्मोड़ा के शीतलाखेत में ऊंचे पेड़ों से लदी पहाड़ियां, जो कभी हरी-भरी हुआ करती थीं, गांवों में घरों की बालकनियों से दिखाई नहीं दे रही हैं; वे धुंध की मोटी चादर में गायब हो गई हैं।

पेड़ अब काले हो गए हैं, और जली हुई चीड़ की पत्तियों की राख जंगल के फर्श को ढक रही है। पहाड़, जो हमेशा स्वच्छ और ठंडी हवा का वादा करते हैं, गर्मी बिखेरते हैं। फूलों की सुगंध के बजाय, जली हुई लकड़ी की गंध हवा में बनी रहती है।

सीतलाखेत और पास के भाकर गांव की करीब 20 महिलाएं जंगल में लगी आग बुझाने के बाद पहाड़ी से नीचे उतरती हैं। ऊंचे-ऊंचे एम्स के खिलाफ अपने एकमात्र हथियार, हरी झाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने 10 घंटे तक कड़ी मेहनत की। उनके कपड़े पसीने और राख से भीगे हुए हैं; वे थकी हुई दिख रही हैं।

ये महिलाएँ शीतलाखेत में 300 सदस्यों वाले समूह 'जंगल के दोस्त' से जुड़ी हैं। उनके गुरु 56 वर्षीय गजेंद्र पाठक हैं, जो एक स्थानीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र में फार्मासिस्ट हैं और पिछले साल उन्होंने जंगल के कीड़ों से निपटने के लिए एक सामुदायिक पहल में इन महिलाओं और कुछ पुरुषों को एक साथ लाया था। उनके आह्वान पर, समूह के सदस्य, जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं, कीड़ों से निपटने के लिए निकल पड़े।

इस प्रयास के बदले में महिलाओं को 125 मिलीलीटर टेट्रा पैक के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है।

फ्रूटी, एक लोकप्रिय, मीठा आम-स्वादिष्ट पेय; और कुछ बिस्कुट। पाठक ने इनका ऑर्डर दिया है, और वन रेंजर, मनोज लोहानी ने इनके लिए भुगतान किया है। महिलाएँ अपने बच्चों के लिए घर ले जाने के लिए पैकेट को अपनी साड़ियों के कोने में बाँधती हैं।

उनमें से एक गृहिणी इंदुमती घर जाने के लिए बेचैन है। वह पाठक से कहती है, "सर, कृपया मुझे ले चलो।" "मेरा छह महीने का बच्चा भूखा होगा। मैं यहाँ आने से पहले सुबह 10 बजे उसे स्तनपान कराती हूँ। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं," वह अपनी घिसी हुई चप्पलें पोंछते हुए कहती है।

पाठक पास से गुज़र रही एक जीप को रोकते हैं और महिलाओं से अंदर बैठने को कहते हैं। लोहानी कुछ महिलाओं को गाड़ी में चढ़ने से पहले बागवानी की रेक देते हैं। वे इसका इस्तेमाल जंगल की रेखा को साफ करने के लिए करती हैं ताकि बचाव अभियान को जल्दी रोका जा सके।

"इन महिलाओं की वजह से ही आपको चारों ओर हरियाली दिखती है। अन्यथा, जंगल की आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया होता। यह दुखद है कि हम उनके लिए कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं।

पाठक कहते हैं, "वे हमारे पहाड़ों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।" उनका मानना है कि सरकार को राज्य के उन लोगों के लिए जीवन बीमा मुहैया कराना चाहिए जो वन संरक्षण में मदद करते हैं।

यह पूछे जाने पर कि समूह में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक क्यों हैं, 65 वर्षीय देबुली देवी कहती हैं, "ये आदमी ही तो जंगल में आग लगाते हैं। वो क्या इसे बुझाएंगे?" इसी तरह, नैनीताल जिले के पटवा डागर गांव में, सुनील रावत कहते हैं कि उन्होंने 19 अप्रैल से 20 से अधिक जंगल की आग बुझाने में मदद की है। "शीतलखेत एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसा होता है। राज्य भर के ग्रामीण बड़ी संख्या में वन विभाग का समर्थन करने के लिए आते हैं, जो अब इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी नींद से जागा है," वे कहते हैं।

नैनीताल के जिला वन अधिकारी चंद्र शेखर जोशी कहते हैं कि वन विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि वनों की कटाई में मदद करने वाले ग्रामीणों को पारिश्रमिक दिया जाए। नैनीताल जिले में राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र (70.67%) है और यहां करीब 300 वन निरीक्षक हैं। इनमें से आधी महिलाएं हैं।

उत्तराखंड में 38,000 वर्ग किलोमीटर के दर्ज वन क्षेत्र में से वन विभाग 26.5 लाख हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र का प्रबंधन करता है, जहां मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है, जबकि वन पंचायतें या समुदाय के नेतृत्व वाले वन प्रबंधक 7.32 लाख हेक्टेयर का प्रबंधन करते हैं। वन विभाग के बुलेटिन के अनुसार, वन पंचायतों द्वारा प्रबंधित क्षेत्र की तुलना में आरक्षित वनों को अधिक नुकसान हुआ है।

हालिया समीक्षा के बाद, राज्य सरकार ने वन विभाग के 4,000 संविदा कर्मचारियों के लिए 3 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा की।

राजनीति खेलना 8 मई को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि "वनों में होने वाले सभी नुकसान मानव निर्मित हैं।" उसने कोर्ट को बताया कि 388 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

जंगल की आग बुझाने के लिए समुदाय द्वारा संचालित पहल जंगल के दोस्त की महिलाओं को उनके प्रयासों के बदले में फ्रूटी का 125 मिलीलीटर टेट्रा पैक और कुछ बिस्कुट दिए जाते हैं। शशि शेखर कश्यप

> ये महिलाएँ ही हैं जिनकी वजह से आपको चारों ओर हरियाली दिखती है। अन्यथा, जंगल के जंगल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया होता। वे हमारे पहाड़ों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती हैं।
>
> गजेन्द्र पाठक
> 'जंगल के दोस्त' के प्रमुख

पूरे राज्य में जंगलों को आग लगाने वालों के खिलाफ़ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि ज़्यादातर मामलों में गिरफ़्तार किए गए लोगों ने पराली जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वे तेज़ हवाओं के कारण फैली आग को नियंत्रित करने में विफल रहे।

सरकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत ३८० पृष्ठों की अंतरिम स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग ने रिपोर्ट किया है कि उत्तराखंड का ४० प्रतिशत हिस्सा जल रहा है, जो कि "भ्रामक" है, और केवल ०.१ प्रतिशत वन क्षेत्र ही आग से प्रभावित हुआ है।

राज्य ने न्यायालय को बताया कि वन्य आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को तैनात किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय वायु सेना बाम्बी बकेट (एक प्रकार का ढहने वाला कंटेनर जो हेलीकॉप्टर से लटकता है और लक्षित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ता है) का उपयोग कर रही है।

सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड वन अग्नि शमन परियोजना 2023-28 केंद्र सरकार के पास लंबित है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य में वन संरक्षण कोई "नई" बात नहीं है और अब कोई "आपातकालीन" स्थिति नहीं है।

सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह वर्षा बढ़ाने और वर्षा को बढ़ावा देने के लिए क्लाउड सीडिंग के विकल्प का पता लगाने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ गठजोड़ कर रही है। इस समाधान को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि वन संरक्षण के लिए "क्लाउड सीडिंग या वर्षा देवताओं पर निर्भर रहना समाधान नहीं है।"

अगले दिन, बारिश के बाद, सरकार ने दावा किया कि उसने जंगल के जंगलों को पूरी तरह से "नियंत्रित" कर लिया है। लेकिन जंगल के जंगल अभी भी भड़के हुए हैं। अकेले 17 मई को ही 11 जंगल के जंगल जल गए।

उसी दिन, न्यायालय ने समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर राज्य की प्रतिक्रिया से संतुष्टि व्यक्त करने के बाद मामले को सितंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्य ने कहा कि उसने पूरे प्रतिपूरक वनीकरण कोष का उपयोग वनों की कटाई और बचाव के लिए किया है और अन्य चीजों के अलावा वन विभाग में क्षेत्र स्तर पर रिक्त पदों को भर रहा है।

कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव अभियान में इस मुद्दे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए किया। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा, "जब अप्रैल में जंगल जल रहे थे, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा करने में व्यस्त थे। यहां तक कि वन मंत्री सुबोध उनियाल भी असम में प्रचार कर रहे थे।"

अपना अभियान पूरा करने के बाद, धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस को आदेश दिया कि वे जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर गैंगस्टर अधिनियम और उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2024 के तहत मुकदमा चलाएं।

समाधान कहां है? पाठक का मानना है कि चीड़ के पेड़ के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जिसे उत्तराखण्ड के कई लोग इस घटना का मुख्य दोषी मानते हैं।

वे कहते हैं, "यह पेड़, जिसे शायद ही कभी रख-रखाव की ज़रूरत होती है, लकड़ी और ईंधन की लकड़ी का एक प्रमुख स्रोत है। इसके तने का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। इसकी छाल चारकोल, राल और कोल टार का स्रोत है, जिसका उपयोग न केवल ग्रामीण करते हैं, बल्कि पैसे कमाने के लिए इसे बेचते भी हैं।" "क्या कोई और पेड़ है जो हमें इतना कुछ देता है?"

राज्य ने देवदार की सुइयों से बिजली बनाने की अवधारणा विकसित की है, जो हर साल मार्च के मध्य से जुलाई में बारिश शुरू होने तक पेड़ों से गिरती हैं। लेकिन इन सुइयों के संग्रह के लिए प्रस्तावित कम कीमत से मदद नहीं मिल रही है।

इस वर्ष, धामी ने पिरूल लाओ-पैसे पाओ (चीड़ के पत्ते लाओ और पैसे पाओ) नामक योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत राज्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीड़ के पत्ते खरीदता है, जो अब तक की दर 3 रुपये प्रति किलोग्राम से काफी अधिक है।

पाठक का सुझाव है कि सरकार वनों की कटाई को कम करने के लिए सामुदायिक भागीदारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करे। उनका यह भी मानना है कि सहायक प्राकृतिक उत्थान (ANR) तकनीक को पूरे राज्य में अपनाया जाना चाहिए। इस सरल और कम लागत वाली वन बहाली पद्धति में देशी वृक्ष प्रजातियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करके क्षरित या वनों की कटाई वाली भूमि के प्राकृतिक उत्थान को सुगम बनाना शामिल है। इसमें कई तरह की तकनीकें शामिल हैं जैसे कि हमलावर प्रजातियों को हटाना, पौधों की स्थापना के लिए माइक्रोसाइटों का निर्माण, और चराई और अन्य गड़बड़ियों से प्राकृतिक उत्थान की सुरक्षा। वे कहते हैं, "ANR की लागत सरकार द्वारा पेड़ लगाने पर खर्च की जाने वाली राशि का आधा भी नहीं होगी। और अंत में, हम जो सरकार की पहल के बारे में देखते हैं वह लगाए गए कुल पौधों का 10% भी नहीं है।"

उन्होंने कहा कि पहाड़ों पर जलस्तर कम करने के लिए जलरेखा स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उत्तराखंड में वन संरक्षण अधिनियम ने सांप्रदायिक तनाव को भी हवा दे दी है, जब एक वीडियो सामने आया जिसमें युवा लड़के जश्न मना रहे थे, जबकि उनके पीछे विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कुछ लोगों ने मुसलमानों पर आरोप लगाया कि वे राज्य सरकार से "बदला लेने" के लिए वनों को आग लगा रहे हैं, जिसने समान नागरिक संहिता लागू की और फरवरी में हल्द्वानी में "अतिक्रमण विरोधी अभियान" शुरू किया, जिससे दंगे भड़क गए। पुलिस ने बिहार के रहने वाले लोगों को गिरफ्तार किया और दावा किया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ 'लाइक' पाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था।

जबकि आग बुझाई जा रही है, गंगा नदी को बचाने के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन गंगा आह्वान के हेमंत ध्यानी, बार-बार होने वाली जंगल की आग के स्नोबॉल प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। "आग के दौरान जंगल जल जाते हैं। इससे पहाड़ों और मिट्टी की ताकत कम हो जाती है। जब बारिश होती है, तो ढीली मिट्टी पानी को बरकरार रखने में विफल हो जाती है और भूजल पुनर्जीवन को प्रभावित करती है, जिससे राख बनती है। जैसे ही ढीली चट्टानें टूटती हैं और पानी भी नीचे गिरता है, भूस्खलन होता है," वे बताते हैं। उत्तराखंड के पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा का कहना है कि राज्य में वन विभाग के पास जंगल की आग को नियंत्रित करने की "बहुत कम या कोई क्षमता नहीं" है। वे कहते हैं, "जब तक वे स्थानीय लोगों को सशक्त नहीं बनाते और उन्हें विश्वास में नहीं लेते, जंगल की आग को कम करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता।"

सेमी वाईके

एम एनडी-एनडीई

Machine Translated by Google

विभाजन के खतरे

उत्तर के नागरिकों को दक्षिणी दलों के विरुद्ध खड़ा करना एक खतरनाक चाल है

आम चुनाव के चौथे चरण के बाद, पार्टियों का चुनावी अभियान समाप्ति के करीब पहुंच गया है। हालांकि, चुनाव 543 में से 379 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है। अभियान कैलेंडर में मतदाताओं की चिंताओं और अभियान की बयानबाजी - खासकर भाजपा के मुख्य नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की - के बीच का अंतर, दुर्भाग्य से, बरकरार है। जबकि रोजगार सृजन, रोजगार और विकास को मतदाताओं ने प्राथमिक मुद्दों के रूप में महत्व दिया है, श्री मोदी मुख्य रूप से अपने सरकार के 10 वर्षों के शासन के रिकॉर्ड पर चुनाव लड़ने और मुख्य चिंताओं को दूर करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के विचार से प्रेरित होने से इनकार करते हैं। इसके बजाय, वह वही करना चाहते हैं जिसमें उन्हें हमेशा आनंद आता है - विपक्ष पर सत्य, अर्धसत्य और बेबुनियाद बातों से हमला करना।

श्री मोदी के इस प्रयास में टेलीविजन और सोशल मीडिया का शोर भी सहायक है, जो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई बयानबाजी से ध्यान हटाने के लिए उपयोगी साधन है, चाहे वह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण हो या हिंदुत्व के अनुयायियों से समर्थन जुटाने के लिए कुत्ते की सीटी बजाना। कांग्रेस और उसके सार्वजनिक चेहरे राहुल गांधी सहित अन्य दल भी - भले ही उतने ही नहीं - जाति की राजनीति से जुड़े पहचान के मुद्दों को उठाने के दोषी हैं। लेकिन श्री मोदी और उनके कुछ सहयोगियों ने प्रचार के साधन के रूप में गाली-गलौज को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। जौनपुर में अपनी रैली में उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्ष, सपा और कांग्रेस पर चुप रहने का आरोप लगाया, जब उनके दक्षिणी सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश के लोगों और "सनातन धर्म" के लिए "बेतुकी और अपमानजनक भाषा" का इस्तेमाल किया।

भारत ब्लॉक के कुछ उत्तरी दलों ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की "सनातन धर्म" पर टिप्पणी से सार्वजनिक रूप से असहमति जताई है, जबकि सामाजिक न्याय पर अपने रुख पर जोर दिया है और जाति पदानुक्रम के मुद्दे को उठाया है।

इन पार्टियों द्वारा समर्थित संघवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति को जोड़ने वाली चीजें उन्हें विभाजित करने वाली चीजों से कहीं अधिक हैं - भाषाई राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न जैसे कि अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की आवश्यकता - लेकिन अलग-अलग राजनीतिक दलों से बने गठबंधनों से यही उम्मीद की जाती है। श्री मोदी को भाजपा और भारत ब्लॉक के बीच सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने के तरीकों पर जोर देते हुए मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन, इसके बजाय, हिंदी पट्टी के लोगों को दक्षिणी दलों के खिलाफ भड़काने के लिए उनके द्वारा अर्ध-सत्य का इस्तेमाल करना समस्याजनक है, ऐसे समय में जब उत्तर-दक्षिण आर्थिक एकीकरण अधिक है, उत्तर से कामकाजी वर्ग के नागरिक रोजगार के लिए दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं। हाल ही में, भाजपा ने मनीष कश्यप को शामिल किया, जो एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों पर हमले की झूठी खबर फैलाने के लिए जेल भेजा गया था। इस तरह की कार्रवाइयां विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे सकती हैं जो पूरे भारतीय राष्ट्र की मदद नहीं करती हैं।

गृह युद्ध के बाद श्रीलंका में जारी गतिरोध

डेढ़ दशक भी इसे ठीक नहीं कर सकता

लंबे समय से चले आ रहे गृहयुद्ध के गहरे घाव। श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में हज़ारों लोग मारे गए, जबकि भारी तबाही भी देखी गई।

अहिलन Kadirgamar

एक राजनीतिक अर्थशास्त्री और वरिष्ठ हैं व्याख्याता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जना, श्रीलंका

एसत्य, जवाबदेही और न्याय की चिंताएँ बनी हुई हैं, जबकि अतीत और भविष्य के राजनीतिक विकल्पों के प्रश्न बड़े हैं। इस संदर्भ में, एक नई पीढ़ी के उभरने से कम से कम युद्धग्रस्त क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलना शुरू हो जाना चाहिए। हालाँकि, आर्थिक पुनर्निर्माण शायद ही आगे बढ़ा है, बाद के संकटों ने विकास को और पीछे धकेल दिया है। राजनीति ध्रुवीकृत और राजनीतिक समाधान के बिना भरी हुई है। तमिल मध्यम वर्ग की सामाजिक आकांक्षाएँ किसी तरह प्रवासी समुदाय में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि द्वीप के उत्तर और पूर्व में रहने वाले कामकाजी लोग कुछ विकल्पों के साथ निराश्रित हैं। युद्ध के बाद के इस गतिरोध को कोई कैसे समझा सकता है? और, श्रीलंका के युद्धग्रस्त लोगों के लिए क्या रास्ता है?

पटरी से उतरी पुनर्निर्माण ट्रेनें जो उत्तर में पीढ़ियों से नहीं देखी गई थीं, एक दशक पहले फिर से शुरू हुईं। कालीन वाली सड़कों के किनारे बैंक और सुपरमार्केट बनाए गए, यहाँ तक कि पर्यटकों के लिए आलीशान होटल खोले गए और तमिल प्रवासी जना शहर में आने लगे।

फिर भी, इस समृद्धि के नीचे, ग्रामीण इलाकों में कुछ ही मील की दूरी पर, स्थिर आजीविका के लिए उनकी हताशा में लोगों की पीड़ा स्पष्ट थी। जैसे ही कुछ ग्रामीण समुदाय इन चुनौतियों पर काबू पाने लगे, जब उनके खेत, घरेलू बगीचे और नारियल के पेड़ फल देने लगे, श्रीलंका फिर से अराजकता में डूब गया।

अप्रैल 2019 में ईस्टर के दौरान हुए आतंकी हमलों ने देश को हिलाकर रख दिया था, उसके बाद कोविड-19 महामारी और अब आर्थिक संकट, श्रीलंका की आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति है। युद्ध और बेदखली के दंश से उभर रही आबादी के लिए, और अपने बच्चों की शिक्षा और युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने वाली आबादी के लिए, वर्तमान समय एक और पीढ़ी के नुकसान का संकेत है।

पूरे देश में आर्थिक बदहाली देखी जा रही है, साथ ही पासपोर्ट कार्यालय के बाहर लंबी-लंबी कतारों के साथ पलायन भी। युद्ध से पीड़ित वंचित और भूमिहीन लोगों के लिए पलायन का सवाल ही नहीं उठता, आर्थिक अवसर लगभग शून्य हैं और भूख नई सामान्य बात है। फिर भी, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उन्हें सहायता प्रदान करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। अपने संकटों में डूबते हुए, अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित मितव्ययिता उपायों से और भी जटिल हो गया है, राज्य ने उन्हें छोड़ दिया है।

तमिल प्रवासियों की भारी जेबों से युद्धग्रस्त क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का मिथक निवेश निधियों के अल्प प्रवाह से उजागर हो गया है। युद्ध के बाद बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय दाता विकास परियोजनाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को शायद ही पुनर्जीवित किया है। वास्तव में, गैर-सरकारी द्वारा व्यक्तिगत सहायता संगठनों ने परिवारों को केवल अशक्त ही किया है और उन्हें निर्भरता में फंसा दिया है। कई परिवार, खास तौर पर महिलाएं, हिंसक माइक्रोनेंस ऋण में धकेल दी गई हैं।

तमिल राजनीति स्थानीय आजीविका की चिंताओं के प्रति लापरवाह रही है, क्योंकि वे अपने वर्ग और सामाजिक हितों के प्रति समर्पित हैं, तथा उनका एक पैर तमिल प्रवासी समुदाय पर टिका हुआ है।

जो राजनेता जवाबदेही की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के प्रति, वे आम लोगों से शायद ही कभी जुड़ते हैं। वे युद्ध प्रभावित समुदायों को सहारा देने के लिए प्रवासी धन प्रेषण के मिथक को बढ़ावा देते हैं, जबकि हकीकत में, ऐसे धन प्रेषण शहरी तमिल मध्यम वर्ग के एक बहुत छोटे हिस्से तक ही पहुँच पाते हैं।

ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यक युद्ध के बाद उत्तर और पूर्व में आर्थिक और राजनीतिक प्रक्षेपवक्र के लिए, यह राजपक्षे शासन है जिसे अपने युद्ध विजय उत्सव, निरंतर सैन्यीकरण और सिंहली बौद्ध राष्ट्रवाद के अश्लील प्रक्षेपण के लिए बहुत अधिक दोष लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिल राष्ट्रवादी राजनीति ध्रुवीकरण प्रवचन के माध्यम से अपने स्वयं के पोषण में अपने सिंहली समकक्ष को प्रतिबिंबित करना जारी रखती है। तमिल अधिकारों के लिए इसके प्रमुख शोर में बहुत कम बदलाव आया है, क्योंकि यह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम की बयानबाजी की ओर लौटता है, कमजोर पीड़ित होने का आनंद लेता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक अंतहीन विश्वास रखता है। राजनीतिक अभिनेताओं, नागरिक समाज में सामाजिक सहयोगियों और तमिल प्रवासी के विषैले वर्गों द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में युद्ध के बाद की नियमित तीर्थयात्राएं तमिल सार्वजनिक क्षेत्र में आडंबरपूर्ण उम्मीदें जगाती हैं। उनके लिए, यह तथाकथित जवाबदेही प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप करने पर आधारित है।

तमिल लोगों का भविष्य उनके और पूरे देश के लिए समानता और स्वतंत्रता पर आधारित एक नई दृष्टि बनाने पर निर्भर है।

इस बीच, दक्षिण के राजनीतिक कलाकार और उत्तर ने राजनीतिक सुलह की दिशा में समुदायों के बीच सामाजिक और आर्थिक पुल का निर्माण मुश्किल से ही किया है। कोलंबो में सत्ता पर काबिज लोगों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्षेत्रों को सत्ता का हस्तांतरण और केंद्र में सत्ता की साझेदारी को बार-बार दरकिनार किया गया है।

दरअसल, 2015 में सत्ता परिवर्तन के समय भी यही हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण राजनीतिक समझौते की दिशा में एक बड़ा रास्ता खो गया था। राष्ट्रीय नेतृत्व की लगातार अड़ियल नीति, तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाली भूमि पर राज्य द्वारा कब्ज़ा और युद्ध में मारे गए लोगों के स्मारकों पर लगातार हमले एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाते हैं।

2013 में प्रथम उत्तरी प्रांतीय परिषद के चुनाव के साथ ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन 2018 में इसका कार्यकाल पूरी तरह से अपमानजनक तरीके से समाप्त हो गया, जहाँ तमिल राष्ट्रवादी नेतृत्व के पास अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि के मामले में भी दिखाने के लिए कुछ नहीं था। कोलंबो में राजनीतिक अभिजात वर्ग का नस्लवाद और अहंकार और तमिल राजनीतिक नेतृत्व का खोखलापन श्रीलंका के लिए अभिशाप रहा है।

राजनीति। उत्तर और पूर्व में तमिल-मुस्लिम संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अक्टूबर 1990 में LTTE द्वारा जातीय सफाए के एक कृत्य में निकाले गए उत्तरी मुसलमानों को जना में शायद ही फिर से शामिल किया गया हो। भारतीय मूल के पहाड़ी तमिल, या मलैयाहा तमिल, जिन्हें लगातार नरसंहारों के दौरान उत्तर में बागानों से विस्थापित किया गया था, और उनके मताधिकार से वंचित होने के बाद, उत्तर में बहुत कम एकजुटता मिली। वे बंधुआ मजदूर बन गए, फिर गृहयुद्ध के लिए तोप का चारा बन गए, और आज भी उनमें से कई भूमिहीन हैं या कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर बसे हुए हैं। जना में जाति उत्पीड़न अब तमिल प्रवासियों द्वारा वित्तपोषित मंदिरों के आसपास चुपके से फिर से मजबूत हो रहा है, जबकि कुछ समूह हिंदुत्व-शैली के सांप्रदायिक लामबंदी का प्रयास कर रहे हैं।

तमिल लोगों का भविष्य आज हमारे लोगों की दुर्दशा और बेदखली को देखते हुए, तमिल वामपंथी वी. करालसिंहम के शक्तिशाली शब्द याद आते हैं। तमिल भाषी लोगों के लिए रास्ता नामक अपनी पुस्तक में, उन्होंने स्वतंत्रता के मात्र 15 वर्ष बाद 1963 में निम्नलिखित बातें कही थीं।

"अब हम एक अजीब विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। तमिल भाषी लोगों का नेतृत्व पिछले दशक में एक दृढ़ नेतृत्व द्वारा किया गया है, जो सबसे अच्छे इरादों से प्रेरित है, जिसे न केवल लोगों का व्यापक समर्थन मिला है, बल्कि उनका उत्साही सहयोग भी मिला है, फिर भी तमिल भाषी लोग अपने इतिहास में सबसे निचले स्तर पर हैं। अपने सभी प्रयासों के बावजूद लोगों को एक के बाद एक हार, एक के बाद एक अपमान का सामना करना पड़ा है। लोगों के प्रयासों और उनके द्वारा खुद को जिस निराशाजनक गतिरोध में पाया जाता है, उसके बीच की गहरी खाई को कोई कैसे समझा सकता है?"

छह दशक पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि, तमिल लोगों की स्थिति कितनी बदतर हो सकती है और तमिल राजनीति किस हद तक गिर सकती है। तमिल लोगों का भविष्य दिवालिया तमिल राष्ट्रवाद को खारिज करने और अपने और पूरे देश के लिए एक नया दृष्टिकोण बनाने पर निर्भर है।

2022 के महान विद्रोह या 'अरागालय' में, जहां विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमियों से आए श्रीलंकाई लोगों ने एक ऐसे राष्ट्रपति को खदेड़ने के लिए एकजुट हुए, जिन्होंने सर्वोच्च युद्ध नायक और सिंहली-बौद्ध राष्ट्रवाद के संरक्षक होने का दावा किया था, वहां हमारे देश के लिए प्रेरणा है कि वह क्या बन सकता है।

आज सत्तावादी और आर्थिक दमन के बावजूद, आने वाले वर्ष हमें एक अलग रास्ते पर ले जा सकते हैं, जो कि लगभग एक सदी के सबसे भयानक आर्थिक संकट का सामना करते हुए सामाजिक और आर्थिक न्याय के संघर्षों द्वारा निर्धारित होगा।

तमिल लोगों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा, अलगाववादी और आत्मघाती राजनीति से दूर होना होगा जिसने उन्हें ऐतिहासिक रूप से अप्रासंगिक बना दिया है, और सभी लोगों के साथ मिलकर न केवल अपना भविष्य निर्धारित करना होगा, बल्कि समानता और स्वतंत्रता के आधार पर देश का लोकतांत्रिक भविष्य भी निर्धारित करना होगा।

निवेशित रहें

भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों को अमेरिकी विदेश नीति में होने वाले बदलावों के अनुरूप नहीं बनाना चाहिए

ईरान के साथ 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर करके पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद भारत ने इस्लामी गणराज्य के साथ अपने बुनियादी ढांचे और व्यापार साझेदारी को अगले स्तर पर ले लिया है। भारत चाबहार के शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह और संबंधित परियोजनाओं में अपने टर्मिनल को और विकसित करने के लिए 120 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा और 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि, सौदे पर हस्ताक्षर होने के बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाली संस्थाओं को "इस बात से अवगत होने की आवश्यकता है कि वे खुद को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के लिए खोल रहे हैं"। अतीत में, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने परियोजना में देरी की थी। 2003 में परिकल्पित, इस परियोजना ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेहरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगाने के बाद वर्षों तक काम नहीं किया।

भारत ने 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जब वाशिंगटन ने उस वर्ष के परमाणु समझौते के बाद ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दी थी, और 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका के एकतरफा हटने और ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से तेहरान के साथ भारत के निरंतर सहयोग पर सवाल उठे। लेकिन भारत अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट पाने में कामयाब रहा, जिससे उसे तदर्थ उपायों के माध्यम से बंदरगाह का संचालन करने की अनुमति मिल गई।

चाबहार बंदरगाह भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह पाकिस्तान को दरकिनार करके अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जिससे मध्य एशिया के साथ बेहतर व्यापार संभव हो पाता है।
और, चाबहार को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (NSTC) से जोड़े जाने की उम्मीद है, जो भारत को ईरान, अज़रबैजान और रूस के माध्यम से यूरोप के करीब लाएगा। स्वेज मार्ग के विकल्प के रूप में, एक पूरी तरह से चालू NSTC अंतर-महाद्वीपीय व्यापार पर खर्च होने वाले समय और धन को कम करेगा। यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जहाँ चीन अपने BRI के हिस्से के रूप में एक बंदरगाह विकसित कर रहा है, इससे भारत को मध्य एशिया में अपने भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी।

लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान के साथ अपनी दुश्मनी के कारण अमेरिका ने इस परियोजना के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। इस क्षेत्र में अमेरिका के हित भी बदल गए हैं। 2018 में, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक सरकार का समर्थन कर रही थी, तो उसने भारत को प्रतिबंधों में छूट दी थी क्योंकि काबुल को भी बंदरगाह परियोजना से लाभ मिलने वाला था। आज, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर है, तालिबान ने इस्लामिक रिपब्लिक की जगह ले ली है, और अमेरिका का ध्यान ईरान को नियंत्रित करने पर है। भारत ने अतीत में वाशिंगटन डीसी में नीतिगत बदलावों के आधार पर ईरान के साथ अपने जुड़ाव में यू-टर्न लिया था। इसे अब ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे चाबहार में निवेश करना जारी रखना चाहिए और मध्य एशिया के साथ अपने व्यापार और संपर्क परियोजनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो भारत के निरंतर विकास के लिए आवश्यक है।

भारतीय उच्च शिक्षा का अति-राजनीतिकरण

मैं भारतीय उच्च शिक्षा हमेशा से ही राजनीतिक रही है। राजनेताओं ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय शुरू किए और समर्थन जुटाना। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कभी-कभी राजनीतिक रूप से लाभप्रद स्थानों पर नए पोस्ट सेकेंडरी संस्थान स्थापित किए। उनमें से कई की स्थापना विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के आधार पर मतदाताओं की मांगों को पूरा करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालयों का नामकरण और पुनर्नामकरण, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा, अक्सर राजनीति से प्रभावित होता है।

फिलिप जी. अल्टबाक

प्रतिष्ठित है बोस्टन कॉलेज, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा केंद्र में फेलो

अकादमिक नियुक्तियाँ या पदोन्नति कभी-कभी प्रोफेसर, कुलपति या प्रिंसिपल की गुणवत्ता के अलावा अन्य कारणों से की जाती थीं। और, विशेष रूप से कई स्नातक कॉलेजों में, अकादमिक स्वतंत्रता के मानदंडों का हमेशा दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता था - और शिक्षक जो पढ़ाते या लिखते थे उसमें सावधानी बरतते थे।

फिर भी, कुल मिलाकर, भारतीय उच्च शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन किया गया।

आम तौर पर, प्रोफेसरों को अपने विचारों के लिए अनुशासन या दंड के भय के बिना पढ़ाने की स्वतंत्रता थी।
वे स्वतंत्र रूप से शोध करने और अपने काम को प्रकाशित करने तथा सार्वजनिक मंचों और मीडिया में बोलने और लिखने में सक्षम थे। विश्वविद्यालय, अक्सर नौकरशाही में उलझे रहते थे, कभी-कभी संकाय सदस्यों की भर्ती में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों का सामना करते थे। हालाँकि, जब मौजूदा संकाय की पदोन्नति की बात आती थी, तो उन्हें सापेक्ष स्वायत्तता प्राप्त थी।

मौलिक राजनीतिक परिवर्तन यह कहना उचित है कि भारतीय उच्च शिक्षा मौलिक रूप से राजनीतिक हो गई है। यह शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षणिक पेशे और आम तौर पर बौद्धिक जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है। इन प्रवृत्तियों को, निश्चित रूप से, समाज में आम तौर पर "अनुदारवादी" प्रवृत्तियों के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है - और, निश्चित रूप से, भारत इन विकासों में अकेला नहीं है।

और, किसी समय, भारत के संभावित अकादमिक साझेदारों सहित शेष विश्व, अकादमिक क्षेत्र में इस गिरावट को नोटिस करेगा, और यह उस समय उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जब भारत वैश्विक उच्च शिक्षा के शीर्ष स्तरों में शामिल होना चाहता है।

शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षणिक पेशे और सामान्य रूप से बौद्धिक जीवन के लिए गंभीर खतरा है

बदलाव के उदाहरण कुछ समय पहले, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने राजनीतिक रूप से नियुक्त कुलपतियों के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं- और उन्हें काफी आलोचना मिली थी। लेकिन तथ्य यह है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अधिकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को राजनीतिक रूप से लचीले नियुक्तियों से बदल रहे हैं, जिनमें से कई के पास उच्च शिक्षा का बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है। और, ये नियुक्तियां राजनीतिक रूप से संबद्ध संकाय और अन्य परिवर्तनों के माध्यम से विश्वविद्यालयों को नया रूप दे रही हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में यह पहली बार है कि अकादमिक में इस तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आम हो गया है। यह इतना गंभीर है कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब में गैर-भाजपा सरकारें राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य के राज्यपालों को हटाने की कोशिश कर रही हैं, जो उन्हें कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति देता है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता पर भी हमला हो रहा है।
शायद सबसे भयावह पहलू यह है कि स्व-सेंसरशिप आम हो गई है, खासकर सामाजिक विज्ञान और मानविकी में। यहां तक कि वरिष्ठ शिक्षाविद भी ऐसे काम को प्रकाशित करने से डरते हैं जो उन्हें लगता है कि राज्य के अधिकारियों या भाजपा समर्थक मीडिया से उनके लिए समस्याएँ पैदा कर सकता है। ऐसे कई व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए मामले हैं जहाँ जाने-माने प्रोफेसरों ने विवादास्पद सामग्री प्रकाशित की है और उनके विश्वविद्यालयों ने उन्हें संरक्षित नहीं किया है। यह बताया गया कि 2021 में अशोका विश्वविद्यालय को दिए अपने त्यागपत्र में, प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक प्रताप भानु मेहता ने लिखा था कि स्वतंत्रता और सभी नागरिकों के लिए समान सम्मान के संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करने की कोशिश करने वाली राजनीति के समर्थन में उनके सार्वजनिक लेखन को विश्वविद्यालय के लिए जोखिम भरा माना गया था।

अपनी स्वतंत्रता के लिए जाने जाने वाले प्रतिष्ठित पत्रिकाओं पर सीमाएं लग गई हैं। सच्चाई यह है कि ये दबाव शीर्ष स्तर पर भी महसूस किए जा रहे हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की संकाय सदस्य प्रोफेसर समीना दलवई को हाल ही में दक्षिणपंथी समूहों द्वारा चलाए गए ऑनलाइन बदनामी अभियान का सामना करना पड़ा, साथ ही उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई।

यहां तक कि छात्र भी कैंपस के राजनीतिकरण में उलझ गए हैं। हाल ही में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने कथित "राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों" के लिए एक पीएचडी छात्र को निलंबित कर दिया।

हालांकि, प्रगतिशील छात्र मंच, जिसका नेतृत्व पूर्व में छात्र करता था, ने दावा किया कि उसका निलंबन केंद्र सरकार की "छात्र विरोधी नीतियों" के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लेने के कारण हुआ था।

बेशक, पारंपरिक परिसर की राजनीति जारी है, हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे दक्षिणपंथी संगठन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे पारंपरिक वामपंथी विश्वविद्यालयों में भी अतीत की तुलना में अधिक सक्रिय हैं।

लेकिन नई बात यह है कि छात्र अपने प्रोफेसरों की शिकायत कैंपस प्रशासन से कर रहे हैं, अगर वे उनकी कक्षाओं की विषय-वस्तु से असहमत हैं। और, कभी-कभी, इसके कारण संकाय सदस्यों को अनुशासित किया जाता है।

ये प्रवृत्तियाँ भारतीय उच्च शिक्षा और सामान्यतः नागरिक जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी समाज के लिए एक स्वतंत्र और मुक्त शैक्षणिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक पेशे को बिना किसी बाधा के शोध में शामिल होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपनी अकादमिक विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रकाशित करने और बोलने की क्षमता होनी चाहिए। यह "सॉफ्ट साइंस" के लिए उतना ही सच है जितना कि STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों के लिए। यह विशेष रूप से भारत में मामला हो सकता है, जहां कई शीर्ष बुद्धिजीवी और विश्लेषक विश्वविद्यालयों में हैं।

इसके अलावा, चूंकि भारत विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों का निर्माण करना चाहता है तथा विश्व भर के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ना चाहता है, इसलिए शैक्षणिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता एक आवश्यक शर्त है।

संपादक के नाम चिठी

एक अवैधता
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए, वरिष्ठ पत्रकार प्रबीर पुरकायस्थ पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, इस आधार पर कि उन्हें गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित नहीं किया गया था।

कानून के पवित्र सिद्धांतों को सही रूप से सुदृढ़ किया है।
यह संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन था और यह आश्चर्यजनक है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अवैधता को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत को यह नहीं भूलना चाहिए था।
लागत लागू करें क्योंकि यह एक था

एजेंसी द्वारा संवैधानिक चूक। भविष्य में, यदि किसी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया जाता है, तो अदालतों को जुर्माना लगाना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह भी समय है कि यूएपीए को कानून से हटा दिया जाए
कितावें. बोलने का अधिकार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुमूल्य अधिकार है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए।

एनजीआर प्रसाद, चेन्नई

अद्वितीय फुटबॉलर
शीर्ष फुटबॉलर और पूर्व खिलाड़ी का फैसला
भारतीय टीम के कप्तान,

सुनील छेत्री के संन्यास लेने से भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक के शानदार करियर का अंत हो जाएगा। ('स्पोर्ट' पेज, 17 मई)। छेत्री को प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ गोल करते हुए देखना बहुत ही आनंददायक था।
रक्षा और गोल स्कोर,

कई बार तो अकल्पनीय कोणों से भी। भारत को फुटबॉल में महान प्रतिभाओं का आशीर्वाद मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छेत्री खेल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की इस सूची में जगह पाने के हकदार हैं।

सी.वी. अरविंद, बेंगलुरु

सेमी वाईके

एम एनडी-एनडीई

Machine Translated by Google

mp

EDITORIAL

उच्च नोट पर समापन

सुनील छेत्री के रूप में एक युग का अंत

2026 फीफा विश्व कप क्वालीफायर में अंतिम बार राष्ट्रीय जर्सी 6 जून 2024 को भारतीय फुटबॉल में होगा-

छेत्री की विरासत को किसी विशेष युग से जोड़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने भारत की दो बिल्कुल अलग फुटबॉल पीढ़ियों के बीच सेतु के रूप में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी साख अमर कर दी है। पिछली सदी में पैदा हुए फुटबॉल प्रेमियों के लिए छेत्री बाइचुंग भूटिया के बाद की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदी में पैदा हुए लोगों के लिए निस्संदेह वे भारतीय फुटबॉल की धड़कन हैं। हालांकि "छेत्री के बाद कौन" वास्तव में एक कठिन सवाल है, लेकिन इसका जवाब फिर से उनकी प्रेरक विरासत और युग बदलने वाली उपलब्धियों और प्रयासों में निहित हो सकता है।

फुटबॉल की इस प्रतिभा ने सचमुच बहुत मेहनत की है यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय फुटबॉल चुनौतीपूर्ण समय में अपनी राह से भटक न जाए। उन्होंने भारत में खेल में पेशेवरपन लाया, फिटनेस, आहार और प्रतिबद्धता के लिए मानक स्थापित किए, जिसने अनगिनत युवा खिलाड़ियों के करियर को आकार दिया है। 2000 के दशक के मध्य में उनके उभरने से प्रशंसकों को निरंतरता और उम्मीद मिली। और अब यह पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि छेत्री ने किसी को निराश नहीं किया।

12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार डेब्यू के बाद, जहां उन्होंने भारत के लिए अपना पहला गोल किया, छेत्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, कुछ महीने पहले उनके मन में संभावित समापन का एहसास हुआ। आज तक, उन्होंने 150 मैचों में 94 गोल किए हैं, जिससे वे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर में तीसरे स्थान पर हैं, जो केवल दिग्गज लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं। संख्या के संदर्भ में, यदि कोई सर्वकालिक महान खिलाड़ियों पर विचार करे, तो छेत्री अभी भी ईरानी दिग्गज अली डेई के बाद चौथे स्थान पर रहेंगे, जिन्होंने 148 मैचों में 109 गोल किए हैं। संयोग से, छेत्री ने अपना अंतरराष्ट्रीय करियर मेस्सी के लगभग उसी समय शुरू किया था और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो साल बाद। एक चीज जो अली डेई, मेस्सी और रॉन-एल्डो को एक तरफ और छेत्री को दूसरी तरफ अलग करती है, वह है उन देशों की फुटबॉल परंपरा जहां से वे आते हैं।

भले ही छेत्री को तुलनात्मक समर्थन और माहौल न मिला हो, लेकिन उन्होंने भारत में फुटबॉल की साख बढ़ाने में अपनी सारी प्रतिभा, धैर्य, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का निवेश किया है। इस लिहाज से, वे अपने आप में एक अग्रणी हैं।

एक सफल गोल स्कोरर होने के अलावा, उन्होंने उन्होंने एक ऐसे नेता की भूमिका निभाई जिसने टीम को हर मुश्किल परिस्थिति में संभाला। उन्होंने भारत को एएफसी चैलेंज कप, सैफ चैंपियनशिप, नेहरू कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जैसे टूर्नामेंटों में जीत दिलाई। उनका नेतृत्व पिछले साल सैफ चैंपियनशिप में भारत की जीत में सबसे हाल ही में स्पष्ट हुआ, जहां उनका निर्णायक प्रदर्शन एक बार फिर सामने आया।

भारत अब मैदान पर छेत्री के बिना भविष्य की तैयारी कर रहा है, उम्मीद है कि उनका प्रभाव अन्य तरीकों से खेल को आकार देना जारी रखेगा। चाहे कोचिंग के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो या मेंटरशिप के माध्यम से हो, छेत्री का अनुभव और दूरदर्शिता भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद कर सकती है। उनका संन्यास एक अध्याय का अंत है, लेकिन उनकी विरासत निस्संदेह अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। सुनील छेत्री को विदाई देते हुए, हम न केवल एक फुटबॉलर का जश्न मनाने का लुत्फ़ उठाते हैं, बल्कि एक सच्चे आइकन का भी, जिनके भारतीय फुटबॉल में योगदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा।

मुद्रास्फीति के विरुद्ध तैयारी

भारत में व्याप्त 'आय' और 'आर्थिक' असमानताओं के मद्देनजर नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति के खिलाफ संकुचनकारी उपायों का सहारा लेने के अलावा लोगों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करने पर भी विचार करना चाहिए।

केडीपी राव

खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनियमित उतार-चढ़ाव से भविष्य में अनिश्चितताएं पैदा हो सकती हैं

10 मई को जारी खुदरा मुद्रास्फीति एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले मार्च में 4.85 प्रतिशत से 4.83 प्रतिशत - मामूली गिरावट (0.01 प्रतिशत)। हालांकि , खाद्य मुद्रास्फीति मार्च में 8.52 प्रतिशत से बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई, जबकि सब्जी मुद्रास्फीति मार्च में 28.30 प्रतिशत से घटकर 27.80 प्रतिशत हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति, जो अक्टूबर 2021 में 1 प्रतिशत से कम थी , जनवरी 2022 तक कुल मिलाकर 5.4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.9 प्रतिशत हो गई। वर्तमान में, अनाज और दालों - भारतीयों का मुख्य आहार - की मुद्रास्फीति दर क्रमशः 8.63 प्रतिशत और 16.84 प्रतिशत दर्ज की गई है। आरबीआई को संदेह है कि हालांकि दिसंबर 2023 में मुख्य मुद्रास्फीति अपने चरम से कम हो जाएगी , लेकिन खाद्य कीमतों की अनिश्चित चाल भविष्य के लिए अनिश्चितताओं का कारण बन सकती है । मुद्रास्फीति हमेशा कामकाजी वर्ग और निम्न आय वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करती है , क्योंकि उनकी आय सीमित होती है।

> खाद्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि इससे संरचनात्मक मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जो लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, जिससे घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं, ईंधन, बिजली आदि की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

हाल का अतीत.

सैद्धांतिक रूप से, मुद्रास्फीति के सबसे सामान्य कारण हैं: डिस्पोजेबल आय में वृद्धि और क्रय शक्ति में वृद्धि जिसे मांग खींच मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है, उच्च ईंधन लागत (कच्चा तेल) वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करती है जिसे लागत धक्का मुद्रास्फीति कहा जाता है (जो कि भारतीय संदर्भ में ज्यादातर सच है), मजदूरी वृद्धि और परिणामस्वरूप निर्माताओं द्वारा वस्तुओं की उच्च कीमत (अंतर्निहित मुद्रास्फीति), और अचानक युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान । हालांकि, स्थानीय और वैश्विक दोनों कारक मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के अनिरबन भट्टाचार्य और प्रणय राज के अनुसार (www.thewire.in 29 सितंबर 2023), जब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और ओपेक देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती से दुनिया भर में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि हुई , असंगठित क्षेत्र, जो देश के लगभग 85 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है, परिवारों के लिए भोजन के प्रावधानों पर अधिकतम खर्च और बेरोजगारी की स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर प्रभावी तरीके से इसका समाधान नहीं किया गया तो मुद्रास्फीति भविष्य में अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से अस्थिर कर सकती है , हालांकि जरूरी नहीं कि यह उस पैमाने पर हो जैसा कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ हुआ था।

दिसंबर 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है, जबकि शुद्ध बचत 5 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर आ गई है । हालांकि, कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति की मौजूदा दर 4.83 है

यह दर आरबीआई की 2-6 प्रतिशत की 'सहनशीलता सीमा' के अंतर्गत है।

खाद्य मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि इससे संरचनात्मक मुद्रास्फीति हो सकती है जो लगभग सभी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेगी , जिससे घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी।

माल, ईंधन, बिजली, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाएँ। शेयर बाजार का तेजी से बढ़ता प्रदर्शन वास्तव में भविष्य में संभावित आर्थिक संकट को नहीं दर्शाता है क्योंकि भावनाएँ बुनियादी बातों से ज़्यादा मुद्रा बाज़ार को प्रभावित करती हैं । इसी तरह, सरकारी आँकड़े भी ग़रीब और कमज़ोर वर्गों से जुड़ी ज़मीनी हकीकत को सही तरह से नहीं दर्शाते हैं जो शूटिंग के बीच अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।

यूएनडीपी के अनुसार, यहां तक कि देश में महंगाई दर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है क्योंकि वेतन को कभी भी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, 2021 और 2023 के बीच निर्माण श्रमिकों और कृषि श्रमिकों के वेतन में क्रमशः केवल 10.5 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अनाज की कीमतों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोतीलाल ओसवाल द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से तर्कों की पुष्टि होती है , जिसमें पता चला है कि घरेलू ऋण का स्तर बढ़ गया है।

वे हर दिन खाना नहीं जुटा सकते।

दुनिया भर में सरकारें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक रूप से हस्तक्षेप करती हैं , लेकिन भरोसा करने के लिए कोई एक सिद्ध तरीका नहीं है । परंपरागत रूप से, केंद्रीय बैंक उधार लेने को हतोत्साहित करने और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए संकुचनकारी मौद्रिक नीतियों का सहारा लेते हैं । आरबीआई ने लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखा, जैसा कि 5 अप्रैल को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा घोषित किया गया था । हालांकि, विकासशील देशों में जहां वित्तीय समावेशन एक बड़ी चुनौती है, इस प्रकृति के व्यापक आर्थिक उपायों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

विकसित देशों में, जैसा कि विश्व आर्थिक मंच के लिए इप्सोस सर्वेक्षण से पता चला है , 25 प्रतिशत लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। ब्रिटेन में, सात में से एक वयस्क ने कहा कि विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन रिपोर्ट के अनुसार डेटाबेस 2017, हालांकि 80 प्रतिशत भारतीय वयस्कों के पास बैंक है विश्व में निष्क्रिय खातों में भारत का हिस्सा सबसे अधिक है। सबसे अधिक 48 प्रतिशत है, जबकि विकासशील देशों का औसत 25 प्रतिशत है।

यूबीएस के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल डोनोवेन ('द ट्रुथ अबाउट इन्फ्लेशन' के लेखक) के अनुसार, सरकारें वास्तव में कुछ नहीं कर सकतीं, क्योंकि तेल या खाद्यान्नों की कीमतों में अचानक बदलाव नहीं किया जा सकता, उसी तरह जैसे वे यूक्रेन के प्रभाव को प्रभावित नहीं कर सकते।

भारत में भी संकुचनकारी मौद्रिक नीति के अलावा खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों पर युद्ध।

हालांकि, उनका सुझाव है कि सरकारें या तो उन लाभों पर विचार कर सकती हैं जो लोगों को उच्च कीमतों पर मदद करने के लिए दिए जा रहे हैं , या जहां किसी चीज़ पर कर लगाया जा रहा है। कुछ देशों ने संकुचनकारी मौद्रिक नीतियों के अलावा लोगों को सीधे सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। फ्रांस ने एकमुश्त सहायता देने के लिए 13 बिलियन यूरो खर्च किए आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के प्रत्येक लाभार्थी को 84 यूरो का अनुदान , बिजली पर करों में कमी और ऊर्जा बिलों में वृद्धि को 4 प्रतिशत तक सीमित करना। जर्मनी ने निम्न आय वर्ग के लिए सब्सिडी की घोषणा की और पेट्रोल और डीजल पर करों में भी कटौती की ।

अन्य उपायों में शामिल हैं: प्रति व्यक्ति 300 यूरो का एकमुश्त अनुदान , सार्वजनिक परिवहन पर छूट और बाल कल्याण अनुदान आदि। इटली ने 14 अरब यूरो की ईंधन सब्सिडी की घोषणा की और करों में भी वृद्धि की

बिजली कम्पनियाँ ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से लाभान्वित हो रही हैं।

स्पेन ने तीन महीने के लिए 300 किलोमीटर तक मुफ्त रेल यात्रा की अनुमति दी है जबकि जर्मनी ने 9 अमेरिकी डॉलर मासिक सार्वजनिक परिवहन पास शुरू किया। स्कॉटलैंड में, नागरिकों को जीवन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करने के लिए किराए को स्थिर कर दिया गया । ब्रिटेन 8 मिलियन कम आय वाले परिवारों को 780 अमेरिकी डॉलर का सीधा भुगतान और 480 अमेरिकी डॉलर का ऊर्जा अनुदान दे रहा है।

इस संदर्भ में, हम यूरोपीय देशों के प्रयोगों का अनुकरण करते हुए लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। लोगों को सीधे सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाते समय , अमर्त्य सेन द्वारा 'आय असमानताओं' और 'आर्थिक असमानताओं' के बीच अंतर को ध्यान में रखना भी आवश्यक है; जबकि पूर्व में मजदूरी असमानताओं को संदर्भित किया जाता है, बाद में लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि जैसे कारकों के कारण असमान अवसरों का मतलब है । आर्थिक असमानताओं से पीड़ित लोग मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं ।

नकद सहायता, सार्वजनिक परिवहन पर छूट , संचार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, प्रवासी मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लोगों को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद कर सकती हैं। जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रथाओं को रोकने के लिए वितरण तंत्र को पुनर्जीवित करके सुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है । ग्रामीण आबादी की आय सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा जैसी चल रही रोजगार सृजन योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। अंत में, कृषि क्षेत्र और किसानों के मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मानसून आने वाला है । मुश्किल समय में बंपर फसल वरदान साबित होगी।

लेखक छत्तीसगढ़ के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं।

व्यक्त किए गए विचार निजी हैं

जलवायु परिवर्तन, क्या?

चुनाव का मौसम भीषण गर्मी में चल रहा है, लेकिन बार-बार चरम जलवायु परिदृश्यों के बावजूद मतदाता अभी भी जलवायु जवाबदेही की मांग नहीं कर रहे हैं

शुतापा पॉल

जो हमारे बीच रहते हैं. वहाँ शरणार्थी हैं

उन्होंने हिंसा के कारण अपना घर खोया है। वे बेहतर जीवन की तलाश में छिद्रपूर्ण सीमाओं के पार से नहीं आए हैं , बल्कि ये हमारे अपने हैं , जिन्होंने अपरिहार्य आपदाओं के कारण अपने घर खो दिए हैं।

जलवायु परिवर्तन की ताकत। 2023 में बाढ़, भूकंप, तूफान और अन्य आपदाओं के कारण भारत में पाँच लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए । 2022 में यह संख्या 2.5 मिलियन थी। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इन चरम जलवायु घटनाओं में से कई को ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे-जैसे हम एक और पर्यावरण दिवस के करीब पहुँच रहे हैं और नेक हरित उद्देश्य के लिए दिखावटी सेवा दे रहे हैं, जान लें कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आती है या उसे बनाए रखती है, उसके पास कोई कार्य योजना नहीं होती है।

> वर्ष 2023 में भारत में बाढ़, भूकंप, तूफान और अन्य आपदाओं के कारण पाँच लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे

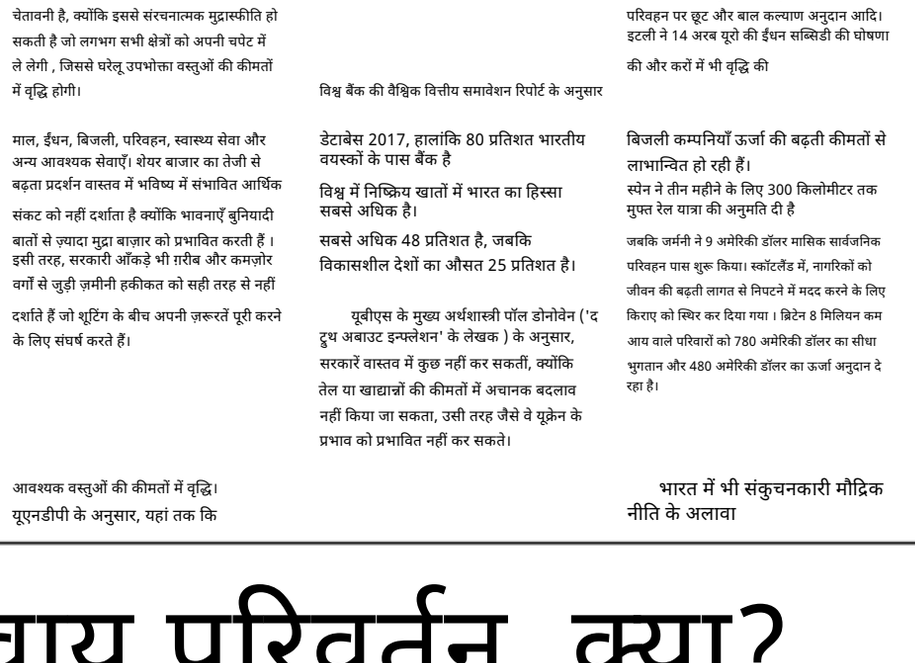

मतदाता के रूप में, भारतीय राष्ट्र के सामने सबसे बड़े संकट - जलवायु परिवर्तन - को नजरअंदाज कर रहे हैं

राजनीतिक दल बिना किसी विशेष विवरण के विस्तृत योजनाएँ पेश करते हैं, हालाँकि, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुवर्ती कार्रवाई शायद ही अन्य क्षेत्रों की तरह उत्साहपूर्ण हो। भाजपा के घोषणापत्र में 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, अगले 6 वर्षों में अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के 500 गीगावाट लक्ष्य को छूने और एक नई प्रतिबद्धता की बात कही गई है । देश को "मौसम के लिए तैयार" और "जलवायु के प्रति स्मार्ट" बनाने के लिए 'मौसम' नामक राष्ट्रीय वायुमंडलीय मिशन शुरू करने की बात कही। इस बीच कांग्रेस के घोषणापत्र में मौजूदा सरकार की कई जलवायु प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया गया है , जिसमें एक " स्वतंत्र" पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी शामिल किया गया है । प्राधिकरण, पर्यावरण मानकों को ट्रैक करने और लागू करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएँ लागू करने के लिए । शायद ही किसी अन्य राजनीतिक दल ने जलवायु परिवर्तन को कोई महत्व दिया हो । मतदाताओं के रूप में, हमने इसकी मांग नहीं की है ।

चुनाव के मौसम के चरम पर (कई राज्य थे) और भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं), यह विडम्बना है कि मतदाता के रूप में हम जलवायु पर प्रतिबद्धता की मांग नहीं करते हैं

बदलाव। एक मतदाता के रूप में, हम रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़ चुके हैं , ऐसा नहीं है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम समुदाय -वार प्रजनन दर, चमकदार, विचलित करने वाली वस्तुओं जैसे अधिक लुभाए जाते हैं

सेलेब्स के फर्जी राजनीतिक समर्थन और उन ब्रांडों की रद्द संस्कृति का प्रचार जो पर्याप्त रूप से भारतीय नहीं लगते। हम देश के सामने सबसे बड़े संकट - जलवायु परिवर्तन - से चूक रहे हैं ।

इस पर विचार करें - ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार , पिछले तीन दशकों में, दुनिया भर में गर्मी की लहरों के कारण होने वाली सभी मौतों में से पाँचवाँ हिस्सा भारत में हुआ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान सभी ने जलवायु से संबंधित विस्थापन की सूचना दी है । जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) की रिपोर्ट के अनुसार , विस्थापन में मुख्य रूप से एल नीनो प्रभाव के कारण कमी आई है , हालाँकि, बाढ़ और तूफान ने अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में लोगों को विस्थापित किया है ।

सच्चे भारतीय अंदाज में हम आज में जीते हैं, जुगाड़ करते हैं

जब हालात मुश्किल हो जाएं, तो एक राष्ट्र के तौर पर हमारी लचीलेपन की प्रशंसा करें । जलवायु संबंधी आपातस्थितियां इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर भारतीय क्षत्रप जलवायु संबंधी चुनौतियों के प्रति सचेत नहीं हैं, तो वे जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाएंगे।

यदि ऐसा हुआ तो हमारे क्षेत्र को क्रूरतापूर्वक दंडित किया जाएगा।

लेखक एक लेखक और मीडिया उद्यमी हैं।

व्यक्त किए गए विचार निजी हैं

प्रिय संपादक

एक स्वागत योग्य विकास

यह समाचार रिपोर्ट, "सुप्रीम कोर्ट: अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता" और "फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण स्वागत योग्य है" के संदर्भ में है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि जब कोई आरोपी समन के अनुसरण में न्यायाधीश के समक्ष पेश होता है, तो एजेंसी को उसकी हिरासत प्राप्त करने के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा। यह फैसला ईडी के लिए एक और झटका है, जो हाल के महीनों में गहन न्यायिक जांच के दायरे में रहा है और विपक्षी दलों द्वारा बार-बार उस पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। इन दलों, विशेष रूप से आप ने दावा किया है कि उनके नेताओं को सत्तारूढ़ दल के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में कोई अपवाद नहीं बनाया गया था। पीठ ने कहा, "हमने अपने आदेश में वही कहा जो हमें उचित लगा।" साथ ही कहा कि फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण स्वागत योग्य है। ये टिप्पणियां अदालत द्वारा ईडी से श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में पूछे जाने के दो सप्ताह बाद आई हैं - लोकसभा चुनावों से ठीक पहले। स्पष्ट रूप से, ईडी को एक के बाद एक मामलों में बहुत कुछ स्पष्ट करना होगा।

— खोकन दास, कोलकाता, ईमेल द्वारा

millenniumpost.in

संपादक को पत्र लिखने के लिए लॉग ऑन करें अथवा उन्हें letter2editor.mp@gmail.com पर भेजें । आप अपनी टिप्पणियाँ संपादक, प्रताप भवन, 5 बहादुर शाह सहस्राब्दि डाक, जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 को भी भेज सकते हैं।

Machine Translated by Google

The Statesman
शामिल करना और सीधे उतरना
द फ्रेंड ऑफ इंडिया से - स्थापित 1818

चाय संकट

जैसे ही सूरज तराई की पहाड़ियों पर डूबता है और डुआर्स के मैदान, लंबी छाया डालते हुए हरे-भरे चाय बागानों पर एक खामोश संकट
सतह के नीचे की सच्चाई सामने आती है। चाय उद्योग, जो कभी
क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की आधारशिला, अब
प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
मौसम की स्थिति। लंबे समय से चल रहा सूखा
अक्टूबर 2023 की शुरुआत में खराब वर्षा वितरण के साथ, इस क्षेत्र पर अनिश्चितता की छाया पड़ गई है।
डुआर्स और तराई में चाय की खेती का भविष्य
क्षेत्रों में उत्पादन आधा हो जाएगा और व्यवहार्यता को खतरा होगा
बागानों की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाते हुए नीलामी की कीमतें भी कम हो रही हैं।

उत्पादन कर रहे हैं। इस संकट के मूल में एक महत्वपूर्ण तथ्य छिपा है
फिर भी अक्सर अनदेखा किया जाने वाला समाधान: सिंचाई। जबकि चाय
उत्तर बंगाल के उद्यानों में हरियाली का विशाल विस्तार है
हरियाली, वर्षा पर उनकी निर्भरता, जो अक्सर
अनियमित, उन्हें प्रकृति की सनक के प्रति संवेदनशील बनाता है।
अब समय आ गया है कि चाय बागान मालिक और प्रबंधन इस पर ध्यान दें।
सिंचाई में निवेश की तत्काल आवश्यकता को पहचानना
बुनियादी ढांचे को विलासिता के रूप में नहीं, बल्कि उनके लिए जीवन रेखा के रूप में
उद्यानों में सिंचाई के बुनियादी ढांचे की मौजूदगी के बावजूद, सिंचाई की क्षमता

पूरा बगीचा सीमित रहता है। सिंचाई उपकरण कुल क्षेत्रफल का केवल एक अंश ही कवर करने में सक्षम हैं
एक ही दिन में पूरे क्षेत्र में चाय की झाड़ियों को पानी देने का प्रयास
अक्सर सब बेकार हो जाता है। जब तक अंतिम भाग समाप्त होता है
सिंचित, पहले सिंचित क्षेत्र लंबे समय से सूख चुके हैं
जिससे पूरा प्रयास व्यर्थ हो गया।

यदि बड़े क्षेत्रों की सिंचाई के लिए पर्याप्त सिंचाई उपकरण उपलब्ध हो तो प्रबंधन द्वारा उसमें निवेश करने में अनिच्छा।
एक संपूर्ण उद्यान नहीं, बल्कि इसमें शामिल लागतों से उपजा है।
1,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।
शुष्क अवधि या अपर्याप्त वर्षा की अवधि के दौरान।
हालांकि, जैसा कि कहावत है, "दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक कष्ट।" प्रारंभिक निवेश कठिन लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ लागत से कहीं अधिक हैं।

एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां चाय बागानों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
अप्रत्याशित मौसम पैटर्न की दया पर।
मजबूत सिंचाई बुनियादी ढांचा मौजूद है, चाय उत्पादक
फसलों को पोषण देने के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है,
यहां तक कि सबसे सूखे मौसम में भी। बारिश पर निर्भरता अतीत की बात हो जाती है, और उसकी जगह एक ऐसी भावना आ जाती है जो
प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सुरक्षा और लचीलापन। लेकिन
सिंचाई के लाभ सिर्फ़ पानी की आपूर्ति से कहीं ज़्यादा हैं। मिट्टी में नमी का इष्टतम स्तर बनाए रखने से,
सिंचाई से झाड़ियों का समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता बढ़ सकती है, जिससे अधिक उपज और बेहतर उत्पादन हो सकता है।
चाय की पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा, सिंचाई से कीटों के संक्रमण का जोखिम कम हो सकता है, जिससे महंगे कीट नियंत्रण उपायों की ज़रूरत कम हो सकती है और लंबे समय में खेती की स्थिरता की रक्षा हो सकती है।

वर्तमान की चुनौतियों का सामना करें, हार न मानें
एक उज्जवल भविष्य के वादे की दृष्टि। उपजाऊ में
उत्तर बंगाल की धरती पर, आइये बदलाव के बीज बोएं,
और एक समृद्ध और टिकाऊ चाय उद्योग की फसल काटें।

हत्या की कोशिश

स्लोवाक प्रधानमंत्री पर हत्या का प्रयास रॉबर्ट फिको राजनीतिक स्थिरता की कमजोरी की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं, यहां तक कि उन देशों में भी जहां
राजनीतिक हिंसा दुर्लभ है। इस घटना ने न केवल
स्लोवाकिया पर लंबी छाया, लेकिन लहरें भी भेजता है
यूरोप भर में, अक्सर आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए
समकालीन लोकतंत्रों में सुरक्षा और राजनीतिक असहमति की प्रकृति के बारे में। तथ्य यह है कि हमलावर
71 वर्षीय पूर्व सुरक्षा गार्ड और लेखक थे,
आम तौर पर इसे ख़तरे के तौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन यह एक परेशान करने वाली सच्चाई को रेखांकित करता है: सामाजिक विभाजन और राजनीतिक कुंठाएँ व्यक्तियों को चरमपंथी कार्रवाइयों की ओर ले जा सकती हैं।
हमें इन विभाजनों की गहराई पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है और
वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए उपलब्ध रास्ते। प्रधानमंत्री फिको, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे देश पर अपना दबदबा बना लिया है
पिछले दो दशकों से स्लोवाक राजनीति में ध्रुवीकरण करने वाले नेता रहे हैं। उनकी हालिया नीतियों में बदलाव देखने को मिला है
यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस समर्थक रुख अपनाने और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को कम करने का प्रयास
उपायों ने न केवल घरेलू बहस को तेज कर दिया है
लेकिन स्लोवाकिया के यूरोपीय संघ और नाटो साझेदारों को भी चिंता में डाल दिया है। यह राजनीतिक माहौल, जहां महत्वपूर्ण नीति
तीव्र सार्वजनिक जांच और विरोध के बीच होने वाले बदलाव, तनाव को बढ़ाने के लिए मंच तैयार करते हैं।
गोलीबारी को न केवल एक व्यक्ति पर हमले के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले के रूप में भी देखा जाना चाहिए।
स्लोवाकिया। जब राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जाता है, तो यह हिल जाता है
लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद,
भय और अनिश्चितता पैदा करना। यह सामान्य जीवन को बाधित करता है
राजनीतिक विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया,
जैसा कि संसद के तत्काल निलंबन से देखा जा सकता है
बहस को स्थगित करने और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकाश में, नए सिरे से वकालत करना महत्वपूर्ण है
नागरिक संवाद और जोरदार तरीके से प्रतिबद्धता
राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में हिंसा को अस्वीकार करें। राजनीतिक असहमति, चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अवश्य होनी चाहिए
बातचीत के ज़रिए और कानून और लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम किया जाना चाहिए।
स्लोवाक सरकार
और इसके नेताओं को, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, आगे आना होगा
जनता को आश्वस्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक संपर्क को बाधित किए बिना सभी राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए जाएं,

पहुँच.

इस घटना को भी उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए
स्लोवाक समाज के व्यापक मुद्दों को संबोधित करना,
सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास का क्षरण भी शामिल है
भ्रष्टाचार से निपटने और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता है।
विश्वास का पुनर्निर्माण
यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे विभाजनकारी या सत्तावादी उपायों के माध्यम से नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिको और

हमले की निंदा सार्वभौमिक भावना को दर्शाती है
लोकतांत्रिक मानदंडों और सामूहिकता के प्रति सम्मान
उन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी। यह देखकर खुशी होती है
वैश्विक नेता हिंसा के खिलाफ एकजुट हुए,
लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में एकजुटता की आवश्यकता को बल मिलता है। चूंकि स्लोवाकिया इस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि सभी हितधारक

एक ऐसा माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां राजनीतिक भागीदारी सुरक्षित, सम्मानित और रचनात्मक हो।

संग्रहालय की कहानियाँ~I

सर आशुतोष मुखर्जी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को रेखांकित किया, अर्थात्, प्रतिष्ठित
ज्ञान के उन्नयन के महान कार्य में भारतीय संग्रहालय द्वारा निभाई गई भूमिका।
जैविक और भूवैज्ञानिक महत्व को कम आंकना कठिन होगा
हमारे अधिकारियों द्वारा कड़ी मेहनत से अनुसंधान किया गया, हालांकि यह किसी भी तरह से आसान नहीं था
प्राणिविज्ञान के मामले को छोड़कर, ऐसे कार्य के लिए श्रेय का सटीक हिस्सा आवंटित करें
भारतीय संग्रहालय को सरकार के संबंधित वैज्ञानिक विभागों से अलग रखा गया है।

28 नवंबर 1913 को न्यायमूर्ति सर आशुतोष मुखर्जी, अध्यक्ष के ट्रस्टियों की
कलकत्ता स्थित भारतीय संग्रहालय में उद्घाटन भाषण दिया गया।
की पहली शताब्दी मनायी जा रही है
संग्रहालय। उनका पता प्रपत्र
'भारतीय' का पहला अध्याय
संग्रहालय 1814-1914', एक स्मारक खंड प्रकाशित

एक संस्था के लिए जो एक
संग्रहालयों के बीच मील का पत्थर
भारत. 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय
संग्रहालय दिवस, यह उचित ही है
सर आशुतोष जैसे कई पीढ़ियों के पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करना
जो विरासत को संरक्षित करने के लिए जिए,
खुद इतिहास बनाते हुए
उनके जीवनकाल के दौरान.

"इतिहास की सराहना करने के लिए
की उत्पत्ति और विकास
भारतीय संग्रहालय," सर ने समझाया
आशुतोष, "हमें वापस यात्रा करनी चाहिए
अठारहवीं सदी की आखिरी तिमाही
सदी में जब भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ,

इस प्रांत के सर विलियम जोन्स,
सबसे प्रखर विद्वानों में से एक,
जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया
भारत की सेवा, की स्थापना की
1784 में एशियाटिक सोसाइटी, और
साहस जो उनकी प्रतिभा की विशेषता थी, ने कहा कि

इसकी जांच की सीमाएं
भौगोलिक सीमाएँ होंगी
एशिया के, और इनके भीतर
सीमाएँ, इसकी पूछताछ होगी
मनुष्य द्वारा किया गया या उत्पादित जो कुछ भी है, उस तक विस्तारित
प्रकृति।" 1808 तक, एशियाई
सोसायटी को स्थायी परिसर की तलाश थी क्योंकि उसकी
जमा पूंजी बढ़ती जा रही थी।

राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया
पार्क स्ट्रीट के कोने पर.

सर आशुतोष ने जीवंत कर दिया
आकर्षक डॉ हेनरी वालिच, एक
डेनिश वनस्पतिशास्त्री को बंदी बनाया गया
लेकिन सेरामपुर की घेराबंदी पर
उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के सम्मान में जारी किया गया। 1814 में, डॉ.
वालिच ने एशियाटिक सोसाइटी को पत्र लिखकर एक
संगठन के गठन की वकालत की थी।
संग्रहालय और "न केवल की पेशकश की
मानद क्यूरेटर के रूप में कार्य करने के लिए लेकिन
इसके अलावा डुप्लिकेट की आपूर्ति करने के लिए
अपने बहुमूल्य संग्रह को
एक नाभिक का निर्माण करें। प्रस्ताव
के साथ तत्पर स्वीकृति मिली
समाज और यह निर्धारित किया गया था
एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी जिसे दो भागों में
विभाजित किया जाएगा: एक जो
अब इसे पुरातात्विक, नृवंशविज्ञान और तकनीकी कहा जाएगा,
और अन्य भूवैज्ञानिक और
प्राणिविज्ञान."

डॉ. वालिच ने कर्नल स्टुअर्ट, डॉ. टाइटलर, जनरल मैकेंजी, ब्रायन हॉजसन, कैप्टन डिलन और बाबू रामकमल सेन जैसे संग्रहकर्ताओं को प्रेरित किया, जिन्होंने आसानी से इसमें योगदान दिया।
समाज के विभिन्न भागों से एकत्रित दिलचस्प और
जिज्ञासापूर्ण वस्तुओं का निपटान

देश में 1836 में,

वित्तीय समस्याओं की भरमार और
सोसायटी ने सरकार को धन के लिए पत्र लिखा। सर
एडवर्ड रयान,
सोसायटी के अध्यक्ष, और
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
न्यायालय ने संग्रहालय के लिए समर्थन जुटाने में अग्रणी भूमिका निभाई,
रखरखाव और वेतन
क्यूरेटर और कीपर्स.

उनके जीवन में क्या घटित हुआ?
पत्राचार आज तक प्रासंगिक और सत्य है। "एक
संग्रहालय की स्थापना नहीं की जा सकी

स्वैच्छिक सदस्यता न ही
विश्वसनीय और में बनाए रखा
उपयोगी शर्त आवश्यक है
वस्तु की प्राप्ति
वांछित, जब तक कि उदारतापूर्वक सहायता न दी जाए
सरकार भी इसी प्रकार
यूरोप में इसी प्रकार की संस्थाओं
जनता से समर्थन मिला
कोषागार।" डॉ. जेटी पियर्सन, डॉ.
मैक्लेलैंड, एडवर्ड ब्लीथ:
नामों की सूची
के माध्यम से जारी है
19वीं सदी के रूप में
एशियाई सोसायटी
संग्रह के साथ बढ़ी जो भी

जरूरतों को प्रतिबिंबित किया
औपनिवेशिक काल का एक
आर्थिक भूविज्ञान संग्रहालय

स्थापित और बड़े
नमूनों का बहुमूल्य संग्रह

जमा किये गये
1840 से आगे-डी.एस. यह एक
विरोधाभास है
औपनिवेशिक राज्य का जबकि
यह था
व्यापार, वाणिज्य के माध्यम से
प्रांतों को बेरहमी से अधीन करना, उनका शोषण करना,

और क्रूर युद्धों के अलावा, यह महान लोगों को सशक्त
भी बना रहा था
सीखना और समर्पण
संस्थाएं स्थापित करें.

1857 के विद्रोह और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत पहले, सोसायटी एक स्वतंत्र भारत संघ की स्थापना के लिए अपील कर रही थी।

इंपीरियल संग्रहालय; इसमें लगभग
एक दशक बाद, 1866 तक भारतीय
संग्रहालय अधिनियम लागू किया गया।
"का बहुमूल्य संग्रह
सोसायटी, के दौरान संचित
उत्साही सदस्यों की लंबी उत्तराधिकारिता द्वारा आधी सदी से
औपचारिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया
श्रीमान, जिसके न्यासी मंडल में
बार्न्स पीकॉक, जो उस समय बंगाल के मुख्य
न्यायाधीश थे, को नियुक्त किया गया।
राष्ट्रपति महोदय," सर आशुतोष ने कहा
उनका पता। यह 1875 तक था कि
संग्रहालय अब अस्तित्व में नहीं रहा
एशियाटिक सोसाइटी की संपत्ति
बंगाल और बदल गया था
एक शाही संस्था में और
संग्रहालय भवन बन गया
शहर में सबसे बड़ा में से एक.

1880 के दशक और उसके प्रारम्भिक वर्षों में
1900 के दशक में संग्रहालय का नेतृत्व डॉ.
जॉन एंडरसन, श्री जेम्स वुड-
मेसन, सर थॉमस हॉलैंड, श्री
थर्स्टन, डॉ. वाट और सर हर-

बर्ट रिस्ले। नई दीर्घाएँ बनाई गईं
खोला गया और संग्रहालय
प्राणिविज्ञान और नृवंशविज्ञान, भूवैज्ञानिक, कला,
औद्योगिक और पुरातत्व में विभाजित। पुरातत्व संग्रह
जल्द ही जनरल के साथ केंद्र मंच पर कब्जा कर लिया

अलेक्जेंडर कनिंघम को बढ़त
श्रेष्ठता, अपनी छाप छोड़ना
20वीं सदी के विकास पर.
"हम उसे हटाने के लिए ऋणी हैं और
भरत स्तूप का संरक्षण
रेल, अब सबसे बेहतरीन और
सबसे दिलचस्प मौजूदा अवशेष
प्रारंभिक भारतीय वास्तुकला," कहा गया
सर आशुतोष अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।
एशियाई लोगों द्वारा उधार दिए गए सिक्कों का व्यापक
अमूल्य संग्रह
सोसायटी द्वारा निर्मित कैटलॉग
श्री सी.जे. रॉजर्स, श्री विंसेंट
स्मिथ और श्री नेल्सन राइट
राजा सर
सौरिन्द्र मोहन टैगोर का भारतीय साहित्य का संग्रह

राजू
मनसुखानी

लेखक इतिहास और इतिहास पर लेखक-शोधकर्ता हैं।
विरासत के मुद्दे, और एक पूर्व
के उप क्यूरेटर
प्रधानमंत्री संग्रहालय

संगीत वाद्ययंत्रों की प्रस्तुति की गई

संग्रहालय. जा रहे हैं
आगे सर आशुतोष
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को
रेखांकित किया, "अर्थात्,

विशिष्ट भाग
भारतीय संग्रहालय द्वारा लिया गया
इस महान कार्य का
की उन्नति
ज्ञान प्राप्त करना कठिन होगा।

अधिक आंकलन करना
का महत्व
हमारे अधिकारियों द्वारा
जैविक और भू-वैज्ञानिक अनुसंधान कठोरता से किया जाता है, यद्यपि यह
किसी भी तरह से असाइन करना आसान नहीं था,
प्राणि विज्ञान के मामले को छोड़कर,
इस तरह के ऋण का सटीक हिस्सा
भारतीय संग्रहालय को सौंपे गए कार्य
सरकार के संबंधित वैज्ञानिक विभागों से अलग। इसे
बनाए रखा जा सकता है,

बिना किसी विरोधाभास के जोखिम के
सभी शोध कार्य न केवल
प्राणि विज्ञान और भूविज्ञान में भी बल्कि
मौसम विज्ञान और पुरातत्व,
अब अलग-अलग लोगों द्वारा किया जा रहा है
सरकारी विभागों पर बकाया
इसकी उत्पत्ति बंगाल की एशियाई सोसायटी की गतिविधियों में हुई है।
और अनुप्रयुक्त विज्ञान की जांच, विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान
और रसायन शास्त्र की उत्पत्ति भी लगभग ऐसी ही थी।'' सर आशुतोष के अनुसार
जो जीवंत है उसे संबोधित करें
एक शताब्दी पहले एक छोटा सा समूह
के अध्ययन में लगे विद्वान
इतिहास, भाषा और पुरावशेषों ने एक ऐसी नींव रखी

कलकत्ता में संग्रहालय, पूरी तरह से
सीमित निजी साधनों के साथ
उनका निपटान; यह कैसे हुआ
सत्ताधारी अधिकारियों को तीस साल तक
अपनी जिम्मेदारियों का एहसास
इस दिशा में.

क्या भारतीय संग्रहालय ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है? सर आशुतोष से-

जवाब के लिए झुके, "यह अब है
आम तौर पर यह माना जाता है कि
संग्रहालय एक संस्था है
उन वस्तुओं का संरक्षण
जो प्रकृति की घटनाओं और कार्यों का सबसे अच्छा चित्रण करते हैं
मनुष्य, इनके उपयोग के लिए
ज्ञान की वृद्धि में,
और लोगों की संस्कृति और ज्ञान-प्राप्ति के लिए। एक
राष्ट्रीय या शाही संग्रहालय को, परिणामस्वरूप, तीन
प्रमुख कार्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित
होना चाहिए: पहला,

नमूनों का संचयन और संरक्षण जैसे कि फॉर्म

ज्ञान का भौतिक आधार
कला और विज्ञान में; दूसरे, इस प्रकार एकत्रित नमूनों की
व्याख्या और जांच के लिए और प्रसार के लिए

इसके लिए आवश्यक ज्ञान;
और तीसरा, लोगों को जगाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना
जनता के हित और
उनकी शिक्षा को बढ़ावा दें।"

उन्होंने संतुष्टि के साथ कहा, "जहां तक इनमें से
पहले दो कार्यों का संबंध है, भारतीय संग्रहालय के पास इन्हें
स्थगित करने का कोई कारण नहीं है।"

खुद को दोषी मानना। लेकिन मुझे खेद है
निराशा की भावना के साथ स्वीकार करता हूँ कि जब मैं
जांच करता हूँ
भारतीय संग्रहालय का इतिहास
अपने तीसरे पक्ष के दृष्टिकोण से
एक संभावित शक्तिशाली के रूप में कार्य करें
निर्देश के लिए साधन
मैं यह नहीं कह सकता कि जनता
सफलता का पूर्ण मापदंड है
हासिल किया गया है। संग्रहालय
सबसे पहले, इसे एक के रूप में माना जा सकता है
कक्षा कक्ष के सहायक और
व्याख्यान कक्ष; दूसरे रूप में
सूचना ब्यूरो; और
तीसरा, एक संस्था के रूप में
लोगों की संस्कृति।"

सर आशुतोष का भाषण, सभी पीढ़ियों के लिए
एक आह्वान,
टिप्पणी की, "यदि हम किसी को कुछ देना चाहते हैं,
उन्नत या पेशेवर
छात्र, सामग्री, और प्रयोगशाला प्रशिक्षण के लिए अवसर;
यदि हम
प्राथमिक, माध्यमिक या तकनीकी ज्ञान के शिक्षक को
अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के सिद्धांतों को समझाने में
सहायता करने की इच्छा

कला, प्रकृति और इतिहास; हमारे वैज्ञानिक कर्मचारियों
को भौतिक रूप से सक्षम होना चाहिए
मजबूत...आकर्षक प्रदर्शनी-श्रृंखला के प्रदर्शन के माध्यम
से, अच्छी तरह से योजनाबद्ध, पूर्ण

और सटीक रूप से लेबल किया गया है और इस प्रकार
प्रोत्साहित करने और व्यापक बनाने के लिए
जो लोग नहीं हैं उनके मन
मैं विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान में संलग्न हूँ।
फलस्वरूप इसकी तत्काल आवश्यकता पर बल देने की
इच्छा
हमारी सार्वजनिक दीर्घाओं में सुधार।" सर आशुतोष के शब्द

25 जनवरी को, कालातीत ज्ञान की शताब्दी मनाने के
लिए भी यह एक उपयुक्त अवसर है।

मई, इस के निधन के
शिक्षाविद्-असाधारण विधिवेत्ता.

(जारी है)

एक सदस्य की ANN ASIA NEWS NETWORK

एशियाई आवाज़ें

अपनी बात पर कायम रहें

राजनीतिक दल ~ सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ताकतें
सात प्रमुख संगठनों के वरिष्ठ नेता
~ ने रविवार को देश की प्रगति के लिए अधिकतम प्रयास करने का स्पष्ट सामूहिक संकल्प लिया।

निवेश और कारोबारी माहौल।
नेपाली कांग्रेस महासचिव
गगन थापा, सीपीएन-यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल, सीपीएन (माओवादी)
केंद्र) उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल,
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगडेन, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी

मुख्य सचेतक संतोष परियार, सीपीएन (एकीकृत समाजवादी) महासचिव
घनश्याम भूसल और जनमत
पार्टी अध्यक्ष सीके राउत ने अपनी बात रखते हुए कहा
कांतिपुर में संबंधित पार्टियों के विचार
आर्थिक शिखर सम्मेलन-2024 में राजनीतिक ताकतों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया
और अन्य हितधारकों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना
निवेश आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अभी दो सप्ताह पहले ही शीर्ष
प्रधानमंत्री सहित देश के नेता
मंत्री पुष्प कमल दहल, मुख्य
विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा
नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली,
प्रमुख गठबंधन सहयोगी सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ने दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा
निवेश शिखर सम्मेलन, प्रतिबद्ध
नेपाल को एक नए राष्ट्र में बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
निवेश के अनुकूल गंतव्य। नेपाल को विशाल निवेश वाले देश के रूप में प्रस्तुत करना
संभावित रूप से, नेताओं ने 1,600 से अधिक प्रतिनिधियों के समक्ष वादे किए
सरकार द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में 55 देशों से भागीदारी हुई।

घरेलू के साथ-साथ विदेशी की भी जरूरत
प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक ताकतों के निवेश और संयुक्त राजनीतिक प्रतिबद्धताओं
अपने आप में एक सकारात्मक संकेत है। हालाँकि यह
नेपाल के राजनेताओं ने
बार-बार ऐसे वादे किए

THE KATHMANDU POST

लेकिन उन्हें अनुवाद करने में असफल रहे
परिणाम। इसके लिए, नेपाल को अभी भी राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता और पूर्वानुमेयता की आवश्यकता है। विभिन्न देशों ने

जबरदस्त प्रगति की है तब भी जब
सरकारी नेतृत्व में अस्थिरता है। उन्होंने विकास गतिविधियों को राजनीति से अलग रखकर और नीति की पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करके ऐसा किया,

भले ही इसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हों
सरकारों की एक बड़ी चिंता
व्यापार जगत के प्रतिनिधि
कानपुर-तिरुवल्लूर आर्थिक शिखर सम्मेलन में व्यक्त की गई प्रतिक्रिया भी यही थी।
उन्होंने कहा कि वास्तविक निवेशक नीतिगत पूर्वानुमेयता को एक पूर्वापेक्षा के रूप में चाहते हैं
एक बड़ा निवेश करने से पहले.
यह एक वैध चिंता है और नीति
निर्माताओं को इतना तो सुनिश्चित करना ही होगा।

फिर भी सरकार और हमारे राजनेताओं की पहल अधिक प्रतीत होती है
वास्तविक से ज़्यादा सतही। बस आगे
निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने एक विधेयक पारित कर कुछ अधिनियमों में संशोधन किया।
कानूनी जटिलताओं को दूर करने के लिए अध्यादेश
निवेश के लिए सरकार की मंशा यह धारणा बनाने की थी कि

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के समक्ष
नेपाल इस मुद्दे पर गंभीर है
विदेश से धन प्राप्त करना। लेकिन अध्यादेशों को पहले सत्र में पेश नहीं किया जा सका
शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है

मुख्य विपक्ष की बाधा
नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद संसद में गतिरोध की स्थिति बन गई है।
सत्ताधारी और विपक्षी दल एकमत हैं
संसदीय पैनल पर आमना-सामना
उप प्रधान मंत्री की जांच और
गृह मंत्री रबी लामिछाने।

मंत्री पर कई सहकारी धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है।
सदन में मुख्य न्यायाधीश द्वारा बाधा उत्पन्न की गई
पहली बार की गई मांग पर विरोध
शीतकालीन सत्र में जारी रहा
यहां तक कि शुरू होने के बाद भी
10 मई को बजट सत्र। अगर हमारी राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ नहीं आ सकतीं
राष्ट्रीय बजट पारित करने के लिए,
विदेशियों के लिए हम पर भरोसा करना कठिन होगा
उनका धन।

एक मृत व्यक्ति की स्मृति में लिखा मृत्युलेख

कुतु दासगुप्ता — (जन्म - 18-05-1999, मृत्यु - 20-05-1999) — कुटू
सोना, तुम्हारे 25वें जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार। - माँ और बाबा।

संपादक के नाम चिठी

editor@thestatesman.com

संबंधों को बढ़ावा देना

महोदय, भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
समुद्री और वाणिज्यिक विजय
का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर
चाबहार बंदरगाह को 10 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया है।
इसे विदेश में अपनी पहली यात्रा बताया जा रहा है
परियोजना जो सुचारू होने की संभावना है
अफगानिस्तान, ईरान और के साथ संबंध
पश्चिमी यूरोपीय देश।

जबकि दोनों के बीच आम सहमति है
भारत और ईरान के बीच विकास पर चर्चा
चाबहार बंदरगाह पर पहुंचा गया।
2003, थोड़ी प्रगति हुई
पिछले कुछ वर्षों में वाशिंगटन और तेहरान के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं।

वैश्विक परिदृश्य और दोष रेखाएं
हाल ही में इजरायल-हमास युद्ध के मद्देनजर उभरने वाले

दिल्ली का पुनर्निर्माण और पुनर्संतुलन
ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना। इस पृष्ठभूमि में, चाबहार में हाल ही में एक टर्मिनल का संचालन शुरू किया गया है।
के बीच हुए समझौते के आधार पर
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीसी) और

ईरान के बंदरगाहों और समुद्री संगठन में 10 वर्षों तक काम करना हमारी क्षमताओं का दोहन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
बुनियादी ढांचे और व्यापार क्षमताओं। यह माल और
सेवाओं का निर्बाध हस्तांतरण भी प्रदान करेगा

पारगमन समय में कमी और कटौती
माल ढुलाई लागत में अनुमानित 30% की वृद्धि
प्रतिशत। अमेरिका और पश्चिमी
शक्तियों को चाबहार पर विचार करना चाहिए
सुरक्षा वाल्व के रूप में पोर्ट का उपयोग
चीन के साम्राज्यवादी मंसूबे।
भारत से भी सहयोग की उम्मीद
मध्य एशिया के साथ इसके संबंध,
पश्चिम एशिया, अफ्रीका और भारतीय
महासागरीय देश। तेहरान को मिलेगा
अपने अंडे देने का अवसर
बीजिंग की तुलना में अधिक टोकरियों में
अकेला।

आपका, आदि, विजय सिंह अधिकारी,
नैनीताल, 17 मई।

परमाणु विकल्प

महोदय, मैं आज प्रकाशित आपके संपादकीय "पावर डेफिसिट" का संदर्भ दे रहा हूँ। यदि भारत को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो
इसकी शक्ति की कमी और जीआरई को कम करना
एनहाउस गैस उत्सर्जन, परमाणु
शक्ति को इस मिश्रण का हिस्सा होना चाहिए।
पवन और सौर ऊर्जा पर्याप्त रूप से लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगी।
केवल तभी उत्पादन करें जब सूर्य चमक रहा हो और हवा चल रही हो।
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर या एसएमआर
कम बिजली पैदा करने की क्षमता रखते हैं
कार्बन ऊर्जा, के बराबर
150 से अधिक तटवर्ती पवन टर्बाइन लगभग
यह एक पारंपरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल के आकार का दसवां हिस्सा है।
छोटे, सस्ते और अधिक
पहले के डिजाइनों की तुलना में अधिक सुरक्षित।

यदि हम पूर्णतः विद्युत चालित होना चाहते हैं
और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त करना,
परमाणु ऊर्जा अवश्य लानी चाहिए
परमाणु ऊर्जा में ऊर्जा घनत्व का लाभ है, जो एक वास्तविकता है
कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
पहुंचाया नहीं जा सकता।

वर्तमान में हमारे पास कोई कुशल, किफायती ऊर्जा भंडारण तकनीक नहीं है और कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा है।
क्षितिज। परमाणु ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है
जीवाश्म ईंधन का विकल्प। दुनिया भर में लगभग 54
रिएक्टर निर्माणाधीन हैं; 23 चीन में हैं। भारत का रिकॉर्ड मजबूत है

परमाणु सुरक्षा के दिनों से
पंडित नेहरू ने जब डॉ.
होमी भाभा को भारत का सबसे महान योद्धा कहा जाता है।
ओपेनहाइमर को परमाणु ऊर्जा मिशन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। भारत तेजी से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है।
प्रजनक, एक कम प्रदूषणकारी परमाणु
थोरियम जैसे स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करके रिएक्टर प्रौद्योगिकी
जिसकी हमारे पास प्रचुरता है।

थोरियम परमाणु रिएक्टरों के लिए एक आदर्श
वैकल्पिक ईंधन है, और
हम आयात पर निर्भर नहीं हैं।
भारत में प्रतिभा, कौशल और
विशेषज्ञता, स्वच्छ सुरक्षा रिकॉर्ड
और निर्माण, रखरखाव के लिए प्रौद्योगिकी
और परमाणु संयंत्रों का संचालन करेंगे।

आपका, आदि, एच.एन. रामकृष्ण,
बेंगलुरू, 14 मई।

ऑडिट बिलबोर्ड

महोदय, मुंबई में 50-60 किलोमीटर की तेज हवाएं चलीं, जिसके कारण सोमवार को एक विशाल होर्डिंग गिर गया और 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 88 लोग घायल हो गए। यह घटना सभी नगर निगमों और स्थानीय निकायों के लिए चेतावनी है।
देश में सभी निकाय। सरकारों को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी बिलबोर्डों की सुरक्षा ऑडिट का आदेश देना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में
शहरों और राजमार्गों पर ऐसी कई अनाधिकृत या अवैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई संरचनाएं हैं।

यह लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि किसी भी लापरवाही से नागरिकों के जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए संघ
सरकार को स्थानीय निकायों को यह भी निर्देश देना चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि
सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता है.

आपका, आदि, रमेश जी जेठवानी, बैंगलोर, 15 मई।

Perspective

The Statesman
नई दिल्ली, शनिवार 18 मई 202407

शनिवार का साक्षात्कार

दक्षिणी राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ेंगी

प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी 1991 में भगवा ब्रिगेड में शामिल हुए। वे पार्टी में रैंक और फ़ाइल के माध्यम से आगे बढ़े और एक गंभीर व्यक्ति की प्रतिष्ठा हासिल की।

उत्तर

समझदार आदमी.

मुरादाबाद के जाट चौधरी योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में शामिल रहे और 2022 में उन्हें भाजपा की राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

वर्तमान में वह राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं।

द स्टेट्समैन के मनोज भद्र ने मृदुभाषी नेता से चल रहे लोकसभा चुनावों और चुनावी प्रक्रिया के चार चरणों के पूरा होने के बाद भाजपा की संभावनाओं के बारे में बात की।

मोदी जी और योगी जी द्वारा गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए किए गए कार्यों के कारण पार्टी ने जनता का जो विश्वास अर्जित किया है, वह इसी का परिणाम है।

अंश:

प्रश्न: 2024 के आम चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या आपकी पार्टी का 'अबकी बार, 400 पार' नारा व्यावहारिक है?

उत्तर: 2014 (लोकसभा) चुनावों में भाजपा ने समाजवादी पार्टी (सपा) और राज्य के अन्य राजनीतिक दलों को करारी शिकस्त दी थी। यह सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा और हम 400 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करेंगे। पार्टी को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।

देश में भाजपा के पक्ष में स्पष्ट लहर है, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी भाजपा को चुनकर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे।

जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो लोग खुद ही भाजपा को सभी सीटें जिता रहे हैं।

प्रश्न: विपक्षी भारतीय ब्लॉक और उसके सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भाजपा सरकार पर कई मोर्चों पर, खासकर बेरोजगारी और महंगाई पर विफलता का आरोप लगा रहे हैं। आप इसका जवाब कैसे देंगे?

जवाब: विपक्ष बिना किसी ठोस सबूत के बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन विपक्ष को इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता उन्हें 'शून्य' सीटें देगी।

प्रश्न: सपा ने हाल ही में कहा कि केंद्र में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की होगी। आपकी टिप्पणी?

जवाब: वे दिवास्वप्न देख रहे हैं। सरकार बनाने की बात तो दूर, वे एकजुट भी नहीं हैं। जब उनके गठबंधन के साथी पहले से ही एक-दूसरे के खिलाफ हैं, तो मतदाता उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?

जिनके पास मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं, वे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं।

वे (सपा) पश्चिम-उत्तर प्रदेश लहर की बात करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि पश्चिम से पूर्व तक एक ही लहर है और वह है 'मोदी लहर'।

अखिलेश कन्नौज और मैनपुरी भी हार रहे हैं।

प्रश्न: समाजवादी पार्टी अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदान प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाती रही है। इसने इस गड़बड़ी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

उत्तर: सपा अपनी हार की जमीन तैयार कर रही है और वोटिंग मशीनों को दोष दे रही है। पिछले चार चरणों में जिन सीटों पर मतदान हुआ, वहां सपा नेताओं ने 'खराब' ईवीएम का शोर मचाया है। मुझे यकीन है कि 4 जून को नतीजे आने पर वे सभी 400 सीटों की ईवीएम को खराब कहेंगे। सपा हारेगी, यह भाजपा की गारंटी है।

प्रश्न: भाजपा ने विकास और राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पर चुनाव अभियान शुरू करने के बाद अचानक हिंदू-मुस्लिम, सनातन धर्म और अल्पसंख्यक आरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर लिया।

यह परिवर्तन क्यों?

उत्तर: हम कभी भी अपने मुद्दों और एजेंडे से नहीं भटके हैं। हमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के घोषणापत्र में शामिल मुद्दों को उठाना है। हमें मतदाताओं को इन (विपक्षी) दलों द्वारा बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाने और अपमानित करने की साजिश के बारे में जागरूक करना है।

भाजपा नेताओं के बयान को सांप्रदायिक कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी दलों ने अल्पसंख्यक आरक्षण को मुद्दा बनाकर विवाद की शुरुआत की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातन का अपमान किया है। ये देश और यूपी को पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं होने देगा।

राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को हटाना, तीन तलाक और सीएए जैसे मुद्दे भाजपा नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार में उठाए हैं। हम अपने मुद्दों से नहीं भटके और जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रश्न: सपा योगी आदित्यनाथ सरकार की विफलताओं और उसके खोखले वादों की बात करती है। विपक्षी दल एनडीए के सत्ता में आने पर संविधान और लोकतंत्र को खतरा होने की बात भी कह रहा है। आपकी क्या टिप्पणी है?

उत्तर: जो लोग दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और खराब कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, वे आज यह जानकर हैरान हैं कि पुलिस की सक्रियता देखिए। यह हास्यास्पद है कि नकल माफिया को बढ़ावा देने वाले लोग पेपर लीक को लेकर चिंतित हैं।

उनके लिए विकास का मतलब अपने घर का विकास है, लेकिन हमारे लिए विकास का मतलब पूरे देश का विकास है, इसीलिए यूपी सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। ये डबल इंजन वाली सरकार का विकास मॉडल है।

प्रश्न: सभी राजनीतिक खिलाड़ी कम मतदान प्रतिशत को लेकर चिंतित हैं।
भाजपा इसका आकलन कैसे करती है और अधिकाधिक मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने के लिए वह क्या कर रही है?

उत्तर: पार्टी ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है कि वे अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ पर लेकर आएं। भाजपा की ताकत बूथ में है और हमें गर्व है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सिपाही हैं और हमारा बूथ किले की तरह मजबूत है।

हमने पन्ना प्रमुखों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक मतदाता से संपर्क करने और उनसे वोट देने का अनुरोध करने के लिए लगाया है। पार्टी के पोलिंग एजेंटों को भी निर्देश दिया गया है कि वे परिवार के प्रत्येक सदस्य को मोदी का गारंटी पत्र दें और उन्हें इसके बारे में समझाएं।

लेकिन गर्मी की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं और हम इस पर विचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत में गिरावट से चिंतित है और उसने भी कई कदम उठाए हैं।

भाजपा ने हर बूथ पर पिछली बार से 370 वोट अधिक जोड़ने की घोषणा की थी।

इजराइल-हमास साइबर युद्ध में नागरिकों की मौत

रयान शैंडलर,
डेफना कैनेटी और ताल
मिमरान

हमास युद्ध में इजरायली परिवारों के लगातार रॉकेट हमलों से भयभीत होकर घरों में दुबकने, इजरायली टैंकों और तोपों द्वारा गाजा पट्टी में इमारतों को ध्वस्त करने, सैकड़ों अपहृत बंधकों को भूमिगत सुरंगों में कैद करने और लड़ाई के कारण लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर करने की खबरें भरी पड़ी हैं।

इजराइल के बारे में खबरें

लेकिन आंतरिक हिंसा से परे युद्ध की एक छिपी हुई परत है - एक ऑनलाइन संघर्ष। हम साइबर युद्ध के विद्वान हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान हमास, इज़राइल और अन्य देशों और एक पक्ष या दूसरे का समर्थन करने वाले हैकिंग समूहों द्वारा किए गए विभिन्न साइबर ऑपरेशनों को सूचीबद्ध और विश्लेषित किया है। डेटा संघर्ष के एक अनदेखे पहलू की तस्वीर पेश करता है, और यह साइबर संघर्ष की प्रकृति के बारे में अधिक व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करता है।

हमने जो मुख्य निष्कर्ष निकाला है, वह यह है कि साइबर संघर्ष के परिणाम मुख्य रूप से नागरिकों द्वारा महसूस किए जाते हैं, न कि लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल सैनिकों या आतंकवादियों द्वारा। हम पाते हैं कि साइबर हमलों से डिजिटल सिस्टम को होने वाला नुकसान मनुष्यों को होने वाले नुकसान और हिंसा के बढ़ते चक्र से कहीं कम महत्वपूर्ण है।

इज़रायली सरकार और नागरिक प्रणालियों पर साइबर हमलों का मिला-जुला असर हुआ है। कुछ तकनीकी रूप से सरल हमलों से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिली, जिससे हमास के लड़ाकों को इज़रायल में घुसपैठ करने में मदद मिली।

अन्य हमलों में बिखरे हुए तरीके अपनाए गए, डिजिटल पहुंच के भीतर किसी भी चीज़ को निशाना बनाया गया - अस्पताल, विश्वविद्यालय, बैंक और समाचार पत्र। इन हमलों का कोई सैन्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य केवल इज़रायली जीवन को बाधित करना और जनता को आतंकित करना था।

हमलों की मात्रा और परिष्कार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान सरकार के लिए काम करने वाले हैकर्स, जो हमास के लिए एक प्रमुख वित्तपोषक और आपूर्तिकर्ता है, हमास के ऑनलाइन नेटवर्क का समर्थन कर रहे हैं।

युद्ध। सूडान, पाकिस्तान और रूस जैसे विभिन्न देशों में स्थित अन्य "हैक्टिविस्ट" और निजी हैकिंग समूह भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं।

7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए घातक आतंकी हमले से पहले, जिसने मौजूदा युद्ध को जन्म दिया, हमास के साइबर ऑपरेटिव हमले की योजना का समर्थन करने के लिए काम कर रहे थे। गाजा साइबरगैंग नामक हमास की हैकिंग इकाई ने इजरायली सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी की तलाश में इजरायल की जासूसी की।

हमले के दौरान उनसे प्राप्त जानकारी महत्वपूर्ण साबित हुई।

हमास के हैकरों ने फिशिंग हमले भी किए, जो अपेक्षाकृत सरल हमले थे, जिनमें नकली ईमेल या टेक्स्ट संदेश, वैध संदेशों के समान होते थे, तथा उपयोगकर्ता को या तो संवेदनशील जानकारी के साथ उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करते थे, या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते थे, जिससे उनके कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता था।

7 अक्टूबर के हमले के समय, फिलिस्तीन समर्थक हैक्टीविस्ट समूह एनोनघोस्ट ने एक मोबाइल ऐप जारी किया, जिसका नाम एक प्रमुख प्रतिष्ठित ऐप के समान था, जो इजरायली नागरिकों को इजरायल में हमास द्वारा किए जाने वाले हमलों के बारे में चेतावनी देता था।

एनोनघोस्ट ने झूठे अलर्ट जारी किए - जिनमें, कथित तौर पर, परमाणु हमले के बारे में एक अलर्ट भी शामिल था - और उपयोगकर्ताओं के डेटा एकत्र किए, जिनमें उनके संपर्क, कॉल लॉग और टेक्स्ट संदेश शामिल थे।

हालाँकि, जब से पूर्ण शत्रुता शुरू हुई है, हमास अपने युद्ध प्रयासों में सहायता करने वाले प्रभावी साइबर हमले करने में काफी हद तक असमर्थ रहा है।

परिणामस्वरूप, समूह ने सूचना युद्ध का सहारा लिया, तथा भय पैदा करने तथा जनमत बदलने का प्रयास किया।

हमास के साइबर योद्धाओं और उनके सहयोगियों द्वारा अब किया जाने वाला सबसे आम प्रकार का हमला वितरित सेवा निषेध है, जब निरर्थक इंटरनेट ट्रैफिक की बाढ़ एक या अधिक वेबसाइटों, ईमेल सर्वरों या अन्य इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों को लक्ष्य करके की जाती है।

वे निरर्थक ट्रैफिक से अभिभूत हो जाते हैं और या तो बंद हो जाते हैं या ठीक से काम करना बंद कर देते हैं।

समाचार मीडिया आउटलेट्स की वेबसाइटों पर सेवा अस्वीकार करने के हमले हुए हैं।

बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकारी एजेंसियाँ। एक हमले ने जेरूसलम पोस्ट की वेबसाइट को दो दिनों के लिए ऑफ़लाइन कर दिया। जिस समूह ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी, वह एक धार्मिक हैकटिविस्ट समूह था, जिसका नाम एनोनिमस सूडान था, जिसके रूसी हैकिंग समूहों से संबंध ज्ञात हैं।

हमास और उसके ऑनलाइन सहयोगी वाइपर मैलवेयर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंप्यूटर को संक्रमित करके उसके डेटा को नष्ट कर देता है। इस तरह के हमले का उद्देश्य जबरन वसूली या निगरानी करना नहीं है - इसका उद्देश्य बस अपने पीछे आने वाली हर चीज़ को नष्ट करना है।

हमने कई हमलों को भी दर्ज किया है, जिनमें डेटाबेस में घुसपैठ की गई और उनकी विषय-वस्तु को सार्वजनिक कर दिया गया, जैसे कि ओनो एकेडमिक कॉलेज के छात्रों का निजी डेटा ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया गया।

हमलों की एक और श्रृंखला ने इजरायल के आसपास के स्थलों पर फिलिस्तीनी ध्वज को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल बिलबोर्ड पर नियंत्रण कर लिया, साथ ही सैन्य हार के बारे में झूठी खबरें भी फैलाईं। ये हमले घरेलू बहस को आकार देने और इजरायली नागरिकों को आतंकित करने के लिए डिज़ाइन किए गए व्यापक गलत सूचना प्रयास का हिस्सा हैं।

हमास के विपरीत, इजराइल एक वैश्विक साइबर शक्ति है, जिसकी सेना के पास दुनिया की सबसे मजबूत साइबर युद्ध क्षमताएं हैं।

फिर भी इजरायल के साइबर शस्त्रागार की प्रभावशीलता सीमित है क्योंकि हमास इंटरनेट पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है।

डिजिटल युद्ध के मैदान पर हमला करने के लिए, इज़राइल की प्राथमिक रणनीति गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी को चालू या बंद करना रही है। वह ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि इज़राइल गाजा की सेवा करने वाली बिजली और इंटरनेट केबलों को नियंत्रित करता है।

27 अक्टूबर 2023 को, इज़राइल ने लगभग पूर्ण दूरसंचार ब्लैकआउट लागू किया जो लगभग 34 घंटे तक चला। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दूरसंचार ब्लैकआउट की निंदा की गई, जिसके महानिदेशक ने पोस्ट किया कि ब्लैकआउट ने "घायलों तक एम्बुलेंस का पहुँचना असंभव बना दिया।" इंटरनेट या टेलीफ़ोन कनेक्शन के बिना, गाजा में घायल फिलिस्तीनी लोग एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकते हैं, न ही चिकित्सा कर्मचारी अपने डिस्पैच केंद्रों से जुड़े रह सकते हैं।

उसके बाद से इसी तरह की इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं अक्सर होती रही हैं। नुकसान, विस्थापन और बिजली और इंटरनेट व्यवधानों के कारण गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य दर के 15 प्रतिशत तक कम हो गई है।

गाजा में जब इंटरनेट सेवा थी, तब इजरायल समर्थक हैकटिविस्ट सक्रिय हो गए थे। उदाहरण के लिए, WeRedEvils समूह ने गाजा नाउ समाचार साइट को क्रैश कर दिया। यू.एस. स्थित क्लाउडफ्लेयर के अनुसार, जैसे-जैसे शत्रुता बढ़ती गई, फिलिस्तीनी वेबसाइटों पर आने वाले सभी ट्रैफ़िक का 60 प्रतिशत तक सेवा-निषेध हमले ट्रैफ़िक से बना था।

डेटा-ट्रांसफर और ट्रैकिंग कंपनी।
अधिकांश हमले बैंकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों को लक्ष्य करके किये गये।

अमेरिका भी इसमें शामिल है। संघीय साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सुरक्षा एजेंसी कुछ साइबर हमलों को विफल करने में मदद करने के लिए इजरायल के साथ काम कर रही है।

साइबर युद्ध के हॉलीवुड चित्रण के विपरीत, जहाँ बिना रोक-टोक के हैकर एक बटन दबाकर पूरी सेना और देश को पंगु बना सकते हैं, साइबर शक्ति की वास्तविकता अधिक सीमित है। डिजिटल लड़ाइयाँ युद्ध नहीं जीत सकतीं। इज़राइल-हमास युद्ध में अधिकांश ऑनलाइन ऑपरेशनों का वास्तविक युद्धक्षेत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

इनमें जासूसी या दुष्प्रचार शामिल है, व्यापक विनाश नहीं।

हमारे डेटा से पता चलता है कि साइबर युद्ध से आतंकवादी समूहों को बड़ी शक्तियों का समान शर्तों पर सामना करने की क्षमता नहीं मिलती है। हमास के ऑनलाइन ऑपरेशन इजरायल की सैन्य श्रेष्ठता को कम करने में सक्षम नहीं हैं।

लेकिन इजरायल की ऑनलाइन क्षमताएं, एक बड़े पैमाने पर ऑफलाइन प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हैं।

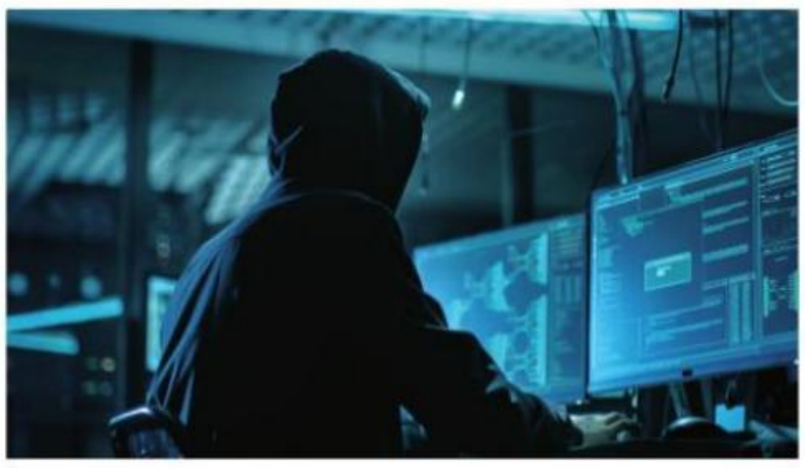

हालाँकि, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बार-बार पाते हैं कि युद्ध के दौरान साइबर हमलों के सबसे ज़्यादा शिकार नागरिक होते हैं। 10 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा लोगों के बीच किए गए हमारे प्रयोगों में, हमने देखा है कि साइबर हमले गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट पैदा करते हैं - यहाँ तक कि शारीरिक आतंकवाद से होने वाले नुकसान के समान। जब साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है, तो लोग फँसे हुए और चिंतित महसूस करते हैं, और उनकी सुरक्षा की भावना कम हो जाती है। नतीजतन, पीड़ित भड़क उठते हैं और इस तरह से कड़ी जवाबी कार्रवाई की माँग करते हैं जिससे हिंसा का चक्र और भी तेज़ हो जाता है।

इजराइल और हमास के बीच साइबर हमले लगातार जारी हैं, और निर्दोष लोग इस गोलीबारी में फंस रहे हैं। साइबर युद्ध का यह मानवीय पहलू ही वह खतरा है जो हमें चिंतित करता है।

(लेखक क्रमशः जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर हैं; हाइफा विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और ज़ेफ़त अकादमिक कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय कानून के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। यह लेख www.theconversation.com पर प्रकाशित हुआ था)

100 साल पहले

सामयिक नोट

कल हमारे स्तंभों में प्रकाशित विज्ञप्ति बजट के कुछ मदों को अस्वीकार करने के संबंध में बंगाल सरकार की मंशा का विवरण पूरा करती है। चिकित्सा विभाग को पहले की विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि एक हस्तांतरित विभाग होने के बावजूद, इसके कर्मचारियों के सदस्यों को आंशिक रूप से आरक्षित विभागों से संबंधित कर्तव्यों पर नियुक्त किया जाता है, जिसके संबंध में राज्यपाल-सभा पर निश्चित दायित्व लगाए जाते हैं।

अब यह अधिसूचित किया गया है कि जेल सेवा को जारी रखने के लिए कुछ नए पद सृजित करके तथा उन पर कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करके कदम उठाए जाएंगे जिनका वेतन स्वीकृत नहीं किया गया था, तथा सर्जन जनरल और अन्य अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यालय स्टाफ उपलब्ध कराकर कदम उठाए जाएंगे। इस तरह के कुछ उपाय निस्संदेह अपरिहार्य थे, लेकिन यह आशा की जानी चाहिए कि जब परिषद अगली बार बैठक करेगी तो उस निर्णय को पलटने का अवसर मिलेगा जिसने सरकार को इस कार्यवाही के लिए मजबूर किया है।

समाचार आइटम

चक्रवात ने रेलगाड़ी को हिला दिया

भयंकर क्षति ओले और मूसलधार बारिश

(एक संवाददाता से)

पिछले रविवार को पाकुड़ जिले में असाधारण तीव्रता का चक्रवात आया।

दोपहर करीब 3 बजे हवा चलनी शुरू हुई और 3-15 बजे तक इसकी गति 120 मील प्रति घंटे हो गई। बारिश शुरू हो गई और उसके साथ ओले भी गिरने लगे, कई मामलों में ओले मुर्गी के अंडे जितने बड़े थे और कुछ मामलों में तो मैंने जो नापा, वह गोलाकार थे, जिनका व्यास 2 इंच और मोटाई 1 इंच थी। छतें उड़ गईं, बड़े पेड़ उखड़ गए और स्थानीय बस्तियों में आधे से ज़्यादा घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। हवा की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए यह बताया जा सकता है कि यहां साइडिंग में खड़ी एक पूरी गिट्टी ट्रेन लाइन के साथ उड़ गई।

बारिश 1 इंच थी और पूरा तूफ़ान लगभग 40 मिनट में खत्म हो गया। विभिन्न बिंदुओं से रिपोर्ट बताती है कि लगभग सात या आठ लोग मारे गए और कई लोग बहुत बुरी तरह से कट गए और घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। तूफ़ान का क्षेत्र केवल 8 या 10 मील चौड़ा प्रतीत होता है, लेकिन इसके बाद जो विनाश हुआ वह भयावह है।

युद्ध की घोषणा

युद्ध की घोषणा श्री लॉयड जॉर्ज के आक्रामक भाषण के बाद हालात पहले जैसे नहीं रह सकते, जो युद्ध की घोषणा के बराबर है, जब तक कि लेबर पार्टी अपने तौर-तरीके नहीं बदलती। ऐसी अफ़वाहें हैं कि लिबरल पार्टी में श्री लॉयड जॉर्ज के खिलाफ़ विद्रोह हो गया है।

एस्क्विथ के नेतृत्व में। आधिकारिक तौर पर इसका खंडन किया गया है, और श्री लॉयड जॉर्ज ने इस खंडन पर जोर दिया है। लिबरल पार्टी में विद्रोह है, लेकिन, श्री लॉयड जॉर्ज के अनुसार, यह उन अपमानजनक परिस्थितियों के खिलाफ विद्रोह है, जिनके तहत पार्टी से सत्ता में बने रहने की उम्मीद की जाती है- "सरकार कभी भी उस (लिबरल) पार्टी के प्रति अपनी शत्रुता को नहीं छिपाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसे एक ऐसा अपराध मानती है जिसे देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।"

श्री लॉयड जॉर्ज, जो अभी भी एक महान शक्ति हैं, निश्चित रूप से इस अर्थ में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने सत्ता में लेबर के प्रति अपने भाषण में कुछ स्पष्ट घरेलू सच्चाइयों के साथ परंपराओं को तोड़ दिया है और लेबर के दावों की प्रदर्शनों से तुलना करने और यह इंगित करने में कि सरकार के कार्यक्रम में जो कुछ भी सही है वह पारंपरिक लिबरल विचारों को उधार लेने और अनुकूलित करने से ज्यादा कुछ नहीं है, लिबरल दृष्टिकोण से उनका यह कदम निश्चित रूप से उचित है। उनका विचार है कि लेबर जानबूझकर उन लोगों को अलग-थलग करने की कोशिश कर रही है जो सहयोग की उचित शर्तों की व्यवस्था होने पर उसके मित्र बनने के लिए तैयार हैं। बेशक यह कहा जाएगा कि श्री लॉयड जॉर्ज नेतृत्व को वापस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके शीघ्र ही श्री एस्क्विथ के हाथों से प्रकृति के क्रम में विफल होने की उम्मीद है।

सच तो यह है कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वे निस्संदेह स्वयं को आज की औसत उदारवादी भावना का वास्तविक प्रवक्ता बना रहे हैं।

आरोपी को आजीवन कारावास

दुर्ब-हंगा के जिला सत्र न्यायाधीश ने उस मामले का निपटारा किया जिसमें एक ग्रामीण की मौत के लिए उसके बेटे और भाई को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस मामले में गुदर, जुमन और पांच अन्य पर चुल्हाई नामक ग्रामीण की हत्या का आरोप लगाया गया था।

गुदर और जुमन क्रमशः चुल्हाई के भाई और बेटे थे। मामले के तथ्य यह थे कि चुल्हाई और जुमन के बीच मतभेद के कारण पिता ने अपने बेटे को विरासत से वंचित कर दिया। जुमन ने अपने चाचा गुदर की मदद ली, जो अपने भाई चुल्हाई के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रखता था। पिछली 15 जनवरी को चुल्हाई और जुमन के बीच किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और उस रात, यह आरोप लगाया गया कि सभी सात आरोपियों ने चुल्हाई की बेरहमी से हत्या कर दी।

सत्र न्यायाधीश ने जूरी से सहमति जताते हुए मृतक के बेटे और भाई सहित छह आरोपियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

क्रॉसवर्ड

29783

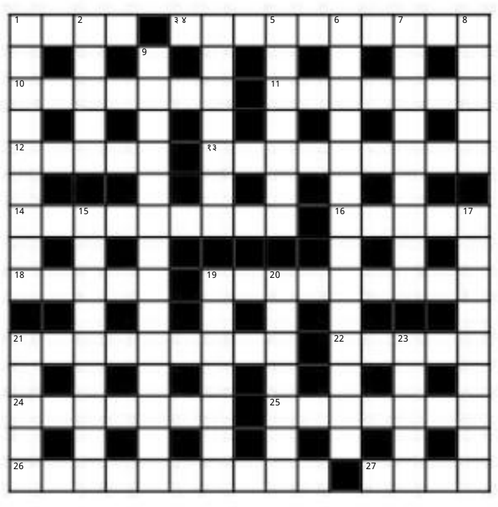

कल का समाधान

ACROSS

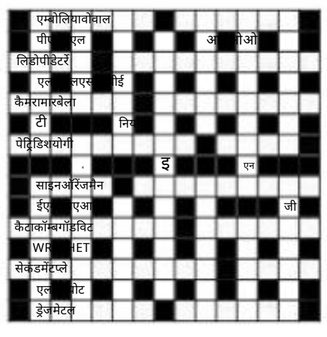

1 समुद्री पक्षी या पश्चिम की ओर से आने वाला समुद्री पक्षी (4)

3 पूर्वी फिल्म निर्देशक गिलोटिन के आसपास चला गया (10)

10 लोहार का काम छोड़ दिया (7)

11 पिछले महीने का आंकड़ा उपलब्ध कराया गया नवंबर (7)

12 दो लोगों के लिए गीत में कवर छंद (5)

13 शरीर का चक्कर लगाना चिंतित छात्र जोड़ी प्रवेश कर रही है (9)

14 प्रतिशोध चर्च में सीसा मारने के बाद जीन (9)

16 असीम समृद्ध अयस्क जिससे प्राचीन बर्तन भरे जाते थे (5)

18 पुराना चरित्र काँटेदार किस्म का है (5)

19 अनुबंध बोली से पहले एक आकांक्षा होती है (9)

21 अर्जेंटीना के केंद्र में उत्कृष्ट संगीत कार्यक्रम (9)

22 बाज के सिर वाले भगवान के गुण को गले लगाते हुए पक्षी (5)

24 परमेश्वर चाहता है कि नूह शुरू में समुद्र में उसके जहाज़ में जाए (7)

25 घर को चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ होने से रोकें (5,2)

26 जल्दबाजी में शिक्षक ने बदल दिया सुर? (10)

27 पवित्र ग्रंथ में अंतहीन विजयी समय (4)

DOWN

1 फीफा द्वारा जारी किया गया बयान: अमेरिकी वकील इसके खिलाफ (9)

2 क्रांतिकारी पेय प्रेमी का पर्दाफाश (5)

4 पुस्तक विमोचन के बाद भी कवि सक्रिय (7)

5 उपदेशक ने बार में पत्थर फेंका (7)

6 टीवी के लिए काम करने वाले होशियार लोग खबरें सुनते हैं (14)

7 स्कॉट्स क्षेत्र में एक दुखद घटना जिसके तहत उसे जाना पड़ा (9)

8 ड्राइव-इन से आदमी रेस्तरां चालू हुआ (5)

9 खगोलीय घटनायें नाविकों का नहीं बल्कि सितारों का अनुसरण करती हैं (8,6)

15 चलो, मुस्कुराओ यह असभ्य नया शब्द है (9)

17 होप लैंड में अमेरिका में पली-बढ़ी गेम गर्ल (9)

19 रैपर संशोधित ड्राफ्ट में अंग्रेजी (7)

20 पेड़ पर शांत म्यूज़ कंट्री क्लब में झूमते हुए? (7)

21 हाथ से हाथ की लड़ाई के लिए धातु की छड़? (5)

23 वह अंश जिसे आपका कंपाइलर जोर से पढ़ेगा (5)

नोट: कोष्ठक में दिए गए अंक आवश्यक शब्दों में अक्षरों की संख्या दर्शाते हैं। (द इंडिपेंडेंट, लंदन के साथ व्यवस्था द्वारा)

Machine Translated by Google

the pioneer

pinion

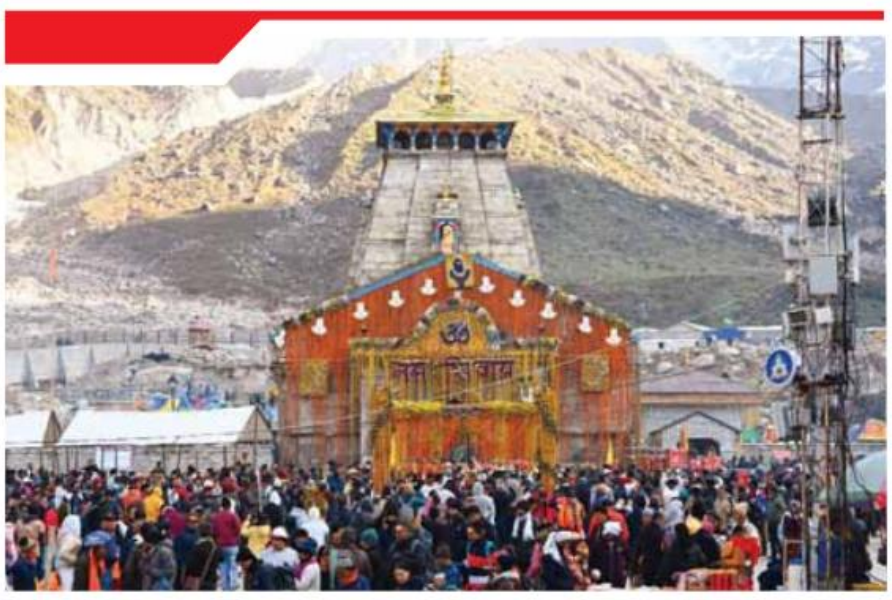

२५ प्रत्येक पीढ़ी करती है अपना योगदान दें

भाषा की शब्दावली जो वह इस्तेमाल करता है। शब्दावली वर्तमान भावनाओं और भावनाओं की काल्पनिक अभिव्यक्तियों की उसकी समझ को दर्शाती है, जो कभी-कभी मानव जाति जितनी पुरानी होती है।

यह खुशी, उल्लास या विशुद्ध 'निष्क्रियता' हो सकती है।

कभी-कभी गंभीर भावनाएं भी

जब किसी समय के किसी प्रमुख व्यक्ति द्वारा इसमें शामिल और नेतृत्व किया जाता है, तो वे काल्पनिक महत्व प्राप्त कर लेते हैं। बहुतों को वह समय याद होगा जब राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार के शिक्षा

विभाग को 'मानव संसाधन विकास विभाग' घोषित कर दिया गया था और रातों-रात कॉर्पोरेट उद्यमों के कार्मिकों

के कई विभागों ने खुद को मानव संसाधन विकास विभाग घोषित कर दिया था।

विषय-वस्तु में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था, यहां तक कि दृष्टिकोण में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी फैशन को नया स्वरूप मिल गया था।

हर बार जब कोई वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई अवधारणा पेश करता है, तो बहुत से लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि मानव स्वभाव कैसे आगे बढ़ता है और उन विशेष समय के व्यापक संदर्भ में शब्दों का क्या महत्व है। मूल्य निर्णय किए बिना विश्लेषण करना सबसे अच्छा है। ऐसा कहने के बाद, कोई भी वर्तमान समय में आ सकता है और देख सकता है कि राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था के 'कौशल' पर जोर ने कौशल शब्द को सीखने के केंद्र में ला दिया है।

कुछ खास तरह के कौशल निर्माण के लिए डिग्री देने की कोशिश की जा रही है। कुछ दशक पहले, कौशल इतना सुखद शब्द नहीं था।

किसी विश्वविद्यालय का कोई भी उप-निर्णयकर्ता 'कौशल' में डिग्री की बात नहीं करेगा। शिक्षा को एक 'महान अवधारणा' माना जाता था, जो वास्तव में है। कौशल के साथ भ्रम, हालांकि, शिक्षा की प्रक्रिया की भव्यता के महत्व को कम कर रहा था। इस स्तर पर उस बहस में शामिल होना शायद मददगार न हो।

सच तो यह है कि अब समय बदल गया है और कौशल ने एक उच्च स्तर की खोज हासिल कर ली है। जैसा कि पहले बताया गया है, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं

कौशल निर्माण में डिग्री।

शायद यह व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देने की मान्यता है। जो कुछ भी किया जा सकता है, उसे अब अधिक महत्व दिया जा रहा है।

अपने आप में यह अच्छी बात हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन यह कार्रवाई को बड़े पैमाने पर परिचालन मोर्चे तक सीमित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

इसलिए, अवधारणाओं और विचारों की उपेक्षा आनुपातिक है। अपने आप में, विषय-वस्तु पर बहस हो सकती है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, वह 'एक और मामला' है। यह अपरिहार्य है और कुछ चिंतन की ओर ले जाता है। कौशल अपने आप में महत्वपूर्ण है और शायद रोज़मर्रा की बातचीत में इससे जुड़े मूल्य से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

कौशल सभी रिश्तों की नींव है। अगर कोई किसी की ओर आकर्षित होता है, तो वह केवल उस व्यक्ति के कौशल के आधार पर होता है। वह कौशल गायन, खाना पकाने, बोलने या नृत्य में हो सकता है और यह सूची अंतहीन हो सकती है। सच तो यह है कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता, अगर उस व्यक्ति में कोई कौशल न हो।

माता-पिता भी अपने बच्चे की ओर तभी आकर्षित होते हैं, जब वह बच्चा कुछ हरकतें करता है, चाहे वह सिर्फ मुस्कुराहट ही क्यों न हो। यह कौशल कितना महत्वपूर्ण है। मुस्कुराहट के बिना, बच्चा किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता।

कोई भी वयस्क किसी बच्चे को देखता है और उसके साथ कुछ संवाद स्थापित करना चाहता है और उस बच्चे की प्रतिक्रिया ही किसी के ध्यान का केन्द्र होती है।

बाद में, इस तरह की बातचीत संचार और बहुत कुछ सीखने का आधार बन जाती है।

मानवीय रिश्तों में कौशल की इस मौलिक स्थिति पर अक्सर ध्यान नहीं दिया गया है, चाहे विश्लेषणात्मक उत्साह के साथ हो या काव्यात्मक उत्साह के साथ। अगर ऐसा किया गया होता, तो यह अधिक मान्यता होती कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि भावनात्मक संबंध भी, बिना किसी कौशल के आधार के संभव नहीं है। जो भी हो, यह चंचलता, दोस्ती और रिश्तों का एक अतिरिक्त आयाम है और वहां से यह कमाई और आजीविका तक जाता है।

आज जो हो रहा है वह यह है कि इस कौशल निर्माण को शिक्षा जैसे मानकीकृत प्रारूप में शामिल किया जा रहा है, जिससे डिग्री प्राप्त होती है। आज निर्माण में ईंट बिछाने के कौशल को भी डिग्री का दर्जा मिल सकता है। डिग्री वास्तव में मानकों का मानकीकरण मात्र है। इसी तरह, अभिनय और उससे भी अधिक में डिग्री का प्रस्ताव है।

दूसरे शब्दों में, किसी भी अन्य डिग्री की तरह, कौशल में डिग्री से कमाई और आजीविका हो सकती है। यह परिदृश्य पर नया है। पहले की तुलना में इसके साथ कमाई करने के लिए और भी अधिक तरीके हैं।

इसने सीखने की प्रकृति को व्यापक और गहरा कर दिया है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'शिक्षा' के रूप में संबोधित किया गया है। उद्योग, अगर कोई ऐसा कह सकता है,

शिक्षा के अपने घटक हैं, जिन्हें व्यापक रूप से समझा जाता है लेकिन हमारे परिचालन शब्दों में समान रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऐसा होने पर, विभिन्न प्रकार के सीखने और विभिन्न प्रकार के कौशल को वर्गीकृत करने का समय आ गया है। यह शिक्षा का वह घटक है जिसके लिए डिग्री की ओर ले जाने वाली 'शिक्षा' के लिए अब तक किए गए विचार और विश्लेषण की तुलना में अधिक विचार और विश्लेषण की आवश्यकता है।

इसलिए, यह कहना उचित होगा कि 'कौशल' को सीखने के एक भाग के रूप में समझने के लिए, हमें सीखने की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत 'शिक्षा' में डिग्री की सीखने की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन के साथ करनी होगी।

परिचालनात्मक रूप से इसका मतलब यह हो सकता है कि सबसे पहले बी.एड. और एम.एड. डिग्री के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए। यह आम तौर पर माना जाता है कि वैचारिक प्रतिबिंब को परिचालन वास्तविकता में बदलने के लिए हस्तक्षेप के एक आधार बिंदु की आवश्यकता होती है। उपरोक्त पाठ में, कौशल पर दार्शनिक प्रतिबिंब को कार्रवाई और अनुसंधान की दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। यह आगे की चर्चा और कार्रवाई के लिए गंभीरता से लिया जाने वाला एक बिंदु हो सकता है।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रसिद्ध प्रबंधन सलाहकार हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं)

हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में उत्साह की लहर देखी गई वाराणसी
मंत्री मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया-

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए। इस आयोजन ने न केवल राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने में उत्तर प्रदेश के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में मोदी-योगी साझेदारी के स्थायी प्रभाव को भी उजागर किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले मंगलवार को एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पर प्राचीन शहर वाराणसी में उत्साह का माहौल रहा।

अपने भरोसेमंद सहयोगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समर्थकों के साथ, मोदी की मौजूदगी ने उनके नामांकन दाखिल करने से पहले एक विशाल रोड शो के दौरान सड़कों पर हलचल मचा दी। पवित्र शहर में माहौल भगवा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जो लोकसभा चुनावों में उनकी आसन्न जीत के प्रति दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भाग्य का निर्धारण करने में उत्तर प्रदेश (यूपी) के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब वे सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के लिए प्रयास करें। 80 लोकसभा सीटों के साथ, उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति पर, वर्तमान और भविष्य दोनों पर काफी प्रभाव रखता है। कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जो सच है, यह इस बात पर जोर देता है कि राज्य देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नतीजतन, राजनीतिक दल आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

राजनीतिक दांव-पेंच के बावजूद, विश्लेषकों का अनुमान है कि इस बार यूपी में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसमें भाजपा 2019 की चुनावी सफलता को दोहराने के लिए तैयार है। मोदी और योगी की मजबूत जोड़ी से एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है, जिससे उनकी अपराजेय राजनीतिक ताकतों के रूप में स्थिति मजबूत होगी। मोदी-योगी की साझेदारी जीत का पर्याय बन गई है, जिससे संदेह की छाया पड़ गई है विपक्ष की संभावनाओं पर सवाल उठाया गया।

यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों को हासिल करने का भाजपा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस गतिशील जोड़ी पर रखे गए भरोसे से प्रेरित है। मोदी ने कई मौकों पर योगी की विकास पहल की सराहना की है, यूपी की प्रगति के लिए उनके सामूहिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। अमरोहा में मोदी की हालिया रैली के दौरान भी यही भावना प्रतिध्वनित हुई, जहां उन्होंने योगी के नेतृत्व में पिछले चुनावी रिकॉर्ड को पार करने और यूपी में इतिहास रचने के बारे में आशा व्यक्त की।

2014 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए, जिसने राज्य में भाजपा के चुनावी सूखे को समाप्त कर दिया। 80 में से 71 सीटें हासिल करके भाजपा बिना किसी महत्वपूर्ण विपक्षी गठबंधन के विजयी हुई।

इसके बाद 2019 के चुनावों में भाजपा ने मोदी लहर और योगी के शासन का लाभ उठाते हुए अपनी स्थिति को और मजबूत किया, जबकि उसे एकजुट विपक्षी मोर्चे का सामना करना पड़ा। कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर योगी के सक्रिय रुख ने मतदाताओं को प्रभावित किया, जिससे भाजपा की शानदार जीत हुई।

आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए यह अभियान चलाया गया है।

उनके नेतृत्व में, यूपी में अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो अतीत की अराजकता से एक प्रस्थान है। विकास पहलों के लिए केंद्र सरकार के समर्थन ने यूपी की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

जैसे-जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, केंद्र में मोदी सरकार और योगी के शासन मॉडल की संयुक्त सफलताओं के कारण भाजपा खुद को यूपी में अनुकूल स्थिति में पा रही है।

शासन और आर्थिक संकेतकों में ठोस सुधार उनके प्रशासन की प्रभावशीलता के प्रमाण हैं, जो मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा करते हैं। हालांकि चुनाव का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है: मोदी-योगी गठबंधन को यूपी के लोगों का अटूट समर्थन प्राप्त है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और दो पुस्तकों के लेखक हैं; उनके विचार निजी हैं)

मुख्यमंत्री के रूप में योगी का कार्यकाल

मैडम - यह खबर 15 मई को प्रकाशित हुई "आप ने मारपीट की बात स्वीकार की" से संबंधित है। हालांकि सीएम के पीएस बिभव कुमार की हरकत निंदनीय है, लेकिन आप नेता संजय सिंह द्वारा इस कृत्य को स्वीकार करना अपराध स्वीकार करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह जानकर राहत मिलती है कि पार्टी ने अपने ही लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है।

इसकी तुलना इस बात से करें कि कैसे एक मजबूत पार्टी (भाजपा), जो लोकसभा चुनावों में "चार सो पार" स्कोर की उम्मीद कर रही है, बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही, जबकि उन पर यौन शोषण के कई आरोप लगे थे, और उसने किसी तरह से राहत के तौर पर उनके बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया।

हालांकि AAP ने अभी तक अपने वादे पर काम नहीं किया है, लेकिन गलत कामों को स्वीकार करना उन सभी पार्टियों के लिए सबक है जो ऐसी घटनाओं में अपनी पार्टी के लोगों के शामिल होने पर आंखें मूंद लेते हैं। कम से कम अभी के लिए, यह AAP है न कि भाजपा, जो "बेटी बचाओ" के वादे पर चल रही है।

अविनाश गोडबोले | देवास

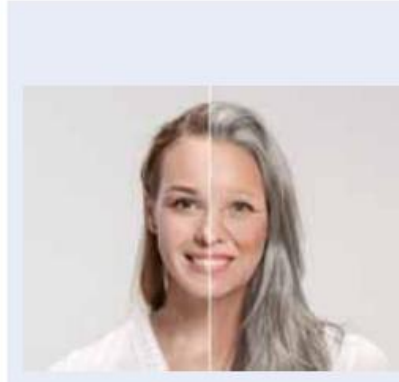

ख़ीरबड़ी | नोएडा

महोदया - 15 मई को प्रकाशित संपादकीय "कड़वी चुनावी लड़ाई" के अनुसार, वर्तमान लोकसभा चुनाव स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक के सबसे तीखे संघर्ष के रूप में जाने जा सकते हैं। इस लेखक जैसे वरिष्ठ नागरिक उस समय को याद किए बिना नहीं रह सकते जब राजनेता चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों से लड़ने में गरिमापूर्ण व्यवहार करते थे। उदाहरण के लिए, 1969 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के दौरान, जब कांग्रेस के दिग्गज कामराज ने कहा कि वे विरुधुनगर निर्वाचन क्षेत्र से 'झूठ बोलकर' जीतेंगे, तो राजाजी ने जवाब दिया, "उनका झूठ बोलना निश्चित है, लेकिन जीतना मुश्किल है"! राजाजी की स्वतंत्र पार्टी और डीएमके ने गठबंधन में वह चुनाव लड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस हार गई और डीएमके ने सरकार बना ली।

राजाजी और अन्ना के बीच मतभेद उभर आए। निराश राजाजी ने एक प्रेस वार्ता में कहा - "स्वतंत्र पार्टी और डीएमके के बीच हनीमून खत्म हो गया है"!

जब अन्नादुरई ने यह सुना तो उन्होंने चुटकी ली - "हां, हनीमून खत्म हो गया है और परिवार-

"अब जीवन की शुरुआत हो चुकी है"! 1976 में फिर से, आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोकनायक जेपी नारायण ने जनता पार्टी के लिए लगातार प्रचार किया। लेकिन इसके तुरंत बाद, पराजित श्रीमती गांधी से मिलने वाले पहले व्यक्तियों में से एक जेपी थे। बैठक के बाद, जब प्रेस रिपोर्टरों ने उनसे एक बयान मांगा, तो जेपी ने कहा "मैं चाहता हूं कि श्रीमती गांधी इस पर चर्चा करें।

इंदिरा गांधी, उनके उज्ज्वल अतीत की तुलना में एक उज्जवल भविष्य! हमारे पास राजाजी, कामराज और जेपी जैसे नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों से पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन कभी उनसे नफरत नहीं की, व्यक्तिगत रूप से निंदा या कीचड़ उछालने में लिप्त नहीं हुए। क्या हम कभी उनके जैसे लोगों को फिर से देखेंगे?

वी जयरामन | चेन्नई

मैडम - भारत-नेपाल संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। भौगोलिक रूप से करीबी पड़ोसी होने के कारण, यह छोटा हिमालयी देश हमेशा भारत की ताकत को लेकर सतर्क रहा है। हालांकि भारत ने नेपाल में आए भयावह भूकंपों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जमीनी हकीकत की असंवेदनशील रिपोर्टिंग से काठमांडू नाराज है।

गणपति भट्ट | अकोला

एक बड़े भूकंप के दौरान टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया गया।

मधेसी आंदोलन ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल ने चीन की ओर हाथ बढ़ाया है। कुल मिलाकर, सद्भावना की गति को बनाए रखने में नई दिल्ली की अक्षमता ने काठमांडू को परेशान कर दिया है। पुष्प कमल दहल सरकार द्वारा अपने करेंसी नोटों पर विवादास्पद भारत-नेपाल-चीन त्रि-जंक्शन को दर्शाने के हालिया फैसले ने भारतीय कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। यह व्यापक रूप से महसूस किया जाता है कि पारंपरिक मुद्दों के अलावा, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शुरू न होने या हस्ताक्षर किए जाने के बाद भी उन्हें बनाए न रखने को लेकर नई दिल्ली के साथ काठमांडू की नाखुशी, करेंसी नोटों को लेकर उसके कदम के लिए कुछ कारणों में से एक हो सकती है। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए परिपक्वता दिखानी चाहिए कि बीजिंग के नकारात्मक प्रभाव का असर आपसी मित्रता पर न पड़े। क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए करेंसी नोट मुद्दे को चुनावों के तुरंत बाद सुलझाया जाना चाहिए।

Machine Translated by Google

the pioneer analysis

प्रथमस्तंभ

मैं एक रणनीतिक कदम की याद ताजा करती है
भारतीय परिवार अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा
भारत (आरबीआई) सक्रिय रूप से देश की आर्थिक लचीलापन को मजबूत कर रहा है
सोने के भंडार को हासिल करना। यह साहसिक पहल घरेलू बचतकर्ताओं की समझदारी को दर्शाती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक खुद को संभावित आर्थिक उथल-पुथल से बचाने और देश की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।

आरबीआई के पास अब 817 टन का स्वर्ण भंडार है।

इस उछाल के लिए पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, इजरायल द्वारा फिलिस्तीन पर हमला, रूस-यूक्रेन युद्ध और लगातार मुद्रास्फीति सहित कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे सोने का आकर्षण बढ़ गया है।

दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने भंडार में विविधता लाने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सक्रिय रूप से सोना जमा कर रहे हैं। चीन, विशेष रूप से, लगातार 17वें महीने सोने की खरीद में लगा हुआ है, जिसका उद्देश्य मुद्रा अवमूल्यन और भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाव करना है।

विश्व अनौपचारिक रूप से उन स्वर्ण मानकों की ओर लौट रहा है जिन्हें उसने 1971 में त्याग दिया था।

भारत भी शेयर बाजार में लगातार छह दिनों की गिरावट से प्रभावित है। इससे काफी निवेश खत्म हो गया है। अनुमान है कि नुकसान 7 लाख करोड़ रुपये का है।

बेशक, घरेलू बचतकर्ताओं की बचत में कमी आई है क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों ने उन्हें प्रभावित किया है। 9 मई को एक स्पष्टीकरण नोट में आरबीआई ने उल्लेख किया है कि "वे अपनी बचत रियल एस्टेट में लगा रहे हैं और केंद्रीय बैंक इस घटना से चिंतित नहीं है"।

बैंक ने खुद सोने की खरीद बढ़ा दी है ताकि "अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव के बीच अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने में मदद मिल सके"। फरवरी में अमेरिकी मुद्रास्फीति दर पिछले साल की तुलना में 3.2 प्रतिशत पर पहुंच गई।

चूंकि फेडरल रिजर्व ने 2022 में दरें बढ़ाना शुरू किया है, उसने जुलाई 2023 में दरें 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दी हैं।

अमेरिकी चुनावों को देखते हुए आगे भी वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है।

वर्ष की शुरुआत से सोने की कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे मुद्रास्फीति के खिलाफ़ एक बेहतर बचाव और राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के बीच एक आश्रय के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई उल्लेखनीय खरीद और सुरक्षित-संपत्तियों की बढ़ती मांग के कारण है।

भारत में सोने की कीमतों में 2024 में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिल रहा है, जिसमें एक उल्लेखनीय उछाल आया है, जिसने अक्षय तृतीया से दो दिन पहले 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के अभूतपूर्व सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, जब पारंपरिक सोने की खरीदारी चरम पर होती है। यह उछाल सिर्फ़ एक साल के भीतर लगभग 21.1 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन, यह थोड़ा गिरकर 72,788 रुपये पर आ गया।

छह महीने में घरेलू स्तर पर सोने की कीमतें 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 73,958 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं।

कोई भी यह समझ सकता है कि सोने से अधिक तेजी से मूल्यवृद्धि किसी भी चीज में नहीं हो सकती और आरबीआई की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
एक डॉलर 83.88 रुपये पर है। छह महीने में रुपया बढ़कर 82.50 रुपये पर पहुंचने की उम्मीद है, जो करीब 1.1 प्रतिशत की बढ़त है और एक साल में यह 82 रुपये पर पहुंच सकता है - जो 1.7 प्रतिशत की बढ़त है। इसका मतलब है कि आरबीआई के डॉलर रिजर्व में एक साल में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इसलिए आरबीआई ने डॉलर से ज्यादा सोना खरीदने का फैसला किया है। इसका निवेश 10 ग्राम के लिए 73000 रुपये से भी कम होगा और 20 प्रतिशत से ज्यादा का लाभ होगा। यह एक बुद्धिमान अर्थव्यवस्था है।

आरबीआई ने भंडार में विविधता लाने के लिए सोने की खरीद बढ़ा दी है।

सोने के मूल्य ने विदेशी मुद्रा भंडार को 3 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 648.5 बिलियन डॉलर तक पहुँचाया। RBI

2024 की शुरुआत में और अधिक सोना खरीदेगा, जिसका लक्ष्य विविधीकरण और मुद्रास्फीति से बचाव करना है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) का कहना है कि जनवरी-मार्च के दौरान RBI ने 19 टन सोना खरीदा। यह पूरे 2023 में खरीदे गए 16 टन सोने से कहीं ज़्यादा है।

डब्ल्यूजीसी के अनुसार, सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देशों की बात करें तो अमेरिका 8,133 टन के साथ पहले स्थान पर है, जिसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूसी संघ क्रमशः 3,366.49, 2,451.84, 2,436.01 और 2,271.16 टन स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में उछाल अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद आया। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण लगाए गए इन प्रतिबंधों में रूसी रिजर्व डॉलर को फ्रीज करना और कच्चे तेल जैसे महत्वपूर्ण कमोडिटी ट्रेड पर प्रतिबंध लगाना शामिल था।

इन उपायों के वैश्विक परिणाम बहुत गंभीर थे, तथा इससे पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं की कमजोरियां उजागर हुईं।

शेयरों में निवेश का विकल्प जोखिमपूर्ण हो गया है।

फरवरी में चीन ने अमेरिकी बाजार में 22.7 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया।

फेडरल रिजर्व के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ट्रेजरी सिक्योरिटीज में उसकी कुल होल्डिंग घटकर 775 बिलियन डॉलर रह गई है।

इस कमी के बावजूद, चीन अमेरिकी ऋण का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी धारक बना हुआ है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आंकड़ों के अनुसार, चीन डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है।

आईसीआईसीआईडायरेक्ट अध्ययन के अनुसार,

आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना चाहता है और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है।

सोना स्थिरता प्रदान करता है और किसी एक मुद्रा के प्रदर्शन से सीधे जुड़ा नहीं होता है। यह आर्थिक अनिश्चितता या डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव के समय विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है।

सोने को मुद्रास्फीति के खिलाफ़ बचाव के रूप में माना जाता है। जब मुद्रास्फीति के कारण मुद्राओं का मूल्य कमज़ोर होता है, तो सोना अपना मूल्य बनाए रखता है या यहाँ तक कि बढ़ भी जाता है। यह भारत के विदेशी भंडार की क्रय शक्ति की रक्षा करता है।

आरबीआई का कहना है कि पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर स्वर्ण भंडार में निवेश करने से विदेशी निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हो सकता है।

यह मजबूत वित्तीय स्थिति और स्थिरता का संकेत है, जो संभावित रूप से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।

हालाँकि आज सोने का प्रचलन कम है, फिर भी इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के लिए किया जा सकता है। सोने का भंडार रखने से भारत को ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देशों के साथ कर्ज चुकाने में मदद मिलती है, या अगर वे देश रुपया स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

अगले कुछ साल उथल-पुथल भरे हो सकते हैं और सोना अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने वाला कारक हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईटी क्षेत्र, उद्योग, बाजार अस्थिर स्थिति में हैं और उन्हें शांत होने में समय लगेगा। ऐसे अस्थिर समय में सोने की मांग कागजी मुद्राओं की तुलना में अधिक होने की संभावना है। आरबीआई ने सही कदम उठाया है और भारत की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने का प्रयास कर रही है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं; विचार निजी हैं)

एक ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में, मेरा

दिन सबसे खतरनाक और जानलेवा कैंसर का सामना करने से भरे हुए हैं, कैंसर रोधी दवाओं के एक शस्त्रागार के साथ

उपचार हल्के से लेकर उतने ही भयानक तक होते हैं।

लेकिन इस बेरहम बीमारी के खिलाफ लड़ाई के बीच, मुझे यह समझ में आ गया है कि चिकित्सा विज्ञान पूर्णता से कोसों दूर है।

हर बार जब मैं किसी मरीज़ और उसके परिवार के साथ बैठकर उपचार विकल्पों पर चर्चा करता हूँ, तो मैं एक नाजुक संतुलन बनाने की प्रक्रिया में लग जाता हूँ। हाँ, मैं उपचार के संभावित लाभों की रूपरेखा बताता हूँ, लेकिन मैं इसकी खामियों और इससे जुड़े जोखिमों को समझाने में भी पर्याप्त समय लगाता हूँ - जोखिम जो कभी-कभी बहुत बड़े हो सकते हैं, न केवल रोगी के स्वास्थ्य पर बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी असर डालते हैं।

यह न केवल मरीज़ के जीवन बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

ये चर्चाएं कभी भी संक्षिप्त नहीं होतीं; औसतन, मैं अपने परिवार के 2 से 8 सदस्यों के साथ चर्चा करती हूं, तथा यह सुनिश्चित करती हूं कि हर कोई इसमें शामिल जटिलताओं को समझे।

और इन बातचीत में, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सफलता की गारंटी नहीं है। मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा है और मैं मानता हूँ कि मेरे नैदानिक निर्णय-

बयान अचूक नहीं हैं।

ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में, जिम्मेदारी का भार बहुत अधिक है। बीमारी के कारण होने वाली मानवीय क्षति, साथ ही परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनात्मक उथल-पुथल, हर दिन मुझ पर भारी पड़ती है। ऐसे क्षण आते हैं जब इसकी गंभीरता मुझे अभिभूत कर देती है, लेकिन मैं अपनी ताकत जुटाता हूँ, खुद को इन अशांत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आवश्यक गरिमा, धैर्य और करुणा की याद दिलाता हूँ।

पानी.

हाल ही में, मुझे श्री सी.वाई. गोपीनाथ द्वारा लिखा गया एक लेख मिला, जिसमें संदिग्ध अग्नाशय कैंसर से जूझ रहे एक मरीज की यात्रा का वर्णन किया गया था। मरीज को ऐसा लग रहा था जैसे उसका ऑन्कोलॉजिस्ट उसे एक डॉक्टर के पास ले जा रहा है।

उन्हें कैंसर का पता चला।
ऐसी स्थितियाँ असामान्य नहीं हैं, खासकर जब ऐसे कैंसर का इलाज किया जाता है जिसकी बायोप्सी करना बेहद मुश्किल होता है। गलत निदान और घातक निदान से चूकने का डर ऑन्कोलॉजिस्ट के दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है।

मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बढ़ता विश्वास का अंतर चिंता का विषय है। मरीज और उनके परिवार हमारे कार्यों और सिफारिशों को विभिन्न तरीकों से देख सकते हैं, कभी-कभी उन्हें गुप्त उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म होती है।

निजी और सरकारी दोनों स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में बड़े पैमाने पर काम करने के बाद, मैंने नैदानिक और चिकित्सीय दोनों तरह की समस्याओं को देखा है।

चिकित्सीय त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ चिकित्सा की अंतर्निहित खामियों और एक जटिल स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नेविगेट करने की चुनौतियों से उत्पन्न होती हैं।

आधुनिक युग में, डॉक्टर विश्वास के प्रति बहुत जागरूक हैं।

हमारे और हमारे रोगियों के बीच जो कमी है, उसे दूर करना है। 'ईश्वरीय परिसर' की धारणा एक मिथक है; इसके बजाय, हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और खुले संचार और पारदर्शिता के माध्यम से अंतर को पाटने का प्रयास करते हैं।

जबकि दवाएँ और सर्जरी रामबाण नहीं हैं, वैकल्पिक उपचार भी हमेशा उत्तर नहीं होते हैं। यह ज़रूरी है कि हम अपने फ़ैसले सबूतों पर आधारित करें, न कि किसी किस्से-कहानी के बहकावे में आकर लें।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, सभी के लिए एक ही समाधान नहीं है। प्रत्येक रोगी की यात्रा अद्वितीय होती है, जो उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिस्थितियों से आकार लेती है। डॉक्टरों के रूप में, हमें अपने दृष्टिकोण को व्यक्तिगत बनाना चाहिए, रोगियों को उनकी उपचार प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।

एक ऐसा माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है जहाँ मरीज़ सवाल पूछने, सीखने और दूसरी राय लेने में सक्षम महसूस करें। आखिरकार, सूचित निर्णय लेना ही सुधार है।

प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की आधारशिला।

निष्कर्ष में, विवाद और गलत सूचना के कोलाहल के बीच, विशेषज्ञता की आवाज़ को प्रबल होना चाहिए। चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है जो अनुमान से नहीं, बल्कि साक्ष्य से निर्देशित होता है।

आगे आने वाली चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद, मैं सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हूं, अपने गुरु के शब्दों को दोहराते हुए: "किसी को यह काम करना है और आपको चुना गया है। इसे अच्छे से करो।"

-लेखक अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फरीदाबाद के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार और कार्यक्रम निदेशक (लिम्फोइड नियोप्लाज्म और सेलुलर थेरेपी) हैं।

ये मेरे निजी विचार हैं।

THE ASIAN AGE

18 मई 2024

संसाधन, धर्म, कोटा:

प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण से विपक्ष घबरा गया।

उनके स्कूल में कक्षा 9 या 10 के आसपास प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में पढ़ाया जाता है। यह उपयुक्त है क्योंकि वे उस उम्र में हैं जब उनमें से अधिकांश चिंतन करते हैं

आमतौर पर, इसका विरोधाभास, न केवल भौतिकी के संदर्भ में, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी है

भौतिकी, मानव स्वभाव और रिश्तों को समझना कठिन है।

प्रकाश की दोहरी प्रकृति - यह कैसे मौजूद रह सकता है और एक कण के रूप में तथा एक प्रकाश के रूप में कैसे यात्रा कर सकता है। एक लहर, एक साथ। लेकिन अगर किसी को अंधकार से लड़ना है और मानव आंखों के लिए स्पष्ट रूप से देखना संभव बनाना है, तो उसके पास दोनों गुण होने चाहिए।

प्रकाश की तरह, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी दोहरी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं, तथा विविध संसाधनों से प्रेरणा लेते हैं, चाहे वह प्राचीन भारतीय संस्कृति हो संस्कृति और दर्शन, इसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के साथ "(सारी दुनिया मेरा परिवार है), या लोकतंत्र की जननी वसुधैव कुटुम्बकम" या भारत, जिसका उदाहरण वे धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिक मानवतावाद जैसे संवैधानिक मूल्यों को कायम रखकर पेश करते हैं, या यहां तक कि एक मजबूत, राणा प्रताप या शिवाजी जैसे नायकों के आधार पर तैयार किया गया मर्दवादी हिंदुत्व जिन्होंने अनुचित भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया और न्याय के लिए लड़े, कि वह मूर्त रूप देता है।

सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या मुसलमान वोट देंगे उनके लिए, श्री मोदी हमेशा से यह माना जाता रहा है कि इस देश के लोग देश वोट करेगा उसके लिए इस पर आधारित उनका ट्रैक रिकॉर्ड और उस पर भरोसा उदाहरण भी देते हैं

ग़लतफ़हमी और अति-अनुमान दोनों राजनीतिक आख्यान में स्थिरता का गुण चुनाव से पहले विपक्ष तर्कों की श्रृंखला से भ्रमित है धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर उनके द्वारा प्रस्तुत, लोकतंत्र, संविधान और समानता हिंदू और मुसलमान, तथा अन्य धर्मों के लोग भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, सभी धर्मों के बीच एकता होना आवश्यक है।

जब श्री मोदी ने अल्पसंख्यकों को पहले संसाधन आवंटित करने के मुद्दे पर सवाल उठाया, तो यह कोई मुद्दा नहीं था। मुसलमानों या किसी भी समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई बयान अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव का मुद्दा, भले ही सकारात्मक हो, धर्म की कसौटी पर आधारित है। भारतीय संविधान ऐसा नहीं करता किसी भी सकारात्मक भेदभाव के लिए जगह किसी भी व्यक्ति के चुने हुए धर्म के आधार पर, खास तौर पर यह देखते हुए कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इसे बदल सकता है। दूसरी ओर, श्री मोदी और भाजपा डॉ. यह बी.आर. अंबेडकर की आरक्षण नीति का उद्देश्य उन लोगों का उत्थान करना था जो सदियों से जातिगत भेदभाव से पीड़ित रहे हैं।

इसी तरह, जबकि श्री मोदी कहते हैं कि यदि उन्होंने कभी हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण लाने की कोशिश की तो वे सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार खो देंगे चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस की इच्छा के खिलाफ आवाज उठाई थी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, सबसे पहले मुसलमानों को संसाधन दिए जाएंगे। वे छद्म धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोल रहे थे। प्रस्तावित नीति निर्माण में समानता और निष्पक्षता का अभाव, न कि सांप्रदायिक घृणास्पद भाषण देना, बाद के उदाहरण में।

विभिन्न मीडिया के दौरान उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या मुसलमान उन्हें वोट देंगे? बातचीत में, श्री मोदी ने हमेशा कहा है कि इस देश के लोग उनके ट्रैक रिकॉर्ड और उनके द्वारा पैदा किए गए विश्वास के आधार पर उन्हें वोट देंगे। यह एक ऐसे राजनेता का रुख है जो अपने साथी नागरिकों को अपने से कमतर नहीं समझता। किसी भी विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्ति को भारतीय नहीं बल्कि केवल भारतीय माना जाएगा। भारत सदैव अपने सबसे साहसी, आत्मविश्वासी और वीर योद्धाओं में से एक के प्रति श्रद्धा रखेगा। वर्तमान समय के साहसी नेता.

स्वाति मालीवाल पर हमले की जांच हो

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार को एक प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

अब पुलिस को उससे पूछताछ में जल्दबाज़ी दिखानी चाहिए आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले और कानून को अपना काम करना चाहिए बेशक, और वह भी जल्दी से।

एक राष्ट्रीय विधायक पर हमले की शर्मनाक घटना, जो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर उच्च सदन के सदस्य यह केवल उस लापरवाही की फाइल को बढ़ाता है जिसके साथ दुखों को भड़काया जाता है पितृसत्ता और स्त्रीद्वेष के कारण जो समाज के ऊपरी तबके में व्याप्त है भारत का राजनीतिक वर्ग, जिसे आमतौर पर नेता या नेता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, नेताओं पूर्णाधिकारी।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर बिना किसी भय या पक्षपात के कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा महिलाओं को कोई नुकसान हो सकता है। देश की आधी आबादी को गलत संदेश जाएगा। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के कृत्य, जो घरेलू हिंसा के मामलों में घर पर काफी आम हैं, उच्च और शक्तिशाली लोगों द्वारा किए जाने पर तीव्र हो जाते हैं। वे शायद यह मानते हैं कि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है और इसलिए वे इससे बच सकते हैं।

स्वाति ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने के बारे में विचार-विमर्श किया होगा कथित तौर पर इतने प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा लात मारने और हमला करने के लिए एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री के निजी सहायक के रूप में। उन पर मुकदमा दायर करने के संबंध में राजनीतिक दबाव पुलिस शिकायत की कल्पना की जा सकती है।

अब जब उसने सारी पीड़ा झेलने के बाद इस बात को सामने लाने का फैसला कर लिया है, आघात के बाद, अब समय आ गया है कि एक तुच्छ राजनीतिक सहयोगी को उदाहरण बनाया जाए। मामले की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से संबंधित सीसीटीवी फुटेज जारी करने से हुई जांच अधिकारियों ने कहा।

राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को जिस तरह की छूट दी गई है, उससे आम आदमी के लिए सबसे बुरा संकेत जो विरोधियों के सामने खुद को शक्तिहीन महसूस करता है। सत्ता में बैठे लोग अपने आप को शक्ति से ढक लेते हैं।

एक कथित सीरियल अपराधी - संसद का एक मौजूदा सदस्य - के खिलाफ देश छोड़ने के बाद महिलाएँ आज़ाद हो जाती हैं। सभी के लिए एक आम पैटर्न यह वह बेशर्मी है जिसके साथ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग तब तक व्यवहार करते हैं जब तक मुखबिर सोशल मीडिया का उपयोग उन लोगों को उजागर करने के लिए करते हैं जो महिलाओं के खिलाफ आपराधिक दुर्व्यवहार के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, चाहे वह यौन उत्पीड़न हो या सिर्फ शारीरिक पिटाई।

एशियाई युग

कौशिक मित्तर
संपादक

के. सुधाकर
प्रिंटर एवं प्रकाशक

एशियन एज का कार्यालय यहां स्थित है:
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र, 219 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002. फ़ोन: (011) 23211124.
की ओर से और के लिए प्रकाशित और मुद्रित
डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र, 219 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली दिल्ली 110 002, बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-III, नोएडा -201301 पर।
लंदन: क्विकमार्श लिमिटेड, 8वीं मंजिल, ब्लॉक 2, एलिजाबेथ हाउस, 39 यॉर्क रोड, लंदन, SE1 7NQ.
आरएनआई पंजीकरण संख्या: 57290/94

सुभानी

अस्पष्ट राजनीतिक 'मंडी'

माइनस 'हीरास' मुश्किल में

शोभा की राय

फिल्म बाज़ार है कि एस.एल.बी. औट्यूर का शब्द में हीरामंडी — डायमंड बाज़ार (नेटफ्लिक्स इंडिया का सबसे ज्यादा प्रचारित) महंगी पेशकश), उसे मिला संख्याएं गलत हैं। मतलब, उन्हें उम्मीद थी कि उनका आठ-भाग सभी अवधि श्रृंखला को तोड़ने के लिए रिकॉर्ड और वितरित ज़बरदस्त सुपरहिट. अफसोस, हीरामंडी लिखा गया एक आदमी की घमंड परियोजना के रूप में बंद जो कनेक्ट करने में विफल रहा दर्शकों के साथ. एस.एल.बी., सनकी के रूप में जाना जाता है प्रतिभा (एक व्यंजना के लिए मेगालोमैनियाक) अपनी काल्पनिक सिनेमा की दुर्लभ दुनिया में, एक भव्य फिल्म बनाने की कोशिश में मुंह के बल गिर पड़ा। असाधारण आयोजन लाहौर। यह एक आलसी और कई बातों पर उलझन अलग-अलग विषयों के साथ — आज़ादी और — बरबादी " अत्याचारी "एक भव्य पैमाने पर हुज़ूर चलाना

हवेली, जो दस वर्षीय नवाबों द्वारा संरक्षण प्राप्त थी खुशी। क्या हो सकता था के बारे में एक शक्तिशाली कहानी रही है व्यभिचार और शक्ति, विश्वासघात और शोषण जर्जर हो गया था, उथली कहानी जो चली गई कहीं नहीं। अनजाने में व्यंग्यात्मक टिप्पणी आज़ादी से पहले की "नबाब और कबाब" संस्कृति

लाहौर, जिसमें कार्डबोर्ड क्रांतिकारियों " चिल्लाओ इंकलाब जिंदाबाद "समय-समय पर जबकि "नच लड़कियाँ" घूमती हैं और दरवेशों की तरह शानदार कढ़ाई वाले शरारा पहनकर घूमें और घाघरा. और शराब मोगरा इत्र, अंजन और करो इसकी भरपाई नहीं की जा सकती इस स्तुति में आत्मा की कमी है एस.एल.बी. का दंभ। खैर! समय था उत्तम।

चुनाव का अंतिम चरण समाप्त हो चुका था बिना किसी स्पष्ट जीत के कुछ सप्ताह पहले ही किस बात का भव्य समापन के रूप में वर्णित किया गया था " पृथ्वी पर सबसे बड़ा चुनाव", भारत की राजनीतिक मंडी थी दोनों पक्षों की हताश "वेश्याओं" से भी भरा हुआ है विभिन्न लिंगों के लोग पैसों की थैलियों के साथ ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने की होड़ में लगे हुए हैं। होनहार उम्मीदवारों के साथ भारत में बहुत सारे प्रलोभन नये नवाब, बिना कपड़ों के रेशमी लेकिन जैसे लिबास सूती डिजाइनर कुर्ते, राजनीतिक क्षेत्र में घूमते हुए, शेखी बघारते हुए

400 सीटों का बखान, अगर और नहीं। महिलाओं की तरह हीरामंडी में सीटें थीं उच्चतम तक पहुँचने के लिए बोली लगाने वाले। राजनीतिक "" नाथ उथरना समारोह थे पूरे देश में हो रहा है देश, लालची के रूप में नेताओं चारों ओर खरीदारी की संभावित सितारे जो कर सकते हैं पार्टी के लिए एक सीट जीतना। किसी तरह, संख्या यह मंडी भी, जोड़ नहीं था.

क्या नमो शो खत्म हो जाएगा? एसएलबी पराजय का रास्ता?

क्या भाजपा का मेगा शो सफल होगा?

से कनेक्ट करने में विफल रहा मतदाता?

बहुत से चतुर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए, लेखन दीवार पर पहले से ही था. वहाँ अशुभ थे लेकिन अव्यक्त संकेत और भाजपा की जीत के संकेत दिन बीतते जा रहे थे तेजी से. कोई नहीं बोला इस बारे में खुलकर डर। और जब भाजपा ने ऑटोपायलट पर सिर हिलाया तो सभी ने सिर हिलाया समर्थकों ने इस बात का बखान किया क्लीन स्वीप। यह केवल जब बाजार शुरू हुआ यह स्लाइड करने के लिए कि पैनिक बटन दबाए गए थे मुख्यालय. कुछ सही नहीं था! क्यों सेंसेक्स इस तरह प्रतिक्रिया दे रहा है यह? विदेशी निवेश डालना चाहिए था में! सभी गणना और पुरानी निश्चितताएं

ऐसा लग रहा था कि यह गिरावट की ओर जा रहा है। आशावादी नाक भौं सिकोड़ी: "बकवास! वहाँ एक छोटा सा बाजार रहा है सुधार. सब कुछ ट्रैक पर। बस देखो क्या यह घटना 4 जून को होगी।"

हाँ, सर! हमारी आँखें छिला हुआ।

एक सशक्त हिन्दी है " शब्द — — जो सचाई अनुवाद करना बहुत कठिन है मात्र "सत्य" के रूप में सचाई इससे उत्पन्न बहस

जयराम रमेश का मूर्खतापूर्ण टिप्पणी, सही ढंग से डब किया गया 'नस्लवादी', अब एक पूर्ण विकसित नस्लवाद बनाम सांप्रदायिकता मुद्दा। जैसे कि कोई है से बेहतर अन्य।

सचाई ! लोग इसे समझते हैं। महसूस करें इसे समझो। जसप्रीत सिंह, 10 साल का बच्चा दिल्ली के तिलक नगर में रहने वाले रातों-रात स्टार बन जाना उनके वीडियो बनाने के बाद एक खाद्य गाड़ी से रोल चला गया वायरल, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सचाई खेल में। यहाँ एक था मेहनती छोटा लड़का जिसने त्रासदी को आने नहीं दिया उसके बाद उसे नीचे रखें पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माँ उसे छोड़कर गायब हो गया और एक छोटी बहन को संभालना है खुद के लिए. जसप्रीत स्थिति को संभाला और बेचना शुरू किया

अपने चचेरे भाई से रोल गुरमुख की भोजन गाड़ी। ए एक खाद्य पदार्थ विक्रेता द्वारा शूट किया गया एक भटका हुआ वीडियो ब्लॉगर ने लोगों की कल्पना को पकड़ा,

10 मिलियन से अधिक बार देखा गया. इनमें से कुछ भी योजनाबद्ध नहीं था या हेरफेर किया गया है। जसप्रीत स्पष्ट छुआ सचाई लोगों के लिए पर्याप्त दिल जैसे आनंद महिंद्रा और सोनू सूद आगे आएं और प्रायोजित करने की पेशकश जसप्रीत और उसकी बहन का शिक्षा बाधित हुई. इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद सोशल मीडिया, गुरमुख गर्व से कहते हैं: "हम प्रतिदिन 400 रुपये कमाने से लेकर लगभग 100 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गए हैं।" `8,000.' घर सचाई हमारा दौड़ना!

नागरिक जो चुपचाप इस घटना को झेल रहे हैं

पिछले दस वर्षों में लोग अपनी पहचान फिर से तलाश रहे हैं सचाई एक ऐसे भारत का सपना देखना जहाँ वे नहीं होंगे कुचले गए क्योंकि वे की लाइन पर नहीं चल रहे हैं उनके स्वामी। वह शब्द "मास्टर्स" को एक जार में रखना चाहिए लोकतंत्र जहाँ हम हैं सभी को बराबर माना जाता है कानून की नज़रों से बचो। हम बराबर हैं? कितना अलग है राजनीतिक से मैदान शाही हवेली हीरामंडी , जहां एक अकेला अत्याचारी व्यक्ति किसी के भाग्य को नियंत्रित करता है बहुत से. जहाँ कोई नहीं चुनौती देने का साहस करता है

" हुज़ूर " या बोलो. जहाँ विश्वासघात, हत्या, विश्वासघात, द्वेष और पीठ में छुरा घोंपना तो रोज़ की बात है घटनाएँ और उत्पीड़न खेल का नाम।

इससे उत्पन्न बहस जयराम रमेश की मूर्खता टिप्पणी, सही ढंग से डब की गई "नस्लवादी", एक पूर्ण विकसित नस्लवाद बनाम सांप्रदायिकता मुद्दा बन गया है। मानो कोई

दूसरे से बेहतर। महाराष्ट्र में गड़बड़ जारी है एक और स्तर। कौन होगा सोचा है कि प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी ख़त्म हो जाएंगे शरद पर लड़ाई पवार? या यह कि यह होगा " एक "लड़ाई के बारे में गुंडा बनाम गुंडा कम दादागिरी ?

अचानक, नागरिकों में आशा की एक किरण दिखाई देती है एक नई शुरुआत, अधिक शांतिपूर्ण युग। शायद हम सभी भ्रमित हैं और बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। लेकिन जनता का उत्साहपूर्ण मूड इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है, और लोग अधिक आसानी से साँस ले रहे हैं इन दिनों, और बात कर रहे हैं जितना उन्होंने किया है उससे अधिक स्वतंत्रतापूर्वक एक दशक में। क्या यह जादू करता है डर के मनोविज्ञान का अंत? क्या हम अपने कंधों पर नज़र रखना बंद कर देंगे

देखो हमारा पीछा कौन कर रहा है? हमारे फोन टैप किये जा रहे हैं? हर महत्वपूर्ण निगरानी सोशल मीडिया पोस्ट? भी इतनी जल्दी इतनी गुलाबी तस्वीर खींचना चित्र, विशेष रूप से तब से जब आकर्षक विकल्प इसके अलावा, दस वर्ष एक लम्बा समय है, और पहली पीढ़ी के मतदाता अब बीस की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं और बड़े हो गए हैं प्रतिबंधों को स्वीकार कर लिया गया उनके प्रारंभिक दौर में उनके लिए, 200 मिलियन सह-नागरिकों के बारे में अपमानजनक प्रवचन और स्पष्ट रूप से गलत प्रतिनिधित्व सुनना "सामान्य" है, जो

मुसलमानों के लिए यह सामान्य बात है नफरत के साथ बड़े हो जाओ और विभाजनकारी भावना हावी विषयों. यह लेने जा रहा है अब समय आ गया है उन कहानियों को तोड़ने का जो उनके प्रभावशाली दिमाग में क्या घुस गया। और क्या परिवर्तित पाठ्यपुस्तकों के मनगढ़ंत इतिहास के साथ? कौन बदलेगा इन्हें और कब? किसी तरह, मैं नहीं हूँ बिलकुल भी चिंतित नहीं हूँ। अगर कुछ है, मुझे पूरा विश्वास है। जानते हो क्यों? क्योंकि, दिन के अंत में, हमेशा जीत होती सचाई है।

इंस्टाग्राम हैंडल @ShobhaaDe; ट्विटर हैंडल @DeShobhaa

पत्र

परिवार को टीका लगवाएं

नवीनतम रिपोर्ट लैंसेट लगभग 150 मिलियन बच्चों को बचा लिया गया पिछले 50 वर्षों में टीकाकरण के कारण विश्व स्तर पर आशाजनक है और रेखांकित करता है प्रतिरक्षण का महत्व, जो लंबे समय से मनुष्यों की रक्षा करता रहा है

कुछ सबसे अधिक के खिलाफ घातक बीमारियाँ दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। टीकाकरण से बचाव होता है जीवन बचाता है, शिशु मृत्यु दर कम करता है, और प्रकोप को रोकता है संक्रामक रोगों से, स्वस्थ समुदाय सुनिश्चित करना और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना बच्चों के भविष्य के लिए। अगर हम देखना जारी रखना चाहते हैं जीवन बचाने के लिए हमें यह करना होगा टीकाकरण में निवेश जारी रखें। यह एक नागरिक कर्तव्य है टीकाकरण सुनिश्चित करना अपने आप को और अपने परिवार को.

आर. शिवकुमार
चेन्नई

अपना मत डालें

एक घर में आग लग गई। लेकिन हार्डी ने इसे बुझाने की कोशिश नहीं की। वह बैठा हुआ इसे फैलता देखता रहा घर के बाहर एक कुर्सी. लॉरेल, पर दूसरी ओर, एक हैंडपंप के पास गया, एक बाल्टी में पानी भरा और फेंका पानी को आग में डाल दिया। लॉरेल समझ गया कि उसे जल्दी से काम करना होगा। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह क्या कर सकता था क्या आस-पास पर्याप्त पानी है? लॉरेल के बाद से जब उसने पेट्रोल से भरा एक डिब्बा देखा तो उसने तुरंत आग में डाल दिया! जब लोकतंत्र विफल हो जाता है, तो कुछ लोग वोट का बहिष्कार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हार्डी ने किया था आग को देखते हुए। लेकिन कुछ अन्य की इमारत को और अधिक नुकसान पहुंचाना नफरत का सहारा लेकर लोकतंत्र को नष्ट करना और उनकी बातचीत में हिंसा और उनके कार्यों के साथ-साथ उनके विचार भी।

सुजीत डे
कोलकाता

केस ओवरलोड

के दो मौलिक सिद्धांत न्यायशास्त्र - "जेल नहीं जमानत" और "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष" — हैं कानूनों के तहत लाए गए मामलों में कमजोर जैसे कि PMLA. संक्षेप में, ऐसा कानून सबूत का बोझ दूसरे पर डाल देता है एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि 450 प्रतिशत आरोपी पहली बार पीएमएलए मामलों में प्रतिशत वृद्धि मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल के तीन साल की तुलना में

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले कार्यकाल में भी इसी अवधि में यह उपलब्धि हासिल की थी। ईडी की शक्तियों पर अंकुश लगाना सही है पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी।

शंकर पॉल
चकदाहा, पश्चिम बंगाल

फारुख धोंडी

पत्तागोभी और किंग्स

क्या ट्रम्प खड़े हो सकते हैं? यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी

अगर जेल हुई तो? सुनक का परेशानियां बढ़ रही हैं

"यह फल देता है
लेकिन इसकी छाया में शरण लो
आपका हृदय-विदारक दर्द तीव्र है
अब पता चला कि प्यार हुआ था आप
तुम्हें खुशी और परीक्षा लाओ
देने के लिए तुम्हारा गधा सभी मीलों के बारे में सोचता है —
क्या उसकी दिशा सूचक यंत्र"

— होलीबोली से, बच्चू द्वारा

अमेरिका, ब्रिटेन, और जल्द ही परिणाम भारत में 4 जून को चुनाव होंगे... हम अपना मतदान करेंगे दुनिया के चौबीसों घंटे... इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं

बाकी सभी से पहले, कट्टरपंथी रूस ने दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया था टेंशन में। इस चौंकाने वाले परिणाम की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? इतना करीब!!! सभी लोकप्रिय संभावित चुनौती देने वाले - वे जो दसवें स्थान से बाहर निकल गए अपने अभियान के हिस्से के रूप में फर्श की खिड़कियाँ; जिन्होंने उन विमानों को उड़ा दिया जिनमें वे उड़ रहे थे; जिन्होंने साइबेरियाई गुलाग में खुद को जहर दे लिया इस विश्वास के साथ कि यह उन्हें सिंहासन तक ले जाएगा क्रेमलिन में बैठे ज़ारों के, जिन्होंने परमाणु जहर और नोविचोक को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था। उनका यह भ्रमपूर्ण विश्वास कि इससे रूसी मतदाताओं को उनकी सराहना करनी चाहिए...

रूसी "चुनाव" के "विजेता", के अलावा यूक्रेनियनों की सामूहिक हत्या करने से और भर्ती हुए सैनिकों की गंभीर क्षति को नजरअंदाज करते हुए उसकी अपनी सेनाओं को नुकसान उठाना पड़ा है, अब ले लिया है "वैगनर" भाड़े की सेना का प्रभार जिसका नेता येवगेनी प्रिगोझिन की उसने हत्या कर दी थी, और उन्हें नाइजर, बुर्किना फासो और में तैनात किया गया है माली इन मुस्लिम विरोधियों का सफाया कर देगा तानाशाही। वह इन मुस्लिम विपक्ष को लेबल करता है बदले में, "जिहादी" और "आतंकवादी" तत्वों को शामिल किया गया। व्लादिमीर पुतिन को सोने तक लाभदायक पहुंच है और यूरेनियम जो उप-अल्जीरियाई में प्रचुर मात्रा में हैं पश्चिमी अफ्रीका.

और अब, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आने वाले अमेरिकी चुनाव ट्रम्प का अदालत में जाना पिछले कुछ हफ़्तों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और फिर भी, मुक़ाबले के इस चरण में, यह नीतियों, इरादों और वादों का टकराव नहीं रह गया है। कोई उम्मीद कर सकता है कि यह एक ऐसा मामला होगा जिसमें कोई भी पक्ष या विपक्ष एक साथ नहीं आ पाएगा। अमेरिकी चुनाव में आव्रजन, गर्भपात, मुद्रास्फीति, स्वास्थ्य योजनाओं आदि पर बहस होगी।

बेरोज़गारी, एलजीबीटी+ अधिकार, विदेश नीति, इजराइल या यूक्रेन आदि के लिए हथियार। लेकिन नहीं! आने वाले अमेरिकी के बारे में पढ़ें चुनाव आत्म-प्रशंसा का अभियोग है डोनाल्ड ट्रम्प पर झूठे दावे करने के 34 आरोप चुप रहने के लिए पैसे देने के बाद वित्तीय कर रिकॉर्ड उसने दो महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए थे।

सख्त कानूनी दृष्टि से, 34 मामले इस प्रकार हैं: "कथित" अपराध, लेकिन अपराध का जारी रहना सभी मीडिया पर विस्तृत समाचार कवरेज मुझे मजबूर करता है खुद को जूरी के सदस्य के रूप में कल्पना करना, और जब उनसे पूछा गया कि क्या विग्वर्म पर आरोप के अनुसार वह दोषी है, हालांकि मुकदमा अभी पूरा होना बाकी है, फिर भी मैं जवाब दूंगा: "क्या पोप कैथोलिक हैं?"

और फिर भी, और फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में जनमत सर्वेक्षण राज्यों का कहना है कि विग्गी का दृढ़ समर्थन उसकी आपराधिकता, उसकी शानदार मूर्खता को नजरअंदाज करता है कोविड-19 के लिए ब्लीच के घातक इंजेक्शन की वकालत करने में, उनकी स्त्री-द्वेष, नस्लवाद, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट रूस के साथ रिश्ते, 6 जनवरी को लोकतंत्र पर उनका हमला और बीस अन्य कारक जो

उसे सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए या रवांडा भेज देना चाहिए। इसके बजाय, उसका "आधार" (दोनों इंद्रियाँ?) रखना चाहता है उन्हें व्हाइट हाउस में लाकर अमेरिका को मजबूत बनाया पुनः भोला!

सर्वेक्षणों का कहना है कि अमेरिका में चुनाव बहुत नज़दीक हैं कॉल करने के लिए। यह एक दिलचस्प परिदृश्य है। मान लीजिए विग्गी दोषी पाया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। क्या वह अभी भी खड़ा रह सकता है राष्ट्रपति पद के लिए? और अगर वह जीतता है, तो क्या संघीय जेल उनके कार्यालय के बजाय काम करता है व्हाइट हाउस? हम उत्सुकता से उस स्थान पर नज़र रखते हैं।

और इसलिए, प्रिय पाठकगण, अब ब्रिटेन के चुनावों की बात करते हैं, कानून के अनुसार जनवरी 2025 तक इसे वापस बुलाना होगा। हेजगी सूनगोन को सुनामी की मार झेलनी पड़ी हाल के सप्ताहों में। मई में स्थानीय चुनावों में, उनका पार्टी ने स्थानीय परिषदों में अपनी आधी सीटें खो दीं - स्थानीय स्तर पर नगर पालिका पंचायतों का प्रभार मामले.

वे महत्वपूर्ण सदन में पराजित हुए। कॉमन्स उपचुनाव उसी दिन हुए और हार गए पश्चिम का बहुत प्रतिष्ठित मेयर पद मिडलैंड्स। टोरीज़ ने केवल एक मेयर को बरकरार रखा पद - टीसाइड में लॉर्ड बेन हाउचेन का। उन्होंने टोरी का उल्लेख किए बिना ही प्रचार किया पार्टी, सत्ताधारी पार्टी से दूरी बनाए रखती है वेस्टमिंस्टर में पार्टी। जब उन्होंने अपनी मई- मौखिक रूप से, स्थानीय सुधारों पर अभियान चलाना हेगडी ने दावा किया कि उसने यह उपलब्धि हासिल कर ली है, टोरी पार्टी की एकमात्र जीत का लाभ उठाना टीवी फुटेज में, हाउचेन की शारीरिक भाषा से हेडगी के राजनीतिक कोढ़ का पता चलता है।

हेज-फंड-बाबा के लिए और भी अधिक कष्ट हाल के सप्ताहों में। नेतृत्व प्रतिस्थापन के हर उम्मीदवार ने अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि टोरीज़ को हार की ओर ले जाना और उसका अनुसरण करना हेजगी को अंतरतारकीय अंतरिक्ष में ले जाया गया। और अब दो प्रमुख टोरी सांसदों ने सदन का रुख बदल लिया है और लेबर पार्टी में शामिल हो गए।

उनमें से एक, डॉक्टर टॉम पॉल्टर ने कहा कि वह टोरीज़ के कामकाज के तरीके से मोहभंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को बंद करना। ठीक है। अन्य दलबदलू, नताली एल्फिके, के पास एक फर्म है एक समर्पित दक्षिणपंथी टोरी के रूप में प्रतिष्ठा।

वह फर्श पार कर गई और उसका स्वागत किया गया लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारमर का स्वागत, हालांकि हेगडी के लिए क्रॉच में एक लात, नहीं था लेबर पार्टी में सर्वत्र समर्थन प्राप्त, एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि सुश्री एल्फिके को चंगेज खान का अधिकार क्या था और वह क्या थी क्या आप उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं?

ऐसा नहीं है कि लेबर को किसी विशेष तरीके से नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। गाजा पर छाया मंत्रिमंडल का रुख, युद्ध विराम की मांग को लेकर मतदान में भाग न लेने के कारण मुस्लिम सांसदों और पार्षदों को अलग-थलग कर दिया गया जैसे शहरों की मुस्लिम मतदाता आबादी ओल्डम। लेकिन, ज़ाहिर है, वे मतदाता आगे नहीं बढ़ेंगे टोरीज़ के लिए। अल्लाह हू अकबर!

Machine Translated by Google

The Hindustan Times
ई एस्टेट बिल्डिंग 1 9 24

{ हमारा विचार }

अमेरिकी चुनाव दुनिया को आकार देंगे

डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ी बढ़त हासिल है लेकिन जो बिडेन को कम मत आंकिए। यह एक खुला चुनाव है जो किसी भी तरफ जा सकता है

इ हर अमेरिकी चुनाव परिणामकारी है, न केवल अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी। लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो चुनाव उतना ही परिणामकारी रहा है जितना कि आगामी चुनाव देखें मतदाता तय करते हैं कि जो बिडेन को फिर से चुनना है या नहीं इस नवंबर में डोनाल्ड ट्रम्प को व्हाइट हाउस में वापस लाना है। वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में, बिडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से किसी भी महत्वपूर्ण प्राथमिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा और अगस्त में शिकागो में पार्टी सम्मेलन में आधिकारिक रूप से इसके उम्मीदवार बन जाएंगे। एक पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने अमेरिकी राजनीति के हर मानदंड को खिड़की से बाहर फेंक दिया, 2020 के चुनाव हार गए लेकिन सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को रोकने का प्रयास किया, और 91 आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, ट्रम्प को रिपब्लिकन प्राइमरी के भीतर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

लेकिन यह उनके आधार पर पकड़ का प्रमाण है कि ट्रम्प ने जीत हासिल की और जुलाई में मिल्वौकी में होने वाले पार्टी सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। इस सप्ताह, दोनों उम्मीदवारों ने जून और सितंबर में एक-दूसरे के साथ बहस करने पर सहमति जताई।

यह चुनाव अनूठा है, क्योंकि मतदाताओं को एक ऐसे राष्ट्रपति के बीच चयन करना होगा जो दोबारा जीतने पर 82 वर्ष के होंगे और एक पूर्व राष्ट्रपति जो जीतने पर 78 वर्ष के होंगे। यह अनोखा है क्योंकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के आधार खंडित हैं। जबकि बिडेन को इजरायल युद्ध पर अपने रुख और विश्वविद्यालयों द्वारा विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके के लिए मुस्लिम-अमेरिकियों, प्रगतिवादियों और उदार युवा मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ट्रंप ने अपने कथित अपराधों से हैरान उदारवादी रिपब्लिकन को अलग-थलग कर दिया है, और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके अधीन चार और साल अमेरिका के लोकतंत्र और इसके वैश्विक नेतृत्व के लिए क्या मायने रख सकते हैं। यह अनोखा है क्योंकि यह चुनाव एक महिला के अपने शरीर पर अधिकार के मुद्दे को केंद्र में रखता है, जब ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवारों ने न्यायिक संतुलन को झुका दिया और गर्भपात के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खत्म कर दिया। यह अनोखा है क्योंकि एक पार्टी के संभावित उम्मीदवार ऐसे मामलों में उलझे हुए हैं जहां वह खुद को आरोपों से बचा रहे हैं

वर्गीकृत फाइलें चुराना, चुनाव परिणामों को बदलने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालना, चुनाव परिणामों के प्रमाणीकरण में बाधा डालना, तथा न्यूयॉर्क में चल रहे मुकदमे में, एक वयस्क फिल्म को चुप कराने के लिए पैसे देने हेतु व्यावसायिक अभिलेखों में हेराफेरी करना
अभिनेत्री। यह अनोखा है क्योंकि ट्रम्प ने सबसे विध्वंसकारी घरेलू नीति एजेंडे का वादा किया है, जिसमें अवैध अप्रवासियों का बड़े पैमाने पर निर्वासन और अमेरिका की सभी जलवायु प्रतिबद्धताओं को उलटना और कट्टरपंथी बाहरी शामिल हैं

एजेंडा, जिसमें अमेरिकी सरकार के साथ स्पष्ट पुनर्वार्ता शामिल है
यूरोपीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और सभी आयातों पर 10% टैरिफ।

अमेरिकी चुनावी प्रणाली की ख़ासियतों का मतलब है कि दुनिया का भविष्य अनिवार्य रूप से छह से सात स्विंग राज्यों में केवल दसियों हज़ार वोटों पर टिका होगा। फिलहाल, पोल बताते हैं कि ट्रम्प के पास स्पष्ट बढ़त है। अवैध आव्रजन और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दे, एक अधिक अमूर्त भावना कि बिडेन नौकरी के लिए बहुत बूढ़े हैं और अव्यवस्था में दुनिया की अध्यक्षता कर रहे हैं, और हिस्पैनिक और यहां तक कि अश्वेत मतदाताओं के समर्थन में उछाल ट्रम्प की मदद कर रहा है। लेकिन बिडेन हमेशा से ही अंडरडॉग बनकर फलते-फूलते रहे हैं। अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, जलवायु और बुनियादी ढांचे और विनिर्माण में निवेश और स्वतंत्रता की सुरक्षा से लेकर उनके शासन का रिकॉर्ड प्रभावशाली है। उनके पास ट्रम्प की तुलना में कहीं अधिक पैसा है, महिला मतदाता रिपब्लिकन से नाराज़ हैं, और जैसे-जैसे मतदान का दिन नज़दीक आता है, यहाँ तक कि प्रगतिशील मतदाता भी जो चाहते हैं कि

इस समय मतदान से दूर रहने वाले लोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह बहस अमेरिका की एक स्वस्थ विशेषता है, जो अपनी लोकतांत्रिक गिरावट का सामना कर रहा है, इससे नागरिकों को उन दो उम्मीदवारों का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा, जिन्हें वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

बीएसपी के बावजूद दलित वोट एक नहीं है

देश की आबादी में 16.6% हिस्सेदारी रखने वाले दलित, भारत के लोकतंत्र और चुनावी नतीजों के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते कि वे राज्यों में समान राजनीतिक विकल्प विकसित करें।

सुनील घोष/एचटी फोटो

पहचान की राजनीति दलितों की विकासात्मक आकांक्षाओं से टक्कर लेगी

बद्री नारायण

डब्ल्यू
दलित किसे वोट देंगे?
मौजूदा लोकसभा चुनावों में क्या हो रहा है?
सवाल यह है कि
कई लोगों द्वारा दो कारण पूछे गए-
बेटे: एक, दलितों की पकड़-
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा), महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) और अन्य पार्टियों का नेतृत्व भाजपा ने किया है।
विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके)
तमिलनाडु काफी हद तक कमजोर हो गया है, और
दो, मुख्यधारा के राजनीतिक दल जैसे
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस
दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए वे आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं।

दलितों की जनसंख्या 16.6% है।
देश की जनसंख्या, एक भूमिका निभा सकती है
निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका
भारत के लोकतंत्र और चुनावी नतीजों का स्वरूप, यदि वे समान रूप से विकसित होते हैं
राज्यों में राजनीतिक विकल्प। वे
पंजाब जैसे राज्यों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इनका है

(31.9%), उत्तर प्रदेश (20.5%), और
तमिलनाडु (18%) और बिहार, पश्चिम बंगाल और
तमिलनाडु में उनकी अच्छी-खासी उपस्थिति है।
हिमाचल प्रदेश।

हालाँकि, मतदान पैटर्न का विश्लेषण
पिछले कुछ दशकों में दलित आबादी के बीच जो रुझान देखने को मिला है, उससे कोई अखिल भारतीय रुझान सामने नहीं आता।
उन्होंने कई कारणों से अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों को वोट दिया है। कुछ राज्यों में
(यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) में, उन्होंने दलित नेतृत्व वाली पार्टियों (बीएसपी, आरपीआई और वीसीके) के पक्ष में अपने वोटों को एकजुट किया।

विभिन्न राष्ट्रीय और के बीच विभाजित किया गया है
क्षेत्रीय पार्टियां।

मौजूदा चुनावों में दलितों की राजनीतिक पसंद में तीन रुझान दिखाई दे रहे हैं।
मतदान में एक भी पैटर्न संभवत: मायावी होगा
इस बार भी तथाकथित दलित वोट मिल सकता है।
विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के बीच बंटा हुआ है।
क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना कुछ हिस्सा हासिल कर सकती हैं
दूसरा, अगर कोई अखिल दलित रुझान है,
यह प्रभुत्वशाली के लिए प्राथमिकता होगी
राष्ट्रीय पार्टी, जिसने उनका विश्वास हासिल कर लिया है
उन्हें बढ़ी हुई भागीदारी प्रदान करके
राजनीति, विकास और शासन में तीसरा,
भारतीय ब्लॉक की ओबीसी-केंद्रित राजनीति (जाति जनगणना) के प्रति दलित मतदाताओं की प्रतिक्रिया।

हालांकि दलितों की एक बड़ी संख्या वोट कर सकती है
उत्तर में भाजपा को वोट, दक्षिण में वोट
कांग्रेस और कांग्रेस के बीच विभाजन हो सकता है।
भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियां। कांग्रेस के भी संभावित उम्मीदवार
कर्नाटक और तेलंगाना में जहां पार्टी सत्ता में है, वहां दलितों के अच्छे वोट पाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है।
लोकसभा सीटों के लिए मुख्य दावेदार
वोटों का बड़ा हिस्सा बीएसपी और बीजेपी को मिलेगा।
बसपा दलितों के नेतृत्व वाली है, इसलिए राज्य में उनका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है।
जाटव/गैर-जाटव रेखा पर विभाजित हो जाना - जाटव
अनुमान है कि दलितों में इनकी संख्या 11.7% है।
वहां की आबादी बहुत ज़्यादा है। जाटवों के प्रति वफादारी की संभावना है
गैर-जाटव बसपा के साथ बने रहेंगे
भाजपा के साथ जा सकते हैं। जबकि बसपा
पहचान भागफल से लाभ,
मतदाताओं का एक वर्ग आकर्षित हो सकता है
सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति एक कारण
आगे विकास की इच्छा, और
अपील और सफलता के कारण भी
केंद्र के मौजूदा सामाजिक क्षेत्र का
और कल्याणकारी योजनाएँ। शायद
इस बात को स्वीकार करते हुए बीएसपी
सुप्रीमो मायावती लगातार लाभार्थी पर हमला बोल रही हैं

भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजनीति) की राजनीति
केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है।

बसपा ने चुनावी समर की शुरुआत हमला बोलकर की
भाजपा और इंडिया ब्लॉक दोनों, जिनमें से
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा)
सदस्यों के नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले,
बसपा ने उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर पहले से घोषित उम्मीदवारों की सूची वापस ले ली है और
इसके तुरंत बाद मायावती ने आकाश को पार्टी से बाहर कर दिया।

यहां तक कि एक बड़ी संख्या के रूप में दलितों में से कितने वोट कर सकते हैं?
उत्तर में भाजपा के लिए, दक्षिण में वोटों में भारी अंतर हो सकता है। के बीच विभाजित हो जाओ
कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय पार्टियाँ

आनंद, उनके भतीजे और उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी,
उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए बयान दिया था।
विश्लेषकों के एक वर्ग ने कहा कि ऐसा किया गया
भाजपा की ओर से दबाव, लेकिन मायावती और
बीएसपी जानबूझकर तीखे बयानों से बचती रही है
अन्य दलों और सामाजिक वर्गों के खिलाफ हमले
दशकों से ऐसा हो रहा है क्योंकि पार्टी समझती है
कि वह केवल दलितों के बल पर सत्ता में नहीं आ सकती
समर्थन। अन्य सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त करना
मायावती ने समावेशी विकास पर जोर दिया
ऐसी भाषा जो राजनीतिक दुश्मनी को बढ़ावा न दे
और सामाजिक तनाव। उसने यह भी सलाह दी है
बसपा के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं करेंगे आयोजन
विजय रैलियों और उनके संयम बरतने के लिए
राजनीतिक जीवन। उन्होंने कहा है कि बीएसपी
यह सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक मिशन भी है।

उम्मीदवारों को बदलने का निर्णय भी लिया जाना चाहिए।
इस संदर्भ में देखा जा सकता है। इसे शायद इस संदर्भ में लिया गया हो
भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक कारणों से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बसपा द्वारा की गई हत्या के कुछ दिनों बाद
अपने उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी सिंह की जगह ली,
पति पूर्व सांसद धनंजय सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया
भाजपा को समर्थन। अपने शासन के 10 वर्षों में
संघ स्तर पर भी भाजपा सफल रही है
दलितों के बीच और बदलते परिवेश में "हिंदुत्व चेतना" का बीजारोपण और सुदृढ़ीकरण करना
राजनीतिक परिवेश में, इससे आकर्षण बढ़ेगा
पार्टी। ऐसा कहा जाता है कि, कुछ लोग अभी भी इससे परे देख सकते हैं
बसपा/भाजपा के बीच विभाजन पैदा हो गया है और इस प्रकार एक वर्ग खंडित हो गया है
कांग्रेस-सपा के बीच वोटिंग का नतीजा
अन्य पार्टियां भी मैदान में हैं।

भारत ब्लॉक का ध्यान जाति जनगणना पर
कई लोगों में निराशा पैदा हो सकती है
युवा दलितों। यह महत्व की वजह से है
जाति जनगणना से अन्य पिछड़ा वर्ग को
वर्ग (ओबीसी) कोर। भारत में कई पार्टियाँ
ब्लॉक ओबीसी की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए जाना जाता है
युवा दलित इस मामले में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं
ओबीसी नेतृत्व वाली राजनीतिक दुनिया। अगर यह अंतर्धारा
जमीनी स्तर पर बढ़ता है, यह महत्वपूर्ण रूप से हो सकता है
इससे भाजपा और बसपा को फायदा होगा।

पंजाब में दलित वोट बंट जाएंगे
आम आदमी पार्टी, अकाली दल और
कांग्रेस, क्योंकि बसपा उसकी एक फीकी छाया है।
पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जन्मभूमि में दलितों के लिए दलित पहचान आधारित व्यवस्था थी।
विकल्प अनुपस्थित है, दलित जीतने की धारणा के साथ चलते हैं, प्रमुख
सामाजिक का अनुसरण करते हैं
समूह, अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए वोट करें
अपनी जाति के आधार पर निर्णय लें, या व्यक्तिगत सहमति के आधार पर निर्णय लें
संलयन.

जैसा कि स्पष्ट है, कोई भी सर्वदलित समुदाय नहीं है।
राजनीतिक विकल्प, हालांकि लाभार्थी राजनीति
भाजपा उसे लाभ देती है।
जिसका दलितों के बीच अभी भी प्रभाव है
दक्षिण भारतीय राज्यों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है
बदलते स्वरूप के बीच इस प्रभाव को बनाए रखें
और दलित लामबंदी का संदर्भ।

बद्री नारायण निर्देशक हैं।
जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद।
व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

चीन-रूस धुरी दुनिया को और विभाजित करने के लिए तैयार

मोहन कुमार

आर अमेरिकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भुगतान किया
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन की राजकीय यात्रा
चीन में 16 और 17 मई को पुतिन का दौरा हुआ।
पूरे सम्मान के साथ प्राप्त किया गया, लेकिन
यात्रा प्रतीकात्मकता पर लंबी थी और कुछ हद तक
सारहीन। लेकिन भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से
परिप्रेक्ष्य में, इससे अधिक की कल्पना करना कठिन है
किसी एक राष्ट्राध्यक्ष की महत्वपूर्ण यात्रा
एक और।

यह स्मरण करने योग्य है कि पहले
राष्ट्रपति पुतिन का राजकीय स्वागत
यात्रा के दौरान, चीन में पश्चिमी देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आए,
जिन्होंने अपने-अपने देशों के बारे में बताया।
वही संदेश: चीन को अभ्यास करना चाहिए
रूस के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें
यह सैन्य सहायता की बात आती है, और यह
रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए राजी करने हेतु अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करना चाहिए
यूक्रेन। इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के विदेश मंत्री
एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की यात्रा पर हैं।
अप्रैल में बीजिंग से कहा कि रूस इसे ढूंढ लेगा
चीन के समर्थन के बिना यूक्रेन में युद्ध जारी रखना असंभव है। उन्होंने आगे कहा कि अगर
चीन ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, फिर "अमेरिका"
जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ थे
अधिक अस्पष्ट लेकिन चीन से इसका उपयोग करने के लिए कहा
युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर प्रभाव डालना। फ्रांस
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ
यूरोपीय संघ (ईयू) आयोग के अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा
चीन की भूमिका के बारे में यूरोपीय संघ की लाल रेखाएँ
यूक्रेन में संघर्ष में.

इसलिए यह पूछना महत्वपूर्ण है कि क्या शी जिनपिंग
जिनपिंग ने उपरोक्त बातों पर कोई ध्यान दिया?
चीन में पुतिन से मुलाकात के दौरान उन्होंने काफी नसीहतें दीं।
जवाब स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। संयुक्त वक्तव्य में एकमात्र सकारात्मक संकेत यह है कि
चीन और रूस का मानना है कि वे यूक्रेन में आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक समाधान चाहते हैं। लेकिन
यह संयुक्त में एक संदर्भ द्वारा संतुलित किया गया है
पश्चिम की “ब्लॉक मानसिकता” के खिलाफ बयान। दरअसल,
दोनों देश उत्तरी अटलांटिक के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं
संधि संगठन (नाटो) और
AUKUS. वास्तव में, संयुक्त वक्तव्य
विशेष रूप से सूचीबद्ध अमेरिका की मिसाइल
रक्षा प्रणालियाँ, उच्च परिशुद्धता वाले गैर-परमाणु हथियार और तैनाती
यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में मध्यम और छोटी दूरी के हथियार।

यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो शी ने एक और धमकी दी
पश्चिम को धोखा देने के लिए सहमत होना
रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस, अपने
उन्होंने कहा कि यह सब चीन की शांति योजना के लिए था।
यूक्रेन। यह 12 सूत्री योजना, अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई है
सामान्यताओं को कोई महत्व नहीं मिला
वेस्ट द्वारा निर्मित यह फिल्म पिछले वर्ष रिलीज हुई थी।

व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, जहां
दोनों देश अभूतपूर्व तेजी का आनंद ले रहे हैं, जो दोनों के लिए मुख्य चुनौती है
देशों के सामने चुनौती यह है कि वे अपने व्यापार को कैसे "डी-डॉलराइज़" करें
पूरी तरह से। पहले से ही उनका 90% व्यापार होता है
स्थानीय मुद्राओं में भुगतान निपटान
सिस्टम जिसे वे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

शी जिनपिंग नहीं चाहेंगे कि पुतिन युद्ध हारें, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनका समर्थन करने का फैसला कर लिया था। एपी

प्रगति दर्ज की गई हो सकती है, लेकिन चीन
इस मुद्दे में एक प्रणालीगत रुचि है
इसकी संभावित वजह से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताएं
ताइवान से संबंधित कार्रवाइयां। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ चीनी
कंपनियां सैन्य तकनीक जैसे चिप्स मुहैया करा रही हैं

रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, अब तक चीन पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं
बैंकों को वैश्विक स्तर पर अलग नहीं किया गया है
स्विफ्ट जैसी वित्तीय प्रणाली। अगर ऐसा होता
अगर ऐसा हुआ तो चीन को नुकसान होगा। इससे यह बात स्पष्ट होती है
रूस के साथ व्यापार के मामले में चीन अपेक्षाकृत सतर्क है।

दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र का पुरजोर बचाव किया
न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ प्रणाली और
लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्थापित बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है।
यह स्पष्ट रूप से "नियम-आधारित" को अस्वीकार करना है
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" जिसका अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने विरोध किया है।
इसके विपरीत, चीन ऐसा करने से कतराएगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, विशेषकर यदि
इसका मतलब था जापान और भारत को इसमें शामिल करना।

इन सबका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है
दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे।
दिलचस्प बात यह है कि इसमें "कोई सीमा नहीं" का अभाव है
अपनी साझेदारी का अन्यथा वर्णन करते हुए
बहुत ही विस्तृत संयुक्त वक्तव्य। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि,
"साइबेरिया 2 की शक्ति" पाइपलाइन पर कोई सहमति नहीं थी, जो कि बहुत ही दिलचस्प है
रूस के लिए। दरअसल, GAZPROM के मुख्य कार्यकारी
चीन में पुतिन के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे और
अलग से ईरान की यात्रा पर थे
उसी समय।

यह भी स्पष्ट है कि पुतिन ही “मांगकर्ता” हैं
रिश्तों में और चीन की बहुत जरूरत है
शी जिनपिंग को इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा करेंगे।
पुतिन युद्ध हार जाएं, यह निर्णय लेकर
शुरुआत में ही उनका समर्थन किया गया। लेकिन यूक्रेन में मौजूदा
गतिरोध शी के लिए कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इससे
यूरोप और अमेरिका को उलझाए रखता है
यह यूरोप पर केन्द्रित है तथा चीन से ध्यान हटाता है।
इसलिए, चीन उचित आवाजें उठाता रहेगा
(रूस के साथ) राजनीतिक समझौते के लिए
यूक्रेन में, वास्तव में इसके बारे में ज्यादा कुछ किए बिना
ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे सके
चीन ने रूस के साथ मिलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी
यूक्रेन में युद्ध का शीघ्र अंत।

तो, इन सब बातों से विश्व व्यवस्था कहाँ रह जाती है?
सामान्य रूप से और विशेष रूप से भारत में। यह स्पष्ट है
कि चीन-रूस धुरी यहीं रहेगी, और
इससे विश्व व्यवस्था और भी अधिक खंडित हो जाएगी
अब तक की तुलना में यह बहुत अधिक है। एक गिरता हुआ अमेरिकी, एक
विभाजित यूरोपीय संघ, अशांत पश्चिम एशिया, नाराज
रूस और चिढ़ता हुआ चीन ही भारत है
वह उठकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है
सूर्य के नीचे अपने लिए। इसके लिए सभी की आवश्यकता होगी
भारत की कूटनीतिक निपुणता और चपलता
जुटा सकते हैं.

मोहन कुमार भारत के पूर्व राजदूत हैं।
फ्रांस और वर्तमान में ओपी जिंदल में डीन/प्रोफेसर
ग्लोबल यूनिवर्सिटी। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

मलयालम फिल्मों में केरल की कहानी की खोज

अनुराधा वेल्लाट

ए मलयालम सिनेमा का बड़ा हिस्सा
जो पिछले दशक में उभर कर आया है
— मोटे तौर पर नई पीढ़ी कहा जाता है
सिनेमा ने बड़े पैमाने पर प्रगतिशील दिमागों का ध्यान
आकर्षित किया है
क्योंकि वे घरेलू या अति-स्थानीय ट्रॉप्स का सहारा लेते हैं

कथानक की मुक्ति की यात्रा
महिला नायक.
आनंद एकर्षी निर्देशित
पहला नाटक ' आट्टम ' था
इस वर्ष की शुरुआत में जारी किया गया और
एक शानदार नाट्य प्रस्तुति होने के बावजूद
अपने कथानक के चित्रण में, इसने सुदीप्तो सेन की विवादास्पद
द केरल स्टोरी जैसी लहरें पैदा नहीं कीं, केरल के बाहर। दोनों
कहानियाँ महिलाओं के शरीर के बारे में हैं

और उनके उल्लंघन - फिर भी दोनों को प्राप्त हुआ
बहुत अलग स्वागत की वजह से
उनके षड्यंत्रों के इरादे। केरल की कहानी,
जिसे आम चुनावों से पहले दूरदर्शन पर प्रदर्शित करके तथा राज्य के कुछ परगनों में विशेष शो के माध्यम से नया जीवन दिया गया।

केरल को एक खिड़की के रूप में प्रचारित किया गया था
गैर-मूल निवासियों के लिए झांकने के लिए
“विद्रोही में क्या चल रहा है
राज्य"। घिसी-पिटी बातों के अलावा
केरल की महिलाओं का चित्रण,
केरल स्टोरी में गहनता से प्रयोग किया गया है
यौन हिंसा के संवेदनशील मुद्दे पर
सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाना
राजनीति। इसका उद्देश्य लोगों को बचाना नहीं है
हिंसा से महिला लेकिन
एक समुदाय को संकट से बचाने के लिए
काल्पनिक महामारी - "प्यार" का खतरा
जिहाद”।

इसके विपरीत, कोई भी हिंसा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती
आट्टम में दर्शाया गया है ।
शरीर शांत है, लेकिन उसकी लहरें सरसराती हैं।
अंजलि के लिए, जिसका किसी ने यौन शोषण किया
वह जिनके साथ काम करती है, उनके सहकर्मियों की खामोशी
और उसके बाद की उदासीनता ही सबसे बड़ी वजह है।
यह हमला खुद हमले से भी ज्यादा दुखद है।
मंच एक खाने की मेज है जो एक में बदल जाता है
अदालत कक्ष में ले जाकर पीड़िता से मुलाकात की
वही सवाल जो सोशल मीडिया पर छाए रहे
#MeToo आंदोलन के दौरान। “क्या थे
क्या तुमने शराब पी रखी थी? शायद तुम
समझौता कर लेना चाहिए।” एक पात्र ने तो यहां तक कहा कि पीड़ित के साथ जो हुआ वह “स्पर्श संबंधी भ्रम” था।

इसी तरह, जियो बेबी की द ग्रेट
इंडियन किचन (2021) और विपिन दास की जया
जय जय जय हे (2022) — दोनों महत्वपूर्ण
कला के कार्य - रेखांकित करें कि क्या बनता है
एक औसत मलयाली परिवार में एक महिला के लिए घरेलू जीवन। कुछ
आलोचकों ने तो यहां तक कहा है
बताया कि यह दोहराव था
ऐसी हरकतें जिनसे दर्शकों को निराशा हुई
ऐसी फिल्में देखना, जो बाद में शांत हो जाती हैं
उनके रेचनकारी अंत द्वारा।

बावजूद इसके सामाजिक संकेतक बताते हैं कि
उच्च साक्षरता दर की ओर अग्रसर
स्वतंत्रता और समानता की तस्वीर, वास्तविकता
केरल की हकीकत कुछ और ही है।
औरत क्या है प्रिया पॉल का किरदार
अमल नीरद के वराथन में
(2018) — नैतिक पुलिसिंग, मर्मज्ञ
पुरुष की नज़र, और प्रत्याशित यौन
उस पर हमला किया जाता है।

स्त्री-द्वेषी वास्तविकता फटकारती है
महिला अपने निर्णयों में बहुत आगे निकल जाती है
कपड़ों के मामले में, यह साक्षरता को सक्षम बनाने का आरोप लगाता है
उसकी स्वतंत्रता, उसके मूल्यों की निंदा करता है, और फिर
इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाता है। आट्टम में, अंजलि की दुर्दशा
बार-बार पूछा गया क्योंकि वह
आचरण के स्वीकृत मानदंडों से विचलित हो जाता है।

इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि "वास्तविकता क्या है"
केरल की कहानी', विशेष रूप से इसके बाद की स्थिति में
सेन की फिल्म की कहानी। हालांकि, केरल की महिलाओं की असली कहानी दुनिया भर की महिलाओं की कहानी है।
महिला सशक्तिकरण कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए जटिल सिद्धांतों की ज़रूरत नहीं है
जैसा कि राजनीतिक घोषणापत्रों में उल्लेख किया गया है
चुनावों से पहले यह सब घर पर ही सीखा जाता है,
सामाजिक मेलजोल के दौरान, और
कला जिसे हम उपभोग करते हैं। यह एक साथी मानव को एजेंसी प्रदान करने से शुरू होता है, बिना किसी
जिस मार्ग से वे वहां पहुंचते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न होती है
सशक्तिकरण के असंख्य अर्थ.

व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं

{ संपादक की पसंद }

एचटी के संपादक हर शनिवार को एक पुस्तक की सिफारिश करते हैं, जो इतिहास, संदर्भ प्रदान करती है और हाल की समाचार घटनाओं को समझने में मदद करती है

एक गड़बड़ अलगाव

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) ने चीन के साथ अपने व्यापार युद्ध को तेज कर दिया है। चीन ने अनेक आयातों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक वाहन, चिकित्सा उपकरण और कंप्यूटर चिप्स सहित। ऐसा करने में, बिडेन प्रशासन ने चीन पर ट्रम्प प्रशासन की रणनीति का पालन किया है। साथ ही, अमेरिका के आलोचक इसके मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम की ओर इशारा करते हैं, जिसके तहत अमेरिकी सरकार उभरते उद्योगों का समर्थन करने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करेगी।

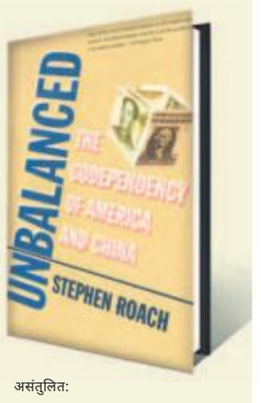

दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव की उम्मीद थी। कोविड के बाद की दुनिया में, अमेरिका चीन से दूर जाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त करने के लिए उत्सुक है। लेकिन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ शुरू से ही एक असहज आलिंगन में क्यों बंधी हुई थीं? और क्या वे दर्द से बचते हुए "जानबूझकर अलग हो सकते हैं"? मॉर्गन स्टैन-ले के पूर्व अध्यक्ष और येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एस रोच की अनबैलेंस्ड: द कोडिपेंडेंसी ऑफ अमेरिका एंड

चीन, 1970 के दशक से चीन-अमेरिकी संबंधों की आलोचनात्मक जांच, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और सुराग देता है
रिश्ते में दरार कैसे पड़ सकती है।

असंतुलित:
सह-निर्भरता
अमेरिका और चीन:
स्टीफन एस रोच
वर्ष: 2014

आरएनआई संख्या 503/1957 • डाक पंजीयन संख्या डीएल(एनडी)-11/6058/2018-19-20 'पूर्व भुगतान के बिना पोस्ट करने का लाइसेंस' लाइसेंस संख्या यू(सी)-113/2006-08, हवाई अधिभार: रायपुर और उससे आगे रेल या सड़क मार्ग से - 5 रुपए, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोयंबटूर, चेन्नई, कोचीन, गोवा, हैदराबाद, खजुराहो, मुंबई, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और उससे आगे रेल या सड़क मार्ग से - 10 रुपए;
[illegible] प्रेस में मुद्रित, पिन-201306।
बोर्ड: (011)23361234 • संपादकीय: (011)66561234 एक्सटेंशन 1254, 1268 • प्रसार: (011)66561111 • विज्ञापन: (011)66561389 • फैक्स: (011)66561270.
संपादक: कुणाल प्रधान

Machine Translated by Google

India needs to 'Grow Safe Food', curb adulteration

AFTER India witnessed in 2023 the lowest rainfall in five years, as the El Nino weather pattern made August the driest in more than a century. Agricultural production has been hit in the country. For a few years, India has been experiencing cereal shortages, fuelling a persistent surge in food inflation, despite the government placing curbs on some exports.

As if that is not enough, there has been rampant adulteration of food items, especially spices. The situation has been so concerning that a parliamentary panel has mooted that at least six year jail be awarded for food adulteration. At present, under the Indian Penal Code (IPC) Section 272 in the Bharatiya Nyaya Sanhita, the offence of "sale of noxious food and drinks" is punishable with a term extending to six months, or with a fine extending to Rs 1,000, or with both. The punishment is considered quite inadequate given the serious health issues such as food poisoning, cancer, nutritional deficiencies, increased disease risk, allergic reactions, respiratory issues, toxicity, infertility, brain damage, even paralysis.

Another disconcerting news for the Indians is increasing presence of residues of pesticides and insecticides in the food items. Pesticide residues can be found in significant amounts in many foods, including fruits, vegetables, cereals, pulses, grains, wheat flour, oils, eggs, meat, fish, poultry, bovine milk, butter, and cheese. According to ncbi.nlm.nih.gov, 95.6% of fresh fruit and vegetable samples contain multiple pesticide residues, with the most common being organophosphates, carbamates, pyrethroids, dithiocarbamates, and neonicotinoids. Such residues, when consumed regularly, are found to cause serious health risks, including: food poisoning; neurological disorders, hormonal imbalances, reproductive issues, birth defects, genetic changes, skin conditions, miscarriage, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, and cancer, too.

At a time when India is registering increasing food exports to Europe, the European Union (EU) has flagged over 400 export quality products from India for being highly contaminated. As many as 14 of the products are known to damage various organs and use dangerous elements like mercury and cadmium in fish among other products, while, 21 products including octopus and squid had cadmium, which is a toxic heavy metal, and poses serious health risks when ingested or inhaled.

Already, the Gulf countries are wary of pesticide residues in our rice exports and cut back on them. Hong Kong food regulator banned certain spice mix of two leading Indian brands MDH and Everest over presence of pesticide Ethylene Oxide in their samples.

India, which has just signed a free trade agreement (FTA) with the European Free Trade Association (EFTA), an important bloc in Europe, the other two being the EU and UK. The EFTA is made up of Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. It has potential to bring in about $100 billion investments and create 1 million direct jobs over the next 15 years.

The report on quality of Indian food exports should not be brushed aside. The authorities must wake up and address this disturbing phenomenon. For their part, the countrymen, too, who have been silently consuming adulterated food items and those with residues must mount pressure on governments to remedy the situation at once. The Food Safety and Standards (FSS) Act must not only be strengthened but must be implemented in letter and spirit. Staff shortage is a major lacuna. Merely asserting that India has one of the most stringent norms for pesticides residues in food items cuts no ice with food inspection regulators abroad. Integrated Pest Management is obviously found wanting. "Grow Safe food" Campaign must be ramped up across the country.

Elephant census to be undertaken in South Indian states

Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh forest departments will participate in the synchronised elephant census

CHENNAI: The three-day annual synchronised elephant census in four south Indian states will now commence from May 23, it was announced on Wednesday.

The elephant census for 2024 was to commence on May 17 for three days but was put off after Kerala expressed some difficulties and requested a week's extension.

Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh forest departments will participate in the synchronised elephant census from May 23.

In Tamil Nadu, the elephant study will be conducted in Coimbatore, Erode, Nilgiris, Dharmapuri, Hosur, Vellore, Tiruvanamalai, Megamalai, Srivilliputhur, Tirunelveli, and Kanniyakumari.

Tamil Nadu Forest Department officials told IANS that the number of forest staff and volunteers for the exercise would be decided in the coming days.

According to a senior official, a team of four to five members would be deputed to cover a region of around 15 km and they would walk through it from 6 am to 6 pm and assess the age and sex of the elephants directly.

The team would also find out whether any elephant has any external injuries, their tusk size, and the number of "Makhna" (tuskless male elephants) present.

They will also assess the elephant dung to differentiate between the elephants. The team will also study the elephant's behaviour and movements of these elephants.

In the 2023 census in Tamil Nadu forests, 2,961 elephants were identified, or 200 more than the earlier exercise which recorded 2,761 elephants. The 2023 elephant census was held from May 17 to May 19.

The four states would be releasing the list of elephants in each state together.

Tamil Nadu Forest Department officials told IANS that the state's Conservator of Forests, D. Venkatesh, who is also the Director of the Madumalai Tiger Reserve (MTR), will be the nodal officer for the census for the Tamil Nadu region.

Meanwhile, with an aim of avoiding train-elephant collisions, Railway Minister Ashwini Vaishnaw on Wednesday said that the national transporter has developed an indigenous software named 'Gajraj', using optical fibre cable (OFC), to issue warning to the loco pilot about any suspicious movement on or near the rail tracks.

The Minister also said that the AI-based software device has been tested successfully in Assam and will be installed in the 700 km elephant corridors spread in several states within a time period of eight months.

He also said that the entire cost of installation of Gajraj software with its device for the 700 km corridor is estimated at Rs 181 crore.

Explaining how the Gajraj technology system works, the Minister said: "In its AI-based software using OFC, alerts are issued in case any suspicious traffic is detected from the distance of 200 metres from the railway tracks.

It can also specifically tell the distance where the movement has been detected. Any mammal which walks on land has a specific movement signature. The AI-based software has been trained to even detect the number of animals at a site. The loco pilot, those in the control room and the section station master receive alerts raised upon detection of any movement.

According to the Railway Ministry data shared in Parliament in July last year, 45 elephants have died in train accidents in the last three years. On Monday, three elephants, including a calf were killed at Rajabhat Khawa in Alipurduar district of West Bengal following a collision with a goods train. The three elephants, a mother and her two babies, died on the spot.

States' role key in achieving $5 trillion economy for India

BOLD talk
V RAMU SARMA

FOUR PHASES of elections are over. The stage is set for the fifth phase where some prominent leaders including Rahul Gandhi whom the Prime Minister Narendra Modi calls as 'Shehzada' would be testing the waters from Rae Bareli. There will be two more phases before the entire poll process comes to an end. On June4, the country will know whether it is Modi 3.0 or bloc INDI who would rule the country for the next five years.

Well, the question here is not who will come to power. The question is about making India one of the world's fastest growing economies and see that it becomes the third largest by 2027 by achieving a goal of $ 5 trillion economy.

The Central government's roadmap comprises focusing on growth at the macro level and complementing it with all-inclusive welfare at the micro level, promoting digital economy and fintech. India's economy is expected to grow at a rate of 6.5% in 2024 and 2025, with technology-enabled development, energy transition and climate action and reliance on a virtuous cycle.

The government has several ongoing initiatives across sectors focused on growth. In agriculture, it aims to reorient policy focus from being production-centric to becoming income-centric. The emphasis on incomes provides a broader scope towards achieving the needed expansion of the sector. It should have a globally competitive Indian industry that is modern, sustainable and inclusive.

For that to happen, there should be a perfect eco system in the country. All states need to work to create such eco system, enhance their brand image, attract investments and generate higher revenue. This means that there should be perfect law and order situation in all parts of the country and the political executive, ruling parties and opposition should have a progressive mind set.

Unfortunately, this is one area where we are not what we should be. Opposition still feels that their job is to oppose everything and remain non-cooperative, showcasing everything the government does in poor light. The party in power feels that they should decimate the opposition.

We also have some states like Andhra Pradesh where development took a nose dive in the last five years. We have seen and heard more of arrests and victimisation of those who raised their voice against the government, political vendetta, concentration on direct cash benefit schemes and slow pace of progress regarding the ongoing projects and failure to create jobs as promised had a negative impact on its brand image.

This Telugu state has once again hit the headlines because of the kind of post poll violence that was witnessed since May 13. Here the question is not who is at fault. Apparently, there has been failure of law and order system. Though four phases of polls across the country are over so far, such a situation has been reported anywhere.

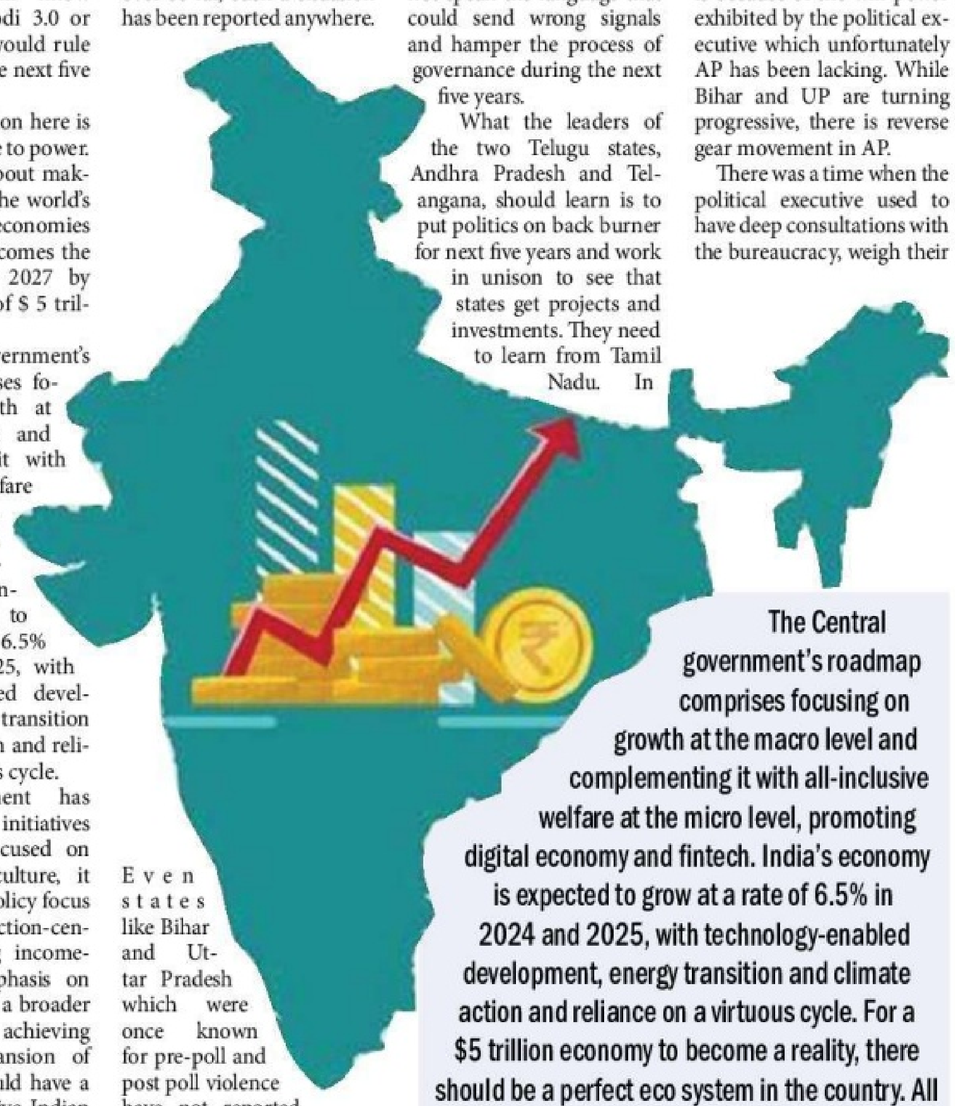

Even states like Bihar and Uttar Pradesh which were once known for pre-poll and post poll violence have not reported such incidents.

In fact, the ECI was also surprised as to why the administration failed to pre-empt such a situation though it had sent central forces in large numbers. The opposition alleges that the measures taken by the ECI like changing some SPs in various districts also did not help as there were some lower rung officials who were acting as per the diktat of the government. What is worse is that the two top officials when summoned by ECI took the stand that the post poll violence was because of personal and political rivalry. No one is willing to own the responsibility. The ruling YSRCP blames TDP saying it was they who had resorted to attacks fearing that they would lose the elections. The opposition claims that the ruling party was giving vent to its frustration as it smelled defeat. No one has the patience or decency to wait till the results are announced.

Unless such a culture changes, the state can never develop an eco system which can help the country move towards achieving $ 5 trillion economy by 2027 irrespective of whether the BJP gets 400 paar at centre or YSRCP gets 175 or the NDA alliance comes to power in Andhra Pradesh.

What the political parties and leaders should understand is that they need to put an end to all kinds of cheap comments which amounts to hitting below the belt against each other. They can tear into the policies of each other but should know their limits. They should not speak the language that could send wrong signals and hamper the process of governance during the next five years.

What the leaders of the two Telugu states, Andhra Pradesh and Telangana, should learn is to put politics on back burner for next five years and work in unison to see that states get projects and investments. They need to learn from Tamil Nadu. In Tamil Nadu, DMK and AIADMK have always been bitter rivals at the state level. But when it comes to issues pertaining to state like getting industries or projects, they become one and fight against the centre and get what they want. Even the officials at centre and in the state work at tandem so that the state benefits.

Despite being arch political rivals, the two political parties DMK and AIADMK do not indulge in the kind of post poll or pre poll violence as we had witnessed in Andhra Pradesh both in 2019 and now in 2024.

Everyone says Modi is hijacking all projects to Gujarat. How is he able to do it? Because, during his tenure as Chief Minister, Modi successfully created an atmosphere and systems which had helped in attracting investments and industries otherwise despite being PM, he would not have been able to attract that kind of investments.

When we speak of a conducive eco system, it is not just the politician, but the bureaucrats, too, should learn to be the real eyes and ears of the government and not dance to their tunes. How did things change in Bihar and UP which were known for gun culture? It is because of the will power exhibited by the political executive which unfortunately AP has been lacking. While Bihar and UP are turning progressive, there is reverse gear movement in AP.

There was a time when the political executive used to have deep consultations with the bureaucracy, weigh their suggestions, and then take a final policy decisions and the officials used to implement it. But that kind of atmosphere at least in Telangana and AP is not visible now.

Presuming that Modi-led NDA 3.0 government would come to power at the centre, it should first focus on creating repairing the systemic failures in these states so that it can move forward in the direction of $5 trillion economy. If it displays not before me kind of attitude as it did in regard to AP in last five years, its efforts to become a $5 trillion economy will hit a road block and the pace of development would slow down.

The Central government's roadmap comprises focusing on growth at the macro level and complementing it with all-inclusive welfare at the micro level, promoting digital economy and fintech. India's economy is expected to grow at a rate of 6.5% in 2024 and 2025, with technology-enabled development, energy transition and climate action and reliance on a virtuous cycle. For a $5 trillion economy to become a reality, there should be a perfect eco system in the country. All states need to work to create such eco system, enhance their brand image, attract investments and generate higher revenue. This means that there should be perfect law and order situation in all parts of the country and the political executive, ruling parties and opposition should have a progressive mind set

LETTERS

Another Jumla by BJP leaders

THIS is one more of those 'Jumlas" thrown at the electorate by the BJP. Earlier, it was about depositing Rs 15 lakh into the bank accounts of every citizen of India after bringing back black money stashed away abroad by the corrupt Congress leaders. Reclaiming PoK is not as easy as said. China has heavily invested in that area on infrastructure and therefore won't be sitting idle while India reclaims PoK by engineering some agitation there. Even though Pakistan is not in a position to provide succour to the people of PoK due to the ongoing economic crisis, it won't be keeping quiet as well. Both China and Pakistan would pose problems and might even start counter agitations in PoK in favour of remaining within Pakistan. Alternatively China might occupy PoK by paying some compensation to the cash starved Pakistan.

Govardhana Myneedu, Vijayawada

Provide big thrust to organ donation

THIS has reference to the article on 'Windows and mirrors to our souls' by Dr Mohan Kanda . The God gives wake up call to all living beings across the globe daily. To many, He says get up and to some others He says come up. As per the WHO, there are 285 million people who are blind in the world; 300 millions are deaf and 1 million as dumb. In addition, many suffer with their disabilities. Trees and the animals always look peaceful as they can not express their physical and mental discomforts. Fortunately, many humans are gifted with working organs. In addition, they have wisdom, intelligence and professional knowledge. Some, including me, are ready for their usable organs donations. Noble-minded professionals, officials and service renders shall focus frequently on organ donors so that using their organs some people can have second life!

G Murali Mohan Rao, Secunderabad

Acid test for Revanth Reddy govt

"REVANTH Reddy, the Chief Minister of Telangana, is currently facing a daunting challenge in fulfilling his election promises, more particularly regarding the crucial issue of waiving farmers' loans from Scheduled Banks at Rs 2 lakh per farmer," (Hans India, dt 16-5-24). The Telangana government is in a precarious financial situation, and is actively exploring avenues for fund mobilization and seeking ways to secure fresh loans to fulfil the commitment of waiving farmers' loans by the stipulated deadline of August 15. As CM Revanth Reddy navigates through these turbulent waters, his leadership will be tested, and the success of his administration in overcoming these challenges will significantly impact the political landscape of Telangana.

Ganti Venkata Sudhir, Secunderabad

Campaigns fail to touch upon key issues

THERE were times when the voters would look forward to hearing the speeches of leaders from both ruling as well opposition parties. At times, we used to wait for leaders like Atalji who would be late to arrive and soon after he got onto the stage, he would apologise for the delay before making the speech. In fact, he would know the pulse of the people. Over a period, campaigning style has changed totally. PM Modi is not even sparing a responsible party like BJD in Odisha which has always played a constructive role throughout. In Odisha, PM went on to challenge Odisha to list the names of districts and their capital (which I don't think exist in any state) and outsiders should not be allowed to run the government by referring to Navin Patnaik's close aide and former IAS officer Pandian. In Hyderabad, BJP candidate was seen misusing the Bharatnaryam mudras and even slokas in order to capture the attention of majority voters. It is time campaign turns more decent and is focussed on real issues.

N Nagarajan, Hyderabad

A glaring violation of constitution

THE Supreme Court declared the arrest and remand of 74-year-old journalist and online portal NewsClick founder Prabir Purkayastha "invalid in the eyes of law". He was arrested on October 3, 2023 by the Delhi Police under the Unlawful Activities Prevention Act, 1967 (UAPA). The right to be informed about the grounds of arrest flows from Article 22(1) (an arrested person shall be informed of the grounds of arrest and allowed to consult a lawyer of his or her choice) of the Constitution and any infringement of this fundamental right would vitiate the process of arrest and remand. Purkayastha was accused of using Chinese funding to promote "anti-national propaganda" through digital media. He was given a copy of the FIR only after he was remanded to police custody by a Sessions Judge at 6 a.m. on October 4, 2023.

Anandambal CK Maniam, Chennai

thehansreader@gmail.com

BENGALURU ONLINE

Passengers to be fined if they stay at Metro stations more than 20 minutes

BENGALURU: Passengers are confused about the rules of Namma Metro. There is a lot of rush and if you wait for more than 20 minutes at the station, fine is guaranteed. Recently, an incident took place at Vijayanagara metro station at 9:55 pm in which a passenger was fined for staying in the metro stations for 5 minutes more. Therefore, the passengers are revolted by these rules of BMRCL. As there is was less battery in the mobile phone, a passenger charged it at the metro station. The metro staff has asked the passenger to pay the fine before starting the journey after charging for 5 minutes. The staff has stated that you have stayed for more than 5 minutes, so you will be fined. When the passenger stated that it was raining, there was no charge, so it was late, but the metro staff did not care. The staff claimed only 20 minutes stay at the station is allowed. Even if it is only 1 minute more, the fine should be paid. Passengers have expressed outrage over the current move by Bangalore Metro Rail Corporation Limited. These rules have been in place since the inception of Metro. This is not the newly made rules. Metro officials are saying that these rules have been made so that one should not spend hours in the metro station by taking the token and not cause trouble to fellow passengers.

Read more at https://epaper.thehansindia.com

Printed & Published by K. Hanumanta Rao on behalf of M/s Hyderabad Media House Pvt. Ltd Door. No.50-753-7, Opp : R. R. Women's Hostel, Eshwar Dental Hospital Up stair, Tagore Nagar, Kurnool - 518 002
and Printed at Jagati Publications Ltd, Survey No. 726, Laxmipuram Village, Kallur Mandal, Kurnool District-518218. **Chief Editor:** V Ramu Sarma. RNI No: APENG/2015/66605

Machine Translated by Google

कुत्तों के लिए गंदी सड़कें कोई खुशहाल घर नहीं हैं

भारत में 60-80 मिलियन स्ट्रीट डॉग्स हैं, और अगले 10-15 वर्षों में उनकी आबादी में कमी देखने के लिए 90% से अधिक को बहुत ही कम समय में नसबंदी करानी होगी।

पंथ टकराव

संदीप रॉय

जुनून हो सकता है.

क्रिकेट अंततः अमेरिकी क्रांति की याद दिला रहा है। वह क्रिकेट है, कुत्ता, क्रिकेट नहीं। हाल ही में प्रकाशित उनकी आत्मकथा नो गोइंग बैक: द ट्रुथ ऑफ़ व्हाट्स रॉंग विद पॉलिटिक्स में,

साउथ डकोटा की रिपब्लिकन गवर्नर क्रिस्टी नोएम ने क्रिकेट नामक 14 महीने के पिल्ले को गोली मारने के बारे में लिखा, जिसे वह "अप्रशिक्षित" समझती थी। उसने शिकायत की कि क्रिकेट ने तीतर के शिकार में बाधा डाली, पड़ोसी की मुर्गियों को मार डाला और उसे काटने की कोशिश की। नोएम लिखती हैं, "मुझे उस कुत्ते से नफरत थी।" इसलिए वह उसे बजरी के गड्ढे में ले गई और उसे मार डाला। और जब वह ऐसा कर रही थी, तो उसने एक "बुरी और दुष्ट" बकरी को भी मारने का फैसला किया, जिसका नाम अज्ञात है।

नोएम, जो डोनाल्ड ट्रम्प के उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने की उम्मीद कर रही हैं, ने सोचा था कि यह किस्सा एक व्यावहारिक, सीधी-सादी राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को चमकाएगा, जो कठिन विकल्पों से नहीं कतराती। इसके बजाय उन्हें द्विदलीय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिकी राजनेता गाजा, कैम्पस प्रदर्शनकारियों, यूक्रेन, ब्लैक लाइव्स मैटर में हुई मौतों पर अत्यंत सख्त रुख अपना सकते हैं।

लेकिन पिल्लों का मामला अलग है। यह किसी जानवर को मारने के बारे में नहीं है। यह उसके बारे में शेखी बघारने के बारे में है। यह बिलकुल भी सही नहीं है।

दक्षिणपंथी मीडिया से जुड़े सभी लोग- वॉल्ट डिज़्नी की भतीजी, फ़िल्म निर्माता एबिगेल डिज़्नी, उस पर तीखा हमला कर रही हैं। नोएम को पहले से पता होना चाहिए था। रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी के 2012 के राष्ट्रपति अभियान में तब हलचल मच गई थी जब उन्होंने 1983 में 12 घंटे की यात्रा के दौरान अपने आयरिश सेटर (केनेल में) को कार की छत पर बांधने के बारे में एक मज़ेदार पारिवारिक कहानी सुनाई थी।

अब तो रोमनी भी नोएम को ट्रोल कर रहे हैं।

"मैंने अपने कुत्ते को नहीं खाया। मैंने अपने कुत्ते को गोली नहीं मारी।"

हफ़-पोस्ट के अनुसार, रोमनी ने कहा, "मैं अपने कुत्ते से प्यार करता था और मेरा कुत्ता मुझसे प्यार करता था।" अमेरिकी राजनीति की विचित्र स्थिति को देखते हुए, कोई नहीं जानता कि नोएम ने खुद को नुकसान पहुंचाया या वास्तव में ट्रम्प की उप-राष्ट्रपति पद की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने के अपने अवसरों को बेहतर बनाया। लेकिन कुत्ते दुनिया भर में तीव्र भावनाएं जगाते हैं। जैसा कि घर के करीब एक प्रसिद्ध राजनेता ने यादगार ढंग से कहा था कि जब कोई पिल्ला कुचला जाता है तो बुरा लगता है।

दुर्घटना में मारे गए पिल्ले के प्रति दया को हमारी मानवता का सबसे निम्नतम मानक माना जाता है। लेकिन कोई भी चीज, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी-कांग्रेस के बीच कीचड़ उछालने वाली लड़ाई भी भारत में व्हाट्सएप ग्रुपों को देश की कुत्तों की समस्या के बारे में पोस्ट करने जितना उत्तेजित नहीं करती। एक पक्ष बच्चों पर हमला करने वाले आवारा कुत्तों के झुंड की हर खबर को साझा करता है।

दूसरा पक्ष उन्हें बेरहम पिल्ले-हत्यारे कहता है। सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की है जो कुत्तों से प्यार करते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि भारत में आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रण से बाहर है और उन्हें कुछ कठोर विकल्पों की आवश्यकता है।

वे एक कुत्ते और एक कठिन परिस्थिति के बीच फंस गए हैं।

पारिस्थितिकीविद अबी टी. वनक ने इस साल की शुरुआत में मुझसे कहा था कि बहुत से लोग करुणा के नाम पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। "असली करुणा में राज्य को अधिक जिम्मेदारी लेने और अच्छी गुणवत्ता वाले आश्रयों का निर्माण करने के लिए मजबूर करना शामिल होगा। और अगर आपको लगता है कि आप आश्रयों में कुत्तों को नहीं देख सकते हैं, तो कृपया उन्हें गोद लें।" उन्हें लगता है कि सभी शुभचिंतक सड़क के कुत्तों को लगातार खाना खिलाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। "हम जितने अधिक कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उतने ही अधिक कुत्ते सड़क पर होते हैं।"

वनक एक कुत्ता प्रेमी है। उसके पास एक बचाया हुआ कुत्ता है घर में कुत्ता पालना। और उन्हें पता है कि उनके विचार कई कुत्ते प्रेमियों को परेशान कर देंगे। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में अभी 60-80 मिलियन स्ट्रीट डॉग हैं।

और कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या के साथ नसबंदी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम पर्याप्त संख्या में कुत्तों की नसबंदी नहीं करते हैं और हम यह काम पर्याप्त तेजी से नहीं करते हैं।

कुत्तों की 90% से अधिक आबादी बहुत ही कम समय में जीवाणुरहित करना पड़ता है

भूखे पिल्ले को खाना खिलाने की इच्छा को रोकना कठिन है। आईस्टॉकफोटो

वनक और अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि 10-15 साल की अवधि में कुत्तों की आबादी में 70% की कमी देखने को मिलेगी। भारत इस मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। और भारत में पशु नियंत्रण कानून बहुत कम प्रभावी हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा कुत्ता है जो लगातार काटता रहता है और पागल नहीं है, तो कोई भी कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकता।

वनक जैसे लोगों से बहुत कम लोग असहमत होंगे कि सड़कों पर कुत्तों की ज़िंदगी कोई पिकनिक नहीं है। वनक का दावा है कि पहले साल में ही 80% पिल्लों की मृत्यु हो जाती है। कुत्तों पर पत्थर फेंके जाते हैं, यातायात दुर्घटनाओं में वे अपंग हो जाते हैं, कूड़े के ढेर में भोजन की तलाश करते हैं। फिर भी हम एक पिल्ला देखते ही आह भरते हैं।

मैं कोई अपवाद नहीं हूँ।

मेरा दिमाग वनक को समझता है। जब मैं कुत्तों द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय बस्टर्ड को मारने के बारे में पढ़ता हूं, तो मैं स्तब्ध रह जाता हूं।

फिर भी भोजन करने की इच्छा को रोकना कठिन है एक भूखा पिल्ला। विकास ने हमें एक प्रजाति के रूप में एक साथ बांध दिया है। हम सोच सकते हैं कि हम कुत्तों को खाना खिलाकर उन पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वे भी हमें पोषण दे रहे हैं। एक प्रजाति के रूप में, हम उस प्यार के भूखे हैं जो एक कुत्ता दे सकता है।

कोलकाता के स्ट्रीट डॉग्स और उनके अजीबोगरीब फीडर्स के बारे में पेरिआडॉग (2019) नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले फिल्म निर्माता जेसी एल्क ने मुझे बताया, "वे सिर्फ खाना नहीं चाहते हैं। वे बहुत अकेले हैं। सबसे ज़्यादा खुजली वाले स्ट्रीट डॉग को ही ले लीजिए। अगर आपके पास खाना नहीं भी है, तो भी अगर आप उसके पास जाकर उसे सहलाएंगे, तो उनमें से ज़्यादातर पिघल जाएंगे।"

कोलकाता में हमारी गली में कुत्तों का एक बड़ा परिवार है। पड़ोसी उन्हें खिलाने, उनकी नसबंदी करवाने, उन्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाने की जिम्मेदारी लेता है। हर दिन पड़ोसी उन्हें दोपहर और रात के खाने के लिए पार्क में बुलाने जाता है और कुत्तों को साथ लेकर पाइड पाइपर की तरह लौटता है।

हमारे ही घर में चटनी का जन्म हुआ

वह चार भाई-बहनों में से एक था।

कुछ ही महीनों में तीन बच्चे कार के पहियों के नीचे दबकर मर गए। चटनी की माँ ने उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारे बगीचे में रख दिया। एक दिन जब हम टीवी देख रहे थे, तो हमने दरवाजे पर दस्तक सुनी।

जब मैंने इसे खोला, तो हमने पाया कि छोटा पिल्ला दरवाज़ा धक्का देने के बाद सचमुच पिल्ला-कुत्ते की आँखों से हमें देख रहा था। अब वह घर में आराम से रहता है। अगर गर्म रातों में एयर कंडीशनर चालू नहीं होता है तो वह नाराज़ हो जाता है, रात के खाने के बाद अमेरिकी स्नैक्स और याक के दूध के च्यूज़ खाता है, हालाँकि उसका असली प्यार मैरी बिस्किट है। वह मेरी भतीजी की शादी में अपनी कस्टमाइज़्ड लाल ब्रोकेड डॉगी "शेरवानी" में गया था।

समस्या यह है कि हमारे पास एक के लिए जगह है घर में चटनी तो है लेकिन एक दर्जन के लिए नहीं। सड़क पर उनका जीवन हमेशा जोखिम भरा रहता है। हमारी गली के दोस्ताना और शोरगुल वाले कुत्तों में से एक हैंडसम को रेबीज होने का संदेह था। किसी तरह

पड़ोसी ने उसे एक कोने में बंद कर दिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। पूरी रात वह सो नहीं पाई क्योंकि कुत्ते ने प्लास्टिक की कुर्सी को तोड़ दिया और चादरें फाड़ दीं।

अगले दिन संजय, पशु चिकित्सक से- किसी भी क्लिनिक में, वह दिखाई दिया। हम घबराए हुए थे क्योंकि उसने कुत्ते को रस्सी से बांधा और उसे सुई से छेद दिया।

“इसमें कितना समय लगेगा?” मैंने पूछा.

संजय ने कहा, "यह उसे शांत करने के लिए सिर्फ एनेस्थेटिक है।" आखिरकार, हैंडसम नीचे गिर गया और शांत हो गया।

घातक खुराक स्वीकार करते समय वह लगभग हार मान चुका था।

“वह कब मरेगा?” किसी ने पूछा।

“वह चला गया है,” संजय ने कहा।

उन्होंने हैंडसम के लिए कब्र खोदी घर के पीछे ले जाकर उसे घसीटकर वहाँ ले आया। ब्लीचिंग पाउडर में लिपटा हुआ हैंडसम अजीब तरह से नम्र लग रहा था - मानो नहाने के बाद टैल्कम लगा हो। पशु नियंत्रण करने वाले लोग कुत्तों के भूतों के बारे में मज़ाक कर रहे थे जबकि कोई कुछ फूल और बेल लेकर आया था

(बंगाल क्विंस) बाहर पेड़ से पत्ते।

"उस पर कुछ मिट्टी फेंक दो," सैन ने कहा- खुशी और हमने ऐसा किया। फिर उस कठोर सनकी आदमी ने उस पर मिट्टी डाली और कुछ प्यारा सा कहा। "बेचारा आदमी, शांति से जाओ। अगली बार बेहतर जीवन के लिए वापस आना।"

अपने घर लौटने से पहले हमने उनकी कब्र पर दो मोमबत्तियाँ जलाईं।

हैंडसम ने हमें फिर से याद दिलाया कि हज़ारों कुत्तों के लिए गंदी सड़कें कोई खुशहाल घर नहीं हो सकतीं, भले ही हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हों। वह दूसरों से ज़्यादा भाग्यशाली था कि कोई उसे खाने-पीने की चीज़ें खिलाने के अलावा उसका ख़्याल रखता था। लेकिन यह एक हैंडसम कुत्ते के लिए दुखद अंत था।

फिर भी ऐसा हर दिन नहीं होता कि कोई गली का कुत्ता रेबीज को पड़ोस से विदाई मिल जाती है।

इन विषाक्त ध्रुवीकृत समय में यह एक बात है।

कल्ट फ्रिक्शन एक पाक्षिक कॉलम है वे मुद्दे जिनसे हम लगातार जूझते रहते हैं।

संदीप रॉय एक लेखक, पत्रकार और रेडियो होस्ट हैं। वे @sandipr पर पोस्ट करते हैं

'किडफ्लुएंसर्स' को उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल में मदद करें

चूंकि सभी आयु वर्ग के बच्चे काफी समय ऑनलाइन बिताते हैं, तो यह कैसे पता लगाया जाए कि कितना समय ज्यादा है?

अवंतिका भुयान
avantika.bhuyan@htlive.com

तेरह वर्षीय एम.के. ऑनलाइन देख रहा हूँ चैनल, रयान वर्ल्ड, जब से वह 6 साल का था। भागो 12 वर्षीय रयान काजी और उनके माता-पिता द्वारा शुरू किए गए इस चैनल के खिलौनों की अनबॉक्सिंग, आसान विज्ञान प्रयोग और दैनिक जीवन के अंशों वाले व्लॉग के साथ दुनिया भर में लगभग 36 मिलियन ग्राहक हैं। एमके उनमें से एक है। जैसे-जैसे वह बड़ा होता गया, दिल्ली के इस छात्र की पसंद विशाल ईस्टर अंडे की अनबॉक्सिंग से बदलकर DIY प्रयोगों की ओर हो गई।

कोविड-19 महामारी के दौरान, जब समय मिला, तो उन्होंने कंटेंट क्रिएशन का भी प्रयास करने का फैसला किया। अपनी माँ का फ़ोन उधार लेकर, उन्होंने व्यापक रूप से उपलब्ध DIY STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) किट का उपयोग करके छोटे वीडियो बनाए।

एक बार उनके माता-पिता - दोनों ही डॉक्टर थे - उनके वीडियो को इसलिए स्वीकृति मिली क्योंकि वे शैक्षणिक सामग्री पर आधारित थे, उन्होंने इन्हें अपने दोस्तों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। प्रशंसा से उत्साहित होकर, एमके ने सोचा कि क्या उन्हें अपना खुद का चैनल शुरू करना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा के बारे में चिंतित, उनकी माँ ने सोशल मीडिया पर एक निजी पेज का सुझाव दिया, जहाँ वे जुड़ रहे फ़ॉलोअर्स पर नज़र रख सकें।

इसलिए, 2022 में, एमके ने अपनी मां के खाते से जुड़ा एक निजी पेज शुरू किया, जो घर पर उनके प्रयोगों को समर्पित था।

जब उसके दोस्तों और उसके माता-पिता के दोस्तों ने उसकी सामग्री की प्रशंसा की, तो एमके को और अधिक वीडियो डालने की इच्छा हुई। उसकी माँ उसे देर रात तक जागते हुए घर पर दोहराने के लिए प्रयोगों की तलाश करते हुए पाती थी।

पिछले साल, उसने अपने वीडियो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपकरण- एक DSLR कैमरा, माइक्रोफोन और बहुत कुछ- मांगना शुरू कर दिया। "मैंने इसे एक घरेलू प्रोजेक्ट के रूप में सोचा था- कुछ ऐसा जो उसे रचनात्मक रूप से व्यस्त रखता है। हालाँकि, यह एक व्यस्तता बन गई थी, जो उसका ध्यान भटका रही थी। उसे जो उपकरण चाहिए थे, उनमें से कुछ महंगे थे, और जब हमने उन्हें खरीदने से मना कर दिया, तो वह चिढ़ गया, "उसकी माँ, 42 वर्षीय स्त्री रोग विशेषज्ञ, आरके कहती हैं। परिवार ने पिछले छह महीनों में एमके की काउंसलिंग में काफी समय बिताया है, साथ ही उसे फुटबॉल और तैराकी जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए भी नामांकित किया है।

ऑनलाइन कंटेंट पर बहुत ज़्यादा समय बिताने से होने वाली चिड़चिड़ाहट के लक्षण दिखाने में एमके अकेले नहीं हैं—चाहे वह निष्क्रिय उपभोक्ता हों या निर्माता। “अगर मैं एक दिन में 10-12 क्लाइंट देखता हूँ, तो सात से आठ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो मुझे परेशान करते हैं।

युवा डिजिटल सामग्री निर्माता इस आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहे हैं,” डॉ. मनोज कुमार शर्मा, नैदानिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर, शट क्लिनिक (प्रौद्योगिकी के स्वस्थ उपयोग के लिए सेवा), निमहंस, बेंगलुरु कहते हैं।

जबकि इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित होता है अत्यधिक लत के मामले में, माता-पिता को उपकरण तक पहुंच से वंचित होने, या बच्चे द्वारा शुरू किए गए चैनल या पेज को अपडेट करने का अवसर न मिलने पर चिड़चिड़ाहट और क्रोध के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए।

सभी आयु वर्ग के बच्चे ऑनलाइन काफी समय बिताते हैं, ऐसे में कोई कैसे पता लगाए कि कितना समय बहुत ज़्यादा है? इसका उत्तर हर बच्चे के लिए अलग-अलग हो सकता है। आपको इस बात पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि बच्चे पर्याप्त नींद ले रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और उनका सामाजिक जीवन स्वस्थ है या नहीं। "हालाँकि, संज्ञानात्मक त्रुटि के रूप में जानी जाने वाली एक चीज़ है

शर्मा बताते हैं, "जब बच्चों को लगता है कि उनके दैनिक जीवन पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्हें डिजिटल मीडिया या कंटेंट निर्माण के साथ अपने जुड़ाव में बदलाव की ज़रूरत नहीं लगती।"

धीरे-धीरे, वे आक्रामक और मांग करने लगते हैं। हालाँकि, चूँकि उनका दैनिक कार्यक्रम ठीक चल रहा है, इसलिए उन्हें खुद पर या अपने परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का एहसास नहीं होता है। इसका समाधान परिवार के भीतर गैर-निर्णयात्मक संचार के रास्ते खुले रखने में निहित है।

माता-पिता या देखभाल करने वालों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा क्या सामग्री डाल रहा है और किस समय। शर्मा कहते हैं, "जब संचार सहयोगात्मक होता है, तो माता-पिता के लिए बच्चों का मार्गदर्शन करना आसान हो जाता है।"

आज, डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामग्री बनाने के तरीकों पर कार्यशालाएँ मिल सकती हैं (देखें 'स्कूली बच्चों को डिजिटल बनाना')

सोशल मीडिया का उपयोग करते समय समय और गोपनीयता का प्रबंधन कैसे करें, यह समझने के लिए कार्यशालाएँ आम हो गई हैं ।

एक प्रासंगिक बातचीत जो परिवारों को युवा डिजिटल सामग्री निर्माताओं के साथ करनी चाहिए, वह है बाहर निकलने की रणनीतियों पर, यहां तक कि बच्चे द्वारा सामग्री डालना शुरू करने से पहले भी।

डिजिटल माध्यम के साथ प्रयोग करते समय समय प्रबंधन और अपनी गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों पर मॉड्यूल हैं ।

मुंबई की एक परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक खुशनाज़ नोरस का मानना है कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन के लिए उनके पास आने वाले किशोरों को वह एक सरल बात सुझाती हैं: अच्छी सामग्री और वायरल सामग्री के बीच अंतर जानें।

"अच्छी सामग्री वह हो सकती है जिसे 50 बार देखा गया हो और 10 लाइक मिले हों, लेकिन गुणवत्ता और मूल्य के मामले में वह उच्च स्थान पर हो। दूसरी ओर, वायरल होने वाली कोई चीज़ वह हो सकती है जिसमें कोई व्यक्ति कैमरे की ओर देख रहा हो, जिसके ऊपर कोई प्रसिद्ध उद्धरण लिखा हो, और वह दस लाख लोगों तक पहुँच सकती है। लाइक गुणवत्ता के अनुपात में नहीं होते," वह विस्तार से बताती हैं।

भले ही एक व्यक्ति को इससे लाभ मिला हो जो अपलोड किया गया है, वह अच्छी सामग्री है।

माता-पिता को भी खुद से पूछना चाहिए कि क्या उनके बच्चे का कंटेंट क्रिएटर होना उनके लिए अहंकार बढ़ाने वाला है। नोरस कहते हैं, "क्या वयस्क लोग समूहों में यह शेखी बघार कर इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि उनके बच्चे के वीडियो को हज़ारों व्यूज़ मिले हैं? याद रखें, जब एक वीडियो हज़ारों तक पहुँचता है और दूसरा सिर्फ़ सैकड़ों तक, तो आपके बच्चे को कमतर महसूस होगा। नौ से 10 साल के बच्चों को जीवन में इस तरह की प्रतिक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है।"

"हर बच्चे को यह समझना होगा कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए, और माता-पिता यह समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।"

एक उचित बातचीत जो परिवारों को करनी चाहिए वह है बाहर निकलने की रणनीतियों पर, बच्चे के कंटेंट डालना शुरू करने से पहले भी। नोरस कहते हैं, "हमें उन्हें आश्वस्त करने की ज़रूरत है कि जब भी वे चाहें, चैनल या पेज बंद करने के फ़ैसले में उनका पूरा समर्थन किया जाएगा।" बच्चे इस बात से सुरक्षित महसूस करते हैं कि बाहर निकलने की रणनीति मौजूद है, और इस तथ्य को लगातार दोहराया जाता है कि वास्तविक दुनिया आभासी दुनिया से स्वतंत्र है। कोई भी आपको वास्तविक जीवन में मिलने वाले लाइक और व्यू से याद नहीं रखेगा।

कठोर वास्तविकता यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने का अर्थ अक्सर स्वयं को साइबर बदमाशी और ट्रोलिंग के लिए खुला छोड़ना होता है।

इस संदर्भ में एक मार्मिक मामला उज्जैन के 16 वर्षीय स्वयं-शिक्षित मेकअप कलाकार प्रांशु का है, जिसने घृणित समलैंगिक-विरोधी टिप्पणियों के कारण नवंबर 2023 में आत्महत्या कर ली।

बच्चे अपनी मानसिक सुरक्षा को बरकरार रखने के बारे में सीख सकते हैं, भले ही इसका मतलब टिप्पणी अनुभाग को अक्षम करना हो। बहुत से मामलों में, चूंकि पेज और अकाउंट माता-पिता द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, इसलिए बच्चों को कभी भी सार्वजनिक फ़ीडबैक तक पहुँच नहीं मिलती है।

एक अन्य विकल्प यह है कि चैनलों और पेजों को निजी रखा जाए, तथा उनके खाते उनके माता-पिता पर निर्भर हों, जिन्हें सुरक्षा उल्लंघनों, टिप्पणियों आदि के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहेगी।

नोरस ने सुझाव दिया, "बच्चों को बताएं कि अगर वीडियो में आप जो दिखा रहे हैं, उससे अलग कुछ भी हो जाता है - जैसे कि आप कला से संबंधित कुछ दिखा रहे हैं - और लोग, चाहे वे आम लोग हों या सहकर्मी, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, आपके दिखने के तरीके या आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पृष्ठभूमि के लिए आपको शर्मिंदा करते हैं, तो पूरी तरह से टिप्पणी बंद कर दें और अपना दिमाग बंद कर लें।" "अगर कोई आपके जीवन को मुश्किल बना रहा है, तो उसे ब्लॉक करने, हटाने में संकोच न करें।"

Machine Translated by Google

EDITORIAL

इंडियन एक्सप्रेस एक उद्योग नहीं है। यह एक मिशन है।

— रामनाथ गोयनका

मजबूत व्यापार संबंधों को रोका जा सकता है वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ

अप्रैल में भारत का व्यापार घाटा चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसकी मुख्य वजह सोने और तेल के आयात में उछाल है। निर्यात में जहां 1.07 प्रतिशत की निराशाजनक वृद्धि देखी गई, जो 35 बिलियन डॉलर हो गई, वहीं आयात में 10.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 54.1 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे घाटा बढ़कर 19.1 बिलियन डॉलर हो गया। सोने का आयात तीन गुना बढ़कर 3.11 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि तेल आयात में पिछले साल के मुकाबले पांचवां हिस्सा बढ़ गया। इन दोनों के अलावा, दालों, फलों, सब्जियों और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित 14 अन्य आयातित वस्तुओं की टोकरी में भी उछाल देखा गया। इसी समय, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण सहित शीर्ष 30 वस्तुओं में से 17 के निर्यात में कमी आई। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर निर्यात-आयात असंतुलन जारी रहा तो रुपया और चालू खाता घाटा (सीएडी) दबाव में आ सकते हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, तेल और सोने की कीमतें ऊंची बनी रहने पर CAD 2024-25 में 1 प्रतिशत बढ़ सकता है, जबकि 2023-24 में यह 0.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा अस्थिर पूंजी प्रवाह और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता को भी जोड़ दें, तो डॉलर के मुकाबले रुपया 84 के करीब पहुंच सकता है।

अधिकांश अन्य देशों की तरह भारतीय निर्यात भी वैश्विक मंदी, ब्याज दरों में सख्ती और व्यापार, निवेश और व्यापार में सुस्ती से प्रभावित हो रहा है। मामले को और जटिल बनाते हुए, पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष और लाल सागर संकट जैसी भू-राजनीतिक चुनौतियाँ वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रही हैं, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2023-24 में कुल 238 गंतव्यों में से भारत का निर्यात 115 देशों तक बढ़ गया है - जो हमारे निर्यात बास्केट का 46.5 प्रतिशत है। शीर्ष 10 गंतव्यों को निर्यात 13 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें यूएई प्राथमिक निर्यात केंद्र के रूप में उभरा। यदि सिंगापुर, चीन और यूके को निर्यात में दो अंकों की स्वस्थ वृद्धि देखी गई, तो रूस, रोमानिया और अल्बानिया जैसे अन्य देशों में तेजी से वृद्धि देखी गई,

व्यापार संबंधों को मजबूत करने से वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और मेक इन इंडिया अभियान जैसी पहलों, जिनमें विशेष रूप से स्मार्टफोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, को और अधिक उत्पादों तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को लगातार व्यापार रणनीतियों को संशोधित करना चाहिए, घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए और निर्यात बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में हुए समझौतों ने उन बाजारों तक पहुंच का विस्तार किया है। व्यापार वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे और समझौते किए जाने चाहिए।

एक बुरा पड़ोसी कचरे का प्रबंधन

जब बात आती है तो ERALA एक आदतन अपराधी रहा है

क तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमावर्ती गांवों और जंगलों में बायोमेडिकल कचरे सहित कचरे का अवैध डंपिंग। जबकि दशकों पुरानी यह प्रथा अंतर-राज्यीय तनाव और प्रभावित लोगों के बीच गुस्से का कारण रही है, केरल ने इसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया है। यहां तक कि कचरे के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए तैनात वाहनों पर जीपीएस ट्रैकर लगाने का उसका हालिया फैसला भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उकसावे पर आया है, जिसने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है।

रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। डंपिंग का जारी रहना उत्पन्न कचरे से निपटने में प्रणालीगत विफलता का प्रतीक है और अपर्याप्तताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), जिसे एनजीटी ने जांच का जिम्मा सौंपा था, ने केरल की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में महत्वपूर्ण खामियों की ओर इशारा किया है। इसने पाया कि केरल अपने द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का केवल 30 प्रतिशत ही संभालने में सक्षम है। एक रिपोर्ट में, सीपीसीबी ने राज्य सरकार और क्लीन केरल कंपनी, अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित एक सरकारी एजेंसी की गैर-जिम्मेदाराना होने और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी के लिए आलोचना की। रिपोर्ट में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रह और बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों द्वारा इसके प्रबंधन में खामियों को भी उजागर किया गया है, जिससे अवैध अपशिष्ट प्रवाह को बढ़ावा मिल रहा है जो राज्य के पड़ोसियों के लिए एक खतरनाक बोझ बन गया है। इसने राज्य की सीमाओं पर अपशिष्ट आंदोलन की निगरानी के लिए एक प्रणाली की अनुपस्थिति के बारे में भी बात की और एक कार्य योजना का सुझाव दिया जिसमें पर्याप्त उपचार और निपटान सुविधाओं की स्थापना और जैव चिकित्सा अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन शामिल है।

जब 2023 में कोच्चि के ब्रह्मपुरम डंप यार्ड में लगी आग ने केरल के सामने कचरा प्रबंधन की चुनौतियों की गंभीरता को उजागर किया, तो जल्दबाजी में कई योजनाएँ बनाई गईं। लेकिन एक साल बाद भी राज्य के पास उन चुनौतियों का जवाब नहीं है।

एक जिम्मेदार राज्य के रूप में, उसे अपने यहां उत्पन्न होने वाले कचरे को संभालने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। इसे कहीं और फेंकना अच्छे पड़ोसी के व्यवहार को दर्शाता नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहरीले कचरे के लापरवाही से निपटान के माध्यम से जीवन को खतरे में डालना पूरी तरह से अपराध है।

इसमें शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए-कार्रवाई ट्रकों को जब्त करने और ड्राइवरों को गिरफ्तार करने से आगे बढ़कर जिम्मेदार प्रतिष्ठानों और एजेंसियों को दंडित करने तक सीमित होनी चाहिए। केरल को सुझावों को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने और अपने पड़ोसियों के हित में अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित करना चाहिए।

त्वरित ले लो

अगले छेत्री की तलाश

बाईचुंग भूटिया के बाद, सुनील छेत्री ने [illegible] गोल के साथ, वह अपने देश के लिए गोल करने के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई और लियो मेसी के बाद दूसरे स्थान पर हैं। मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में छेत्री का नेतृत्व कोचों की पीढ़ियों के लिए अमूल्य रहा है। अब जबकि उन्होंने घोषणा की है कि वह कुवैत के खिलाफ अगले विश्व कप क्वालीफायर के बाद 39 साल की उम्र में संन्यास ले लेंगे, तो नए गोल-गेटर की तलाश में तेजी आनी चाहिए। छेत्री की जगह भरना एक कठिन काम होगा और क्षितिज अनिश्चित दिखता है। क्या लिस्टन कोलाको, मनवीर सिंह या अनिरुद्ध थापा आगे बढ़ पाएंगे?

एम का रूपांतरणकारी वर्गीकरण दलबदलू और ट्रांसपोलिटिकल

ओडर्न युद्ध- जिसमें उद्योग, अर्थव्यवस्था और भू-राजनीति का परस्पर प्रभाव है- इतना खतरनाक है कि इसे जनरलों पर छोड़ना उचित नहीं है। युद्ध के लिए भारी मात्रा में उपकरण, गोला-बारूद और जनशक्ति की आवश्यकता होती है। 20वीं सदी के दो विश्व युद्धों में मित्र राष्ट्रों की सफलता बेहतर औद्योगिक क्षमताओं पर आधारित थी। पश्चिमी शक्तियाँ वर्तमान में अपने ग्राहक देशों के लिए हथियार बनाने में रूस और चीन की बराबरी करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारी विनिर्माण को हथियार बनाने के लिए ज़रूरी मानक से कम करके उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता दी है। इसके विपरीत, उनके विरोधियों ने सैन्य विनिर्माण और संघर्ष के लिए इन्वेंट्री बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। पश्चिमी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, जो अक्सर निजीकृत होते हैं, अब क्षमता और वृद्धि क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं।

संघर्ष को बनाए रखने की क्षमता का आधार अर्थशास्त्र है। पश्चिमी-सज्जित यूक्रेन और इज़राइल के पास बेहतर पारंपरिक गोलाबारी क्षमता है। लेकिन सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके असममित युद्ध और कम तकनीक वाले सुधार संतुलन को बदल सकते हैं, खासकर शत्रुता के बढ़ने को मापकर।

इजरायल ने ईरान के सुनियोजित हमले को विफल करने के लिए गोला-बारूद और ईंधन पर लगभग 1.4 बिलियन डॉलर खर्च किए (जो उसके वार्षिक रक्षा बजट का लगभग 6 प्रतिशत है) जिसकी लागत शायद 30 मिलियन डॉलर थी। यमन में हूथियों ने सस्ते ड्रोन का उपयोग करके परिवहन मार्गों को बाधित कर दिया है। अल-कायदा के 911 ऑपरेशन की लागत

यदि वर्तमान रक्षा और सुरक्षा व्यय को ध्यान में रखा जाए तो 500,000 डॉलर से कम के निवेश से खरबों डॉलर का नुकसान हुआ।

'खिलौनों के साथ लड़के' सिंड्रोम महंगे हाई-टेक हथियारों में एक मार्मिक विश्वास को प्रेरित करता है। रखरखाव और संचालन में मुश्किल F35 जेट विमानों की कीमत लगभग 150 मिलियन डॉलर प्रति जेट है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत 1 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसमें प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 6-10 मिलियन डॉलर है। भारी युद्धक टैंक प्रत्येक 6-10 मिलियन डॉलर के हैं। व्यक्तिगत तोपखाने के गोलों की कीमत 3,000-5,000 डॉलर है। पश्चिमी हथियार अक्सर रूसी और चीनी समकक्षों की तुलना में दोगुने महंगे होते हैं। कई वास्तविक युद्ध स्थितियों में अप्रभावी साबित हुए हैं क्योंकि दुश्मन अपनी रणनीति को समायोजित करता है।

कम लागत वाले हथियारों की बड़ी मात्रा के कारण, बेहतर ढंग से सुसज्जित सेनाओं को सीमित लाभ के लिए पर्याप्त संसाधन खर्च करने पड़ सकते हैं।

इसका उद्देश्य शत्रु को आर्थिक रूप से कमजोर करना तथा लम्बे युद्ध की सीमित इच्छा रखने वाले विरोधियों के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ाना है।

जैसा कि रूसी नेता जोसेफ स्टालिन समझते थे, मात्रा की अपनी गुणवत्ता होती है।

सैन्य कार्रवाई के लिए वित्तपोषण की क्षमता को कम करना आवश्यक है। रूस द्वारा औद्योगिक और कृषि अवसंरचना को निशाना बनाने और मानव शक्ति के विस्थापन के कारण यूक्रेनी उत्पादन में 30-35 प्रतिशत की कमी आई है। पुनर्निर्माण की लागत लगभग 500 बिलियन डॉलर है। यूक्रेन को यह करना होगा

कम लागत वाले हमले आज बेहतर सुसज्जित सेनाओं को सीमित सैन्य लाभ के लिए पर्याप्त संसाधन खर्च करने पर मजबूर कर रहे हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावित कर रहा है

अर्थशास्त्र घर्षण का बदलते युद्ध

सत्यजीत दास

पूर्व बैंकर और लेखक

सौरव रॉय

चूक से बचने के लिए देश के 20 अरब डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय ऋण का पुनर्गठन किया जाएगा।

ग़रीब, सहायता पर निर्भर गाजा का विनाश आर्थिक रूप से व्यर्थ है, सिवाय इसके कि निवासियों को बाहर निकाला जाए, जिससे अंततः यहूदी बस्तियों के लिए रास्ता साफ हो जाए। इसके विपरीत, इज़राइल की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है, शायद 20 प्रतिशत तक। सस्ते फ़िलिस्तीनी श्रम के नुकसान ने निर्माण और कृषि-संस्कृति को पंगु बना दिया है। सैन्य सेवा के लिए रिजर्विस्टों को बुलाए जाने और प्रतिभाओं के पलायन ने इसके उद्योगों को बाधित कर दिया है। इज़राइल की उत्तरी सीमा पर झड़पों ने लगभग 60,000 इज़राइलियों को निकालने की आवश्यकता पैदा कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक अव्यवस्था और पुनर्वास लागत हुई है। संघर्ष की अब तक की लागत $50 बिलियन से अधिक (जीडीपी का 10 प्रतिशत) ने इज़राइल के ऋण को काफी बढ़ा दिया है और इसकी क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया गया है।

यूक्रेन और इजरायल पश्चिमी देशों के समर्थकों पर निर्भर हैं। अमेरिका, नाटो और उनके सहयोगियों ने यूक्रेन को सैन्य, वित्तीय और मानवीय सहायता के रूप में 175 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है, जिसका वित्तपोषण मुख्य रूप से सरकारी उधारों द्वारा किया गया है। कई यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित ऋण सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। अपनी स्थापना के बाद से, इजरायल, अपनी उच्च आय के बावजूद, अमेरिकी विदेशी सहायता का सबसे बड़ा संचयी प्राप्तकर्ता रहा है - कुल आर्थिक और सैन्य सहायता और ऋण गारंटी में 300 बिलियन डॉलर (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित)। स्वतंत्रता और नरसंहार के अपराध के लिए दिखावटी सेवा के बावजूद, दाता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों को सैन्य सहायता पर रोक लगाने वाले घरेलू कानूनों से भी समर्थन को खतरा है।

अर्थव्यवस्था का हथियारीकरण आम बात है। लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाने से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है।

कई देशों ने वित्तीय और वैचारिक प्रोत्साहनों के कारण उन्हें दरकिनार करने में मदद की है, इसलिए वे अप्रभावी रहे हैं। दशकों से अलगाव और पश्चिम से सतर्कता का मतलब है कि रूस और चीन आत्मनिर्भर स्वायत्त देश हैं, जिनकी बाहरी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता सीमित है। वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे कि इज़राइल, कम विदेशी निवेश और प्रतिबंधों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जैसा कि रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका ने पाया है।

दुश्मन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिशें उल्टी पड़ सकती हैं। अमेरिकी हथियार उत्पादन अब दुश्मनों से टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी की आपूर्ति से बाधित है। रूसी ऊर्जा उत्पादन को प्रतिबंधित करने की कोशिश करने के बाद, पश्चिम खुद को कीमतों को दबाने की कोशिश करता हुआ पाता है। जैसा कि गाजा युद्ध से पता चलता है, अर्थशास्त्र और भू-राजनीति अप्रत्याशित दीर्घकालिक परिणामों के साथ प्रतिच्छेद कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अस्थिरता ने स्वेज नहर के माध्यम से पर्यटन और यातायात को कम कर दिया है। सऊदी अरब ने NEOM मेगा-प्रोजेक्ट में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कठिनाई का अनुभव किया है। मिस्र और जॉर्डन में फिलिस्तीनियों का पलायन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर कर देगा। प्रभावित राष्ट्र एक त्वरित समाधान चाहते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब पर इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए दबाव डाला, जिससे एक संयुक्त अरब मोर्चे से खतरा कम हो गया। सऊदी अरब को अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता और परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए समर्थन मिल सकता है। इससे विदेशी निवेश और इजरायली तकनीक तक उसकी पहुंच में सुधार होगा और साथ ही ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

वास्तविक अघोषित अनिवार्यता पश्चिम में अरब राजतंत्रों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह देखते हुए कि उनकी 90 प्रतिशत से अधिक आबादी फिलिस्तीनी कारण का समर्थन करती है, एक कथित विश्वासघात एक नए 'अरब स्प्रिंग' का जोखिम उठाता है। खाड़ी, मिस्र और जॉर्डन में बढ़ते घरेलू तनावों के साथ दमनकारी जवाबी उपायों की आवश्यकता है, नागरिक संघर्ष और अलोकप्रिय वंशानुगत शासनों का पतन असंभव नहीं है।

ऐसी अस्थिरता, जिसे निवेशक बर्दाश्त नहीं करते, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती है। खाड़ी देशों के पास क्रमशः वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस भंडार का 30 प्रतिशत और 21 प्रतिशत हिस्सा है। ऊर्जा की कीमतें प्रभावित होंगी, खासकर अगर 1970 के दशक की तरह हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। इससे स्वेज नहर व्यापार प्रभावित होगा।

गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से, चीन से यूरोप तक एक कंटेनर के परिवहन की लागत 1,000 डॉलर से चार गुना बढ़कर 4,000 डॉलर हो गई है, तथा यात्रा का समय भी दो सप्ताह तक बढ़ गया है।

लेकिन अगर अरब देश इजरायल के खिलाफ एकजुट होते हैं, तो संघर्ष में वृद्धि भी संभव है, जिसके परिणाम भी ऐसे ही होंगे। पश्चिमी लक्ष्यों के खिलाफ गैर-सरकारी तत्वों द्वारा की जाने वाली आतंकवादी कार्रवाई हमेशा मौजूद जोखिम है।

जैसा कि सन त्जु ने युद्ध कला में बताया है, जो लोग लड़ना चाहते हैं उन्हें पहले इसकी कीमत समझनी होगी।

(ये मेरे निजी विचार हैं)

जे हैरी पॉटर की निर्माता के. राउलिंग कुछ प्रमुख ट्रांसजेंडरों को मान्यता देने या सम्मान देने से इनकार करने के बाद विवादों में घिर गई हैं, जो महिला बन गए हैं। उन्होंने सफल ट्रांस-महिला फुटबॉल मैनेजर लूसी क्लार्क को "सीधी, गोरी, मध्यम आयु वर्ग की महिला" बताकर लोगों का ध्यान खींचा।

माधवन नारायणन

वरिष्ठ पत्रकार

रिवर्स स्विंग

मैं ट्रांसजेंडर राजनीति में नहीं उलझना चाहता, लेकिन भारत में आम चुनावों के बीच में मैंने देखा कि उपसर्ग 'ट्रांस' के कई उपयोग हैं। मुझे एक नए शब्द की याद आती है जिसका इस्तेमाल एक गरीब व्यक्ति के लिए किया जाता है जो खर्च करना पसंद करता है - ट्रांसफाइनेंशियल, एक अमीर व्यक्ति जो एक गरीब व्यक्ति के शरीर में फंसा हुआ है।

यह मेरे लिए एक नए शब्द पर पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रेरणा है: ट्रांसपॉलिटिकल। ट्रांसपॉलिटिकल वह व्यक्ति होता है जिसे एक राजनीतिक जनजाति से माना जाता है, लेकिन वह एक नई पहचान के साथ दूसरे में चला जाता है। इस सीज़न में मेरा पसंदीदा उदाहरण वी कार्तिकेय पांडियन है, जो तमिल में जन्मे आईएएस अधिकारी से राजनेता बने हैं और ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के रूप में हलचल मचा रहे हैं। भाजपा अचानक 'ओडिया अस्मिता' या पहचान के नुकसान से परेशान है, लेकिन पांडियन ने अनुप्रास और तुकबंदी के लिए तमिल लोगों के शौक को ओडिया की सभी चीज़ों के प्रति अपने प्यार के साथ मिलाते हुए कहा: "मैं जन्म से भारतीय हूँ, सॉस से ओडिया हूँ।"

पांडियन उड़िया भाषा में पारंगत हैं और मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू उड़िया हैं और धाराप्रवाह तमिल बोलते हैं, और पांडियन की तरह ही आईएएस अधिकारी भी हैं। साहू एक ट्रांसपॉलिटिकल अधिकारी होने के बजाय एक ट्रांसफर होने वाले नौकरशाह हैं।

लेकिन आप ट्रांसपॉलिटिकल्स को टर्नकोट्स के साथ भ्रमित नहीं कर सकते, जो एक अलग समूह हैं और खबरों में बहुत अधिक हैं। ट्रांसपॉलिटिकल्स बस वे हैं जो अलग पहचान रखते हैं, जबकि टर्नकोट दलबदल करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और टर्न-कोट एक बहुत व्यापक शब्द है। मैं उन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव करता हूं। आप केवल "नीला" नहीं कह सकते जब शाही नीला, नेवी ब्लू, आसमानी नीला और फ़िरोज़ा नीला हो। तो, यहाँ दलबदलुओं का एक सूक्ष्म वर्गीकरण है।

दलबदलू प्रजाति का सबसे आम सदस्य अवसरवादी होता है, जो तब दल बदल लेता है जब उसे लगता है कि पार्टी में उसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसा करने का परिष्कृत तरीका यह कहना है कि पार्टी नेतृत्व पहुंच से बाहर है। इस प्रजाति का एक बेहतर सदस्य वह होता है जो अचानक लंबी नींद से जागकर यह घोषणा करता है कि उसकी पार्टी अब वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी।

नमूना: पूर्व कांग्रेसी जो इस आधार पर पार्टी छोड़ देते हैं कि पार्टी धन सृजनकर्ताओं के खिलाफ है। जब यह पता चला

> जब राजनीतिक वफ़ादारी आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों की तरह बेची जाती है, तो हमें उनकी श्रेणियों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। राजनीतिज्ञ कुंभकरण की एक उप-प्रजाति, जो अचानक जागते हैं और महसूस करते हैं कि वे गलत जहाज पर हैं, वह प्रवक्ता है जो उन बुराइयों को खोजता है जहाँ उसने पहले गुण देखे थे

पोलिटिकस कुंब-हकारनस की एक उप-प्रजाति वह व्यक्ति है जो पार्टी का प्रवक्ता हुआ करता था और अचानक उसे गुण दिखाई देने के स्थान पर दोष दिखाई देने लगते हैं। कांग्रेस ने इस वर्ष कम से कम तीन प्रवक्ताओं को खो दिया है, जो त्वरित-निर्णय दलबदल के कारण हैं। करीब से देखने पर, आप पाएंगे कि दलबदलू लोग वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए पार्टी में नहीं थे, बल्कि प्राइम-टाइम चिल्लाने वाले मुकाबलों में अपनी अभिव्यक्ति कौशल के लिए थे। वकीलों की तरह, वे बस बेहतर क्लाइंट के लिए समझौता करते हैं। हम उन्हें क्लाइंट सर्वर कह सकते हैं-

लेकिन समान विवरण वाले नेटवर्क कंप्यूटरों के साथ भ्रमित न हों।

फिर वोट बैंकर हैं। यह एक पेचीदा किस्म है। उनकी पहचान

राजनीतिक रूप से जुड़े दिग्गजों की आलोचना के बहुत बाद की घटना को आप ट्रांस-पॉलिटिकल कह सकते हैं, क्योंकि वे एक लंबी नींद से जागते हुए दिखते हैं। हम उन्हें रिप वैन विंकल के बाद रिप वैन अंकल कह सकते हैं, लेकिन यह पर्याप्त भारतीय नहीं होगा। मेरे लिए, वे राजनीतिक कुंभकार हैं। अब, यह बेहतर काम करता है।

वे किसी भी समय किसी एक राजनीतिक दल के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन अपनी जाति, समुदाय, क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के प्रति समर्पित सदस्य होते हैं। वे पार्टी की वफादारी बदलते हैं लेकिन अपनी जनजाति के प्रति वफादार रहते हैं। आप तमिलनाडु में वन्नी-यार के नेताओं, कर्नाटक में लिंगायतों और उत्तरी राज्यों में ओबीसी के कुछ चुने हुए सदस्यों के बारे में सोच सकते हैं जिनकी वफादारी आईपीएल नीलामी में खिलाड़ियों की तरह बेची जाती है।

फिर ऐसे लोग आते हैं जो राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखकर अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुंचाने के लिए पाला बदल लेते हैं। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली, जो पहले भाजपा में थे, कांग्रेस में चले गए और अब भाजपा में वापस आ गए हैं। उनका कहना है कि यह उनका आखिरी पड़ाव है, लेकिन हम यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि उनकी गारंटी काम करती है या नहीं। उनकी घूमने-फिरने की राजनीति को देखते हुए, मैं उनके जैसे लोगों को रिवॉल्वर कहना चाहता हूँ। लेकिन यह उन लोगों के लिए गलत नाम है जो न तो बहुत बढ़िया हैं और न ही सीधे-सीधे निशाना साधते हैं। उन्हें आया गया कहना सबसे अच्छा है, भारतीय राजनीति में 'आया राम, गया राम' संस्कृति की शुरुआत करने वाले राजनेताओं की शाश्वत याद में। पर्यटक रिसॉर्ट के व्यवसाय में उनके योगदान को भी मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि यह वह प्रकार है जो लक्जरी स्पॉट में तब भी जमा हो जाता है जब प्रतिद्वंद्वी पार्टियाँ विश्वास मत में लोगों की संख्या को लेकर चिंतित होती हैं। हालाँकि, मैं उन्हें रिवर्स स्विंगर नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन सा रास्ता उल्टा है।

दलबदल के लिए ऑस्कर उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें मैं एसेट मैनेजर कहता हूँ। उन्हें उन पेशेवरों के साथ भ्रमित न करें जो आपके म्यूचुअल फंड या शेयरों का प्रबंधन करते हैं। ये वे लोग हैं जो पक्ष बदलकर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। आप ऐसे उद्योगपतियों की कल्पना कर सकते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए पार्टी संबद्धता बदलते हैं कि उनकी संपत्ति कानून लागू करने वालों के निशाने पर न आए। हालाँकि, इस श्रेणी में मेरा पसंदीदा एक पूर्व मंत्री है जिसे बीटल्स नंबर के बाद एक प्रसिद्ध पत्रकार ने 'बंगला बिल' नाम दिया था।

उनका सिद्धांत यह था कि इस राजनेता की वफादारी इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी पार्टी लुटियन दिल्ली के हृदय में स्थित उसके विशाल बंगले को बचाए रखने में उसकी सबसे अधिक मदद करती है।

(ये मेरे निजी विचार हैं)
(एक्स @मैडवर्सिटी पर)

MAILBAG

WRITE TO: letters@newindianexpress.com

सांसद की विनम्रता

संदर्भ: (न्यूज टुडे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने [illegible] निवास

नेता को यह शोभा नहीं देता कि जब उनकी ही पार्टी की एक महिला सांसद पर उनके ही एक पुरुष सहयोगी ने हमला किया तो वे चुप रहें। सरकार को महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराध से जुड़े ऐसे मामलों में सभी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

उल्लात्तिल पकितेरी रघुनाथन, त्रिशूर

देर से कार्रवाई

यह शर्म की बात है कि केजरीवाल ने हाथ नहीं बढ़ाया। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। अब एफआईआर दर्ज हो गई है। यह छेड़छाड़ का स्पष्ट मामला है। अगर राजनीतिक वर्ग के हाथों में एक मौजूदा सांसद की यह दुर्दशा है, तो एक आम महिला की दुर्दशा के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना अच्छा है।

श्रवण रामचंद्रन, चेन्नई

चिकित्सा लापरवाही

संदर्भ: उंगली के बदले जीभ! डॉक्टर ने बच्चे की सर्जरी में गलती (17 मई)। यह पीड़िता और उसके परिवार के लिए वाकई दुखद है। हाल ही में चिकित्सा लापरवाही बढ़ रही है। गलत आंख का ऑपरेशन, ट्यूबेक्टोमी का असफल होना और इसी तरह के अन्य मामले सामने आए हैं। सरकार को स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने से पहले ही उसे ठीक करना चाहिए।

एनआर रामचंद्रन, चेन्नई

बदनाम हुई प्रतिष्ठा

यह बहुत ही भयानक है कि जिस डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, उसने बिना यह जांचे कि बच्चे को अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया है, लापरवाही से उंगली के बजाय जीभ का ऑपरेशन कर दिया। यह पेशे के प्रति उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के होने से इस महान पेशे की छवि धूमिल होगी। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा उनका बचाव करना भी काफी चौंकाने वाला है।

एच.पी. मुरली, बेंगलुरु

संदिग्ध आचरण

चुनाव आयोग द्वारा मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने में देरी और मीडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में आनाकानी करना अच्छे संकेत नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वे सत्तारूढ़ सरकार की कठपुतली बन गए हैं।

शिहाब कट्टाथर, पुत्तूर

न्यायपालिका की भूमिका

न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक अधिकारों, खास तौर पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। प्रक्रियागत खामियों के कारण यूएपीए के तहत उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य करार देकर, अदालत ने इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि गंभीर आरोपों वाले मामलों में भी, उचित प्रक्रिया और गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता है।

शमी एस.एन., उप्पिनंगडी

न्यू इंडियन एक्सप्रेस

बोर्ड के अध्यक्ष: मनोज कुमार सोंथालिया संपादक: सांत्वना भट्टाचार्य

रेजिडेंट एडिटर (तमिलनाडु): एंटो टी जोसेफ * एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आरके झुनझुनवाला द्वारा प्रथम तल, डोर नं.1/2, टीएस 1802, 1803, नीला साउथ स्ट्रीट, नागपट्टिनम - 611 001 पर मुद्रित और प्रकाशित और उनके द्वारा वीसीप्रिंटोग्राफ एस 1, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, वडक्कू पालपनैचेरी, नागपट्टिनम - 611 002 पर मुद्रित।

नागपट्टिनम: खंड 8, संख्या 119. आरएनआई पंजीकरण संख्या TNENG/2017/72810. फोन नंबर 04365-242910. * पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार। कॉपीराइट: एक्सप्रेस पब्लिकेशन (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड, सभी अधिकार सुरक्षित। पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा, पूरे या आंशिक रूप से पुनरुत्पादन निषिद्ध है।

Machine Translated by Google

2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ

वैश्विक अवलोकन

टीडीजी नेटवर्क
नई दिल्ली

सतत विकास के बाद से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार हुआ है।

पिछला पूर्वानुमान जनवरी 2024 में जारी किया गया था।

सबसे आक्रामक मौद्रिक सख्ती के बावजूद वैश्विक परिदृश्य में सुधार हुआ है

दशकों में, वैश्विक आर्थिक मंदी का ऐसा परिदृश्य देखने को मिला है। जनवरी 2024 में जारी पिछले पूर्वानुमान के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट काफी हद तक देखी गई है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह सुधार तब से हुआ है जब वे जनवरी 2024 में जारी पिछले पूर्वानुमान को नीचे लाने में कामयाब रही हैं ।

वैश्विक आर्थिक स्थिति के अनुसार, जनवरी से अब तक प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं गंभीर मंदी से बच गई हैं

बेरोज़गारी और मंदी को ट्रिगर करने वाली संभावनाओं के बावजूद , संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2024 का परिदृश्य केवल सतर्क रूप से आशावादी है क्योंकि लंबे समय तक उच्च स्तरीय मौद्रिक कसावट पहले पूर्वानुमानित लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था में, अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु झटके विकासशील देशों के लिए। कई बड़े भविष्य के लिए दृष्टिकोण की तीव्र गति केवल तकनीकी परिवर्तन के प्रति सतर्क है - जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण भी शामिल है।

विश्व अर्थव्यवस्था अब दशकों से स्थिर और सतत आर्थिक विकास की चुनौती दे रही है। अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना जारी रखते हैं, खासकर कम विकसित देशों और छोटे

सीखने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चुनौतियाँ, जोखिम प्रस्तुत करती है, जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय सतत आर्थिक विकास के लिए दृष्टिकोण को बढ़ाएगी ।

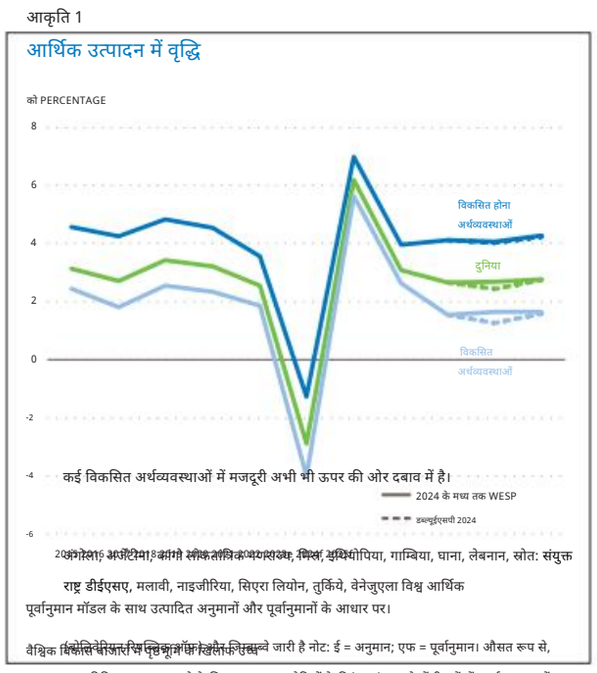

एशिया। संतुलन पर, निकट-झटके वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश करना जारी रखते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था के अब केवल सतर्क रूप से आशावादी आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़ने का अनुमान है, जो 2024 में 2.7 प्रतिशत बना हुआ है (आकृति 1)। भू-राजनीतिक तनावों और विकासशील देशों में ऊपर की ओर संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका में बेहतर संभावनाओं को दर्शाते हैं ।

प्रतिशत की धमकी देता है (जनवरी में पूर्वानुमान से 0.3 प्रतिशत की वृद्धि) और 2025 में 2.8

तकनीकी परिवर्तन की तेज़ गति - विशेष रूप से मशीन लर्निंग और तकनीकी बुद्धिमत्ता में चुनौतियों से जूझना - एक ओर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जबकि दूसरी ओर आलोचनात्मक तकनीकी विभाजनों को बढ़ाने और आवश्यक खनिजों के उपयोग पर ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए - ने श्रमिकों के लिए नए अवसर खोले हैं और उन्हें नया रूप दिया है ।

आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना विश्व अर्थव्यवस्था 2024 में 2.7 प्रतिशत (विशेष रूप से खनिज समृद्ध विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि) और 2025 में 2.8 प्रतिशत (इस तरह के ऑप-एड का लाभ उठाते हुए) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। "संसाधन अभिशाप" वार्ड में नए सिरे से किए गए संशोधन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कई बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से भारत और ब्राजील में बेहतर संभावनाओं को दर्शाते हैं। हालांकि, कई अफ्रीकी देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण में गिरावट आई है।

इसके लिए ठोस राष्ट्रीय नीतियों और प्रभावी कार्यान्वयन क्षमताओं की आवश्यकता होगी।

ये देश ऐसा नहीं कर सकते

अकेले ही। एक सक्षम अंतरराष्ट्रीय वातावरण और

मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होगा

आलोचना की क्षमता का दोहन करें-

पिछले रिलीज के बाद से समीक्षा की गई।

आकृति 1

आर्थिक उत्पादन में वृद्धि

कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरी अभी भी ऊपर की ओर दबाव में हैं।

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र डीईएसए, मलावी, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, तुर्किये, वेनेजुएला विश्व आर्थिक पूर्वानुमान मॉडल के साथ उत्पादित अनुमानों और पूर्वानुमानों के आधार पर।

वैश्विक विकास बाजारों में पृष्ठभूमि के खिलाफ उच्च (बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ) और जिम्बाब्वे जारी है नोट: ई = अनुमान; एफ = पूर्वानुमान। औसत रूप से,

मुद्रास्फीति का अनुभव करने के लिए । भुगतान चुनौतियों के निरंतर संतुलन के केंद्रीय बैंकों, अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से भारत और ब्राजील। हालांकि, आने वाले वर्षों में उम्मीद है कि उनकी मुद्राओं को विनिमय दर अवमूल्यन और पास-2010-2019 के दौरान 3.2 प्रतिशत बढ़ी।

आने की उम्मीद है , जो आने वाले वर्षों में 2019 की तुलना में काफी कम रहने की उम्मीद है।

2024 की पहली तिमाही में वैश्विक वृद्धि दर में तेजी

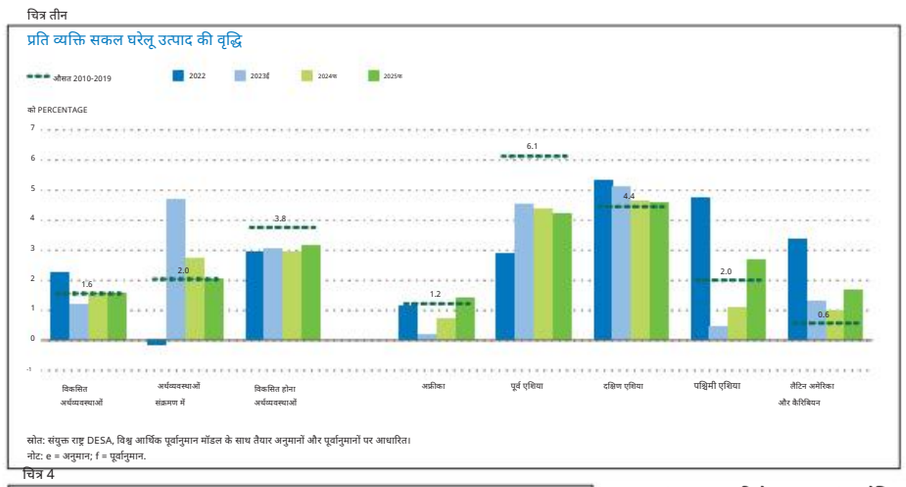

फेडरल रिजर्व की नीति गाज़ा पट्टी में

हाल के आर्थिक वृद्धि को धीमा करने वाली 2010-2019 के दौरान 3.2 प्रतिशत के औसत से नीचे रहे (तालिका 1)।

व्यापार में सुधार के संकेत बैंक की नीति में बदलाव से श्रम बाजार प्रभावित होगा

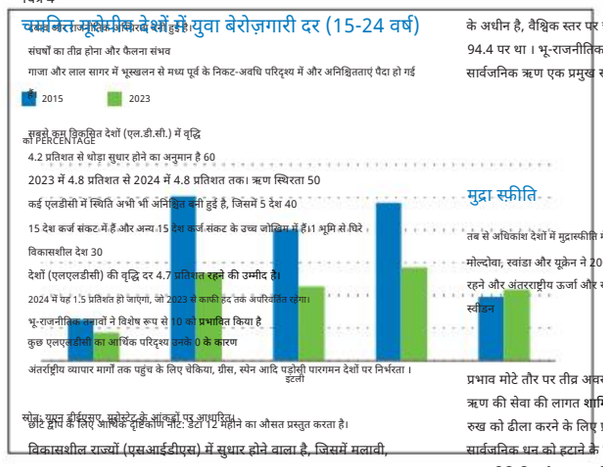

मध्य अफ्रीकी अर्थव्यवस्था और मौद्रिक समुदाय व्यापार प्रदर्शन 2023 की पिछली तिमाही के बाद से बेहतर हो रहा है ।

विकसित अर्थव्यवस्थाएँ

फरवरी में, वैश्विक मौद्रिक और मौद्रिक संघ में चला गया।

2024 के पहले चार महीनों के दौरान, श्रम सूचकांक अगस्त 2022 के बाद पहली बार तंग प्रमुख "प्रतीक्षा करें और देखें" बाजारों से विचलित होकर विस्तारवादी क्षेत्र में चला गया (चित्र 2a)।

अमेरिका में बेरोजगारी की स्थिति सख्त बनी रही, मौद्रिक नीति रुख, दरें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई और कुछ क्षेत्रों में मौद्रिक और केंद्रीय बैंकों ने तीव्र श्रम की कमी का सामना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजकोषीय नीतियां:

अज़रबैजान, ब्राज़ील, चिली, की

आसपास संघर्षों, बेरोजगारी दर प्रवृत्तियों और लोम्बिया, कोस्टा रिका, चेकिया, चुनौतियों के

3.8 प्रतिशत। हालांकि यह जॉर्जिया, ऐतिहासिक निम्नतम स्तर से ऊपर है

अप्रैल २०२३ में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यूक्रेन के श्रम बल में अधिकांश केंद्रीय बैंकों की भागीदारी दर में वृद्धि के कारण काफी हद तक समझाया गया है।

मार्च 2024 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपरिवर्तित रही, करीब से नजर रखी- पहली तिमाही में दरों में कटौती से लगातार 39 महीनों तक नौकरियां जुड़ीं, जबकि 2023 में संघीय और यूरोपीय संघ के मौद्रिक नीति निर्णयों में मामूली ढील दी गई। इसके अलावा, अर्जेंटीना, घाना, इज़राइल, मैक्सिको, सेंट्रल बैंक में उल्लेखनीय "वेतन संकुचन" अवधि के बाद वेतन वितरण, उम्मीद के बावजूद, भले ही आर्थिक विकास लड़खड़ा जाए। दोनों केंद्रीय बैंकों मंगोलिया, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के लिए बढ़ती हुई दर 2024 की पहली तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना नहीं है।

अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि मुद्रास्फीति बनी हुई है यूरोप में, प्राइम रेट 2024 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि के बावजूद केंद्रीय बैंक अधिक होने की उम्मीद है संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों में अनुकूल बनाए रखा । रुख का स्तर ।4

पांच साल के ऋण को कम करना मौद्रिक सहजता आवश्यकता अनुमान बनी हुई है ... रखने या नौकरी प्रशिक्षण लागत से बचने के लिए एक

यूरोपीय युवाओं की मात्रात्मक आर्थिक गतिविधि में। हाल ही में वृद्धि हुई है क्योंकि महाद्वीप के कुछ हिस्सों में कड़े उपायों की आवश्यकता बनी हुई है, हालांकि पिछले दो वर्षों के दौरान अंगोला, मिस्र और केन्या में बांड की आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जबकि ग्रीस, इटली, स्पेन और स्वीडन जैसे कुछ अन्य देशों में युवा बेरोजगारी में तेजी से कमी आई, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई (चित्र 4)।

चित्र तीन

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र DESA, विश्व आर्थिक पूर्वानुमान मॉडल के साथ तैयार अनुमानों और पूर्वानुमानों पर आधारित। नोट: ई = अनुमान; एफ = पूर्वानुमान।

चित्र 4

चयनित यूरोपीय देशों में युवा बेरोज़गारी दर (15-24 वर्ष)

स्रोत: यूरो डीईएसए, यूरोस्टेट के आंकड़ों पर आधारित। नोट: डेटा 12 महीने का औसत प्रस्तुत करता है।

के अधीन है, वैश्विक स्तर पर ऋण-से-जीडीपी अनुपात अधिक लगातार प्राकृतिक 94.4 पर था । भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से घरेलू मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ सकता है। सार्वजनिक ऋण एक प्रमुख संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है। लागत में वृद्धि हो सकती है। उच्च

सामान्य सरकार का दृष्टिकोण उच्च नकारात्मक जोखिम आपूर्ति में और चरम मौसम की घटनाओं के बीच अनुमानित और 2023 में बढ़ गई

मुद्रा स्फीति

तब से अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति में कमी आई है

2020 के शिखर पर, यह 2019 में महामारी-पूर्व स्तर से 11 प्रतिशत अधिक है और

2023 में अपने शिखर से 35 प्रतिशत अंक ऊपर। हंगरी, लातविया, मोल्दोवा, रवांडा और यूक्रेन ने 2007 में वैश्विक वित्तीय संकट का अनुभव किया है । बारह महीने की अवधि में तीव्र अवस्फीति के साथ। ब्याज दरों में गिरावट जारी रहने और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और खाद्य कीमतों में स्थिरता आने तथा दूसरे दौर के कमजोर पास-थ्रू के कारण लंबे समय तक उच्चतर रहने की उम्मीद है , खासकर

प्रभाव मोटे तौर पर तीव्र अवस्फीति की व्याख्या करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोर मुद्रास्फीति, जिसमें आम तौर पर सरकारी ऋण की सेवा की लागत शामिल नहीं होती है , भी उस सीमा के करीब पहुंच रही है जो नीति निर्माताओं को अपने सख्त मौद्रिक नीति रुख को ढीला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। हाल के महीनों में, लाल सागर में भू-राजनीतिक तनाव और सार्वजनिक धन को हटाने के बीच, कई विकासशील देशों में चिंता बनी हुई है कि मुद्रास्फीति फिर से बढ़ सकती है ।

विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) में सुधार होने वाला है, जिसमें मलावी, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया, तंजानिया, मलावी

विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ

गणराज्य) और जाम्बिया में पर्यटन में निरंतर उछाल से मुद्रास्फीति 2023 में 11.1 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है क्योंकि खाद्य और ऊर्जा मौद्रिक कसावट उच्च युवा बेरोजगारी ... वर्ष के दौरान अतिरिक्त नीति ब्याज दरों और मंद इको-दर

विकासशील देशों में व्यापक। आर्थिक वृद्धि के बीच कई विकासशील देशों में आर्थिक राजकोषीय स्थान। उसी देशों में, निकट अवधि में रोजगार की संभावनाएं कमजोर बनी हुई हैं।

चीन में, रोजगार की संभावनाएं और भुगतान संतुलन में वृद्धि जारी रही। बढ़ती हुई आबादी महामारी से संबंधित उपायों को बढ़ा रही है। 2023 में, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि केंद्रीय बैंकों ने 2022 में 5.6 प्रतिशत से कड़ा रुख अपनाया। भारत में, मजबूत वृद्धि और उच्च श्रम बल भागीदारी का सामना कर रहे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मूल्य में भी सुधार हुआ है। इसके विपरीत मुद्राएं। बैंक ऑफ जा- बेरोजगारी दर के लिए नीति समर्थन में वृद्धि लगातार उच्च बनी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में जलवायु 30 प्रतिशत से ऊपर है। ब्राज़ील में, आगे ब्याज दर अनुकूलन और हरित ऊर्जा की संभावना श्रम बाजार में कुछ बढ़ोतरी खोने का अनुमान है , ऊर्जा संक्रमण को छोड़ने के बाद। इसके अलावा, 2024 में गति।

मार्च 2024 में यूक्रेन और मध्य एशिया और प्रशांत में चल रहे सैन्य संघर्षों को स्थिर करने के लिए नकारात्मक नीति दर शासन जापानी येन, जो पूर्वी और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में बढ़ती भू-राजनीतिक और तनाव वापस आ गया है , लगातार पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रहा है । साथ ही, पिछले वर्ष के दौरान कई देशों में महिलाओं के श्रम ने सुनिश्चित किया है।

हाल ही में रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में सेना की भागीदारी बनी है , खासकर दक्षिण एशिया में हालांकि, राजकोषीय नीति

यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है-कोविड-19

महामारी के बाद ... सार्वजनिक ... अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के सभी देशों के समूहों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हो सकती है ।

युवा लोगों को श्रम बाजार में प्रवेश करने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी दर औसतन 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, NEET (शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं) की संख्या

2024 में सरकारी राजस्व का 10% से अधिक हिस्सा।

इस पृष्ठभूमि में, अधिकांश देशों को ऋण स्थिरता में सुधार और राजकोषीय बफर के पुनर्निर्माण के लिए 2024-25 में धीरे-धीरे राजकोषीय व्यय को कड़ा करने का अनुमान है। 2024 में, 37 में से 31 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य सरकार द्वारा चक्रीय रूप से समायोजित प्राथमिक संतुलन में वृद्धि देखने का अनुमान है, जिसका अर्थ है राजकोषीय रुख को कड़ा करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2023 में विकास को मध्यम समर्थन प्रदान करने के बाद, अगले कुछ वर्षों में राजकोषीय नीति के लगभग तटस्थ रहने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में राजकोषीय शासन ढांचे में सुधार को अपनाया है, जिसका उद्देश्य घाटे को कम करने और सदस्य राज्यों को अधिक स्वामित्व देने में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

कई विकासशील देश महामारी और जीवन-यापन की लागत के संकट से लड़ने के लिए समर्थन उपायों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के बाद सरकारें धीरे-धीरे राजकोषीय समेकन का अनुसरण कर रही हैं। अफ्रीका में, सरकारें आम तौर पर एक सख्त राजकोषीय रुख बनाए रखने का लक्ष्य बना रही हैं क्योंकि देश बड़े सार्वजनिक ऋण बोझ और बड़े राजकोषीय घाटे से जूझ रहे हैं, जो मिस्र में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित 4.6 प्रतिशत से लेकर दक्षिण अफ्रीका में 6.4 प्रतिशत और अल्जीरिया में 8.6 प्रतिशत तक है। चीन में, सरकार से 2024 में आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए एक सक्रिय राजकोषीय नीति बनाए रखने की उम्मीद है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नए बुनियादी ढांचे और कम-

2024 में, अफ्रीका की सरकारों द्वारा खर्च किए जाने का अनुमान है

कुल सार्वजनिक राजस्व का एक चौथाई से ज़्यादा हिस्सा ब्याज भुगतान पर खर्च होता है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऋण सेवा का बोझ विशेष रूप से अधिक है, सबसे ज़्यादा अंगोला, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और ज़ाम्बिया में। एसआईडीएस में पहले से ही उच्च स्तर से ब्याज भुगतान में और वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2024 में राजस्व का 15.9 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, जहाँ शुद्ध ब्याज लागत का अनुमान लगाया गया है, अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं और संक्रमण में अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी राजस्व में ब्याज व्यय का हिस्सा कम बना हुआ है।

कार्बन संक्रमण. भारत का सरकार राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि पूंजी निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लैटिन अमेरिका और

कैरिबियाई क्षेत्र के अधिकांश देशों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं

राजकोषीय समेकन, जिसका उद्देश्य बेहतर लक्षित और अधिक कुशल व्यय के माध्यम से ऋण स्थिरता में सुधार करना है।

लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंचने के लिए

दैनिक गार्जियन सर्वेक्षण

भारतीय फुटबॉल पर सर्वेक्षण	दिनांक: 17 मई 2024
पुरुष: 94%	वैश्विक व्यापक आर्थिक रुझान महिला: 6%
प्रश्न-1 क्या आप भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के संन्यास से हैरान हैं?	
उत्तर- हाँ	42.00%
बी-नहीं	54.00%
सी-कह नहीं सकते	4.00%
प्रश्न-2 आप भारतीय फुटबॉल का सर्वकालिक महान खिलाड़ी किसे मानते हैं?	
A-सुनील छेत्री	42.00%
बी- बाईचुंग भूटिया	18.00%
wC- आईएम विजयन	9.00%
डी-नहीं कह सकते	31.00%
प्रश्न-3 क्या भारत में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को उचित सम्मान नहीं मिलता?	
ए-हाँ	45.00%
बी-नहीं	53.00%
सी-कह नहीं सकते	2.00%
प्रश्न-4 आप कौन से खेल मैच देखने के लिए सबसे अधिक उत्साहित हैं?	
ए-क्रिकेट	60.00%
बी-फुटबॉल	17.00%
सी- हॉकी	5.00%
डी- टेनिस	2.00%
ई- कोई अन्य खेल	16.00%

दैनिक गार्जियन सर्वेक्षण

चारधाम यात्रा पर सर्वेक्षण	दिनांक: 17 मई 2024
पुरुष: 95% 5	महिलापुरुष: 5%
प्रश्न-1 चार धाम यात्रा में भारी भीड़ और कुप्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है?	
A-उत्तराखंड सरकार	29.00%
बी- चार धाम मंदिर समिति	13.00%
C- भक्तों की मनमानी	28.00%
टूर कम्पनियों की डी-रिगिंग	21.00%
ई-कह नहीं सकते	9.00%
प्रश्न-2 क्या अपंजीकृत श्रद्धालुओं को ले जाने वाले वाहनों के परमिट रद्द कर दिए जाने चाहिए?	
ए-हाँ	79.00%
बी-नहीं	20.00%
सी-कह नहीं सकते	1.00%
प्रश्न-3 चार धाम या हिन्दू सनातन मंदिरों पर रील बनाने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए?	
ए-रील पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए	50.00%
बी- वित्तीय जुर्माना	29.00%
सी- जेल की सजा	12.00%
डी-नहीं कह सकते	9.00%
प्रश्न-4 क्या चार धाम यात्रा के दौरान वीआईपी दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए?	
उत्तर- हाँ	70.00%
बी-नहीं	29.00%
सी-कह नहीं सकते	1.00%

अर्थशास्त्र को मानवीय रूप देने वाले मनोवैज्ञानिक

अंतरा हलधर

टी हाल ही में मनोवैज्ञानिक का निधन हो गया और नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल व्यवहार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काह्नमैन के अमूल्य योगदान पर विचार करने के लिए यह एक उपयुक्त अवसर है। जबकि अलेक्जेंडर पोप का प्रसिद्ध कथन कि "गलती करना मानवीय स्वभाव है" 1711 से ही मौजूद है, यह काह्नमैन और उनके दिवंगत सह-लेखक और मित्र अमोस टेवरस्की का अग्रणी कार्य था।

1970 और 1980 के दशक के आरंभ में अर्थशास्त्रियों को यह समझने पर मजबूर होना पड़ा कि लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं।

जब मुझे चार साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी इन द बिहेवियरल साइंसेज (CASBS) में फेलोशिप मिली, तो यह वह मौलिक सफलता थी जिसने मुझे वह पद चुनने के लिए प्रेरित किया - या "अध्ययन" (CASBS शब्दावली का उपयोग करने के लिए) - जो 1977-78 में केंद्र में अपने वर्ष के दौरान काह्नमैन ने संभाला था। यह काह्नमैन के तीन प्रमुख आर्थिक योगदानों का पता लगाने के लिए आदर्श सेटिंग की तरह लग रहा था, जिसने अनुशासन में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के एक तत्व को पेश करके आर्थिक सिद्धांत के अपोक्रिफ़ल "तर्कसंगत अभिनेता" को चुनौती दी।

काह्नमैन का पहला बड़ा योगदान उनका और टेवरस्की का 1974 में निर्णय और अनिश्चितता पर किया गया एक अभूतपूर्व अध्ययन था, जिसने यह विचार प्रस्तुत किया कि "पूर्वाग्रह" और "हेयू-रिस्टिक्स" या अंगूठे के नियम हमारे निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। पूरी तरह से निर्णय लेने के बजाय प्रत्येक निर्णय का विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि लोग मानसिक शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं।

दूसरा, काह्नमैन और टेवरस्की का "संभावना सिद्धांत" पर कार्य, जिसे उन्होंने 1979 में प्रकाशित किया था, ने जोखिम के तहत निर्णय लेने के एक मॉडल के रूप में अपेक्षित उपयोगिता सिद्धांत की आलोचना की।

"निश्चितता प्रभाव" का लाभ उठाते हुए,
काह्नमैन और टेवरस्की ने तर्क दिया कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ की तुलना में नुकसान से अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, $20 का नोट खो जाने से होने वाला नुकसान, फुटपाथ पर $20 का नोट मिलने से होने वाले लाभ से अधिक होगा, जिससे "नुकसान से बचने" की भावना पैदा होगी।

यह अंतर्दृष्टि "फ्रेमिंग प्रभाव" के मूल में भी है। यह सिद्धांत, उस समय विकसित हुआ जब काह्नमैन CASBS में फेलो थे और टेवरस्की स्टैनफोर्ड में विजिटिंग प्रोफेसर थे, यह मानता है कि जिस तरह से जानकारी प्रस्तुत की जाती है - चाहे वह हानि के रूप में हो या लाभ के रूप में - निर्णय लेने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, तब भी जब फ्रेम की गई चीज़

क्योंकि हानि या लाभ का मूल्य समान होता है।

अंत में, काह्नमैन की लोकप्रिय कृति, बेस्टसेलिंग थिंकिंग, फास्ट एंड स्लो है। 2011 में प्रकाशित और जीवन भर की अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली इस पुस्तक ने आम जनता को मानवीय निर्णय लेने के दो शैलीगत तरीकों से परिचित कराया: "त्वरित," सहज, भावनात्मक तरीका जिसे काह्नमैन ने सिस्टम 1 कहा, और "धीमा," विचारशील, या तार्किक तरीका, जिसे उन्होंने सिस्टम 2 कहा। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य भावनात्मक आवेगों के पक्ष में तर्क को त्यागने के लिए प्रवृत्त होते हैं।

काह्नमैन को 2002 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि उन्होंने मज़ाक में कहा था कि उन्होंने कभी भी अर्थशास्त्र का कोई कोर्स नहीं किया था। फिर भी, उनकी विद्वता ने आर्थिक शोध के एक बिल्कुल नए क्षेत्र की नींव रखी।

विशेष रूप से, काह्नमैन के काम का शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलर पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो आगे चलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़े। स्वयं नोबेल पुरस्कार विजेता बनने के लिए।

1998 में, थैलर ने कैस सनस्टीन और क्रिस्टीन जोल्स के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण पेपर लिखा, जिसमें तर्क, इच्छाशक्ति और स्वार्थ पर "सीमाओं" की अवधारणा को पेश किया गया और मानवीय सीमाओं को उजागर किया गया, जिन्हें तर्कसंगत-अभिनेता मॉडल ने अनदेखा कर दिया था। 2017 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने तक, थैलर ने मानव व्यवहार में "विसंगतियों" को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित किया था, जिसे पारंपरिक अर्थशास्त्र समझाने के लिए संघर्ष करता था और "पसंद वास्तुकला" पर अत्यधिक प्रभावशाली शोध (सनस्टीन के साथ) किया, इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि सूक्ष्म डिजाइन परिवर्तन ("धक्का") मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।

लेकिन जब मैंने व्यवहारिक अर्थशास्त्र के जन्मस्थान CASBS के कार्यालय की खिड़की से पालो ऑल्टो और सैन फ्रांसिस्को प्रायद्वीप के व्यापक दृश्यों को देखा, तो मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या काह्नमैन, अपने प्रसिद्ध सौम्य स्वभाव के बावजूद, शायद मानवीय निर्णय लेने के मामले में बहुत अधिक आलोचनात्मक थे। क्या "शुद्ध" आर्थिक तर्क से सभी विचलन अनिवार्य रूप से "तर्कहीन" हैं? क्या आर्थिक विश्लेषण के आदर्श मॉडल के साथ तालमेल बिठाने में हमारी असमर्थता, और साथ ही हमारी अपरिहार्य - यद्यपि पूर्वानुमानित - तर्कहीनता, वास्तव में एक अंतर्निहित कमजोरी है?

काश मैं काह्नमैन से ये सवाल पूछ पाता। 2020 में वहां रहते हुए-

21, काह्नमैन, जिन्हें सभी प्यार से "डैनी" के नाम से जानते थे, न केवल वह थे जिसे CASBS ने "अध्ययन" का "भूत" कहा था - एक पूर्व निवासी जो मेरे काम पर एक बड़ा प्रभाव रहा था - बल्कि, खुशी की बात है कि, एक जीवंत, जीवित किंवदंती जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्साहपूर्वक आमंत्रित किया था। पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे अपनी "योजना संबंधी भ्रांति" पर पछतावा होता है कि मैंने उनसे हमारी बातचीत को और गहरा करने के लिए उनके प्रस्ताव को जल्दी स्वीकार नहीं किया - एक भावना जो मेरे सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों मोड द्वारा साझा की गई है। अगर "गलती करना मानवीय है," तो डैनी ने मुझे मानवीय त्रुटि का एक मार्मिक अंतिम पाठ पढ़ाया।

लेखक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अनुभवजन्य कानूनी अध्ययन के एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं।
©प्रोजेक्ट सिंडीकेट, 2024

चित्रण: बिनय सिन्हा

सरल चुनावी आख्यान क्यों विफल हो जाते हैं?

नजरिया

देवांशु दत्ता

2024 के चुनाव जनता एक चुनौती अभियान के दौरान भारतीय पार्टी (बीजेपी) प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का कोई अग्रणी उम्मीदवार नहीं खोज पाई है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए "छाया प्रधानमंत्री" के खिलाफ़ प्रचार करना ज़्यादा आसान होगा।

2014 से ही भाजपा ने अपनी लोकसभा रणनीति को राष्ट्रपति शैली के अभियान में एक व्यक्ति को दिखाने पर केंद्रित किया है। यह एक सरल कथा है और यह एक स्टार कैंपेनर के अस्तित्व का लाभ उठाती है। लेकिन इसके लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है - एक विपक्षी "छाया प्रधानमंत्री" जिसे तुलना में बदनाम और उपहास किया जा सके।

इस चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।

"छाया प्रधानमंत्री" की अनुपस्थिति में, उपर्युक्त स्टार प्रचारक को स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जहां क्षेत्रीय दल अधिक सुसंगत तरीके से बात करने में सक्षम हैं।

और भावनात्मक तर्क। विपक्ष भी बेहतर तरीके से संगठित है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल अपने-अपने क्षेत्र में लड़ रहे हैं, और कांग्रेस द्विपक्षीय गठबंधनों की एक श्रृंखला में जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार है।

इसलिए, भाजपा के स्टार प्रचारक अक्सर ठोस मुद्दों पर बात करने के बजाय व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए दावा किया कि सीएम को जिला मुख्यालयों के नाम नहीं पता हैं। उन्होंने कथित तौर पर एक अन्य क्षेत्रीय पार्टी के प्रमुख को "नकली बच्चा" भी कहा है।

पिछले दो आम चुनावों में स्पष्ट, सरल कथानक थे, जिन्हें भाजपा ने अच्छी तरह से गढ़ा और प्रस्तुत किया। 2014 में कथानक था "गतिशील सुधारक जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा और विकास को गति देगा"। वास्तविकता की परवाह किए बिना, कथानक गूंज उठा। 2019 में, यह "राष्ट्रीय सुरक्षा का रक्षक" था। फिर से, एक गूंजता हुआ कथानक।

यही कारण है कि भाजपा दो बार "लहर" में जीतने में सफल रही।

इसने 2009 (22 प्रतिशत) और 2019 (37 प्रतिशत) के बीच अपने वोट शेयर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की, और इसकी सीटों की संख्या 116 (2009) से बढ़कर 303 (2019) हो गई।

2024 में, केवल सरल आख्यान बेरोजगारी और आर्थिक संकट पर केंद्रित हैं, और भाजपा सरकार यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि उसके पास समाधान है, क्योंकि वह 10 वर्षों से सत्ता में है और इन समस्याओं से निपट नहीं पाई है।

भारत अपनी विविधता और विषमताओं के कारण सरल कथाओं के लिए आसानी से उधार नहीं देता है। किसी भी अन्य देश की तुलना में यहाँ अधिक मान्यता प्राप्त भाषाएँ हैं और जलवायु और भौगोलिक विविधताओं की एक विशाल श्रृंखला है। आर्थिक और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) अंतर भी बहुत अधिक हैं।

विविधता के मामले में एकमात्र निकटतम तुलना यूरोपीय संघ (ईयू) की है, जिसमें एक महाद्वीप में फैले 27 अलग-अलग संप्रभु राष्ट्र शामिल हैं। यहां तक कि ईयू भी यकीनन भारत से कम विविधतापूर्ण है, और इसमें निश्चित रूप से कम आर्थिक असमानता और कम एचडीआई रेंज है। असमानताओं के लिए बस प्रति व्यक्ति और साक्षरता के दो मानदंडों को लें।

वित्त वर्ष 23 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुमान लगाया कि बिहार (सबसे गरीब राज्य) में प्रति व्यक्ति आय लगभग ~48,000 प्रति वर्ष थी, जबकि गोवा में प्रति व्यक्ति आय ~4.7 लाख थी - जो कि शीर्ष और निचले राज्यों के बीच लगभग 10:1 का अंतर है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय लगभग ~1.48 लाख थी।

यूरोपीय संघ के देशों में बुल्गारिया सबसे गरीब है, जहां प्रति व्यक्ति आय 16,900 डॉलर है और लक्जमबर्ग सबसे अमीर है प्रति व्यक्ति आय 131,380 डॉलर है। यूरोपीय संघ में प्रति व्यक्ति औसत आय 36,000 डॉलर है। यूरोपीय संघ में साक्षरता दर करीब 100 प्रतिशत है। 2017 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में 96 प्रतिशत बताई गई, जबकि सबसे कम साक्षरता दर बिहार में 71 प्रतिशत थी।

जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, इत्यादि में भी इसी तरह के बड़े अंतर हैं। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और केरल में शिशु मृत्यु दर (सभी 5/हजार से कम) जर्मनी के बराबर है, जबकि असम, यूपी और एमपी में शिशु मृत्यु दर 40 से ऊपर है, जो सूडान के लगभग बराबर है।

इसका तात्पर्य यह है कि एक सरल राष्ट्रीय आख्यान के अनुरूप तैयार की गई नीतिगत पहल बहुत उपयोगी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, पूरे भारत में शिशु मृत्यु दर को एक ही तरह से लक्षित करने वाली पहल बेतुकी होगी। कई मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं में भी बेतुकी बातें हैं।

चुनावी लहरें सरल आख्यानों द्वारा पैदा की जा सकती हैं।
लेकिन भारत को सरल कथानकों के साथ काम करने वाली मजबूत केंद्रीकृत सरकार की जरूरत नहीं है। उसे अंतर्निहित असमानताओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए राज्यों और क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व वाले गठबंधन की जरूरत है।

अबकी बार 90 पार?

भाजपा को अतिरिक्त 30 सीटें मिलने से सरकार की ताकत और गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालाँकि, तीस से कम संख्या के कई महत्वपूर्ण परिणाम होंगे

टी इलांगाणा के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमें वर्तमान परिदृश्य में संभावनाओं पर नजर डालने का संकेत दिया है।
आम चुनावों में भाजपा की संभावित संख्या पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय कांग्रेस पार्टी की संभावित संख्या पर ध्यान केन्द्रित करना।

दिप्रिंट के साथ एक विस्तृत साक्षात्कार में श्री रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी को अगली सरकार बनाने के लिए केवल 125 सीटों की आवश्यकता है, जबकि भाजपा को न्यूनतम 250 सीटों की आवश्यकता होगी।

मुझे पता है, मुझे पता है, आप में से बहुत से लोग पहले से ही परेशान हैं। उसे ये संख्याएँ कहाँ से मिलेंगी? यह किस तरह की कल्पना है? कृपया मेरे साथ थोड़ा और रहें। यह नेशनल इंटरेस्ट मैंने लिखा है, ChatGPT ने नहीं, और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप जटिलताओं की उम्मीद कर सकते हैं। कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है, और हम कभी भी चुनाव की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, संख्याओं को भूल जाइए।

उनका तर्क है कि कांग्रेस के पास अब सहयोगी हैं और उनका भरोसा भी। भाजपा के पास दोनों नहीं हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि इतिहास बताता है कि कोई भी पार्टी 150 से कम स्कोर के साथ गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है।

राष्ट्रीय हित

शेखर गुप्ता

2004 में कांग्रेस ने भाजपा के 138 के मुकाबले 145 सीटें जीतीं और पहली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार बनाई क्योंकि भाजपा के मुकाबले अधिक सहयोगी दल उसके साथ जुड़ने को तैयार थे। एक बार फिर, यह पूछना उचित है: कांग्रेस में कोई भी 125 तक पहुँचने की कल्पना कैसे कर सकता है? हालाँकि, आज सबसे बड़े सवाल का सामना करने का एक तरीका है, पारंपरिक तरीके से हटकर कदम उठाना।

मतगणना में अब केवल तीन सप्ताह शेष रह गए हैं, तथा परिणामों के बारे में चर्चा उम्मीदों के भंवर में उबल रही है: "आपको क्या लगता है, संख्या क्या होगी?"

वे जिस "संख्या" की बात कर रहे हैं, वह भाजपा की है। क्या यह 370 हो सकता है, जो नरेंद्र मोदी ने शुरू में लक्ष्य रखा था, जिसमें सहयोगियों के लिए 30 और जोड़ कर इसे "400 पार" किया जा सकता है? क्या यह 20-
30 प्लस या माइनस 303 (2019 का स्कोर)? क्या पार्टी 272 से नीचे गिर सकती है? यह ऐसा है जैसे आपको पता है कि फाइनल मैच कौन जीतने वाला है, और आप केवल रन, विकेट या, अगर यह फुटबॉल का खेल है, तो गोल के आधार पर बहस कर रहे हैं।

क्या होगा अगर हम समीकरण को उल्टा करके देखें और हारने वाले के प्रदर्शन के बारे में पूछें? अब, यह ट्रिगर हो जाएगा कांग्रेस और मोदी आलोचक। हम कांग्रेस को शीर्ष पर आते नहीं देख सकते, क्योंकि वह केवल 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो इतिहास में सबसे कम है।

2014 और 2019 में कांग्रेस ने 44 और 2019 में 44 सीटें जीतीं। 52, और भाजपा को क्रमशः 282 और 303 सीटें। राज्य-दर-राज्य मुक़ाबले को देखते हुए, हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि अगर भाजपा को अपने 303 में कुछ और जोड़ना है, तो इनमें से ज़्यादातर गैर-कांग्रेसी दलों से आना होगा: एनसीपी, शिवसेना, आप, टीएमसी, बीआरएस, बीजेडी, यहां तक कि डीएमके और फिर आंध्र में वाईएसआरसीपी। कांग्रेस के खिलाफ़, इसने पहले ही अधिकतम 92 प्रतिशत सीटें जीत ली हैं, जहाँ वे 2019 में प्रतिद्वंद्वी थे। इसलिए, कांग्रेस के पास भाजपा से खोने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है।

अब इस समीकरण को उलट दें। भाजपा के बजाय कांग्रेस क्या जीत सकती है? हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से शुरू होकर पश्चिम और दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक तक, कांग्रेस ने भाजपा के हाथों लगभग हर सीट खो दी। वास्तव में, उसने इन राज्यों में कुल 241 सीटों में से केवल नौ सीटें जीतीं। उसके पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। उसने जिन सीटों पर जीत हासिल की, उनमें से अधिकांश ऐसी थीं जहाँ भाजपा उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उदाहरण के लिए, केरल और तमिलनाडु।

कांग्रेस अब जिन 328 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा है। इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी-भाजपा के अश्वमेध को रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है। वह जितनी भी सीटें जीत सकती है, वह भाजपा की अंतिम संख्या पर दबाव डालेगी। उसे 125 की जरूरत नहीं है, जबकि 90 सीटें ही काफी हैं।

ऐसे।

दरअसल, समीकरण सीधा है। अगर कांग्रेस 80 पर पहुंचती है तो भाजपा 25-25 से हार जाएगी।
2019 की तुलना में 30 सीटें अधिक हैं। बेशक, भाजपा और उसके समर्थक कहेंगे कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र में गैर-कांग्रेसी दलों से उसे लाभ होगा और वे सही भी हो सकते हैं। इसके विपरीत, भाजपा को ठाकरे, शरद पवार और तेजस्वी यादव की पार्टियों से कुछ तनाव है। इस तर्क के लिए, हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए कोई भी 10 अतिरिक्त सीटें 52 से ऊपर का मतलब है कि भाजपा के लिए 10 सीटें कम होंगी। उदाहरण के लिए, अगर कांग्रेस 90 तक पहुंच जाती है, तो उसके पास भाजपा को 272 के आंकड़े से नीचे रखने का अच्छा मौका होगा। सौ सीटें राष्ट्रीय राजनीति को हिला देंगी।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा या हो सकता है।
मैं एक बुनियादी समीकरण पर जोर दे रहा हूं कि हारने वाले को आगे चल रहे उम्मीदवार की तुलना में बहुत कम वोटों की जरूरत होती है। या इसे दूसरे तरीके से कहें। भाजपा को 30 सीटें और मिलने से, जो 330 तक पहुंच जाती है, उसकी अगली सरकार की ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीस सीटें कम होने से कई महत्वपूर्ण परिणाम होंगे।

टी ऐसा केवल तभी हो सकता है जब कांग्रेस कम से कम 30 या उससे ज़्यादा सीटें जीतती है। 70 से ज़्यादा कांग्रेस की हर सीट राष्ट्रीय राजनीति को संतुलित करेगी। पार्टी के दावे चाहे जो भी हों, यह एक बड़ी चुनौती है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इनमें से ज़्यादातर में उन्हें भाजपा या ज़्यादा सटीक तौर पर मोदी को हराना होगा। 2019 के सापेक्ष वोटों की संख्या में अंतर का मतलब है कि यह बड़ी कमी के साथ शुरू होगा।

कांग्रेस इन 30 अतिरिक्त सीटों को कहां से लाएगी, जो कि न्यूनतम है, ताकि कोई फर्क पड़ सके? वह उन राज्यों पर नज़र रखेगी, जहां 2019 में उसने भाजपा के हाथों सब कुछ खो दिया था और अब उसके पास या तो गठबंधन है या फिर शक्तिशाली राज्य सरकारें हैं। कर्नाटक और तेलंगाना पहले नंबर पर आते हैं, जहां उसके पास क्रमशः 28 और 17 में से सिर्फ़ 1 और 3 सीटें थीं।

फिर महाराष्ट्र, क्योंकि भाजपा के सहयोगी टूट चुके हैं और कांग्रेस को ठाकरे शिवसेना के रूप में एक नया सहयोगी मिल गया है। अब हम हिंदी राज्यों के करीब आ गए हैं। बिहार में भाजपा का सहयोगी कमजोर है और कांग्रेस को लगेगा कि उसका अपना (तेजस्वी) मजबूत है। झारखंड में भी सहयोगी फैक्टर काम कर सकता है।

फिर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी के दावे चाहे जो भी हों, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाते हैं।

वर्तमान में पार्टी के पास इन 22 में से केवल एक सीट है। भाजपा ने इनमें से एक को छोड़कर सभी पर 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। हालांकि, कांग्रेस और आप अब गठबंधन में हैं। क्या यह और पुलवामा-बालाकोट जैसी उग्रता की अनुपस्थिति अब कुछ लोगों को प्रभावित करेगी, खासकर हरियाणा में?

अगर आप इस सूची पर फिर से नज़र डालें, तो 30 या उससे भी ज़्यादा सीटें जोड़ना असंभव नहीं है। याद रखें, मैंने संभावना नहीं कहा। जहाँ तक मुझे पता है, कांग्रेस 52 से भी कम सीटें जीत सकती है। यह सिर्फ़ अनुमान लगाना है कि भाजपा की अंतिम संख्याएँ कांग्रेस पार्टी की तुलना में कम मज़ेदार हैं। अब, आप समझ गए होंगे कि मैंने इस चुनाव परिणाम पर रेवंत रेड्डी के संकेत को तीखा विरोधाभासी क्यों बताया।

द प्रिंट के साथ विशेष व्यवस्था द्वारा

महाकाव्य अनुपात के सौर नखरे मेगालोमैनिया प्लस पंथ खतरनाक है

नेत्र संस्कृति

कुमार अभिषेक

1 सितंबर, 1859 की तारीख़ बहुत ख़ास है। इस दिन रिचर्ड खगोलीय इतिहास के इतिहास में कैरिंगटन ने अपनी लंदन वेधशाला में सूर्य के धब्बों से दो तीव्र प्रकाश के धब्बे निकलते देखे। हालाँकि आग के गोले कुछ ही मिनटों में गायब हो गए, लेकिन उनका असर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में महसूस किया गया: दुनिया भर में टेलीग्राफ सिस्टम फेल हो गए, मशीनों से चिंगारियाँ निकलने लगीं। रात के आसमान में चमकीली रोशनी से पक्षियों को गाने और कामगारों को अपना दिन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोगों को डर था कि यह दुनिया का अंत है।

लेकिन कैरिंगटन ने पहचान की कारण: एक विशाल सौर ज्वाला, जो 10 बिलियन परमाणु बमों के बराबर है। यह ज्वाला - पृथ्वी पर विद्युतीकृत गैस और कणों को फेंकती है - सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भू-चुंबकीय तूफान या कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) का कारण बनी, जिसे कैरिंगटन इवेंट के रूप में जाना जाता है। यह घटना सौर अधिकतम से कुछ महीने पहले हुई थी, एक ऐसी घटना जो हर 11 साल या उससे भी कम समय में होती है जब सूर्य अपने मजबूत और लगातार बदलते चुंबकीय क्षेत्रों - दूसरे शब्दों में, इसके चुंबकीय ध्रुवों के उलट होने के कारण गतिविधि में चरम का अनुभव करता है।

वर्तमान समय की बात करें तो हम खुद को एक और सौर अधिकतम के शिखर पर पाते हैं और इसके संकेत सभी को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह में भू-चुंबकीय तूफानों ने धरती को औरोरा से रंग दिया है। इनमें से एक तूफान 11 मई को आया था और माना जा रहा है कि यह 21 वर्षों में सबसे शक्तिशाली तूफान था। लद्दाख तक तीव्र औरोरा गतिविधि देखी गई।

विशाल सौर विस्फोट ऊर्जा और प्रकाश के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि अभी संकट समाप्त नहीं हुआ है, तथा संचार और विद्युत ग्रिड नेटवर्क में व्यवधान का खतरा मंडरा रहा है।

नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने खुलासा किया है कि अंतरिक्ष का मौसम सूर्य की चुंबकीय विकृतियों से पैदा होता है, जिससे सनस्पॉट बनते हैं। ये काले धब्बे सौर ज्वालाओं, सीएमई और अन्य विद्युत चुम्बकीय घटनाओं के उद्गम स्थल हैं, जो हमारे तकनीक-निर्भर समाज के लिए जोखिम पैदा करते हैं। सनस्पॉट गतिविधि 11 साल की अवधि में घटती-बढ़ती रहती है, जिसका अगला चरम 2025 तक होने का अनुमान है।

अनिवार्य रूप से, हर 11 साल में, सूर्य का एक बार स्थिर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है और गायब हो जाता है। फिर यह फिर से उगता है - और एक ब्रह्मांडीय चक्कर में, उत्तर दक्षिण बन जाता है और दक्षिण उत्तर बन जाता है।

यह उलटाव प्रत्येक सौर चक्र के चरम के दौरान होता है और इसकी उत्पत्ति "डायनेमो" नामक प्रक्रिया से होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।

डायनमो में सूर्य का अपना घूर्णन तथा उसके पेट में ज्वलन्त गैस का निरंतर प्रवाह शामिल होता है - जो तारकीय ऊर्जा का वाहक बेल्ट है, तथा इसे सौर तूफानों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह चुंबकीय उलझन का कारण बनता है।

सूर्य के चक्र का एक नियमित हिस्सा, सौर तूफान अनिवार्य रूप से चुंबकीय उलझन का एक नृत्य है और इसमें इसकी सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत, कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ शामिल होती हैं, जो आपस में जुड़ती हैं और फिर अचानक अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। यह अचानक उलटाव प्लाज्मा, एक प्रकार का अति गर्म पदार्थ, और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल विस्फोटों को जारी करता है। ये विस्फोट या CME अनिवार्य रूप से विद्युत आवेशित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बादल हैं।

इन सीएमई के साथ हैं सौर ज्वालाएँ, विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो सूर्य से दूर जाती हैं

प्रकाश की गति से। दूसरी ओर, सीएमई, हालांकि तेज़ होते हैं, लेकिन अपना समय लेते हैं, अक्सर पृथ्वी तक पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं।

एक मजबूत CME हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को तनाव की गेंद की तरह निचोड़ सकता है, जिससे भू-चुंबकीय तूफान आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में यह अचानक बदलाव पृथ्वी के भीतर शक्तिशाली विद्युत धाराएँ उत्पन्न कर सकता है, जो हमारे विद्युत ग्रिडों को प्रभावित कर सकता है और संभावित रूप से व्यापक व्यवधान पैदा कर सकता है, जैसा कि 1989 के क्यूबेक ब्लैकआउट से स्पष्ट है जब एक गंभीर CME के बाद क्षेत्र कई दिनों तक अंधेरे में डूबा रहा।

सौर ज्वालाओं का अपना हिस्सा है विनाशकारी क्षमता भी है। उनके एक्स-रे और गामा विकिरण के विस्फोट उपग्रहों पर लगे नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को जला सकते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान इंजीनियर इन खगोलीय झटकों को पिघलने से रोकने के लिए मजबूत विकिरण परिरक्षण के साथ ऑनबोर्ड कंप्यूटरों को मजबूत करते हैं।

हमारा सुदूर अतीत भी फुसफुसाता है सूर्य का प्रकोप। वृक्षों के छल्ले और बर्फ के टुकड़े 774 ई. में आए एक भयानक सौर तूफान की कहानी बताते हैं, जो इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी के वायुमंडलीय रसायन विज्ञान को बदल दिया (scientific american.com के अनुसार)। और साक्ष्य 7176 ई.पू. में एक और भी अधिक महाकाव्य घटना का सुझाव देते हैं, जो पिछले 10 सहस्राब्दियों में ग्रह के लिए अद्वितीय तीव्रता का एक सौर महातूफान था।

इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर सौर ज्वाला या तूफान के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी कोई ब्रह्मांडीय घटना एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है। बिजली, इंटरनेट और उपग्रह कनेक्शन के अदृश्य धागों पर हमेशा निर्भर रहने वाली दुनिया में, शायद भू-चुंबकीय तूफानों के खिलाफ़ तैयारी नुकसानदेह नहीं होगी। आखिरकार, एक धधकती सौर आग हमें सचमुच अंधकार युग में वापस ले जा सकती है।

व्यापार & उद्देश्य

आर गोपालकृष्णन

टी इकारस की उड़ान की कहानी भी सूर्य के करीब रहना अच्छा है ज्ञात है। सभी नेताओं के पास अपने इकारस क्षण (अस्थायी मेगालोमेनिया) होते हैं, जैसा कि मेरी 2019 की पुस्तक क्रैश में बताया गया है। हालांकि, स्थायी मेगालोमेनिया एक न्यूरोटिक स्थिति है; जब पंथ-निर्माण के साथ संयुक्त होता है, तो भयंकर खतरे पैदा होते हैं। जब आप मेगालोमेनिया और पंथ को एक साथ बढ़ते हुए देखते हैं, तो आप जानते हैं कि अत्याचार पनपता है।

एनरॉन, टाइको और वर्ल्डकॉम के महापागलपन और पंथीय पराजय पीछे देखने पर स्पष्ट हो गए - क्या लक्षण विकसित होने पर उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था?
यस बैंक, जेट एयरवेज, किंगफिशर और पतंजलि से मिले धुएँ के संकेतों के बारे में क्या? 1980 के दशक की शुरुआत में एक महापागल वोल्टास नेता को याद करें, एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार सहकर्मियों के साथ अहंकारी था, जिसने टाटा के प्रबंधन के तरीके की निंदा की, बड़े-बड़े दावे किए और उत्तराधिकारियों के लिए सफाई करने के लिए मलबे का ढेर छोड़ दिया।

कम्पनियों की तरह राष्ट्र भी अहंकार और पंथ के जाल में फंस सकते हैं।

अहंकार का लोभ: 1876 में, ओटोमन खलीफा अब्दुल हामिद द्वितीय अपने भाई मुराद को पदच्युत करने के बाद गद्दी पर बैठा।

परिणामी अराजकता के बाद, अब्दुल से एक उदार सुधारक होने की उम्मीद की गई थी, लेकिन वह एक संकीर्ण रूढ़िवादी निकला। जब ईसाई अर्मेनियाई लोगों ने अपने मुद्दे के लिए आंदोलन किया, तो उसने आंखें मूंद लीं, जब कुर्द गुंडों, हामिदये अलायलारी ने अर्मेनियाई लोगों को खत्म कर दिया।

उनकी गुप्त पुलिस, उमर-उ हफ़िये ने असंतोष को रोकने के लिए उनके विरोधियों को गिरफ़्तार किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के उदारवादी सुधारों, तंज़ीमत को गलत ठहराया और एक अखिल इस्लामी विचारधारा का प्रस्ताव रखा। बाहरी खतरों की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने इस्तिबदाद को लागू किया, मंत्रियों को सहायकों में बदल दिया और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। उनका शासन पतन का दौर था।

1930 के दशक में जब नाजी तूफानी बादल छाने लगे, तो जर्मनी आने वाले पर्यटकों में चार्ल्स लिंडबर्ग और डेविड लॉयड जॉर्ज जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां और यहां तक कि पटियाला के महाराजा भी शामिल थे।

सर्वव्यापी प्रचार के माध्यम से, निवासियों और आगंतुकों को ऐतिहासिक अन्याय के घातक प्रभावों के बारे में बताया गया - उदाहरण के लिए, वर्साय संधि, वाइमर शासन और यहूदी।

अपने स्वयं के संघर्षरत लोकतंत्रों से, या उभरते बोल्शेविक खतरे से निराश होकर, कई आगंतुकों ने प्रत्यक्ष खतरों को नजरअंदाज कर दिया।

जूलिया बॉयड (ट्रैवलर्स इन द थर्ड रीच, इलियट एंड थॉम्पसन, 2017) ने आम यात्रियों के लेखन को एकत्रित किया। एडोल्फ हिटलर ने सभी सकारात्मक विकासों का श्रेय खुद को दिया और सभी कमज़ोरियों के लिए किसी न किसी को दोषी ठहराया; उसकी प्रशंसा की गई अपने चाटुकारों के पंथ-जैसे समूह द्वारा। माना जाता है कि क्रुप और आईजी फारबेन जैसी बड़ी कंपनियों ने उसका समर्थन किया था। हिटलर महामहिम और पंथ के "सूप" में खुश था, जबकि आम लोगों ने धार्मिक संघर्ष और फासीवाद के निरंतर उदय का अनुभव किया।

जर्मनों ने बाद में कहा, "विर हैबेन दास निच्ट गेवुस्ट" (हमें यह सब नहीं पता था)। वे गहरी नस्लीय उथल-पुथल को महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विचारों को दबा दिया क्योंकि (i) विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया था, (ii) उनके व्यापारिक हितों को बढ़ावा दिया गया था, और (iii) विशेष रूप से अमेरिकी टिप्पणी नहीं करेंगे, ताकि अश्वेतों के साथ उनके अपने ट्रैक रिकॉर्ड को उठाया न जा सके।

पंथ: पंथ, जिसका नेतृत्व आमतौर पर एक शक्तिशाली नेता करता है, एक संगठित समूह है, जो मनोवैज्ञानिक हेरफेर और दबाव रणनीतियों के माध्यम से अपने सदस्यों पर हावी होता है। पंथ के नेता खतरनाक होते हैं क्योंकि वे धोखे पर भरोसा करते हैं और मनोरोगी होते हैं।

क्या हेरोल्ड जेनीन (आईटीटी), ली इकोका (फोर्ड और क्रिसलर), जैक वेल्च (जीई) और कार्लोस घोसन (रेनॉल्ट निसान) जैसे महापागल कॉर्पोरेट नेता पंथ के नेता माने जा सकते हैं? या महर्षि महेश योगी, चंद्रस्वामी, ओशो रजनीश और बाबा रामदेव, जिन्होंने विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया? कथित तौर पर मॉर्मन चर्च अमेरिका में सबसे बड़े भू-स्वामियों में से एक है। 2016 में आस्था-आधारित संगठनों का वैश्विक राजस्व 400 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जो माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ॅन से बहुत दूर नहीं है। (द डिवाइन इकोनॉमी, पॉल सीब्राइट, प्रिंसटन, 2024)।

चेतावनी संकेत: बावजूद अपरिहार्य अस्पष्टताओं के मद्देनजर, हितधारकों को चेतावनी के संकेतों को पढ़ना और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा न करने पर संस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है; ऐसे नेताओं में निम्नलिखित सात विशेषताओं में से कुछ, सभी नहीं, आमतौर पर दिखाई देती हैं और स्पर्शनीय होती हैं: (i) सत्तावादी बन जाना, (ii) आलोचना के प्रति कम सहनशीलता होना और षड्यंत्रों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, (iii) घरेलू और विदेशी स्रोतों से प्रशंसा को खुशी-खुशी स्वीकार करना, (iv) लाइमलाइट का आनंद लेना और फोटो खिंचवाने के अवसरों के लिए खुद को सजाना, (v) अपने प्रशंसकों से प्यार करना जो नेता की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनात्मक शब्दों से प्रशंसा करते हैं, (vi) बयानों को अविभाज्य सत्य के रूप में पेश करना, और (vii) अंत में, पूर्ववर्तियों की कथित असफलताओं के प्रति तिरस्कारपूर्ण होना और खुद परिणामों को निष्प्रभावी करने की कोशिश करना।

हम अपने नेताओं को नैतिक द्विआधारी में बांध देते हैं - या तो सब महान या सब पाप। वास्तविकता यह है कि यह एक मिश्रण है, और जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। आपको संकेतों की व्याख्या करनी चाहिए - उन्हें अनदेखा करना आपके लिए जोखिम भरा है। क्या एलन मस्क एक शानदार उद्यमी हैं, एक आपदा, या दोनों? वायाकॉम के सुमनेर रेडस्टोन के बारे में क्या? या पैरामाउंट की उनकी बेटी, शैरी रेडस्टोन के बारे में क्या? क्या PayTM, Byju's या Ola स्टार्टअप हैं या अपस्टार्ट?

ऐसी परिस्थितियों में रचनात्मक संदेह और हितधारकों की सतर्कता आवश्यक है - यह उस भारत के लिए विचारणीय बात है जो शीघ्र ही "विकसित" का दर्जा प्राप्त करने की दौड़ में है।

लेखक एक लेखक हैं। उनकी नई किताब, एम्ब्रेस द फ्यूचर: द सॉफ्ट साइंस ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, फरवरी में प्रकाशित हुई थी।
rgopal@themindworks.me

THE GOAN EVERYDAY

यह दैनिक वृद्धि नहीं बल्कि दैनिक कमी है।
अनावश्यक चीजों को हटा दें
ब्रूस ली

ऑनलाइन घोटाले: हम वास्तव में अपने दम पर

गुरुवार को गोवा पुलिस को दो शिकायतें मिलीं - एक

शहर की एक डॉक्टर ने दावा किया कि इंटरनेट पर अज्ञात स्कैमर्स ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, जिन्होंने उसे धोखा दिया करीब 90 लाख रुपये की ठगी, बड़ी रकम देने का वादा उसके निवेश पर रिटर्न, और एक जौहरी से भी

जिसने एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपये गंवा दिए, जिसने उससे वादा किया था कि यदि वह ऐप के माध्यम से बाजार, क्रिप्टोकरेंसी आदि में निवेश करेगा तो उसे भी उतना ही बड़ा रिटर्न मिलेगा।

इन घटनाओं पर हंसना और संबंधित व्यक्तियों की मूर्खता को दोष देना आसान होगा, जो कि अधिकांश लोगों को स्पष्ट रूप से एक घोटाला प्रतीत हो सकता है। हालाँकि, ऐसा करने से हम इन घोटालेबाजों और कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों की अक्षमता से समाज के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे को नजरअंदाज कर देंगे और यह पहचानने में विफल हो जाएंगे कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति कितना असुरक्षित हो सकता है, खासकर जब किसी घोटाले को पहचानने के लिए पर्याप्त शिक्षा की कमी हो।

शिक्षित व्यक्ति जैसे डॉक्टर और वित्तीय रूप से समझदार व्यक्ति जैसे जौहरी भी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, यह दर्शाता है कि केवल भोले-भाले लोग ही धोखाधड़ी के शिकार नहीं होते, बल्कि आधुनिक तकनीकों के साथ, जिसमें मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नई समझ भी शामिल है, घोटालेबाज एक व्यापक जाल बिछा रहे हैं और इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे हर बार जाल में फंस जाएं।

हाल ही में, धोखाधड़ी का एक नया रूप सामने आया है, जिसे सुअर-कसाई के रूप में जाना जाता है, जो कि पुराने अच्छे विश्वासघात व्यक्ति का एक अत्यधिक संशोधित संस्करण है - जिसमें एक घोटालेबाज अपने संभावित शिकार के बारे में सब कुछ अध्ययन करता है और अक्सर संभावित शिकार को महीनों तक बहलाता-फुसलाता और मजबूर करता है, यहां तक कि संभावित शिकार को अपने साथ प्यार में पड़ने के लिए प्रेरित करता है, फिर पीड़ित को अपनी जीवन भर की बचत देने के लिए राजी करता है - यह कुछ वैसा ही है जैसे एक कसाई सुअर को टुकड़ों में काटता है, जब तक कि सुअर के शव से कुछ भी न छूट जाए।

इन घोटालों को पनपने देने के लिए पुलिस को प्रवर्तन की कमी और अपराधियों को पकड़ने में उनकी अक्षमता के लिए दोषी ठहराना भी आसान होगा। हालाँकि, हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर मामलों में, ये घोटालेबाज देश से बाहर के होते हैं, किसी घोटालेबाज़ी एजेंसी के हिस्से के रूप में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं और अपनी असली पहचान, अपना स्थान और यहाँ तक कि जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, उसे छिपाने में माहिर होते हैं।

लेन-देन अक्सर मालिकों की सहमति और प्राधिकरण के साथ एक ऐप के माध्यम से किया जाता है, जिससे लेन-देन को उलटने के लिए बैंकों के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं।

इन सभी बातों को मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जब इन घोटालों पर नज़र रखने की बात आती है तो हम सभी को खुद ही इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। बैंकों, RBI, SEBI द्वारा नियमित रूप से जारी की जाने वाली सलाह के अलावा, अपंजीकृत ब्रोकरों के खातों, इंटरनेट पर मौजूद उन ऐप्स के ज़रिए लेन-देन न करने की सलाह दी जाती है जो SEBI के साथ पंजीकृत नहीं हैं और अन्य संदिग्ध संस्थाओं के साथ OTP साझा न करने की सलाह दी जाती है, ऐसे कई अन्य उपाय हैं जो हम ऐसे घोटालेबाजों से बचने के लिए कर सकते हैं।

एक निश्चित 'लाल' खतरा तब होता है जब इंटरनेट पर कोई अनजान व्यक्ति, चाहे आप उसे कितने भी समय से जानते हों, आपसे पैसे मांगता है या आपको कोई ऐसी वित्तीय योजना या निवेश विकल्प सुझाता है, जिसमें भारी रिटर्न का वादा किया गया हो और दावा किया गया हो कि उसने स्वयं ऐसा किया है।
वास्तविक लोग, यदि उन्हें सचमुच में शीघ्रता से धन कमाने का कोई तरीका पता है, तो वे निश्चित रूप से उस विचार को अपने तक ही रखेंगे तथा उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे, विशेषकर उन लोगों के साथ जिनसे वे वास्तविक जीवन में नहीं मिले हैं।

ध्यान रखने योग्य दूसरी बात यह है कि यदि कोई आपको अगला सर्वोत्तम निवेश विकल्प सुझा रहा है और चाहता है कि आप अपना निर्णय जल्दबाजी में लें - यह बात वास्तविक लोगों के साथ लेन-देन के मामले में भी सत्य है, विशेषकर सेकेंड हैंड बाजार में - तो उसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य है।

अन्य संकेतों में अनचाहा संपर्क, जन्मतिथि, पैन विवरण, व्यक्तिगत पता आदि जैसी संवेदनशील जानकारी सहित व्यक्तिगत जानकारी के लिए अनुरोध शामिल हैं, जिनका उपयोग धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए किया जा सकता है और संभावित घोटालेबाज द्वारा आपको परिवार के सदस्यों, दोस्तों आदि के साथ इस योजना पर चर्चा करने से अलग करने का प्रयास किया जा सकता है, जो इस घोटाले का शीघ्र पता लगा सकते हैं।

याद रखें कि सतर्क रहना ही स्वयं को बचाने का एकमात्र तरीका है।

खुली जगह >>

सरकार बारिश से पहले मडगांव की विरासत इमारतों को सुरक्षित करने में विफल रही

आसन्न बारिश के बावजूद हेरिटेज इमारतें असुरक्षित बनी हुई हैं।

मडगांव

मडगांव विधायक और भाजपा सरकार सहित अधिकारियों द्वारा उपेक्षित, ये ऐतिहासिक स्थल निवासियों और आगंतुकों के लिए समान रूप से जोखिम पैदा करते हैं। सरकार की निष्क्रियता सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालती है और इन स्थलों के मूल्य की उपेक्षा करती है। वादों के बावजूद, मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ है। चुनावों के दौरान भी प्राथमिकताएँ कहीं और होती हैं। यह शर्म की बात है कि सार्वजनिक सुरक्षा राजनीतिक एजेंडे के पीछे चली जाती है। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

रॉनी डिसूजा, चंदोर

क्या ओसीआई दर्जा संवैधानिक अधिकारों पर अंकुश लगा सकता है?

ऐसे व्यक्तियों के लिए शिकायतें व्यक्त करने की क्षमता सीमित होने से लेकर कार्ड रद्द होने तक गंभीर खतरे बने हुए हैं

>लेखक डॉक्टरेट हैं
वह यूरोपीय विश्वविद्यालयों के गठबंधन के तहत काम कर रहे शोधकर्ता हैं और उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक सम्मेलनों में अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए हैं।

एडीवी मोसेस पिंटो

रिट याचिका (सिविल) 1397/2020 में डॉ. राधिका थप्पेटा बनाम भारत संघ के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, जिसे अंतिम बार 07-05-2024 को सूचीबद्ध किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी और धारा के तहत अधिनियमित सरकारी योजनाएं भारत के विदेशी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या नहीं।

(लीगल ऑब्जर्वर ट्रस्ट, 2024)।

डॉ. राधिका थप्पेटा की ओर से 24 नवंबर, 2020 को एडवोकेट सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री द्वारा दायर रिट याचिका में, जिसे रिट याचिका के अंतिम निपटारे के लिए लंबित होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और वर्तमान चरण को देखते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट केस की स्थिति पर प्रतिबिंबित होता है, को अपडेट किया गया है: "पेंडिंग (प्रस्ताव सुनवाई [आदेश (अपूर्ण मामले / आईएएस / सीआरएलएमपी)]) -आदेश दिनांक: 30-04-2024"।

याचिकाकर्ता राधिका थप्पेटा ने 23 नवंबर, 2020 को दायर याचिका में 'ओसीआई द्वारा झेली गई कठिनाई और भेदभाव' को इस तरह से स्पष्ट रूप से चित्रित किया है: "नागरिकता अधिनियम द्वारा ओसीआई के जिन मूल अधिकारों पर अंकुश लगाया गया है, उनमें भारत में निवास का अधिकार, भारत में

रोजगार का अधिकार और भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने का अधिकार शामिल है। याचिकाकर्ताओं द्वारा झेली गई इन कठिनाइयों को नीचे दर्शाया गया है:"

(रिट याचिका (सिविल) 1397/2020, पृष्ठ: जी)

1. प्रवेश में बाधा और भारत में निवास:

ओसीआई कार्ड धारक को भारत में प्रवेश की अनुमति केवल आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा धारक के समान ही दी जाती है और ओसीआई का दर्जा केवल विदेशी पासपोर्ट की वैधता अवधि के दौरान ही वैध होता है। इसके अलावा, नागरिकता अधिनियम की धारा 7डी केंद्र सरकार को ओसीआई के पंजीकरण को रद्द करने और किसी भी कानून के उल्लंघन या भारत के संविधान के प्रति असहमति दिखाने पर उन्हें भारत में रहने से प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है...;

2. भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: नागरिकता अधिनियम की धारा 7डी(बी) केंद्र

सरकार को किसी व्यक्ति के ओसीआई पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देती है यदि वे भारत के संविधान के प्रति असहमति दिखाते हैं और धारा 7डी(डीए) किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए ओसीआई पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देती है।

धारा 7डी के तहत ये दोनों प्रावधान मनमाने हैं और ओसीआई की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिनमें से कई भारत में स्थायी रूप से निवासी होने के बावजूद राज्य के खिलाफ शांतिपूर्ण असहमति व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इस डर से कि ऐसी असहमति या तो भारत के संविधान का उल्लंघन होगी या किसी कानून का उल्लंघन होगी;

3. व्यवसाय और पेशे की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध:

> जबकि तब ओसीआई भारत में स्थायी रूप से काम करते हैं और रहते हैं, उन्हें अक्सर सूचना के अधिकार के तहत राज्य प्राधिकारियों से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं होता है कार्य

जबकि 15 नवंबर 2019 को जारी गृह मंत्रालय के अधिसूचना पैरा 6 (vii) (बी) में ओसीआई को प्रासंगिक अधिनियमों के अनुसार डॉक्टर, आर्किटेक्ट, अधिवक्ता और चार्टर्ड एकाउंटेंट के व्यवसायों का अभ्यास करने की अनुमति दी गई है, ऐसे कई अन्य प्रावधान हैं जिन्हें बिना किसी पर्याप्त कारण के मनमाने ढंग से ऐसी सूची से बाहर रखा गया है।

उन व्यवसायों की संख्या को सीमित करके, जिनमें ओसीआई, एनआरआई के समान अपना सकते हैं, अन्य गैर-गणना किए गए व्यवसायों का अभ्यास करने वाले कई ओसीआई को भारत में अपने पेशेवर क्षेत्रों में सार्थक रूप से भाग लेने और योगदान करने में बाधा उत्पन्न होती है;

4. इसमें भाग लेने पर प्रतिबंध भारत का नागरिक और राजनीतिक जीवन:

यद्यपि कई ओसीआई भारत में रहते हैं और करों का भुगतान करते हैं, ऐसे लोग नागरिक बुनियादी ढांचे पर स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ अपनी शिकायत को सार्थक रूप से व्यक्त करने में असमर्थ हैं, इस डर से कि नागरिकता अधिनियम की धारा 7डी के आधार पर सार्वजनिक शिकायतों को शांतिपूर्वक उठाने के अपने अधिकार को व्यक्त करने के लिए उनकी विदेशी नागरिकता रद्द की जा सकती है;

5. सूचना मांगने पर प्रतिबंध: भले ही ओसीआई भारत में स्थायी रूप से काम करते हैं

और रहते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य अधिकारियों से जानकारी मांगने का अधिकार नहीं होता है। (रिट याचिका (सिविल) 1397/2020, पृष्ठ: I)।

राधिका थप्पेटा की ओर से प्रस्तुत इसी याचिका में, इसके प्रेरक महत्व के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मिसाल का हवाला दिया गया है:

"अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रोइम बनाम. रस्क [387 यूएस 253] ने माना कि अमेरिकी कांग्रेस के पास संविधान के तहत किसी व्यक्ति की संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता छीनने की कोई विधायी शक्ति नहीं है, बशर्ते कि उसने स्वेच्छा से इसका त्याग न किया हो।" (रिट याचिका (सिविल) 1397/2020, पृष्ठ: एम)।

भारतीयों द्वारा दोहरी नागरिकता की मांग

1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में तीव्र वैश्वीकरण के साथ, कुछ भारतीय प्रवासियों के बीच यह मांग बढ़ रही थी कि भारत को दोहरी नागरिकता प्रदान करनी चाहिए, जिसमें एनआरआई, ओसीआई, गोवा के निवासी नागरिक, उच्च योग्यता वाले भारतीय पेशेवर और उनके माता-पिता और रिश्तेदार शामिल थे।

दोहरी नागरिकता चाहने वाले प्रवासी भारतीयों की मांगों पर विचार करने के लिए, केंद्र सरकार ने दोहरी नागरिकता के पहलू पर सिफारिशें करने के लिए डॉ. एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ("एचएलसी") का गठन किया।

समिति ने 2002 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि दोहरी नागरिकता उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जिनके पास भारतीय मूल के लोग या अनिवासी भारतीय जो किसी विशिष्ट सूची के नागरिक थे।

देश.

उच्च स्तरीय समिति भारतीय प्रवासियों की भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने की इच्छा से परिचित थी और इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

"36.6. दोहरी नागरिकता प्रवासी समुदाय की युवा पीढ़ी के भारत के साथ संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने में भी मदद करेगी क्योंकि वे भारत में अपने बुजुर्गों के साथ संपर्क बनाए रखने के साथ-साथ अपनी जड़ों से भी जुड़ने के लिए उत्सुक होंगे। दोहरी राष्ट्रीयता की शुरूआत से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में प्रवासी समुदाय इसके लिए तरसता है और तरसता है। यह भारत की ओर से परोपकार, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सांस्कृतिक प्रसार और विदेशी राजनीतिक वकालत में प्रवासी समुदाय की पूर्ण भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा।" (एचएलसी रिपोर्ट 2002)।

उच्च स्तरीय समिति की टिप्पणियां आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हैं, जहां यात्रा की आसानी ने व्यवसाय करने और अपने मूल देश में परिवार से मिलने में आने वाली कठिनाइयों को कम कर दिया है।

रिट याचिका (सिविल) 1397/2020 में अंतिम सुनवाई के दौरान अंतरिम टिप्पणियां:

20 मई, 2022 को, संबंधित अंतरिम आवेदन संख्या 74336/2022 में:

न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वह राज्य के मेडिकल कॉलेज के प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) श्रेणी के अभ्यर्थियों को विदेशी निवास का प्रमाण प्रस्तुत किए बिना गैर-आवासीय भारतीय सीटों के लिए आवेदन करने की अनुमति दे।

न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश नागरिकता अधिनियम, 1955 ('अधिनियम') की धारा 7डी के लिए ओसीआई की चुनौतियों की सुनवाई करते हुए दिया। ओसीआई का तर्क है कि संसद ने पहले उन्हें प्रभावी रूप से दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए ओसीआई श्रेणी बनाई थी। हालाँकि, धारा 7डी ओसीआई से भारतीय नागरिकता के अधिकार छीन लेती है - निवासियों के रूप में उनकी स्थिति को कार्यकारी के अनियंत्रित विवेक पर छोड़ देती है। ओसीआई का दावा है कि चूँकि उनकी नागरिकता की स्थिति एनआरआई के बराबर है, इसलिए उनके पास समान अधिकार होने चाहिए।

पीठ ने कहा कि आवश्यकता को माफ करने से केवल लाभ का विस्तार होगा- एनआरआई सीटों को व्यापक पूल में शामिल करने के लिए। इस बात से सहमत होते हुए कि कुछ ओसीआई का किसी विदेशी देश से कोई संबंध नहीं हो सकता है, बेंच ने केरल सरकार को निवास के प्रमाण की आवश्यकता को हटाने का निर्देश दिया।

नागरिकता अधिनियम, 1995 की धारा 7डी को लेकर मुख्य चुनौती अभी भी लंबित है।
इसकी सुनवाई जुलाई में होगी, न्यायालय की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद।" (लीगल ऑब्जर्वर ट्रस्ट, 2024)।

इनबॉक्स >>

गोवा में जमीन का मामला?

हर गोवावासी पेरनेम से कैनाकोना तक की ज़मीन की कीमतों और चार्टर्ड इंजीनियरों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार ज़मीन की उपलब्धता की दरों को जानता है। हालाँकि, यह विश्वास करना मुश्किल है कि बिचोलिम में 1500 वर्ग फीट की ज़मीन की कीमत 75 लाख रुपये है। यह किसी के प्रभाव के बिना असंभव लगता है, जिसे हर कोई जानता है।

इसका मतलब यह है कि गोवा के लोगों को उचित मूल्य पर ज़मीन नहीं मिल पा रही है। यह उच्च दर मानक बन सकती है, और यही प्रवृत्ति पूरे गोवा में फैल सकती है। हैरानी की बात है कि इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलता।

इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गोवा को गैर-गोवावासियों को बेचा जा रहा है जिनके पास बहुत पैसा है। गोवा और गोवावासियों को अलविदा!
आइये इस राज्य के लिए एक नया नाम खोजें जो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करे।
विकास सावकर ईमेल द्वारा

ईसीआई की विफलता निराशाजनक

यह देखना वास्तव में निराशाजनक है कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) आंखें मूंदे बैठा है, जबकि भाजपा नेता, विशेषकर प्रधानमंत्री और कई भाजपा राजनेता, वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं।

हम इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कह सकते हैं जब चुनाव आयोग इस तरह का पक्षपात दिखाता है और सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी को तरजीह देता है?

अरविन मेस्कुइटा, कोल्वा

चुनाव आयोग को जागना चाहिए और प्रधानमंत्री

के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया आरोप

कुत्ते के काटने से बचने के लिए पेड़ बनने का नाटक करें?

लोटोलिम की एक महिला पर कथित तौर पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया, जबकि वह बेनौलिम बीच पर सुबह की सैर के लिए निकली थी। इस हमले में उसे कई कुत्तों ने काट लिया। हाल ही में हुई एक अन्य घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति को सुबह की सैर के बाद वापस जाते समय कुत्तों के झुंड ने दौड़ाया। इन भयावह घटनाओं ने निवासियों और पर्यटकों को असुरक्षित महसूस कराया है और वे अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

यह कहना ज़रूरी है कि समुद्र तट पर कूड़ा-कचरा आवारा कुत्तों को आकर्षित करता है। सुबह की सैर के लिए समुद्र तट पर जाने वाले लोग ऐसे हमलों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। कचरा प्रबंधन हमारे समुद्र तटों को आवारा कुत्तों से मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के विभाग ने कुत्तों के काटने से बचने के लिए सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद तरीका सुझाया है।

पोस्ट में कहा गया है कि "अगर कोई कुत्ता आपके करीब आता है, तो पेड़ की तरह व्यवहार करें। अपने हाथों को बगल में रखकर स्थिर खड़े रहें। कुत्ते को आपको सूंघने दें और वह आमतौर पर दूर चला जाएगा," इस सलाह की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने आलोचना की है। कुत्ते अप्रत्याशित होते हैं। अगर कुत्ता फिर भी हमला करने का फैसला करता है तो क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति पर कुत्तों के झुंड द्वारा हमला किया जाता है तो क्या होगा? यह सलाह केवल आवारा कुत्ते से निपटने के लिए अधिकारियों की गंभीरता की कमी को दर्शाती है

खतरा।

एडेल्मो फर्नांडीस, वास्को

चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष और पाकिस्तान के खिलाफ़ कुछ बयानों ने विवाद को जन्म दिया है। ऐसे बयान शालीनता की सीमाओं को लांघते हैं और तनाव को बढ़ावा देते हैं। चुनाव आयोग (ईसी) को हस्तक्षेप करना चाहिए और मोदी को विभाजनकारी टिप्पणी करने से सावधान करना चाहिए। मोदी जैसे राजनीतिक लोगों के खिलाफ़ शिकायतों से निपटने के चुनाव आयोग के तरीके की आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उन्हें या तो मोदी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए

चुनाव प्रचार करना या जिम्मेदार भाषण के लिए प्रतिबद्धता की मांग करना। मोदी की भड़काऊ टिप्पणियों से सामाजिक शांति को नुकसान पहुंचने का खतरा है और अनावश्यक रूप से पाकिस्तान की स्थिति बढ़ जाती है। अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाने की उनकी विफलता, खासकर पाकिस्तान का जिक्र करते समय, इसके नेतृत्व द्वारा कमजोरी के संकेत के रूप में व्याख्या की जा सकती है। चुनाव आयोग को राजनीतिक विमर्श में निष्पक्षता और शिष्टता बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू करने की जरूरत है।

एस कामत, मैसूर

अपने पत्र हमें editor@ पर भेजें thegoan.net. पत्र 150-200 शब्दों का होना चाहिए तथा उसमें लेखक का नाम और स्थान का उल्लेख होना चाहिए

भाजपा गर्मियों में दक्षिण की ओर जा रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। दक्षिण में भाजपा की स्थिति में सुधार की संभावना है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 29 सीटें जीती थीं, जो कोई कम उपलब्धि नहीं थी। हालांकि, इन 29 सीटों में से ज़्यादातर कर्नाटक से थीं।

इस बार केरल में भाजपा एक या दो सीटें जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में बड़ी जीत हासिल करेगी। तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक अधिकांश सीटें जीतेगा। लेकिन, अजीब बात यह है कि कांग्रेस का मुख्य विपक्षी दल लेफ्ट है।

तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को बढ़त मिलेगी, इसका श्रेय वहां की अवसरवादी पार्टियों - टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस को जाता है। कुल मिलाकर, भाजपा कई सालों तक दक्षिण में एक प्रमुख ताकत नहीं बन सकती; यह वह वास्तविकता है जिसे भाजपा को स्वीकार करना होगा।

डायोमेडेस रोमानो परेरा, कोरलिम

आरएनआई: GOAENG/2015/65729. प्रिंट और प्रकाशन: सागर लाडे द्वारा प्रूडेंट मीडिया (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से . प्रिंट: एलिगेंट ओएसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2/3/4, थिविम इंडस्ट्रियल एस्टेट, करसवाड़ा, मापुसा, गोवा. प्रकाशन: सेकंड फ्लोर, फोर्थ एस्टेट (कामत मेट्रोपोलिस), सेंट इनेज़, पणजी 403 001. संपादक: जोएल अफोंसो (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार). सभी अधिकार सुरक्षित. फ़ोन: (0832) 240 5950 या हमें editor@thegoan.net पर मेल करें. अस्वीकरण: उपरोक्त संपादकीय को छोड़कर, सभी कॉलम और पत्र संबंधित लेखकों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जरूरी नहीं कि वे द गोअन एवरीडे के संपादक, प्रकाशक और मालिकों के विचारों को दर्शाते हों .

thehindu businessline.

शनिवार - 18 मई, 2024

लाभ का बंदरगाह

ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास से बड़े लाभ

चुनावी राजनीति के केन्द्र बिन्दु से दूर

राजनीति में भारत में एक बड़ा रणनीतिक समुद्री सौदा करने में कामयाबी हासिल की। 13 मई को (ईरान और भारत के बीच) यह सहमति बनी कि भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह (जिसमें दो टर्मिनल हैं) पर शाहिद बेहस्ती टर्मिनल का विकास और संचालन 10 साल तक करेगा। 2016 में भी इसी तरह का 10 साल का समझौता हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि नवंबर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

परिणामस्वरूप, भारत केवल भारत ने बंदरगाह टर्मिनल को अल्पकालिक अनुबंधों के माध्यम से शुरू किया है। अब, एक दीर्घकालिक व्यवस्था भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ा सकती है और इसके व्यापार में विविधता लाने में मदद कर सकती है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड बुनियादी बंदरगाह उपकरणों के लिए $125 मिलियन का निवेश करेगी, जबकि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण के माध्यम से $250 मिलियन का निवेश अपेक्षित है। इस क्षेत्र में बड़े लाभ को देखते हुए, भारत को अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। लाभ का पहला सेट बंदरगाह और उसके पूर्व (पाकिस्तान) और दक्षिण (हिंद महासागर) के पड़ोस से संबंधित है। ये शायद आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक हैं। दूसरा चाबहार से ईरान, अजरबैजान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप में 7,200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के विकास से संबंधित है। यूरोप के अधिकांश हिस्सों के साथ व्यापार में, INSTC के स्वेज नहर मार्ग की तुलना में तेज़ और सस्ता होने की उम्मीद है। यह स्वेज या अदन की खाड़ी के माध्यम से माल ले जाने से जुड़े विशाल रणनीतिक जोखिमों से भी बचाता है। मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत का व्यापार पश्चिमी दुनिया में संरक्षणवाद को रोक सकता है। गैस से समृद्ध मध्य एशिया भारत को ऊर्जा का एक विकल्प प्रदान करता है।

चाबहार दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के मुहाने के करीब और होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में स्थित है, जिसके पास ईरान का प्रमुख बंदरगाह बंदर अब्बास स्थित है। बंदर अब्बास के विपरीत यह ईरान का एकमात्र गहरा समुद्री बंदरगाह है, जिसका अर्थ है कि बड़े लाइनर यहां डॉक कर सकते हैं। ईरान की कार्गो लागत अधिक है क्योंकि इसके कुछ सामानों को संयुक्त अरब अमीरात के गहरे समुद्री बंदरगाहों से ट्रांसशिप किया जाना है। चाबहार ईरान की लागत कम करेगा, और इसके साथ ही भारत की भी। पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत को ईरान, अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है। दक्षिण में, यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभाव में सुधार करता है। भारत के साथ ईरान के संबंध उसे चीन के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को संतुलित करने में मदद करेंगे।

रणनीतिक रूप से, भारत ने यह संदेश दिया है कि वह अपने आप में एक वैश्विक खिलाड़ी है, तथा उसने अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद ईरान के साथ संबंध जारी रखे हैं। चाबहार पर एकमात्र बादल ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा है। इस मामले में, अमेरिका ईरान पर चीन के प्रभाव और उस संबंध में भारत की भूमिका को नकारने की आवश्यकता को समझते हुए, कभी गर्म तो कभी ठंडा रुख अपनाता रहा है। फिर भी, ईरान और इज़राइल के बीच तलवारें खिंचने के कारण, हमेशा अनिश्चितता की भावना बनी रहती है - जो रिपब्लिकन के सत्ता में लौटने पर और भी बढ़ सकती है।

जैसा कि कहा गया है, चाबहार भारत के लिए एक अच्छा रणनीतिक और व्यापारिक प्रस्ताव बना हुआ है।

जेब

रविकांत

परिपथ
वियोजक।

आरती कृष्णन

खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव्स की लत से मुक्ति की जरूरत

एफएंडओ सेगमेंट में खुदरा निवेशकों की तीव्र वृद्धि को देखते हुए, सेबी को कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत

मैं बीएसई के एक हालिया कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने चेतावनी देते हुए मुद्दा उठाया कि वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) में खुदरा कारोबार में 'अनियंत्रित उछाल' बाजार और निवेशक भावना के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है।

उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति से घरेलू वित्त को "बिखरने" से बचाना आवश्यक है।

सरकारी अधिकारी आमतौर पर डेरिवेटिव बाजार में होने वाली घटनाओं पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसका वास्तविक दुनिया और अर्थव्यवस्था से बहुत कम संबंध है। लेकिन कोविड के बाद से भारत के इक्विटी डेरिवेटिव बाजार में जो घटनाक्रम हुए हैं, उनसे पता चलता है कि जल्द ही कुछ टूटने वाला है।

खुदरा घाटा

चुनावी हलचल के कारण इस महीने भारत के प्रमुख सूचकांकों में 4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, लेकिन नुकसान की चिंता संस्थानों या अरबों डॉलर निवेश करने वाले एचएनआई को नहीं थी। इसके बजाय, सोशल मीडिया खुदरा निवेशकों से भरा हुआ था

विकल्प ट्रेडिंग में अपनी शर्ट खोने की शिकायत करना।

एक व्यापारी ने बताया कि उसे ₹80 का नुकसान हुआ है। जिम में रहते हुए उन्होंने 1 लाख रुपये खर्च किए, जिसके बाद इंडेक्स पुट ऑप्शन प्रीमियम 50 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये हो गया। अन्य लोगों ने सेंसेक्स और मिडकैप निफ्टी ऑप्शन में 'इंजेक्शन' मूव की शिकायत की, जिससे उनके खाते खत्म हो गए।

इस बीच, ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि अमेरिका में एक कोर्टरूम ड्रामा के बारे में रोचक जानकारी, जहां जेन स्ट्रीट, एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म ने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड में से एक, मिलेनियम मैनेजमेंट पर मुकदमा दायर किया था। जेन स्ट्रीट ने मिलेनियम पर अपने दो कर्मचारियों को बहकाने का आरोप लगाया था, जो एक आकर्षक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति चला रहे थे, जिससे 1 बिलियन डॉलर का मुनाफ़ा हुआ। इस रणनीति में भारतीय विकल्प बाज़ार में 'अक्षमताओं का दोहन' शामिल था।

इस समाचार के बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि विदेशी हेज फंडों और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स द्वारा भारतीय खुदरा निवेशकों का शोषण किया जा रहा है, तथा नियामकों से इस बारे में 'कुछ करने' की मांग की गई।

सावधान निवेशक

यह देखना वास्तव में कठिन है कि विनियामक, खुदरा क्षेत्र के लोगों को एफएंडओ में उनके द्वारा उठाए गए मूर्खतापूर्ण जोखिम के परिणामों से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं।

कोविड के बाद, सेबी ने खुदरा निवेशकों को एफएंडओ में जाने से रोकने के लिए कई पहल की हैं। उन्हें असीमित लाभ उठाने से रोकने के लिए, इसने मार्जिन मानदंडों को कड़ा कर दिया और व्यापारियों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले लाभ पर सख्त सीमाएँ लगा दीं। उन्हें जोखिमों के बारे में जागरूक करने के लिए, ब्रोकरों से कहा गया कि वे एफएंडओ के लिए साइन अप करने वाले सभी निवेशकों के साथ विस्तृत जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़ साझा करें।

जब यह कारगर नहीं हुआ, तो जनवरी 2023 में सेबी ने एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें वास्तविक जीवन के डेटा को शामिल किया गया कि कैसे खुदरा व्यापारी डेरिवेटिव में धक्के खा रहे थे। इसने दिखाया कि हर 10 खुदरा F&O व्यापारियों में से 9 को घाटा हुआ, जिसका औसत घाटा ₹1.1 लाख था।

लेन-देन लागत में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई

इन नुकसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस अध्ययन को तब से हर F&O ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के शुरुआती पेज पर अनिवार्य रूप से चिपका दिया गया है, ताकि व्यापारी हर बार लॉग इन करते समय इसे देख सके।

नकदी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है लेकिन यह सब नए व्यापारियों को एफ एंड ओ बाजार में कूदने से नहीं रोक पाया है।

वित्त वर्ष 2019 में एनएसई के कैश मार्केट में 75 लाख सक्रिय खुदरा निवेशक और 12 लाख व्यक्तिगत एफएंडओ ट्रेडर थे। वित्त वर्ष 2024 तक एफएंडओ ट्रेडर्स की संख्या आठ गुना बढ़कर 96 लाख हो गई, जबकि कैश मार्केट निवेशकों की संख्या केवल चार गुना बढ़कर 307 लाख हो गई।

पिछले दो सालों में, सेबी की चेतावनियों के बावजूद, F&O में निवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या 51 लाख से बढ़कर 96 लाख हो गई है। वित्त वर्ष 24 में NSE के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा किया गया टर्नओवर ₹213 लाख करोड़ (प्रीमियम के आधार पर) था, जो उनके ₹131 लाख करोड़ के कैश मार्केट टर्नओवर से कहीं ज़्यादा था।

इसलिए यह मानने के अच्छे कारण हैं कि घरेलू बचत, जिसका उपयोग अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों को खरीदने और रखने में बेहतर ढंग से किया जा सकता था, उसे एफएंडओ में लगाया जा रहा है।

शार्क बनाम छोटी मछलियाँ

अनुभवी व्यापारी यह भी बताते हैं कि नए निवेशक मल्टीबैगर रिटर्न की चाह में एफएंडओ बाजार के सबसे जोखिम भरे क्षेत्रों में भीड़ लगा रहे हैं।

खुदरा दांव साप्ताहिक सूचकांक (विशेष रूप से बैंक निफ्टी) विकल्पों में केंद्रित हैं,

सेबी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, खुदरा निवेशक जोखिमपूर्ण एफएंडओ क्षेत्र से दूर नहीं रह पा रहे हैं।

डीआईआई की अधिक उपस्थिति और बेहतर उपकरण तैयार करने से मदद मिल सकती है

जहां इंट्रा-डे अस्थिरता और उच्च उत्तोलन एक ही सत्र के भीतर पूंजी को कई गुना या कम कर सकते हैं। इससे संतुष्ट न होकर, कुछ लोग मिडकैप निफ्टी और फिन निफ्टी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जो कि तरलता की कमी के कारण और भी अधिक पेट-दर्द वाली चालों के लिए प्रवण हैं।

विकल्पों को धारण करने में अधीरता

सप्ताह से लेकर महीने तक, कई खुदरा व्यापारी एक्सपायरी का पीछा करते हुए रोजाना एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम में "शून्य से हीरो" की चाल चलने से पहले वे गायब हो जाएँगे। पिछले छह महीनों में, बाजार में एकतरफा चाल ने खुदरा व्यापारियों को नेकेड पुट राइटिंग में उतरने के लिए भी प्रेरित किया है, एक ऐसा व्यापार जो उन्हें बाजार में गिरावट आने पर असीमित नुकसान के लिए उजागर करता है।

उपरोक्त 'रणनीतियाँ' स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समर्थित हैं। उन्होंने अपने सबसे अस्थिर बेंचमार्क पर विकल्प अनुबंध शुरू किए हैं और अलग-अलग दिनों पर अलग-अलग अनुबंधों के लिए समाप्ति तिथि निर्धारित की है, ताकि खुदरा व्यापारी अपने आत्मघाती ट्रेडों की दैनिक आदत से वंचित न रहें।

एयर्स की यह स्थिति होने के कारण, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अल्पकालिक व्यापार के वैश्विक शार्क, एल्गोरिदम और सह-स्थित सुविधाओं से लैस हैं जो बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकते हैं

नैनो-सेकंड, भारतीय बाजार में छोटे निवेशकों को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर वैश्विक फंड इस क्षेत्र में नहीं होते, तो ये नए निवेशक अभी भी स्थानीय ब्रोकरों या प्रोपराइटरी ट्रेडर्स के झांसे में आ जाते, जो F&O के बारे में उनसे कहीं बेहतर जानते हैं।

नशा मुक्ति रणनीतियाँ

हालांकि, बढ़ते घाटे के बावजूद खुदरा व्यापारी एफएंडओ का पीछा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए, सेबी को तर्कहीन निवेश को बढ़ावा देने वाले साधनों को हटाकर उन्हें इसकी लत से मुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

पंट.

डीआईआई में निवेश करें: डेरिवेटिव बाजार का वास्तविक उद्देश्य निवेशकों को किसी परिसंपत्ति के भौतिक बाजार में प्रतिकूल मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध बचाव की सुविधा प्रदान करना है।

आज, म्यूचुअल फंड, बीमाकर्ता, पेंशन फंड और कर्मचारी भविष्य निधि जैसे घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) के पास लगभग ₹61-लाख करोड़ मूल्य की इक्विटी (मार्च 2024 तक) है। फिर भी, F&O बाजार में उनकी शायद ही कोई उपस्थिति है। अस्थिरता और घटना जोखिमों के खिलाफ बचाव के लिए DII को सक्रिय रूप से डेरिवेटिव का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने से निवेशकों को उनकी योजनाओं में मदद करने के अलावा अधिक तर्कसंगत F&O बाजार बन सकता है।

बेहतर उपकरण तैयार करें: हेजिंग की सुविधा के लिए, F&O अनुबंधों को महत्वपूर्ण वास्तविक जीवन निवेश द्वारा समर्थित सूचकांकों पर उपलब्ध होना चाहिए। यह अजीब है कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिडकैप सेलेक्ट निफ्टी जैसे संकीर्ण सूचकांकों में सक्रिय F&O अनुबंध हैं, जिनके लिए शायद ही कोई फंड बेंचमार्क है, जबकि निफ्टी मिडकैप 150, निफ्टी 100 या बीएसई 500 जैसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सूचकांकों में कोई भी नहीं है। F&O अनुबंधों को उन बेंचमार्क पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो

संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है या निष्क्रिय परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित होता है। इससे डीआईआई और दीर्घकालिक निवेशकों को एफएंडओ का उपयोग करके उन निवेशों के लिए हेज बनाने में मदद मिल सकती है जो वे वास्तव में करते हैं
अपना।

समाप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना: निवेशकों के लिए बाजार पर दिशात्मक दृष्टिकोण अपनाना या पोर्टफोलियो हेज खरीदने के लिए, लंबी अवधि वाले एफएंडओ अनुबंध महत्वपूर्ण हैं। साप्ताहिक समाप्ति वाले अनुबंध शायद ही इस उद्देश्य को पूरा करते हैं और इन्हें खत्म कर देना चाहिए।

एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तुत अनुबंधों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि समाप्ति तिथियां महीने में एक ही दिन निर्धारित की जा सकें तथा समाप्ति-दिन वाले ट्रेड पीछे रह जाएं।

इस तरह के उपायों से भारतीय एक्सचेंजों द्वारा दर्ज किए जा रहे रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आना तय है। ये उपाय एक्सचेंजों, ब्रोकरों और शेयर बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के व्यावसायिक हितों के खिलाफ भी काम करेंगे, जो खुदरा एफएंडओ उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन खुदरा निवेशकों को एफएंडओ की लत से मुक्त करने और भारत के पूंजी बाजारों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए यह सब जरूरी लगता है।

ब्रांडिंग से भारतीय शहद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं

न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य, शहद क्षेत्र में अधिक एफपीओ और मूल्य वर्धित उत्पाद महत्वपूर्ण हैं

मोहित शर्मा

टी मधुमक्खी सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है और शहद के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है

परागण के माध्यम से वैश्विक भोजन का लगभग 70 प्रतिशत प्राप्त होता है (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम)। शहद का वैश्विक बाजार 5.2 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2023 में 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2031 में 13 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

भारत सातवां सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है और अमेरिका और यूएई सहित प्रमुख देशों को लगभग 75,000 मिलियन टन प्राकृतिक शहद का निर्यात करता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के मधुक्रांति पोर्टल पर लगभग 14,000 मधुमक्खी पालक पंजीकृत हैं, जिनमें 200 से अधिक पंजीकृत समितियाँ हैं।

इसके स्वास्थ्य लाभों के बावजूद, महामारी के बाद भारत में शहद की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत में काफी गिरावट आई है और यह विकसित देशों के 3-4 किलोग्राम की तुलना में 10 ग्राम पर बनी हुई है।

उत्पादकों के दृष्टिकोण से, निम्न खपत और सुस्त बाजार वृद्धि हतोत्साहित करने वाली है और महत्वपूर्ण विपणन चुनौतियां उत्पन्न कर रही है।

सरकार ने हाल ही में एक अमेरिका ने 2 डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया है, जबकि यूएसडीए के हालिया आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका भारतीय प्राकृतिक शहद का आयात लगभग 1.1 डॉलर प्रति पाउंड (एमईपी के समान) पर करता है, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों की तुलना में कम है।

उद्योग जगत के बीच सीमित सहयोग के कारण, मधुमक्खी पालकों को अक्सर स्थानीय बाजारों में मौसम के आधार पर 100-110 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी कीमतें उत्साहजनक नहीं हैं।

शहद का दीर्घकालिक पुनरुद्धार

उद्योग को बहुआयामी विपणन रणनीति की आवश्यकता है। संगठित भारतीय शहद बाजार में सीमित खिलाड़ी हैं, और अधिक खिलाड़ियों, विशेष रूप से स्टार्ट-अप और एफपीओ के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।

जबकि कुछ एफपीओ शुरू हो गए हैं

शहद मूल्य श्रृंखला विकसित करने के अलावा, उन्हें अभी भी अपनी ब्रांडिंग रणनीतियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

सरस मेले की तरह, सरकार को शहद और संबंधित उत्पादों के लिए समर्पित वार्षिक राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख मेला आयोजित करना चाहिए, जिसमें क्रेता और विक्रेता एक साथ आएं।

सुस्त वृद्धि. भारत में शहद की खपत मूरथी एम

इस वर्ष, महाराष्ट्र ने राज्य स्तरीय शहद मेले की पहल की, लेकिन राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

इसके अलावा, एफपीओ और स्टार्ट-अप को फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, वाइन आदि जैसे उद्योगों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादकों को लगातार मूल्य समर्थन प्रदान किया जा सके। उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत से कम से कम 40 प्रतिशत अधिक मार्जिन पर गारंटीकृत मूल्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना

उत्पादकों को नवीन शहद उत्पादन में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा

उत्पादों का विपणन और अपनी आजीविका में सुधार करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शहद की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए, एनएमआर परीक्षण में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, जो निर्यात के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

भारत में एनएमआर परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है। विश्व मधुमक्खी दिवस (20 मई) के अवसर पर, भारत को शहद उत्पादन में लगे स्वदेशी समुदायों की रक्षा करनी चाहिए, तथा उत्पाद लेबलिंग के माध्यम से शहद उत्पादकों की स्थानीय कहानियों और उनके अनूठे उत्पादों को उजागर करना चाहिए।

उत्पाद की उत्पत्ति की रक्षा करने तथा इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, तीन शहद उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग के तहत पंजीकृत किया गया है, लेकिन उनके बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

शहद मूल्य श्रृंखला में मधुमक्खी पालकों, खरीददारों, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और एग्रीगेटर्स को जोड़ने के लिए ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे एक स्थायी डिजिटल शहद बाज़ार का निर्माण हो सके।

लेखक आरपीसीएयू, पूसा, समस्तीपुर में प्राध्यापक हैं। व्यक्त विचार निजी हैं

संपादक को पत्र अपने पत्र ईमेल द्वारा bleditor@thehindu.co.in पर भेजें या डाक द्वारा 'संपादक को पत्र', द हिंदू बिजनेस लाइन, कस्तूरी बिल्डिंग, 859-860, अन्ना सलाई, चेन्नई 600002 पर भेजें।

जमाकर्ताओं को लुभाना

'तरलता की कमी, एसबीआई की ब्याज दर में वृद्धि से बैंकों में जमा के लिए होड़' (17 मई) लेख के संदर्भ में, 75 आधार अंकों की अधिकतम वृद्धि समय सीमा तक सीमित है।

46-179 दिन तथा एक वर्ष तक के अन्य समयावधियों में यह वृद्धि केवल 25 बीपीएस है।

बैंक ने अपनी ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की है।

बड़ी अवधि की जमाराशियों में अधिकतम जमा दर 7 प्रतिशत है, जो कि कुल जमाराशियों का अधिकतम हिस्सा है।

बैंक की खुदरा सावधि जमाराशियाँ। बाजार में अन्य सभी प्रमुख खिलाड़ियों की तरह बैंक ने भी बचत बैंक ब्याज दरों में कोई संशोधन नहीं किया है।

अल्पावधि ऋणों में ब्याज दरें बढ़ाने का कदम

इसे लघु वित्त बैंकों और कुछ निजी क्षेत्र के सार्वभौमिक बैंकों के जमाकर्ताओं को लुभाने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए।

चूंकि उधार का संकेन्द्रण असुरक्षित, क्रेडिट कार्ड बकाया और ऑटो ऋण सहित उच्च उपज वाले व्यक्तिगत अग्रिमों के पक्ष में है, इसलिए इस वृद्धि के कारण शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी आने की संभावना नहीं है (वास्तव में यह मामूली रूप से बढ़ सकता है)।

वी विश्वनाथन

कोयंबटूर

ब्याज दरों में बढ़ोतरी का स्वागत

यह देखकर खुशी हो रही है कि एस.बी.आई.

शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर अपने लाभ को जमाकर्ताओं तक पहुंचाना।

संभवतः, भारतीय बैंक पिछले समय में एनपीए पर हुए नुकसान के बावजूद, काफी लम्बे समय से उच्च एनआईएम का आनंद ले रहे हैं।

फिर भी, फिलहाल, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के लिए बेहतर विभेदक दरों और जमाराशियों पर अच्छे रिटर्न पर विचार करने के लिए संपूर्ण ब्याज दर संरचना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

एमजी वॉरियर

मुंबई

उल्लेखनीय कैरियर इसमें 'विनीत नैयर, एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष' का उल्लेख है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि नैयर भारतीय व्यापार जगत में एक महान हस्ती थे।

एक प्रख्यात सिविल सेवक, जिन्होंने विश्व बैंक और गेल में भी अपनी सेवाएं दी तथा बाद में एचसीएल और फिर महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम (जो अब टेक महिंद्रा है) के साथ निजी क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की।

सत्यम का अधिग्रहण नय्यर के नेतृत्व में सफलतापूर्वक किया गया।

उन्होंने पुराने सत्यम परिसर में महिंद्रा विश्वविद्यालय की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई।

काम भी याद रखा जाएगा.

बाल गोविंद

नोएडा

बाजार में उतार-चढ़ाव 'अनावश्यक घबराहट' (17 मई) के संदर्भ में, भारतीय बाजारों में अस्थिरता सूचकांक पर चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए निर्भरता महत्वहीन है क्योंकि बाजार की चाल हमेशा वैश्विक मुद्दों और फेड की धुनों के अनुसार कैलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा, VIX एनालिटिक्स की संरचना में शामिल पैरामीटर निफ्टी 50 स्टॉक के ट्रेड मूवमेंट पर आधारित हैं जो सटीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह केवल अंतर्निहित स्टॉक के मौजूदा मार्केट कैप को शामिल करता है और मौलिक विश्लेषण द्वारा समर्थित नहीं है।

सीताराम पोपुरी बेंगलुरु

निर्मला लक्ष्मण द्वारा प्रकाशित तथा प्रवीण सोमेश्वर द्वारा मुद्रित, एचटी मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201306, टीएचजी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई-600002 की ओर से। संपादक: रघुवीर श्रीनिवासन (पीआरपी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार संपादक)।

आईएसएसएन 0971 - 7528

सेमी
वाईके

Machine Translated by Google

अंबानी, अडानी को नीचे क्यों घसीटा जाए?

नेताओं का लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि उद्योगपतियों का उपहास उड़ाना

राय

डॉ. विजय दर्डा

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उद्योगपतियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को समझना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि उद्योगपतियों ने स्वतंत्रता के बाद भी भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुछ राजनेता औद्योगिक समूहों को निशाना बना रहे हैं।

चर्चा, मुझे शुरू करने से पहले ऐतिहासिक घटना सुनाना किस्सा। इतिहास गवाह है कि बजाज और बिड़ला परिवारों ने स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान दिया है। रामनाथ गोयनका ने एक बार महात्मा गांधी से पूछा, "बापू, क्या आपको नहीं लगता कि ये दो उद्योगपति, बजाज और बिड़ला, आपका शोषण कर रहे हैं?" बापू ने जवाब दिया, "नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं ही उनका शोषण कर रहा हूँ।" स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण लड़ाई में, श्रमिकों के लिए यात्रा, आवास और भोजन की सुविधा पर पैसा खर्च किया जाता है।

उल्लेखनीय बात यह है कि ये दोनों परिवार इसे संभव बनाने के लिए सक्रिय रूप से आर्थिक योगदान दे रहे हैं।

मैं यह प्रकरण इसलिए याद कर रहा हूं ताकि युवा पीढ़ी-

उद्योगपतियों द्वारा अपने हितों और क्षमताओं के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन करना एक आम बात है। यह चलन भारत में नया नहीं है। जापान में उद्योगपतियों की प्रधानमंत्री चुनने में निर्णायक भूमिका होती है, जबकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में वे राजनीति में भी भूमिका निभाते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमारे देश में हम यह आरोप सुनते हैं कि सरकार अंबानी और अन्य उद्योगपतियों का पक्ष लेती है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में व्यापारी, उद्यमी और उद्योगपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आजकल अम्बानी और अडानी समूहों पर इस तरह हमला करना एक फैशन बन गया है जैसे कि वे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं इन आरोपों की प्रामाणिकता के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन अगर इनमें कुछ सच्चाई है भी तो इसका निर्धारण राजनीतिक क्षेत्र के बजाय न्यायालय के दायरे में किया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार यह दावा करते रहे हैं कि अंबानी और अडानी समूहों के प्रधानमंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार से निकटता उनके विकास को प्रभावित करती है। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना अनुचित है।

उल्लेखनीय बात यह है कि ये दोनों परिवार इसे संभव बनाने के लिए सक्रिय रूप से आर्थिक योगदान दे रहे हैं।

धीरूभाई अंबानी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों के करीबी थे और उन्होंने एक दूसरे का परस्पर सहयोग किया है।

अडानी गुजरात से हैं। हालाँकि, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे आरोपों को खारिज करता हूँ।

लेकिन अब, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उठाया मुद्दा

एक नया सवाल यह है कि राहुल गांधी इन दिनों अंबानी-अडानी पर अचानक चुप क्यों हो गए हैं? क्या उन्हें टेंपो से ढेर सारा पैसा मिला है? प्रधानमंत्री द्वारा इन उद्योगपतियों के नाम का इस तरह उल्लेख करना कई लोगों को हैरान कर गया, यहां तक कि मुझे भी इस विषय पर लिखने के लिए प्रेरित किया। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का जवाब देने में कोई समय बर्बाद नहीं किया।

हालाँकि, मूल प्रश्न यह है कि हम अपने उद्योगपतियों को राजनीतिक झगड़े में क्यों घसीटते हैं?

उन्हें भ्रष्ट करार देने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं?

क्या उद्योगपति होना और अपने देश के विकास में योगदान देना कोई अपराध है?

हम यह क्यों भूल जाते हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में, टीम को एकजुट रखते हुए उद्योग की स्थापना, संचालन और विस्तार करना कोई आसान काम नहीं है? मुकेश अंबानी ने सफलतापूर्वक यह काम किया है।

धीरूभाई अंबानी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना।

दूसरी ओर, अनिल अंबानी ऐसा करने में असमर्थ रहे।

कुमार मंगलम बिड़ला, बिड़ला समूह की परंपरा को आगे बढ़ाने में सफल रहे, जबकि अन्य बिड़ला पीछे छूट गए।

आनंद महिंद्रा ने केशव और हरिश महिंद्रा की विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। आज अडानी द्वारा हासिल की गई तीव्र सफलता उद्योग के मालिकों के समर्पण और कौशल का प्रमाण है।

मैंने राजनीति को लंबे समय से देखा है और राजनीतिक दृष्टिकोण हमेशा उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने का रहा है। अतीत में, प्रतिष्ठित टाटा और बिड़ला समूह वैश्विक मंच पर भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे। हालाँकि, आज भारत में ऐसी कई कंपनियाँ हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र को बहुत गौरवान्वित करना

किसी भी उद्योग के लिए फलने-फूलने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करना अनिवार्य है।

जर्मनी जैसे देशों से इटली, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जापान जैसे कई देश अक्सर उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ दूसरे देशों का दौरा करते हैं और दूसरे देशों से सहयोग मांगते हैं। दुर्भाग्य से, यहाँ यह उत्पीड़न जैसा लगता है!

मैं इन दिनों अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा पर हूँ। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, जहाँ मैं रह रहा हूँ, बहुत से उद्योगपतियों का गढ़ है, जिनमें से कई के पास कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर संपत्ति है। मैं यह बताने के लिए इसे उजागर कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में उद्योगपतियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हमारे देश में क्या स्थिति है? बहुत से उद्योगपति यहाँ से चले गए हैं।

भारत से, जो चिंताजनक है। हिंदुजा, मित्तल, लोहिया, बागड़ी, अनिल अग्रवाल और अन्य जैसे प्रमुख व्यक्ति अब ब्रिटेन या दुबई से अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उद्योगों के बिना, रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं?

सरकार को कर राजस्व कहां से मिलेगा? गौर करने वाली बात यह है कि उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 27 प्रतिशत से अधिक का सीधा योगदान करते हैं। करों के बिना देश का विकास कैसे होगा?

सामाजिक कल्याण के लिए धन कहाँ से आएगा? औद्योगिक समृद्धि की कुंजी उद्योगपतियों की सहायता और समर्थन करने में निहित है, न कि उनका उपहास करना और उन्हें अलग-थलग करना। अगर उद्योग फलते-फूलते हैं, तो राष्ट्र भी फलता-फूलता है।

लेखक लोकमत मीडिया के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं।

परिप्रेक्ष्य

सब ठीक नहीं है

केजरीवाल को स्वाति के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए मालीवाल घटना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने निजी सचिव बिभव कुमार के खिलाफ राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जब वह सोमवार को आप सुप्रीमो के आवास पर गईं तो उनके निजी सचिव बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की।

यह मुद्दा एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है और राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनावों में आप की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। स्वाति, जो हाल ही में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए गुरुवार को मेडिकल जांच भी कराई। बिभव कुमार के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और घटना के बारे में उनका बयान अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्वाति ने बिभव पर आरोप लगाया था कि जब वह मुख्यमंत्री के लिविंग रूम में थीं और उनसे मिलना चाहती थीं, तब उन्होंने उनके साथ मारपीट की। कथित मारपीट के बाद उन्होंने पीसीआर को फोन किया और सिविल लाइंस थाने भी गईं, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हालांकि स्वाति ने भाजपा से इस मामले को राजनीतिक मुद्दा न बनाने का आग्रह किया है, लेकिन गुरुवार को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की तत्काल वजह तब हुई, जब बिभव कुमार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त बैठक के लिए मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ जाते देखा गया।

एक समय ऐसा लगा कि स्वाति को उनके राज्यसभा सहयोगी संजय सिंह द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद मामला शांत हो गया है कि मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है और संदिग्ध के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे, जो व्यावहारिक रूप से उनके खास हैं। स्वाति अभी भी गुस्से में हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस विषय पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है और शायद वे केजरीवाल के पहले बोलने का इंतजार कर रही हैं। इस पूरे मामले ने आप की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह तथ्य कि मुख्यमंत्री के घर पर पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य पर हमला हुआ, लेकिन शीर्ष पदाधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह उनकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है, खासकर चुनावी मौसम में।

जो लोग आप के मामलों पर नजर रखते हैं, उन्हें याद होगा कि स्वाति मालीवाल और बिभव कुमार को पार्टी से निकाल दिया गया है।

2007 से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हैं, अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले। शुरू में स्वाति AAP के गठन के खिलाफ थीं, लेकिन बाद में अपने गुरु और बॉस केजरीवाल के साथ एक बार फिर काम करने की अपनी सोच पर काबू पा लिया। अतीत में उनके और बिभव कुमार के बीच मतभेदों का इतिहास रहा है, लेकिन हमला कुछ ऐसा है जो कार्यकर्ताओं के लिए आश्चर्यजनक है, और इसे अत्यधिक निंदनीय माना जाता है। यह मुद्दा सुलझ सकता था अगर केजरीवाल हमले के लिए उकसावे को समझने के लिए हस्तक्षेप करते, जो किसी भी मामले में अनुचित है। सीएम के सामने दुविधा यह थी कि वह बिभव कुमार पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं, और उन्हें अपने साथ लखनऊ ले जाकर उन्होंने एक संकेत दिया, जिसे उनके राज्यसभा सांसद की तुलना में उनके पीए के लिए उनकी प्राथमिकता के रूप में व्याख्या किया गया।

यहां यह बताना जरूरी है कि आप में अपने राज्यसभा सांसदों के खिलाफ काफी नाराजगी थी, जिनमें से ज्यादातर ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया। स्वाति मालीवाल जाहिर तौर पर विदेश गई हुई थीं और उनकी अनुपस्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती थी, जबकि राघव चड्ढा की लंदन में आंख की जटिल सर्जरी हुई है।

अन्य राज्यसभा सांसद, खासकर पंजाब से हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलाधिपति अशोक कुमार मित्तल ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी के खिलाफ़ AAP के आंदोलन से खुद को दूर रखा है। सूत्रों ने बताया कि जब स्वाति केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंची थीं, तो उनका शत्रुतापूर्ण स्वागत किया गया था। कथित तौर पर हमला इसके तुरंत बाद हुआ और इस तरह यह मुद्दा सार्वजनिक हो गया।

संजय सिंह ने कुछ हद तक मामले को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि स्वाति मालीवाल इस समय अपनी शिकायत वापस लेंगी या उसे हल्का करेंगी। इसलिए, इस मामले में बिभव कुमार की गिरफ़्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना ने दिल्ली के लोकसभा चुनावों पर छाया डाल दी है, जहाँ भाजपा संघर्ष कर रही थी, लेकिन आप के भीतर इन मतभेदों का लाभ उठाना निश्चित है।

राजधानी में आप-कांग्रेस गठबंधन को मजबूत माना जा रहा है, लेकिन इसमें दरारें पहले से ही दिखाई दे रही हैं। उदाहरण के लिए, आप ने अपने सभी प्रमुख खिलाड़ियों को उन निर्वाचन क्षेत्रों से हटा दिया है, जहां कांग्रेस-कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और उन्हें उन सीटों पर खड़ा किया है, जहां पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आप के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि कांग्रेस के क्षेत्रों में सक्रिय हैं, लेकिन वे बहुत प्रमुख नहीं हैं। एक समय ऐसा था, जब आप-कांग्रेस गठबंधन राजधानी की सभी सातों सीटों पर जीत की ओर अग्रसर था, लेकिन इस आकलन को संशोधित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। आप पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कड़ी टक्कर में है और चांदनी चौक में उसके उम्मीदवार वरिष्ठ नेता जय प्रकाश अग्रवाल बढ़त बना रहे हैं। हालांकि, स्वाति मालीवाल प्रकरण ने गठबंधन सहयोगियों को चिंता में डालने के लिए पर्याप्त कारण दे दिए हैं और देखना यह है कि 25 मई से पहले यह मामला कैसे शांत होता है, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को जिंदा रखेगी।

पंकज वोहरा

अति आधुनिक सभ्यता की खामियां

राय

डॉ. जरनैल एस. आनंद

क्या महान लेखक एक ऐसे व्यक्ति का सपना देखते हैं जो अत्यधिक ज्ञान रखता हो और जो भौतिक समृद्धि की खोज में अपना पुरुषत्व और अपनी मानवता खो देता है?

इच्छाओं की डिस्क

आत्म-मुग्धता, आत्म-प्रेम, स्वार्थ, आत्म-प्रचार, आत्म-साक्षात्कार - ये अद्भुत मानवीय गुण हैं जो व्यक्तिवाद और उदारवाद जैसे आंदोलनों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि

एक समय आएगा, जैसा कि वह पहले भी आ चुका है, जिसे हम आधुनिक समय कहते हैं, जो अलगाव की प्रक्रिया को तेज कर देगा और अंततः मनुष्य अपनी सारी कल्पनाशीलता त्याग देगा और केवल इच्छाओं का एक समूह बनकर रह जाएगा।

दोष रेखाएं: कठोर जीवन शैली

जीवन की बारीकियां जो

हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन सदियों से हम अरस्तू, प्लेटो और शेक्सपियर जैसे महान गुरुओं का अध्ययन करते आ रहे हैं, लेकिन वे मानवीय व्यवहार और विचारों से गायब हैं। हमने एक ऐसी असभ्य जीवन शैली विकसित कर ली है जिसमें मनुष्य के आंतरिक जीवन पर भौतिकता हावी हो गई है। सभ्यता की प्रक्रिया खतरे के क्षेत्र में चली गई है और मनुष्य ने ब्रह्मांडीय वास्तविकता के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध के बारे में संवेदनशील होने के बजाय, केवल अपने आप को महिमामंडित करने वाली जीवन शैली अपना ली है। हमारा

सभ्यता एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई है, जहां हमने न केवल अपनी भाषा खो दी है, न केवल अपनी भावनाएं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और सबसे दयनीय बात यह है कि अपनी विरासत भी खो दी है।

जंगल का उदय

हालांकि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। विपत्ति ने मानव जाति को खुद से बचाया है। अगर आप मानवता के बेहतरीन नमूने देखना चाहते हैं, तो गरीब घरों में जाएँ जहाँ पुरुषों और महिलाओं को जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ, आपको ऐसे माता-पिता मिलेंगे जिनके पास अपने बच्चों के लिए समय है, और भाई-बहन जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं और मरते हैं। केवल यहाँ आपको ऐसे सपने मिलेंगे जो इरादे में मानवीय और संतुष्टि में दैवीय हैं। लेकिन गरीब इलाके से बाहर निकलिए। आपको इस शहर के अमीर लोग, उनके खूनी लड़के, अपनी कारों में युवा लड़कियों का अपहरण करने के लिए इंतजार करते हुए मिलेंगे, हिंसा-

लेखक और उनकी विरासत

आज की दुनिया, जिसने महान लेखकों की विरासत को पूरी तरह खो दिया है, - आपको लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, गोर्की का संदेश कहीं नहीं मिलेगा। डॉन (रूस की महान नदी) निराशा में अपना सिर हिलाती है, और मानव जाति के गिरते हुए वंश पर रोती है। शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और डॉन को पढ़कर बड़ा हुआ विश्व, इस तरह बदल जाएगा-

उनके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके सपनों को नष्ट कर देते हैं। समाज के अमीर और धनी वर्गों के बीच जो जंगल हम देख रहे हैं, वह वर्तमान सभ्यता का एक खतरनाक विकास है। न केवल युवा लड़के, बल्कि उनके पिता और माता भी अपना संतुलन खो चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है: यह जंगल तेजी से बढ़ रहा है।

संवेदनशील, कौन कल्पना कर सकता है?

राजा ओडिपस, जिसने सबसे अमानवीय परिस्थितियों का सामना किया, अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गया। कोई सबक नहीं। कोई विरासत नहीं। गंगा की वैदिक चमक के इर्द-गिर्द आकार लेने वाली सभ्यता अब अपने उत्तराधिकारियों की अनदेखी में सूख रही है।

हालाँकि, डॉ. फ़ॉस्टस की अभी भी बहुत मांग है। हमें अरस्तू और प्लेटो के लिए कोई खरीदार नहीं मिलता। और अगर हमने किसी लेखक को पूरी तरह से नकार दिया है, तो वह सुकरात है।

मानव जाति का 'रावणीकरण'

मानव मस्तिष्क ने ऐसी महाशक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं कि वह दैवीय शक्तियों की तरह छद्मवेश धारण कर सकता है। 'कुछ' मनुष्य अपने आकार में बहुत बड़े हो गए हैं और अपनी भूख के कारण रावण बन गए हैं। रामायण का रावण एक विशालकाय भौतिक अवतार वाला राक्षस था। लेकिन

आधुनिक समय का रावण सबसे ज़्यादा मानवीय दिखता है, आप उसे मंदिरों में एक ख़ास ड्रेस कोड में जाते हुए पाएंगे, जिससे वह बिल्कुल 'सामान्य' दिखता है। शारीरिक रूप से वह बिल्कुल आम आदमी जैसा ही दिखता है।

लेकिन बस उसके मन में उतरो। तुम एक लंका देखोगे, वासना का शहर, जुनून का शहर, महत्वाकांक्षा का शहर, भ्रम का शहर। ये वो लोग हैं, रावण, जो इस दुनिया पर राज करते हैं, वे कम हैं, लेकिन इतने शक्तिशाली हैं कि गरीब जनता उनकी शक्तियों और उनके विवेकपूर्ण डिजाइनों की सीमा को भी नहीं समझ पाती।

ऑटो-मैटोनिक मनुष्य इन 'राक्षसी' लोगों ने ऑटो-मैटोनिक मनुष्यों की एक नस्ल बनाई है जो न तो सोचते हैं, न ही महसूस करते हैं, जिन्हें अच्छे और बुरे का कोई बोध नहीं है, सिवाय 'लक्ष्य' को प्राप्त करने के। आज के युवा पुरुष, जिनके पास नाश्ते के लिए समय नहीं है, दोपहर के भोजन के लिए समय नहीं है, उनके 'घर' लौटने का समय नहीं है, [क्या उनके पास कोई है?], जिनका कोई परिवार नहीं है, युवा ऑफिस की लड़कियाँ जो करियर की खातिर शादी नहीं करती हैं, और जोड़े जो बच्चे नहीं चाहते हैं

उनके पास कोई समय नहीं है - और उनके पास अपनी माँ और पिता के लिए कोई समय नहीं है, उन्हें अपनी सास और बहू [सास या यहाँ तक कि बहुओं] के साथ कोई गलतफहमी नहीं है - हम एक उन्नत समाज में नहीं रह रहे हैं, हम एक महान सभ्यता के खंडहरों पर रह रहे हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर है।

जीवन की वे बारीकियां जो हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए थीं, जैसे कि हम अरस्तू, प्लेटो और शेक्सपियर जैसे महान लेखकों का अध्ययन करते आए हैं, वे मानव व्यवहार और विचार से गायब हैं।

और इससे भी अधिक, ऐसा प्रतीत होता है कि घटते प्रतिफल का नियम लागू हो गया है।

लेखक सभ्यता को ही मनुष्यता के लिए एक बड़ी चुनौती मानते हैं। हमें यह देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि आज हम जिस आदमी से मिलते हैं, उसकी मानवता खत्म हो गई है, वह चतुर है, लेकिन उसमें शालीनता नहीं है, वह अपनी बुद्धि और चतुराई पर जीता है, सत्य कहीं भी उसकी परवाह नहीं करता।

क्या हमने वाकई ऐसी स्थिति के लिए सौदेबाजी की थी?

लेखक ने रचनात्मकता के लिए महान सर्बियाई पुरस्कार, चार्टर ऑफ मोरावा का पुरस्कार जीता है, तथा उनका नाम सर्बिया में कवियों की चट्टान पर अंकित है।

संपादकीय निदेशक: प्रो. एमडी नालापत; प्रबंध संपादक: पंकज वोहरा; संपादक: जोइता बसु। गुड मॉर्निंग इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से राकेश शर्मा द्वारा मुद्रित और प्रकाशित; मुद्रित पता: गुड मॉर्निंग इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, खसरा नंबर 39, गांव बसई ब्रह्मुद्दीन नगर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, (यूपी-201301); प्रकाशित पता: 275, पिकाडिली हाउस, फ्लोर-1, कैप्टन गौर मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-110065; संपादकीय कार्यालय: 275 कैप्टन गौर मार्ग श्रीनिवासपुरी ओखला, नई दिल्ली-110065; मुंबई कार्यालय: जुहू होटल, जुहू तारा रोड, सांताक्रूज-पश्चिम, मुंबई-400049; चंडीगढ़ कार्यालय: एससीओ-7, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017 शीर्षक कोड संख्या: DELENG19869; सदस्यता और संचलन शिकायतों के लिए संपर्क करें: दिल्ली: महेश चंद्र सक्सेना मोबाइल: + 91 9911825289, CISN 0976 - 0008

Machine Translated by Google

दैनिक गार्जियन की समीक्षा
शनिवार | 18 मई 2024
नई दिल्ली
WWW.THEDAILYGUARDIAN.COM

ज्योतिरादित्य सिंधिया

शाही सिंधिया परिवार

जयभान सिंह पवैया

ग्वालियर: शाही वंश से परे

अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई दिग्गजों ने ग्वालियर में अपनी क्षमता दिखाई है, लेकिन आजादी के बाद से इस लोकसभा क्षेत्र की निष्ठा ज्यादातर सिंधिया राजवंश के प्रति रही है।

कौशल वर्मा
नई दिल्ली

निर्वाचन क्षेत्र में से एक है
ग्वालियर लोकसभा मध्य प्रदेश के 29 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ इसके इतिहास का अवलोकन दिया गया है:

यह निर्वाचन क्षेत्र 1952 में बना था, जो भारत में पहले आम चुनावों का वर्ष था। ग्वालियर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें ग्वालियर किला भी शामिल है, और यहाँ शहरी और ग्रामीण आबादी का मिश्रण है। यहाँ विभिन्न समुदायों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एक महत्वपूर्ण संख्या के साथ एक विविध निर्वाचन क्षेत्र है। इस निर्वाचन क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व देखा है, लेकिन यह पारंपरिक रूप से शुरुआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का गढ़ रहा है।

1980 के दशक के बाद से, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस क्षेत्र में प्रभाव हासिल करना शुरू कर दिया, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। सिंधिया परिवार का प्रभाव, विशेष रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से, एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य के कांग्रेस से भाजपा में जाने से निर्वाचन क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता में एक नया आयाम जुड़ गया।

ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और गतिशील क्षेत्र बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश और पूरे भारत में व्यापक चुनावी रुझानों और राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है। आइए ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास में गहराई से उतरें:

राजनीतिक वंशवाद का नाटक

सिंधिया परिवार की प्रतिद्वंद्विता:
हालांकि सिंधिया परिवार प्रभावशाली और सम्मानित है, लेकिन इसमें आंतरिक प्रतिद्वंद्विताएं भी रही हैं।

सार्वजनिक राजनीति में भी इसका असर देखने को मिला है। उदाहरण के लिए, 1996 में माधवराव सिंधिया का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस का गठन करना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नाटक था।

उनके परिवार के ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण बदलाव और नाटकीय राजनीतिक पुनर्रेखण है।

अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत ने पार्टी के भीतर गुटबाजी और परिवार की जटिल राजनीतिक गतिशीलता को उजागर किया।

असामान्य चुनावी नतीजे

1967 में बराबरी और पुनर्मतगणना: 1967 के लोकसभा चुनावों में ग्वालियर में कांग्रेस की विजया राजे सिंधिया और जनसंघ के ए.

जी. खेर। परिणाम इतने करीबी थे कि पुनर्मतगणना की आवश्यकता पड़ी, जो उस समय भारतीय चुनावों में एक असामान्य घटना थी।

राजघराना और राजनीति

शाही उपाधियाँ और राजनीति:
ग्वालियर में शाही इतिहास और आधुनिक राजनीति का अनूठा मिश्रण है। विजया राजे सिंधिया, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थीं, जिन्होंने राजघराने से राजनीति में कदम रखा। उनकी शाही पृष्ठभूमि अक्सर उनकी स्थिति के साथ एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा करती थी।

विजया राजे सिंधिया

कांग्रेस।
हत्या के प्रयास

माधवराव सिंधिया पर हत्या का प्रयास: 1989 में ग्वालियर में एक चुनावी रैली के दौरान माधवराव सिंधिया पर हत्या का प्रयास किया गया था। हालांकि वे बच गए, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र के राजनीतिक माहौल में खतरे और नाटकीयता का तत्व जोड़ दिया।

कानूनी लड़ाइयां और विवादों
चुनाव याचिकाएं और कानूनी लड़ाइयां: ग्वालियर के राजनीतिक इतिहास में कई दिलचस्प घटनाएं शामिल हैं

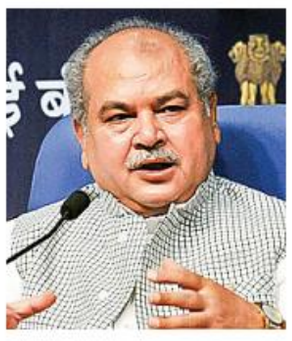

नरेंद्र सिंह तोमर

ऐतिहासिक आवासों का उपयोग कर, उनके अभियानों में भव्यता का स्पर्श जोड़ा गया।
के सदस्यों
संसद

विष्णु घनश्याम देशपांडे: वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और ग्वालियर से पहले लोकसभा सदस्य थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ के मेहकर में हुआ था। वीजी देशपांडे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महासचिव थे।

राजनीति। जनसंघ ने 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा लहर को धता बताते हुए ग्वालियर क्षेत्र में 3 सीटें जीतीं - भिंड से विजया राजे सिंधिया, ग्वालियर से वाजपेयी और गुना से माधवराव सिंधिया, हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। विजयाराजे सिंधिया 1980 में रायबरेली में इंदिरा गांधी से हार गईं। 1989 में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य के रूप में गुना से जीत हासिल की, और 1991, 1996 और 1998 में सीट बरकरार रखी। वह माधवराव की माँ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थीं।

> मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1951 में हुए पहले आम चुनावों के बाद से भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। पिछले दशकों में, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों, उल्लेखनीय नेताओं और विकसित चुनावी गतिशीलता का गवाह रहा है।

अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में एक रैली को संबोधित करते हुए।

राम अवतार शर्मा: वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और भारतीय जनसंघ के सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भारतीय संसद के निचले सदन लोक सभा के लिए चुने गए थे। शर्मा का 29 अक्टूबर 1987 को 79 वर्ष की आयु में ग्वालियर में निधन हो गया।

अटल बिहारी वाजपेयी: वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कवि थे, जिन्होंने भारत के 10वें प्रधान मंत्री के रूप में तीन कार्यकाल पूरे किए, पहली बार 1996 में 13 दिनों के कार्यकाल के लिए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए। वह

वह पहले गैर-भारतीय राष्ट्रवादी थे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान मंत्री को देश में अपना कार्यकाल पूरा करना होगा

वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सह-संस्थापकों में से एक और वरिष्ठ नेता थे। वह हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के सदस्य थे।

1977 और 1980 के चुनाव में नई दिल्ली से जीत हासिल करने के बाद, वाजपेयी चुनाव के लिए अपने गृह नगर ग्वालियर चले गए। विद्या राजदान को शुरू में कांग्रेस (आई) का उम्मीदवार बनाया गया था। इसके बजाय, ग्वालियर राजघराने के वंशज माधवराव सिंधिया को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन लाया गया। वाजपेयी सिंधिया से हार गए, उन्हें केवल 29% वोट ही मिले। उन्होंने 1957 से 1962 तक बलरामपुर से शुरू करके विभिन्न कार्यकालों के लिए लोकसभा के सांसद के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1967 से 1962 तक बलरामपुर से फिर से चुनाव लड़ा।

1971 से 1977 तक ग्वालियर से, और फिर 1977 से 1984 तक नई दिल्ली से।

अंततः, उन्होंने 1991-2009 तक ल्यूक-नो में अपनी सेवाएं दीं।
नारायण कृष्ण राव शे-
ज्वालकर: वे ग्वालियर से लोकसभा के सदस्य थे।

वे ग्वालियर से छठी और सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए। वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे और 1970-71 के दौरान ग्वालियर नगर निगम के महापौर भी रहे। उनके बेटे विवेक शेजवलकर 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए।

2019 में ग्वालियर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से।

माधवराव जीवाजीराव सिंधिया: वे एकमात्र राजनेता थे, जो ग्वालियर से रिकॉर्ड पांच बार सांसद बने और भारत सरकार में मंत्री रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे।

सिंधिया, अंतिम शासक जीवा-जीराव सिंधिया के पुत्र थे।

ब्रिटिश राज के दौरान ग्वालियर रियासत के महाराजा। 1961 में अपने पिता की मृत्यु के बाद, और भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान तय शर्तों के तहत, सिंधिया को प्रिवी पर्स, कुछ विशेषाधिकार और "ग्वालियर के महाराजा" की उपाधि मिली, जो 1971 तक चली, जिसके बाद भारत के संविधान के 26वें संशोधन द्वारा सभी को समाप्त कर दिया गया।

नौ बार लोकसभा के सदस्य रहे माधवराव सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे।

1971 के बाद से यह उनका पहला चुनाव है, जब उन्होंने 26 वर्ष की आयु में गुना निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार जीत हासिल की थी।
उन्होंने भारतीय जनसंघ (वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती) के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसका उनके परिवार ने लंबे समय तक संरक्षण किया था। आपातकाल के समय, वे देश छोड़कर यूनाइटेड किंगडम में स्व-निर्वासन में चले गए। भारत लौटने के बाद, उन्होंने भारतीय जनसंघ से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गुना निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और सीट जीती

1984 में, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए अंतिम समय में उन्हें ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया और वे भारी अंतर से विजयी हुए।

इसके बाद सिंधिया ने चुनाव लड़ा।
ग्वालियर या गुना से
और प्रत्येक अवसर पर जीत हासिल की।

30 सितम्बर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बाहरी इलाके में स्थित मोट्टा गांव में एक विमान दुर्घटना में 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।

यशोधरा राजे सिंधिया:
वे पहली बार ग्वालियर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से 2007 में उपचुनाव के माध्यम से 14वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं और फिर 2009 के आम चुनाव में भी। वे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री थीं। वे मध्य प्रदेश सरकार में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री भी रह चुकी हैं। वे ग्वालियर के मराठा महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और ग्वालियर की दिवंगत राजमाता विजयाराजे सिंधिया की सबसे छोटी बेटी हैं। वे 2013 से मध्य प्रदेश के शिवपुरी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा की सदस्य हैं।

एक भारतीय राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। वे कृषि और किसान कल्याण मंत्री रह चुके हैं। वे ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान और लघु उद्योग मंत्री रह चुके हैं।

भारत सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री

प्रथम और द्वितीय मोदी सरकार के विभिन्न कालखंडों में वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वे 2009 से 2014 तक मुरैना से पंद्रहवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे; 2014 से 2019 तक ग्वालियर से सोलहवीं लोकसभा और 2019 से 2023 तक मुरैना से 17वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। 2019 में उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया और मुरैना से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए।

विवेक नारायण शेजवलकर: वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।
वे 2019 के भारतीय आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में ग्वालियर, मध्य प्रदेश से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके पिता नारायण कृष्ण राव शेजवलकर ग्वालियर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से छठी लोकसभा और सातवीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे ग्वालियर नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं।

जनता पार्टी के पक्ष में लहर के बावजूद वे दूसरी बार चुनाव जीते। 1980 के चुनाव में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और तीसरी बार गुना से जीते।

नरेंद्र सिंह तोमर: वह

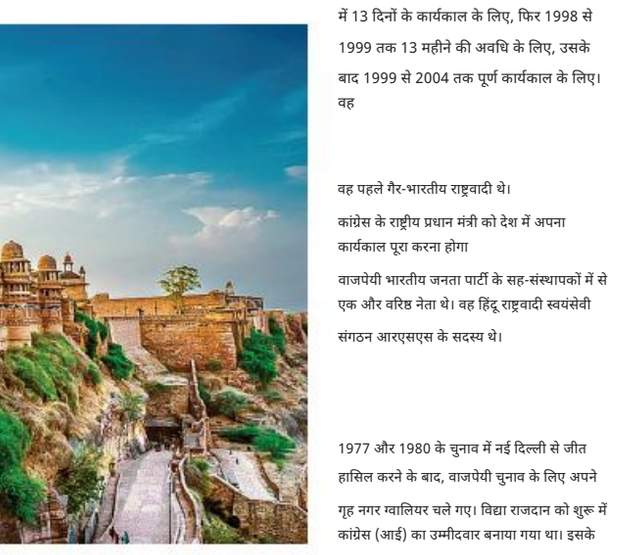

साहित्यिक अभियान और सार्वजनिक संलग्नताएँ।
पार्टी स्विचिंग

बार-बार पार्टी बदलना: इस निर्वाचन क्षेत्र में कई बार राजनीतिक नेताओं द्वारा पार्टी बदलने के मामले देखे गए हैं, कभी-कभी तो बहुत जल्दी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से भाजपा में जाना एक हाई-प्रोफाइल मामला था जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी थी। उनके इस कदम को एक रणनीति के रूप में देखा गया था।

चुनाव याचिकाएँ और कानूनी लड़ाइयाँ। उम्मीदवार अक्सर चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए अदालतों का सहारा लेते हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में कानूनी नाटक की एक परत जुड़ जाती है।

गुना में उन्हें 56,518 वोट (निर्वाचन क्षेत्र में 40.70% वोट) मिले, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार गोपी कृष्ण विजयवर्गीय को हराया। ग्वालियर में उन्हें 65,695 वोट (45.49%) मिले, उन्होंने वैद-ए-ही चरण पाराशर को हराया।

रॉयल का उपयोग
प्रभाव

राजसी स्थानों पर प्रचार: राजनीतिक आयोजनों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में शाही महलों और विरासत स्थलों का उपयोग ग्वालियर की राजनीति की एक अनोखी विशेषता है। खास तौर पर सिंधिया परिवार के उम्मीदवारों ने अपने-अपने स्थानों पर राजनीतिक सभाओं की मेज़बानी की है।

विजया राजे सिंधिया: वे ग्वालियर से तीसरी लोकसभा सदस्य थीं। उनका जन्म ले-खा दिव्येश्वरी देवी के रूप में हुआ था, वे ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी लोकप्रिय थीं।

ब्रिटिश राज के दिनों में ग्वालियर के अंतिम शासक महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी के रूप में, उन्हें देश के सर्वोच्च शाही व्यक्तियों में गिना जाता था। बाद के जीवन में, वह काफी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बन गईं और

भारतीय संसद के दोनों सदनों के लिए बार-बार चुनी गईं। वह भारतीय जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से एक थीं।

विजयाराजे 1957 में चुनावी राजनीति में उतरीं, जब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पांच साल बाद, उन्होंने ग्वालियर से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। बाद में, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1967 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर गुना सीट जीती। वह जल्द ही भारतीय जनसंघ में शामिल हो गईं और राज्य में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दे दिया।

ग्वालियर: संक्षेप में

ऐतिहासिक शहर: ग्वालियर एक महान ऐतिहासिक महत्व वाला शहर है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ग्वालियर किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था।

सिंधिया राजवंश: यह शहर भारत के प्रमुख शाही परिवारों में से एक, सिंधिया राजवंश से जुड़ा हुआ है। इस राजवंश ने क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंधिया परिवार, विशेष रूप से माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर काफी प्रभाव रहा है। उनके योगदान और नेतृत्व ने ग्वालियर के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है।

राजनीतिक निष्ठाओं में बदलाव: ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी, जो बदलती राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाती है।

प्रमुख दलों का गढ़: ऐतिहासिक रूप से, इस निर्वाचन क्षेत्र में मजबूत राष्ट्रपति का दबदबा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों की जीत हुई है। ग्वालियर में इन दो प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक लड़ाई चुनावों की एक परिभाषित विशेषता रही है।

प्रमुख नेता: पिछले कुछ वर्षों में ग्वालियर का प्रतिनिधित्व कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने किया है, जिनमें वसंत साठे (कांग्रेस), माधवराव सिंधिया (कांग्रेस और बाद में एमपीवीसी), और नरेंद्र सिंह तोमर (भाजपा) शामिल हैं।

भौगोलिक विशेषताएं: ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताओं के कारण जाना जाता है, जिसमें चट्टानी भूभाग और चंबल नदी की उपस्थिति शामिल है, जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है।

उच्च मतदाता मतदान: हाल के चुनावों में मतदाता मतदान में वृद्धि देखी गई है, जो मतदाताओं के बीच बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी का संकेत है।

चुनावी रुझान: इस निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी रुझान अक्सर व्यापक राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक पैटर्न को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे यह मध्य प्रदेश में राजनीतिक बदलावों को मापने का एक मापदंड बन जाता है।

लोकसभा सांसदों की सूची		
वर्ष	विजेता	दल
1952	वीजी देशपांडे	हिंदू महासभा
1952^	नारायण भास्कर खरे	
1957	सूरज प्रसाद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1962	विजया राजे सिंधिया	
1967	राम अवतार शर्मा	भारतीय जनसंघ
1971	अटल बिहारी वाजपेयी	
1977	नारायण शेजवलकर	जनता पार्टी
1980		
1984	माधवराव सिंधिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1989		
1991		
1996		मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस
1998		भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1999	जयभान सिंह पवैया	भारतीय जनता पार्टी
2004	रामसेवक सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

^ द्वारा चुनाव

Machine Translated by Google

सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल आदेश पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत पंजाब के पूर्व मंत्री पर लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज

टीडीजी नेटवर्क
नई दिल्ली

एच आर्यना हाई
पंजाब और मामले में अदालत

संधू सिंह धर्मसोत बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के आदेश पर भरोसा किया है और इस पर भी भरोसा किया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दे दी है।

के संबंध में टोरेट

धन शोधन का मामला।

न्यायमूर्ति विकास बहल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उक्त अदालत याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई इस दलील पर संदेह नहीं करती है कि वह पांच बार के पूर्व विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, वह अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, जिसके साथ वह रहे हैं-

1992 से संबद्ध.

इसके अलावा, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी हर समन का जवाब दिया था और किसी भी समन को नहीं छोड़ा था।

मामले में हमारा मत है कि प्रतिवादी-ईडी की ओर से उठाया गया तर्क

इस आशय से कि याचिकाकर्ता उसी लाभ का हकदार नहीं है जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है, सुप्रा अस्वीकार किए जाने योग्य है और याचिकाकर्ता वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

मामले में अदालत

माना जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने कुछ सामग्री रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा था इसलिए नियमित जमानत प्रदान करने हेतु मुख्य याचिका को स्थगित करना आवश्यक है।

वर्तमान मामले में,
धर्मसोत पर मामला दर्ज
धारा 7 के तहत, धारा 7ए,

राज्य के वन विभाग में कथित अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति को लेकर पीसी एक्ट की धारा 13(1)(ए)(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसलिए, प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) पंजीकृत की गई क्योंकि दोनों एफआईआर में अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध थे। इस प्रकार, उन्हें इस वर्ष जनवरी में गिरफ्तार किया गया और ईडी की हिरासत के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल के मामले में 'शर्तों को हटा दिया गया था।

उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना
न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि

इसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता को किसी भी राजनीतिक रैली और बैठक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी शर्त लागू करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।'

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता पांच बार विधायक रह चुका है।

कांग्रेस(आई) पार्टी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और वह भी बने रहे

कैबिनेट मंत्री
पंजाब राज्य और उन्हें वन, मुद्रण और के विभाग
आवंटित किए गए थे

स्टेशनरी और अनुसूचित जातियों का कल्याण

पिछड़ा वर्ग और
याचिकाकर्ता ने

1992 से पंजाब राज्य में सक्रिय राजनीति में।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और पंजाब में मतदान की तारीख 4 जून 2024 है और मतगणना उसी दिन होगी और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता समाज के लिए खतरा है। मामले में जस्टिस बहल की अध्यक्षता वाली बेंच ने पाया कि धर्मसोत ने 18वीं लोकसभा के लिए 100,000 से अधिक वोटों से वोट डाला है।

वह सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित नहीं है और
किसी सार्वजनिक पद पर नहीं है, इसलिए वह
किसी व्यक्ति को प्रभावित करने या सरकारी
फाइलों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है।

इसके अलावा,

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रत्येक समन का जवाब दिया है और किसी भी समन को नहीं छोड़ा है।

अदालत ने धर्मसोत को 05 जून तक अंतरिम जमानत प्रदान की, जिसमें अदालत ने निर्देश दिया कि वह 06 जून को दोपहर 12:00 बजे निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर आत्मसमर्पण करेंगे: -

i) याचिकाकर्ता को विशेष न्यायालय या ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानतदार को प्रस्तुत करना होगा।

ii) याचिकाकर्ता वर्तमान मामलों में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

iii) याचिकाकर्ता

किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न करें।

iv) याचिकाकर्ता देश नहीं छोड़ेगा।

तदनुसार, अदालत ने मामले को आगे के विचार के लिए 01 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एपीएस देओल, अधिवक्ता विशाल रतन लांबा, हिम्मत सिंह देओल, सुमेर सिंह बोपाराय, अरुण कुमार गोयत, करण कालिया, धर्म पाल, स्वाति कटोच शामिल थे।

वकील जगजोत सिंह लाली, भारत के उप सॉलिसिटर जनरल, तथा प्रतिवादी के वकील लोकेश नारंग और मनीष वर्मा।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के आदेश को संशोधित करने के लिए सुझाव मांगे वाहन बीमा के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य

टीडीजी नेटवर्क
नई दिल्ली

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2017 के आदेश पर पुनर्विचार करने का इरादा व्यक्त किया है, जिसके तहत तीसरे पक्ष के वाहन बीमा के लिए प्रदूषण नियंत्रण, पी.यू.सी. प्रमाण पत्र को अनिवार्य बना दिया गया था।

ऐन्स.

मामले में न्यायालय ने पीयूसी मानदंडों और तृतीय-पक्ष बीमा के बीच संतुलन की आवश्यकता के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणी की।

अदालत ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से भी सुझाव मांगे

तुषार मेहता और एम.

आई.सी.यू.एस. क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह से इस मुद्दे का समाधान प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है, ताकि 2017 के निर्देशों को प्रभावी रूप से संशोधित किया जा सके।

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 10 अगस्त, 2017 के न्यायालय के आदेश का पालन न करने की चिंता व्यक्त की गई थी।

न्यायालय ने 2017 के अपने आदेश में कहा था कि यह स्पष्ट किया जा रहा है कि बीमा कंपनियां तब तक किसी वाहन का बीमा नहीं करेंगी जब तक कि उसके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र न हो।

बीमा पॉलिसी के नवीकरण की तिथि।

हालांकि, अदालत ने कहा कि वार्षिक वाहन बीमा को पीयूसी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों के साथ जोड़कर 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त निर्देश पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण, ईपीसीए द्वारा दिल्ली एनसीआर में पीयूसी कार्यक्रम के मूल्यांकन पर दायर 73वीं रिपोर्ट के आलोक में दिए गए।

जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, एसजी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि

सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्देश के आलोक में, 55% वाहन तृतीय पक्ष बीमा के लिए पंजीकरण नहीं करवाते हैं।

अदालत ने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में दावेदारों को मुआवजा मिलना मुश्किल होता है।

मामले में अदालत ने कहा कि पीयूसी मानदंडों के अनुपालन और वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि उक्त अदालत का मानना है कि सही संतुलन होना चाहिए।

यह सुनिश्चित करते हुए कि वाहन पीयूसी मानदंडों के अनुरूप बने रहें, सभी वाहनों पर थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। लेकिन साथ ही, सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए।

अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान न्यायमित्र और विद्वान सॉलिसिटर जनरल को समाधान निकालने की अनुमति दी ताकि 10 अगस्त, 2017 के आदेश में उचित संशोधन किया जा सके।

तदनुसार, अदालत ने मामले को आगे विचार के लिए 15 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध किया।

सुप्रीम कोर्ट: एजेंसी को समाप्त नहीं किया जाएगा प्रिंसिपल की मृत्यु पर यदि एजेंट का इसमें हित है संपत्ति जो अनुबंध का विषय है

टीडीजी नेटवर्क
नई दिल्ली

पी. शेषारेड्डी (डी) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने

उनके एलआर सह अपरिवर्तनीय जीपीए धारक और असाइनी कोटमरेड्डी कोडंडारामी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व ने देखा कि मूल ठेकेदार की मृत्यु एजेंट यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को अनुबंध से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगी यदि एजेंट उस अनुबंध में रुचि रखता है जो पूर्व है-

अनुबंध में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने मामले में कहा,

ने कहा है कि जहां
यदि एजेन्ट का स्वयं उस सम्पत्ति में हित है, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में किया गया है, तथा जो एजेन्सी का विषय-वस्तु है, तो एजेन्सी अनुबंध समाप्त नहीं होगा, जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 201 के अन्तर्गत कहा गया है, प्रधान की मृत्यु होने पर 1872 का अधिनियम लागू होता है।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 201 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें एजेंसी का अनुबंध समाप्त हो जाएगा, यदि उनमें से एक स्थिति मुख्य ठेकेदार की मृत्यु हो।

अपीलकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि वह अनुबंध में हित रखता है, इसलिए मूल व्यक्ति की मृत्यु पर एजेंसी की समाप्ति उचित नहीं है।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 202 उन स्थितियों से संबंधित है, जहां एजेंट का विषय-वस्तु में हित होता है। धारा में कहा गया है कि जहां एजेंट का उस संपत्ति में हित है जो एजेंसी की विषय-वस्तु बनाती है, वहां एजेंसी को, किसी स्पष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में, ऐसे हित के प्रतिकूल प्रभाव के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, उक्त न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि जब मुख्तारनामा, एक एजेंट होने के नाते, अनुबंध में रुचि रखता है, तो अधिनियम की धारा 201 के तहत मुख्य ठेकेदार की मृत्यु पर एजेंसी की स्वचालित समाप्ति नहीं होगी, जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 201 के तहत कहा गया है।

इसके अलावा, मामले में अदालत ने कहा कि विद्वान

एकल न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि

असाइनमेंट डीड के खाते में, उक्त अनुबंध के पक्ष में अर्जित ब्याज

अपीलकर्ता।

अदालत ने यह भी कहा कि
उक्त अनुबंध एजेंसी की विषय-वस्तु थी और इसके विपरीत
किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में अपीलकर्ता उक्त एजेंसी के साथ काम जारी रखने का हकदार था।

आइसोला में पढ़ा नहीं जा सका-
जब एजेंट अनुबंध में हित रखता है, तो अधिनियम की धारा 202 की अनदेखी करके अनुबंध को रद्द करना।

वर्तमान मामले में, प्रधान ठेकेदार ने अपीलकर्ता के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की और प्रधान ठेकेदार की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी ने एजेंसी अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी को समाप्त करने की मांग की।

अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को एजेंसी यानी पावर ऑफ अटॉर्नी जारी रखने की अनुमति दी गई।

तदनुसार, अदालत ने अपील स्वीकार कर ली।

अधिनियम की धारा 201 के आधार पर अंतिम ठेकेदार का चयन नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 202 पर भरोसा करते हुए अदालत के समक्ष तर्क दिया कि चूंकि वह उस संपत्ति में हित रखता है जो एजेंसी की विषय-वस्तु है, इसलिए एजेंसी को, किसी स्पष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में, ऐसे हित के पूर्वाग्रह के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश की पीठ भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 202 की अनदेखी करके भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 201 को अलग से नहीं पढ़ सकती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक संपादक की रिहाई का आदेश दिया यूएपीए मामला: दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की पुलिस और रिमांड अवैध

टीडीजी नेटवर्क
नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ बनाम भारत संघ मामले में यह आदेश दिया है।
राज्य ने निर्णय सुनाया जिसमें न्यायालय ने 'गिरफ्तारी के कारणों' और 'गिरफ्तारी के आधारों' के बीच अंतर किया।

अदालत ने कहा कि इन दोनों शब्दों में काफी अंतर है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 'गिरफ़्तारी के कारण' औपचारिक हैं और किसी भी अपराध के लिए गिरफ़्तार किए गए व्यक्ति पर आम तौर पर लागू हो सकते हैं। अदालत ने इनमें से कई औपचारिक मापदंडों का भी हवाला दिया, जो आरोपी व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने से लेकर मामले की उचित जांच के लिए उपाय करने तक के हैं।

दूसरी ओर, 'गिरफ्तारी के आधार' व्यक्तिगत होते हैं तथा गिरफ्तार व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं।

अदालत ने कहा कि ये कारण सामान्यतः किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो, जबकि 'गिरफ्तारी के आधार' में जांच अधिकारी के पास मौजूद ऐसे सभी विवरण शामिल होने चाहिए, जिनके कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक हो।

मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एक मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित करते हुए यह टिप्पणी की है। इस प्रकार, न्यायालय ने इस तथ्य पर अपना तर्क दिया कि आधार

गिरफ्तारी की सूचना उन्हें लिखित रूप में नहीं दी गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस द्वारा पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। इससे व्यथित होकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के आधार पुरकायस्थ को गिरफ्तारी ज्ञापन के माध्यम से लिखित रूप में बताए गए थे। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार्य पाया।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गिरफ्तारी ज्ञापन में केवल 'गिरफ्तारी के कारण' थे, न कि 'गिरफ्तारी के आधार'।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन के कॉलम क्रमांक 9 में कहा गया है कि

अनुलग्नक पी-7 जो है-
नीचे दिए गए अनुच्छेद में केवल 'गिरफ्तारी के कारण' बताए गए हैं जो कि औपचारिक प्रकृति के हैं और इन्हें आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जबकि 'गिरफ्तारी के आधार' व्यक्तिगत प्रकृति के होंगे और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए विशिष्ट होंगे।

इसके अलावा, अदालत ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने के महत्व पर बल दिया, ताकि वह हिरासत में रिमांड के खिलाफ अपना बचाव कर सके और जमानत मांग सके।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार में गिरफ्तार आरोपी को सभी बुनियादी तथ्य बताए जाने चाहिए, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि उसे अपना बचाव करने का अवसर मिल सके।

उन्होंने हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ अपील की और जमानत मांगी।

इसके साथ ही, अदालत ने कहा कि 'गिरफ्तारी का आधार' हमेशा आरोपी के लिए व्यक्तिगत होगा और इसे 'गिरफ्तारी के कारणों' के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, जो सामान्य प्रकृति के होते हैं।

इसके अलावा, अदालत ने याद दिलाया कि पुरकायस्थ पिछले साल 3 अक्टूबर से यूएपीए के तहत राष्ट्र विरोधी प्रचार करने के लिए चीनी धन प्राप्त करने के एक मामले में हिरासत में हैं और गिरफ्तारी और रिमांड को कानून की नजर में अवैध घोषित किया गया है और अदालत ने पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए रिहाई इस शर्त पर होगी कि वह निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत और बांड प्रस्तुत करें।

सुप्रीम कोर्ट: रिट याचिका एयर इंडिया के खिलाफ कर्मचारी नहीं निजीकरण के बाद भी बनाए रखा जा सकता है

टीडीजी नेटवर्क
नई दिल्ली

आर.एस. मदीरेड्डी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को देखा और उसकी पुष्टि की, जिसमें एयर इंडिया लिमिटेड, ए.आई.एल. के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं ए.आई.एल. के बाद के निजीकरण के कारण अब विचारणीय नहीं होंगी।

दायर याचिका में गैर-प्रोन्नति और ठहराव से संबंधित मुद्दों को उठाया गया

वेतन।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मौखिक रूप से फैसला सुनाया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस अदालत को बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखने में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है।

अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका...सही नहीं पाई गई। इस प्रकार, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

निवेदन।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले में कहा कि

रिट याचिकाएं, हालांकि तारीखों पर सुनवाई योग्य हैं

वे स्थापित किए गए थे, लेकिन अब कायम रखने योग्य नहीं रह गए हैं

एआईएल के निजीकरण के कारण, इसके लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं, अर्थात् संबंधित कर्मचारियों ने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की।

पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल याचिका पर नोटिस जारी किया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंहवी ने इस मामले में पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि जब रिट याचिकाएं दायर की गयी थीं, तो वे स्वीकार्य थीं।

उन्होंने आगे कहा कि यह सिद्धांत कि किसी मामले की सुनवाई योग्यता को रोका जाना चाहिए, वह है-

के संदर्भ में खनन किया गया
तथ्य वैसे ही जैसे वे संस्था की स्थापना की तिथि को विद्यमान थे-
याचिकाओं का निपटान-
सामान्यतः इससे विचलित नहीं होना चाहिए।

दूसरी ओर, एयर इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों से पीठ को अवगत कराया, जहां एयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ याचिकाओं को एक इकाई के बाद के निजीकरण के कारण गैर-रखरखाव योग्य के रूप में निपटाया गया था, जो पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक 'राज्य' था।

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा बलात्कार के मामलों में 'टू फिंगर' टेस्ट पर प्रतिबंध के बारे में

टीडीजी नेटवर्क
नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने सनशाइन खारपन बनाम भारत संघ मामले में यह आदेश दिया।
मेघालय राज्य ने मेघालय उच्च न्यायालय से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'टू-फिंगर टेस्ट' की निंदा किए जाने के बावजूद बलात्कार के मामले में इसका इस्तेमाल किया गया।

अदालत ने लिल्लू उर्फ राजेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बलात्कार पीड़िता पर दो-उंगली परीक्षण उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो वर्तमान घटना घटित होने से पहले पारित किया गया था।

अदालत ने कहा कि यह सच है कि घटना

वर्तमान मामला एक दशक पहले, सटीक रूप से कहें तो, 26 अक्टूबर 2013 को घटित हुआ था। इसलिए, वर्तमान मामले से पता चला कि

अवज्ञाकारी का जारी रहना
लिल्लू उर्फ राजेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद भी 'टू-फिंगर टेस्ट' आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है।

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बलात्कार के अपराध के लिए आरोपी या वर्तमान अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को एक चौंकाने वाली घटना का पता चला, जिसमें बलात्कार पीड़िता पर टू-फिंगर टेस्ट लागू किया गया था।

इससे पहले न्यायालय ने प्रश्न किया था-

मेघालय राज्य से पूछा गया कि राज्य में 'दो-उंगली परीक्षण' की इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

बलात्कार के मामले.
अदालत ने कहा कि
याचिका पर विचार करते हुए और चौंकाने वाली घटना को देखते हुए, जिसमें यह पता चला है कि बलात्कार की पीड़िता को संभोग की आदत थी या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए 'टू-फिंगर टेस्ट' करने की प्रथा पर प्रतिबंध के बावजूद, जिसकी उक्त अदालत ने दृढ़ता से निंदा की है क्योंकि यह परीक्षण की प्रतिगामी और आक्रामक प्रकृति है, इस अदालत ने राज्य के विद्वान वकील से एक प्रश्न पूछा कि इस अदालत के विभिन्न निर्णयों के आलोक में, इस बुरी प्रथा को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

उपस्थित हुए वकील ने इस पद्धति के प्रयोग के विरुद्ध जारी दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया तथा हाल ही में जारी उस पत्र का भी हवाला दिया जिसमें चेतावनी दी गई थी कि शैलेन्द्र कुमार राय के मामले में इसका उल्लंघन कदाचार माना जाएगा।

राज्य के अधिवक्ता जनरल अमित कुमार ने न्यायालय को झारखंड राज्य बनाम शैलेन्द्र कुमार राय उर्फ पांडव राय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अवगत कराया, जिसमें इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए उचित कार्रवाई की गई है।

वर्ष 2022 में न्यायालय ने बलात्कार के मामलों में 'टू-फिंगर टेस्ट' पर रोक को दोहराया था और चेतावनी दी थी कि इस तरह के परीक्षण करने वाले व्यक्ति को कदाचार का दोषी माना जाएगा।

अदालत ने कहा कि जब
एक विशेष प्रथा जिसकी इस न्यायालय द्वारा बार-बार निन्दा की गई है तथा इसे प्रतिगामी और आक्रामक प्रकृति बताया गया है, हमारा यह सुविचारित मत है कि उक्त पत्र दिनांक के अनुसार प्रस्तावित कार्रवाई-

29 अप्रैल, 2024 को जारी अधिसूचना स्पष्ट होनी चाहिए थी तथा इसके परिणाम गंभीर प्रकृति के होने चाहिए थे।

राज्य अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया है कि शैलेन्द्र कुमार राय के मामले के आलोक में उचित आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किए जाएंगे कि उक्त प्रथा का उन्मूलन हो। तदनुसार, न्यायालय ने मामले को आगे के विचार के लिए 29 सितंबर, 2024 को सूचीबद्ध किया।

Machine Translated by Google

आज का विचार: इसीप्रकार सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे प्रतिभाशाली पाखंडी से भी अधिक मूल्यवान बना देती है।

— चार्ल्स स्पर्जन

संपादन करना

THE FREE PRESS JOURNAL 1928 से
संस्थापक संपादक: एस सदानन्द

होर्डिंग्स: जिम्मेदारी कहां रुकती है?

प्रत्येक इस सप्ताह के दूसरे दिन सोमवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बड़े और अवैध होर्डिंग के गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 75 लोग घायल हो गए, इस भयानक त्रासदी के बाद इसमें शामिल हर एजेंसी ने दोषारोपण का खेल खेला है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), जिसका शहर भर में होर्डिंग्स पर अंतिम निर्णय है और जिसका अधिकतम 40x40 वर्ग फुट का शासनादेश इस होर्डिंग द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, जो कम से कम तीन गुना बड़ा था, यह दिखाने के लिए पीछे हट गया है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए रेलवे सहित अन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्र जारी किए, जिनकी जमीन पर अप्रैल 2022 में होर्डिंग लगाया गया था। इससे केवल यह दिखाने में सफलता मिली कि बीएमसी को होर्डिंग की अवैधता के बारे में अच्छी तरह से पता था

रेलवे ने अपने परिसरों में बड़े आकार के होर्डिंग्स को हटाने के बीएमसी के निर्देश का पालन करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि उनके पास "इन संरचनाओं की स्थापना से पहले और बाद में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त तंत्र है"। फिर घाटकोपर में 120x120 वर्ग फीट के होर्डिंग को मंजूरी कैसे मिल गई, जबकि जांच से पता चला है कि इसके खंभे केवल 1.5 मीटर गहरे हैं और स्पष्ट रूप से तेज हवाओं या बारिश का सामना करने में असमर्थ हैं? रेलवे मुंबईकरों के बीच बिल्कुल भी भरोसा नहीं जगाती है।

गिरफ्तार लोगों में अब इस पूरे मामले के केंद्र में रहने वाला व्यक्ति, ईगो मीडिया का भावेश भिंडे भी शामिल है, जिस कंपनी को होर्डिंग लगाने का ठेका दिया गया था। भिंडे इस जानलेवा घोटाले का केवल एक चेहरा है, जिसके दरवाजे पर रेलवे और बीएमसी सारा दोष मढ़ रहे हैं। उन अधिकारियों का क्या, जो अदृश्य लेकिन जवाबदेह पुरुष और महिलाएं हैं, जिन्होंने इस होर्डिंग को मंजूरी दी, जो इतने सारे लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ और लोगों की जान से ज्यादा राजस्व को प्राथमिकता दी? उनकी पहचान सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताई जानी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए? किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को दूसरों पर दोष मढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केवल प्रधानमंत्री ही जानते हैं

प्रधानमंत्री के बारे में एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ा।

नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान के दौरान दिए गए कई बयानों को उन्होंने कुछ ही दिनों में वापस ले लिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो खुद मुंबई उत्तर से उम्मीदवार हैं, ने इस पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि केवल प्रधानमंत्री ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने अपने बयान क्यों वापस लिए। कई लोगों का कहना है कि यह उलटफेर उस व्यक्ति के स्वभाव के विपरीत है, जिसे "एक महान वक्ता" के रूप में सराहा गया है, लेकिन कई बार टेलीप्रॉम्प्टर जीवी भी कहा गया है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोलने की उनकी क्षमता विफल हो गई है। हालांकि मोदी की अपने वफादार दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता पर संदेह नहीं है, लेकिन यह उन्हें एक महान वक्ता नहीं बनाता है, जिसके लिए परिभाषा के अनुसार, विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ठोस तर्क देने में सक्षम होना चाहिए, कुशलता से बोलना चाहिए, भाषा का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए कई तरह की भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए।

आइए हम उनकी वक्तृत्व कला या उसकी कमी को एक तरफ रख दें।
पिछले कुछ दिनों से वे किसी विषय पर मुखर होकर बयान दे रहे हैं, आम तौर पर किसी राजनीतिक रैली में वोट की अपील करते हुए, और फिर कुछ ही दिनों में उसे वापस ले लेते हैं, जिससे मीडिया में उनके प्रशंसक और प्रशंसक भी अचंभित रह जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ है। उन्होंने राजस्थान में गलत तरीके से कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को देश के संसाधनों पर अधिकार मिले; कुछ दिनों बाद, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से कहा कि वे कभी भी हिंदू-मुस्लिम कार्ड नहीं खेलेंगे - लेकिन अगली रैली में वे अपनी बात से पलट गए। फिर, उन्होंने कहा कि उन्हें "400 से ज़्यादा सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे" लेकिन उन्होंने ऐसा कहने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे और भी उदाहरण हैं।

कुल मिलाकर, यह कम से कम दो बातों की ओर इशारा करता है। एक यह कि प्रधानमंत्री अतीत या भविष्य के संदर्भ के बिना, अपने वर्तमान समय के अनुरूप वास्तविकता को बदलते और मोड़ते दिखते हैं, जिससे उनके संतुलन पर सवाल उठता है। दूसरा भारत के लोगों से संबंधित है और इसे अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर कुछ भी हो, तो इन उलटफेरों और वापसी ने यह प्रदर्शित किया है कि प्रधानमंत्री के बयानों को अब संदेह और सावधानी की स्वस्थ खुराक के साथ लिया जाना चाहिए। अनजाने में, उन्होंने अपने बड़े और चापलूस प्रशंसकों और प्रशंसक लड़कियों के क्लब को तथ्य-जांचकर्ताओं में बदल दिया है जो अब बाकी सभी की तरह ही अविश्वसनीय रूप से देखते हैं। अपने नायक के बारे में आँखों से पर्दा हटना एक अच्छी बात है, खासकर लोकतंत्र में।

एफपीजे अभिलेखागार

75 साल पहले का भारत

18 मई, 1949

FREE PRESS JOURNAL

प्रेस के अधिकारों की गारंटी

बेंगलुरु, 17 मई। अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक संघ की एक उप-समिति ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समाचार पत्रों के संपादकों की समिति ने समाचार पत्रों के संपादकों की एक उप-समिति की बैठक में ...

सम्मेलन का उद्देश्य संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रारूप समिति से मुलाकात करना है, तथा भारत के भावी संविधान में प्रेस को उसके मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाला एक खंड शामिल करने का आग्रह करना है।

चुनावों के लिए अंधराष्ट्रीयता ठीक है, पड़ोसियों के लिए नहीं

दोस्ताना आँख

÷के.सी. सिंह

सर्वेक्षणों में पुलवामा आतंकवादी हमले और जम्मू-कश्मीर में भारत के विरोध प्रदर्शन का बोलबाला रहा। 2019 लोकसभा के विपरीत, पाकिस्तान के बालाकोट पर मोदी सरकार के साहसिक हवाई हमले का मुद्दा मौजूदा चुनाव के पहले तीन चरणों में नहीं उठा।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी के बाद यह स्थिति बदल गई कि पाकिस्तान के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं और उसने चूड़ियां नहीं पहनी हैं - यह एक लिंग-पक्षपाती कथन है, जो स्त्रीवत व्यवहार को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी भी अपने भाषणों में कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान और विपक्ष को आड़े हाथों लेने का मौका नहीं छोड़ सकते। बिहार में चौथे चरण के दौरान प्रचार करते हुए उन्होंने भड़काऊ अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान ने "चूड़ियाँ नहीं पहनीं", तो उनकी सरकार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है। इस तस्वीर का उद्देश्य बालाकोट की भावना को जगाना था, जिसका फायदा उठाने में भाजपा अब तक विफल रही है। पाकिस्तान कम से कम अस्थायी तौर पर चुनाव के विषय के रूप में वापस आ गया था। विपक्ष चुनाव प्रचार को अलग-थलग कर रहा था

किसी भी ऐसे मुद्दे से दूर रहें जो प्रधानमंत्री की जिद और उत्पात मचाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता हो।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 14 मई को विस्तार से जवाब दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई सरकार अब तक अपने घरेलू आर्थिक संकट से निपटने में व्यस्त थी, जबकि वह चुपचाप भारतीय चुनावी नतीजों का इंतजार कर रही थी, ताकि यह आकलन कर सके कि अगली सरकार पिछले पांच वर्षों की आतंकवाद के बीच बातचीत न करने की नीति में कोई बदलाव करेगी या नहीं।

एक लंबे बयान में कहा गया है, "हम भारतीय राजनेताओं से आग्रह करते हैं कि वे चुनावी लाभ के लिए पाकिस्तान को अपनी राजनीति में घसीटना बंद करें और संवेदनशील रणनीतिक मामलों को अत्यंत सावधानी से संभालें।"

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे इस बात पर ध्यान दें कि भारत "क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा" के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। बयान में अनुमान लगाया गया कि भारतीय अंधराष्ट्रवाद "लापरवाह और उग्रवादी मानसिकता" को दर्शाता है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जनता के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के कारण चर्चा में आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान की आलोचना में अपना योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निकट भविष्य में पीओके क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लेगी। उनके राजनीतिक घमंड और प्रधानमंत्री के चूड़ियों वाले ताने के बीच एक व्यापक रणनीतिक संबंध छिपा है।

एक ऐसा स्थान जिस पर बहस की जा सकती है, तथा जोखिम और लाभ का मूल्यांकन किया जा सकता है। चुनावों में अंधराष्ट्रीयता उपयोगी हो सकती है, जब जनता भाजपा के मानक विभाजनकारी कथानक से उतनी उत्साहित नहीं दिखती, लेकिन पड़ोस की स्थिति लोकप्रिय छवि से कहीं अधिक जटिल है।

पीओके और सम्पूर्ण कश्मीर मुद्दा आज भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है जैसा कि 1972 के शिमला समझौते में परिकल्पना की गई थी।

गौरतलब है कि जब 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था, तो चीन ने भारत द्वारा एकतरफा बदलाव करने पर आपत्ति जताई थी-

चुनावी बयानबाजी चाहे जो भी हो, अगली भारतीय सरकार के सामने क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है, जितना कि चूड़ियों के तानों से पता चलता है।

विवादित क्षेत्र में चीन भी शामिल है। मई 2020 में गलवान घाटी से शुरू होकर लद्दाख में उनकी सैन्य घुसपैठ उनकी आपत्तियों का ही परिणाम थी। चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में भारी निवेश किया है, जिसका परिव्यय 46 बिलियन डॉलर से बढ़कर 62 बिलियन डॉलर हो गया है। यह गलियारा दक्षिणी शिन-जियांग को बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो POK में गिलगी-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इसलिए भारत द्वारा POK को सैन्य रूप से पुनः प्राप्त करने के किसी भी प्रयास में चीन द्वारा भारी संभावना है।

संघर्ष में शामिल होना।

दरअसल, विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है और भाजपा उसे टाल रही है, वह यह है कि देपसांग मैदानों और डेमचोक में चीनी घुसपैठ को वापस क्यों नहीं लिया गया है। बेशक सरकार ने 2020 में सुस्ती के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारतीय सैन्य स्थिति को मजबूत किया है। सरकार ने LAC पर बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा दिया है। लेकिन सेना-से-सेना वार्ता ने देश के कुछ हिस्सों में शुरुआती सफलता के बाद प्रगति नहीं की है।

पूर्वी लद्दाख में। कुछ लोग कहेंगे कि सफलता का एक हिस्सा तब मिला जब भारत ने कैलाश पर्वतमाला पर प्रमुख स्थानों पर कब्जा करके चीन को चौंका दिया। स्पष्ट रूप से चीन क्षेत्रीय विवाद को अनसुलझा रखना चाहता है क्योंकि इससे वह समय-समय पर उकसावे के ज़रिए भारत को असंतुलित रखने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए, लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर चीन ने न केवल अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखाया बल्कि इसके बसे हुए इलाकों को भी चीनी नाम दिए।

भारत इस मामले में सतर्क रहा है।

चीन को पीछे छोड़ते हुए। इसने एशिया-प्रशांत में अमेरिका द्वारा प्रायोजित छोटे गठबंधनों में शामिल होने से परहेज किया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका से मिलकर बना क्वाड, चीन की आशंका के मुताबिक इंडो-पैसिफिक का नाटो बनने से चूक गया है। भारत की अनिच्छा को देखते हुए, अमेरिका ने AUKUS बनाया - मौजूदा सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ एक त्रिपक्षीय समूह। इसके बाद वे अन्य प्रशांत शक्तियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 जुलाई, 2023 को लिथुआनिया में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया के नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

इसलिए, चुनावी बयानबाजी चाहे जो भी हो, अगली भारतीय सरकार के सामने क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है, जितना कि चूड़ियों के तानों से पता चलता है।

तार्किक रूप से, जब दो शत्रुतापूर्ण विरोधियों का सामना हो तो उद्देश्य उनके गठबंधन को कमजोर करना होना चाहिए।

उन्हें और अधिक निकट लाने के लिए दबाव डालना दीर्घकाल में आत्मघाती होगा।

इजरायल पर हमास के हमले में भारत के लिए सबक है - ऐतिहासिक विवादों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्हें चीनी हथियारों की ओर धकेलना कूटनीतिक विफलता है।

के.सी. सिंह विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं

नैतिक आतंक और हिंदू राष्ट्रवाद की चिंताएं

असहमत कोना

÷कॉनराड बार्वा

सबसे अधिक नियंत्रण में से एक दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल, 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में चुनाव अभियान के दौरान दिए गए दो भाषणों में से एक भाषण में हिंदुत्व विचारकों द्वारा बहुत पसंद किए जाने वाले शब्दों को दोहराया गया, जैसे कि मुसलमानों में अधिक बच्चे पैदा करने की कथित प्रवृत्ति, जिससे मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मुसलमानों का वर्णन करने के लिए "घुसपैठिए" जैसे शब्दों का इस्तेमाल, पिछली गैर-भाजपा सरकारों पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को लाड़-प्यार दिया है, और यह इस दावे के साथ चरम पर पहुंच गया कि कांग्रेस के घोषणापत्र में धन के पुनर्वितरण के प्रस्तावों से व्यक्तिगत जोत और बचत का जबरन अधिग्रहण होगा, जैसे कि "हमारी माताओं और बहनों" के गले से मंगलसूत्र छीनना।

इस भाषण की विषय-वस्तु के पीछे कई ऐसे तत्व छिपे हैं, जो प्रधानमंत्री और भाजपा दोनों की विचारधारा के बारे में जानकारी देते हैं।

सबसे पहले, जैसा कि नीलांजन मुखोपाध्याय जैसे कई टिप्पणीकारों ने कहा है, ऐसी सांप्रदायिक भाषा और विषय-वस्तु का प्रयोग कोई अपवाद नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जो प्रधानमंत्री के भाषणों से दूर हो गया हो, बल्कि यह एक ऐसा तत्व है जो हमेशा से मौजूद रहा है।

उनके कार्यों और शब्दों में हमेशा "अचेतन सांप्रदायिक कोण" रहा है। जैसा कि मुखोपाध्याय तर्क देते हैं, "मोदी के हाथ में हमेशा दो कार्ड होते हैं - विकास और सांप्रदायिक विभाजन। यह स्थिति पर निर्भर करता है कि उनका प्राथमिक कार्ड कौन सा होगा।

सांप्रदायिकता का मुद्दा हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे लाया जाता है, ताकि मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत किया जा सके। जो पर्यवेक्षक इस तर्क से खुद को सहज महसूस करते हैं कि पद पर बने रहना एक नरमपंथी ताकत के रूप में काम करता है या जो मोदी की कल्याणकारी और विकासवादी बयानबाजी पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह किसी तरह उनकी सरकार का असली जोर है, वे इस पहलू को महत्वपूर्ण और अशुभ रूप से नजरअंदाज करते हैं।

यहाँ की अधिकांश शैली अब तक अच्छी तरह से अभ्यास की गई और अल्पविकसित है, जिसका इस्तेमाल पिछले दशक में प्रधानमंत्री द्वारा अपने विभिन्न अभियान अभियानों में अक्सर किया गया है। संवादात्मक शैली स्वर में वार्तालापपूर्ण है, जो लक्षित दर्शकों, मुख्य रूप से पुरुष, के साथ एक काल्पनिक वार्तालाप की नकल करती है, जिसमें किसी भी कठिन शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। यह रूपकात्मक भी है, जो लगातार हिंदुओं और उनके विरोधियों के लिए कथित खतरों की शक्तिशाली छवियों को उजागर करता है। ये रूपक बहादुरी, मर्दानगी और सदाचार के हैं, जो कायरता, स्त्रीत्व और बुराई के विपरीत हैं; या कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बात करें तो कमजोरी, घातक नीतियों और उपहास के रूपक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावधानीपूर्वक नपे-तुले "मानक अतिक्रमण" का प्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए, मुसलमानों को "घुसपैठिए" के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनके डिप्टी और गृह मंत्री अमित शाह की बात को प्रतिध्वनित करता है, जिन्होंने मुसलमानों को कुख्यात रूप से "दीमक" के रूप में संदर्भित किया था, जो कथित रूप से बड़ी संख्या में मुसलमानों की ओर इशारा करता है, जो बांग्लादेश से सीमा पार कर भारत में बस गए थे।

मोदी का कौशल, कई दक्षिणपंथी लोकलुभावन प्रचारकों की तरह, अपने लक्षित दर्शकों के साथ घनिष्ठता बनाने की कोशिश करना है, इस तरह के बयानों को लोकप्रिय मुहावरों, पूर्वाग्रहों और दुनिया की सामान्य समझ की स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत करना;

यह निहित है कि अन्य राजनेता या तो बहुत डरते हैं या उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, भले ही वे जानते हों कि वे सच हैं, जबकि मोदी के पास निश्चित रूप से ऐसी कोई बाधा नहीं है। यहाँ जो बात नहीं कही गई है, वह यह है कि इस तरह के रोज़मर्रा के "सामान्य ज्ञान" को अक्सर प्रतिक्रियावादी, स्त्री-द्वेषी, पितृसत्तात्मक और निश्चित रूप से सांप्रदायिक रूढ़िवादिता द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसी सीमाओं को पार करके ऐसा प्रतीत होना कि उनके श्रोता वैसे भी क्या सोच रहे हैं; लेकिन राजनीतिक भाषणों की परंपराओं के कारण सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी कहा जाता है, बहुत दूर तक जाए बिना ऐसा करना एक मुश्किल काम है, लेकिन मोदी ने अपने भाषण में इसे कुशलता से प्रबंधित किया है।

परिवार और राष्ट्र दोनों को सुरक्षित रूप से बंधे रहना चाहिए, ताकि कमजोर महिलाओं की रक्षा हो सके, और जब यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो नैतिक भय पैदा होता है

प्रोकैटालेप्टिक डायट्रीब्स.

जो बात विशेष रूप से चिंताजनक और भयावह है, वह है उन माताओं और बहनों के संदर्भ में, जिनके मंगलसूत्रों की रक्षा की जानी चाहिए, एक कामुक रूप से भरी विषम राष्ट्रवादी कल्पना का निर्माण, जो एक स्वस्थ हिंदू पुरुषत्व और मुसलमानों, विशेष रूप से मुस्लिम पुरुषों को अन्य बनाने की चिंताजनक भावना पैदा करती है, ताकि सांप्रदायिक रूप से नैतिक आतंक पैदा किया जा सके। हिंदू राष्ट्रवाद सभी सांस्कृतिक राष्ट्रवादों की तरह राष्ट्र, समाज और परिवार के चारों ओर सख्त सीमाओं के निर्माण पर आधारित है। इनके उल्लंघन या उल्लंघन के किसी भी संकेत को अस्तित्व के लिए खतरा माना जाता है, जिसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए।

राष्ट्र की सीमाएं, बहुसंख्यकों की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान तथा विषमलैंगिक परिवार इकाई के चारों ओर की सुरक्षात्मक सीमाएं पवित्र हैं तथा इन्हें हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए।

सभी सांस्कृतिक राष्ट्रवादों की तरह, हिंदुत्व आधुनिकता द्वारा लाए गए तनावों से निपटने की एक प्रतिक्रियात्मक रणनीति है।

पूंजीवादी परिवर्तन, लोकतंत्रीकरण और उदारीकरण के दबाव और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सीमाओं पर दबाव बढ़ रहा है।

आधुनिकीकरण के कारण उत्पन्न तनावों जैसे विस्थापन के पीछे के कारणों का सही निदान करने के स्थान पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमेशा इसका दोष किसी काल्पनिक दूसरे पर मढ़ने का प्रयास करता है, जो किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय विकास को अवरुद्ध कर रहा है, सामाजिक विस्थापन का कारण बन रहा है, तथा सामाजिक व्यवस्था के अंतिम लक्ष्य: परिवार के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।

जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष के विद्वानों ने उल्लेख किया है कि यह महिलाओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसे है।

ऐसी विचारधाराएँ जो अक्सर युद्ध का मैदान बन जाती हैं, जिस पर परस्पर विरोधी विचारधाराएँ और समूह अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जिससे यौन हिंसा के उच्च स्तर सामने आते हैं। इसी तरह, यह महिला की छवि है, जिसे इस वैचारिक मानसिकता में संरक्षण की आवश्यकता वाले परिवार के एक कमजोर हिस्से के रूप में पेश किया गया है; मंगल-सूत्र के साथ - एक हिंदू महिला की विवाहित स्थिति का बहुत ही प्रतीक और समाज के भीतर परिवार के पुनरुत्पादन को सक्षम करने में उसकी भूमिका। हिंदुत्व की कल्पना के उस दूसरे प्रमुख तत्व से सुरक्षा; अति-कामुक मुस्लिम अन्य: जिसकी बहुत सारी पत्नियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सरकार से बहुत अधिक लाड़-प्यार है, बस सब कुछ बहुत अधिक है। यौन दुराचार को हमेशा दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी कल्पनाओं में दूसरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है: गहरे दक्षिण में श्वेत अमेरिकियों द्वारा अश्वेत अमेरिकियों को, नाज़ियों द्वारा यहूदियों को और अफ़्रीकनर्स द्वारा रंगभेद के तहत काले दक्षिण अफ़्रीकी को।

बोल- के खिलाफ लगाए गए सबसे लोकप्रिय और बेतुके आरोपों में से एक यह है कि

रूसी क्रांति के शुरुआती दिनों में शेविकों के बारे में एक आम धारणा यह थी कि वे यौन संकीर्णता की वकालत करते थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सभी मनगढ़ंत मिथक हैं; जंगली, अति-कामुक, लाड़-प्यार में पले-बढ़े मुसलमान की छवि पूरी तरह से एक अमूर्त रचना है, लेकिन फिर भी यह लोकप्रिय कल्पना में एक निरंतर कल्पना बनी हुई है, जो पहले उल्लेखित सांप्रदायिक "रोज़मर्रा की सामान्य समझ" का हिस्सा बनती है, जिसे इस प्रवचन में इतनी आसानी से हथियार बनाया जाता है।

परिवार की महिलाओं के लिए खतरे के इस चश्मे से देखा जाए तो यह समाज और राष्ट्र की ख़तरे में पड़ी स्थिति का प्रतीक है। परिवार और राष्ट्र दोनों को ही सुरक्षित रूप से बंधे रहना चाहिए, ताकि कमज़ोर महिलाओं की रक्षा की जा सके, और जब यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो नैतिक आतंक पैदा होता है।

यह नैतिक आतंक समाज और राष्ट्र दोनों को सुरक्षा के मायावी आश्वासन की तलाश में और भी अधिक चरम, और भी अधिक बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान भी है और हिंदू मर्दानगी के लिए एक अंतर्निहित चुनौती भी है। पिछले दिल्ली राज्य चुनावों के दौरान भाजपा सांसदों ने यह दावा करने की हद तक चले गए कि अगर विपक्ष जीतता है तो हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया जाएगा। गहरी चिंता यह है कि कार्रवाई के लिए इस तरह के बार-बार आह्वान और सांप्रदायिक रूप से आवेशित प्रवचन का उपयोग अंततः सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाएगा जैसा कि अतीत में अक्सर होता रहा है।

यदि सांप्रदायिक विद्वेष को बनाए रखना है, तथा सांप्रदायिक हिंसा के खतरे को हमेशा के लिए टालना है, तो इस तरह के विमर्श को रहस्यमयी बनाना तथा महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के वास्तविक खतरों का पता लगाना आवश्यक है, जैसा कि प्रज्वल रेवन्ना के चौंकाने वाले मामले से पता चलता है।

कॉनराड बरवा एक निजी थिंक टैंक में वरिष्ठ शोध विश्लेषक और एक वरिष्ठ शोध सहयोगी हैं।

बर्मिंघम बिजनेस स्कूल

मेटा बनाम तत्वमीमांसा

— श्रीनाथ श्रीधरन

मैं आज के परस्पर जुड़े हुए

डिजिटल युग में इसका प्रभाव

इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मेटा प्लेटफॉर्म हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो गए हैं, जिससे हम कैसे जुड़ते हैं, संवाद करते हैं और अपने आस-पास की दुनिया को कैसे देखते हैं, यह बदल रहा है। ऐसा लगता है कि यह सभी आयु समूहों, सामाजिक आर्थिक स्तरों, भाषाओं और यहां तक कि डिजिटल विशेषज्ञता को भी प्रभावित करता है। जबकि ये प्लेटफ़ॉर्म हमें जानकारी और बातचीत का खजाना प्रदान करते हैं, हमारे डिजिटल जुड़ाव और हमारी आध्यात्मिक भलाई के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को पहचानना आवश्यक है।

सोशल मीडिया के उदय से पहले भी, आध्यात्मिकता गहन आत्मनिरीक्षण और समझ का स्रोत थी।

मार्गदर्शक प्रकाश

अस्तित्व, वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति की खोज में निहित आध्यात्मिकता ने अनादि काल से ही पारलौकिकता का मार्ग प्रस्तुत किया है। हालाँकि, हमारे डिजिटल समाज में, आध्यात्मिकता की गहरी अंतर्दृष्टि लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन में मिलने वाली तत्काल संतुष्टि के कारण दबने का जोखिम उठाती है।

फिर भी, हमारे डिजिटल व्यस्तता के बीच, हमारे आध्यात्मिक सार से फिर से जुड़ने और तत्वमीमांसा के कालातीत ज्ञान को फिर से खोजने का अवसर बना हुआ है। शांत चिंतन के क्षणों में, हम सभी चीजों के परस्पर-संबंध पर विचार कर सकते हैं,

अस्तित्व की असीम प्रकृति, तथा स्थायी सत्य जो डिजिटल पहलू से परे हैं।

अपने मूल में, आध्यात्मिकता एक शरणस्थली प्रदान करती है - हमारे आस-पास और हमारे अंदर की हर चीज़ के शोर के बीच एक शरणस्थली, यहाँ तक कि डिजिटल युग में भी। ध्यान-साधना अभ्यास, माइंडफुलनेस अभ्यास और आत्मनिरीक्षण चिंतन के माध्यम से, हम डिजिटल युग की जटिलताओं को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के सूक्ष्म स्वरों को अपनाकर, हम अपने आंतरिक संतुलन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उन शाश्वत सत्यों में सांत्वना पा सकते हैं जो आभासी मान्यता के क्षणिक आकर्षण से परे हैं।

अपने दैनिक जीवन में डिजिटल परिदृश्य में आगे बढ़ते हुए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान की इस शाश्वत सलाह पर ध्यान देना चाहिए: "किसी से आसक्त न हों।" जिस तरह यह मार्गदर्शन हमारी भौतिक सम्पत्ति और सांसारिक इच्छाओं पर लागू होता है, उसी तरह यह हमारी डिजिटल और सोशल मीडिया आदतों पर भी लागू होता है।

जिस तरह हम अपने आभासी अंतरक्रियाओं की जटिलताओं को समझते हैं, उसी तरह हम अपने भीतर की यात्रा भी करें, डिजिटल दुनिया और तत्व-भौतिकी के शाश्वत सत्य के बीच सामंजस्य स्थापित करें। क्योंकि इस नाजुक संतुलन में हमारी मानवता का सार निहित है, जो हमारे डिजिटल अनुभवों और हमारी आत्माओं की गहराई दोनों को समृद्ध करता है।

डॉ. श्रीनाथ श्रीधरन एक नीति शोधकर्ता और कॉर्पोरेट सलाहकार हैं। X: @ssmumbai

पत्र संपादक को

हमारी जीवन रेखा बचाओ

एक किफायती, सुरक्षित क्यों है और आरामदायक सार्वजनिक क्या परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना किसी राजनीतिक पार्टी का चुनावी वादा नहीं है? आमची मुंबई आमची बेस्ट - एक नागरिक मंच जो मुंबई की एक समय में प्रशंसित सार्वजनिक बस प्रणाली, बेस्ट, की लगातार गिरावट का अध्ययन कर रहा है, और मांग कर रहा है कि इसे निजीकरण के जबड़े से बचाया जाए - जानना चाहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि इस चुनाव में जीतने पर बेस्ट को बचाने के लिए क्या करेंगे।

बेस्ट द्वारा संचालित सिटी बस सेवा भारत की वित्तीय राजधानी की दूसरी जीवन रेखा है, पहली जीवन रेखा शहर में फैली स्थानीय रेलवे लाइनें हैं। पूरी कामकाजी आबादी अपने कार्यस्थलों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य स्थानों पर जाने के लिए परिवहन के इन साधनों पर निर्भर करती है।

अन्य आवश्यक सेवाएँ। भारी घाटे के कारण इसे चलाने में सक्षम न होने के बहाने इस किफायती परिवहन प्रणाली को धीरे-धीरे खत्म करना, मुंबई के नागरिकों की भलाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और यह एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

हम स्पष्टीकरण की मांग करते हैं वर्तमान और भावी निर्वाचित प्रतिनिधियों से: • भारत के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक इस सिटी बस सेवा को सब्सिडी देने के लिए अपने बजट को BEST बजट के साथ विलय करने से क्यों इनकार कर रहा है?

• बेस्ट घाटे में चलने की शिकायत क्यों कर रहा है, जबकि सार्वजनिक परिवहन एक आवश्यक सेवा है, न कि केवल लाभ कमाने के लिए चलाया जाने वाला व्यवसाय? • बेस्ट के साथ यह भेदभाव क्यों, जबकि घाटे में चल रही मेट्रो रेल पर लगभग एक लाख करोड़ रुपए उधार लेकर खर्च किए जाने हैं? • यदि बेस्ट का नई बसें खरीदने का दावा सही है, तो बस यात्रियों को ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?

बसों के लिए एक घंटे से अधिक समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि पहले यह 15-20 मिनट तक चलता था? बसों की आवृत्ति में भारी गिरावट क्यों आई है? • बेस्ट के स्वामित्व वाली बसों को चरणबद्ध तरीके से क्यों हटाया जा रहा है और उनकी जगह कम बैठने और खड़े होने की जगह वाली छोटी बसें क्यों लाई जा रही हैं? • सुरक्षित, बड़ी बेस्ट बसों को छोटी, खराब रखरखाव वाली वेट-लीज्ड या ठेकेदार के स्वामित्व वाली निजी बसों से क्यों बदला जा रहा है, जो अक्सर खराब हो जाती हैं या कुछ मामलों में आग भी पकड़ लेती हैं? • कई लंबी रूट की बसों का संचालन क्यों बंद कर दिया गया है? • यदि बेस्ट घाटे में चल रही है, तो डिपो को बेहद कम कीमतों पर निजी मालिकों को क्यों बेचा जा रहा है और कुछ मामलों में बिक्री का पैसा भी क्यों नहीं वसूला गया है? इस जमीन की बिक्री से किसे फायदा होगा – बेस्ट को, लोगों को या निजी निगम को? क्या यह जमीन मेट्रो के लिए संसाधन जुटाने के लिए बेची जा रही है?

• निजी बसों को निजी चालकों द्वारा क्यों चलाया जा रहा है, जबकि बेस्ट चालकों को नौकरी से निकालने की तैयारी में बेकार बैठा दिया गया है? • सरकार तटीय सड़क आदि जैसे कार-अनुकूल एक्सप्रेसवे पर प्राथमिकता के आधार पर क्यों खर्च कर रही है और उच्च आय वर्ग के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने वाली मेट्रो को घाटे में क्यों चला रही है, जबकि बहुसंख्यक कामकाजी आबादी, वरिष्ठ नागरिक, छात्र, महिलाएं और अन्य निम्न आय वर्ग के लोग शहर की बसों की संख्या में भारी कमी के कारण असहाय रह गए हैं?

हम, मुंबई के नागरिक, इन सभी सवालों का जवाब मांगते हैं और जानना चाहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि क्या करने जा रहे हैं?

इसके बारे में।
आमची मुंबई आमची बेस्ट
amchibest.wordpress.com/

बंदूकें और पोज़ - एक परिचित कहानी

शस्त्र लॉबी अमेरिकी को कभी भी राष्ट्रपति शांतिवादी बनें। यदि कोई संघर्ष को भड़काता है, तो उसका उत्तराधिकारी उसे आगे बढ़ाएगा या फिर दूसरा संघर्ष शुरू कर देगा। यूक्रेन या गाजा युद्ध भी इसी तरह उनके नवीनतम मेनू में शामिल हैं।

इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का बिडेन का फैसला दिखावटी है, क्योंकि वह फिर से चुनाव जीतने की अपनी कोशिशों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। यूक्रेन भी इससे अलग नहीं है; और एक निष्क्रिय संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पारित करने से संतुष्ट है।

आर नारायणन, नवी मुंबई

फार्मा की कड़वी गोली

क्षेत्र में बेचैनी दवा उद्योग में गड़बड़ी की बात साफ तौर पर सामने आ रही है, पिछले एक महीने में इसके कुछ प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक दलों को किए गए भुगतान को लेकर यह गहन जांच के दायरे में आ गया है। चुनाव आयोग की सूची से पता चलता है कि अस्पतालों, वैक्सीन कंपनियों और दवा निर्माताओं ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं।

उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल कंपनियां दवाओं या उपचारों की लागत कम करने में आने वाली कठिनाइयों के लिए अनेक कारण गिनाती हैं।

फार्मा की कड़वी गोली स्वास्थ्य देखभाल को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है।

जयंती सुब्रमण्यम, मुंबई

प्रिय पाठक,
हम आपकी राय, टिप्पणियाँ और सुझाव जानने के लिए उत्सुक हैं। पत्र के शीर्षक को विषय पंक्ति में लिखते हुए letters@fpj.co.in पर लिखें। क्या आप डाक से पत्र भेज रहे हैं? अपने पत्र फ्री प्रेस जर्नल, फ्री प्रेस हाउस, फ्री प्रेस मार्ग, 215 नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 पर भेजें।

Machine Translated by Google

आज का विचार: ईमानदारी सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे प्रतिभाशाली पाखंडी से भी अधिक मूल्यवान बना देती है।

— चार्ल्स स्पर्जन

फ़्री प्रेस

सत्य के मुक्त प्रवाह के लिए

होर्डिंग्स: जिम्मेदारी कहां रुकती है?

प्रत्येक इस सप्ताह के दूसरे दिन सोमवार को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बड़े और अवैध होर्डिंग के गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 75 लोग घायल हो गए, इस भयानक त्रासदी के बाद इसमें शामिल हर एजेंसी ने दोषारोपण का खेल खेला है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), जिसका शहर भर में होर्डिंग्स पर अंतिम निर्णय है और जिसका अधिकतम 40x40 वर्ग फुट का शासनादेश इस होर्डिंग द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था, जो कम से कम तीन गुना बड़ा था, यह दिखाने के लिए पीछे हट गया है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। इसने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए रेलवे सहित अन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्र जारी किए, जिनकी जमीन पर अप्रैल 2022 में होर्डिंग लगाया गया था। इससे केवल यह दिखाने में सफलता मिली कि बीएमसी को होर्डिंग की अवैधता के बारे में अच्छी तरह से पता था

रेलवे ने अपने परिसरों में बड़े आकार के होर्डिंग्स को हटाने के बीएमसी के निर्देश का पालन करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि उनके पास "इन संरचनाओं की स्थापना से पहले और बाद में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त तंत्र है"। फिर घाटकोपर में 120x120 वर्ग फीट के होर्डिंग को मंजूरी कैसे मिल गई, जबकि जांच से पता चला है कि इसके खंभे केवल 1.5 मीटर गहरे हैं और स्पष्ट रूप से तेज हवाओं या बारिश का सामना करने में असमर्थ हैं? रेलवे मुंबईकरों के बीच बिल्कुल भी भरोसा नहीं जगाती है।

गिरफ्तार लोगों में अब इस पूरे मामले का केंद्रबिंदु भावेश भिंडे भी शामिल है, जो होर्डिंग लगाने के लिए अनुबंधित कंपनी ईगो मीडिया के मालिक हैं। भिंडे इस जानलेवा घोटाले का केवल एक चेहरा हैं, जिनके दरवाजे पर रेलवे और बीएमसी सारा दोष मढ़ रहे हैं। उन अधिकारियों का क्या, जो अदृश्य लेकिन जवाबदेह पुरुष और महिलाएं हैं, जिन्होंने इस होर्डिंग को मंजूरी दी, जो इतने सारे लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ और जिन्होंने लोगों की जान से ज्यादा राजस्व को प्राथमिकता दी? उनकी पहचान सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं की जानी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए? किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को दूसरों पर दोष मढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केवल प्रधानमंत्री ही जानते हैं

प्रधानमंत्री के बारे में एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न का सामना करना पड़ा

नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान के दौरान दिए गए कई बयानों को उन्होंने कुछ ही दिनों में वापस ले लिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो खुद मुंबई उत्तर से उम्मीदवार हैं, ने इस पर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि केवल प्रधानमंत्री ही इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने अपने बयान क्यों वापस लिए। कई लोगों का कहना है कि यह उलटफेर उस व्यक्ति के स्वभाव के विपरीत है, जिसे "एक महान वक्ता" के रूप में सराहा गया है, लेकिन कई बार टेलीप्रॉम्प्टर जीवी भी कहा गया है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोलने की उनकी क्षमता विफल हो गई है। हालांकि मोदी की अपने वफादार दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता पर संदेह नहीं है, लेकिन यह उन्हें एक महान वक्ता नहीं बनाता है, जिसके लिए परिभाषा के अनुसार, विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ठोस तर्क देने में सक्षम होना चाहिए, कुशलता से बोलना चाहिए, भाषा का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए कई तरह की भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए।

आइए हम उनकी वक्तृत्व कला या उसकी कमी को एक तरफ रख दें।

पिछले कुछ दिनों से वे किसी विषय पर मुखर होकर बयान दे रहे हैं, आम तौर पर किसी राजनीतिक रैली में वोट की अपील करते हुए, और फिर कुछ ही दिनों में उसे वापस ले लेते हैं, जिससे मीडिया में उनके प्रशंसक और प्रशंसक भी अचंभित रह जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ है। उन्होंने राजस्थान में गलत तरीके से कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को देश के संसाधनों पर अधिकार मिले; कुछ दिनों बाद, उन्होंने एक टेलीविजन चैनल से कहा कि वे कभी भी हिंदू-मुस्लिम कार्ड नहीं खेलेंगे - लेकिन अगली रैली में वे अपनी बात से पलट गए। फिर, उन्होंने कहा कि उन्हें "400 से ज़्यादा सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे" लेकिन उन्होंने ऐसा कहने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे और भी उदाहरण हैं।

कुल मिलाकर, यह कम से कम दो बातों की ओर इशारा करता है। एक यह कि प्रधानमंत्री अतीत या भविष्य के संदर्भ के बिना, अपने वर्तमान समय के अनुरूप वास्तविकता को बदलते और मोड़ते दिखते हैं, जिससे उनके संतुलन पर सवाल उठता है। दूसरा भारत के लोगों से संबंधित है और इसे अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कुछ भी हो, इन उलटफेरों और वापसी ने यह प्रदर्शित किया है कि प्रधानमंत्री के बयानों को अब संदेह और सावधानी की स्वस्थ खुराक के साथ लिया जाना चाहिए। अनजाने में, उन्होंने अपने बड़े और चापलूस प्रशंसकों और प्रशंसक लड़कियों के क्लब को तथ्य-जांचकर्ताओं में बदल दिया है जो अब बाकी सभी की तरह ही अविश्वसनीय रूप से देखते हैं। अपने नायक के बारे में आँखों से पर्दा हटना एक अच्छी बात है, खासकर लोकतंत्र में।

एफपीजे अभिलेखागार

75 साल पहले का भारत

18 मई, 1949

FREE PRESS JOURNAL

SHANGHAI SUBURB ABLAZE

GUARANTEE RIGHTS OF THE PRESS

Editors Stress Need For Statutory Provision

DEPUTATION TO WAIT ON C.A. PRESIDENT

RADIO CRAFTSMEN CO.

प्रेस के अधिकारों की गारंटी

बेंगलुरु, 17 मई। अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक संघ की एक उप-समिति ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समाचार पत्रों के संपादकों की समिति ने समाचार पत्रों के संपादकों की एक उप-समिति की बैठक में ...

सम्मेलन का उद्देश्य संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रारूप समिति से मुलाकात करना है, तथा भारत के भावी संविधान में प्रेस को उसके मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाला एक खंड शामिल करने का आग्रह करना है।

चुनावों के लिए अंधराष्ट्रीयता ठीक है, पड़ोसियों के लिए नहीं

दोस्ताना आँख

÷के.सी. सिंह

सर्वेक्षणों में पुलवामा आतंकवादी हमले और जम्मू-कश्मीर 2019 लोकसभा [illegible] प्रदर्शन का बोलबाला रहा। पाकिस्तान के बालाकोट पर मोदी सरकार के साहसिक हवाई हमले का मुद्दा मौजूदा चुनाव के पहले तीन चरणों में नहीं उठा।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी के बाद यह स्थिति बदल गई कि पाकिस्तान के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं और उसने चूड़ियां नहीं पहनी हैं - यह एक लिंग-भेदपूर्ण कथन है, जो स्त्रीवत व्यवहार को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी भी अपने भाषणों में कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान और विपक्ष को आड़े हाथों लेने का मौका नहीं छोड़ सकते। बिहार में चौथे चरण के दौरान प्रचार करते हुए उन्होंने भड़काऊ अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान ने "चूड़ियाँ नहीं पहनीं", तो उनकी सरकार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है। इस तस्वीर का उद्देश्य बालाकोट की भावना को जगाना था, जिसका फायदा उठाने में भाजपा अब तक विफल रही है। पाकिस्तान कम से कम अस्थायी तौर पर चुनाव के विषय के रूप में वापस आ गया था। विपक्ष चुनाव प्रचार को अलग-थलग कर रहा था किसी भी ऐसे मुद्दे से दूर रहें जो प्रधानमंत्री की जिद और उत्पात मचाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता हो।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 14 मई को विस्तार से जवाब दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई सरकार अब तक अपने घरेलू आर्थिक संकट से निपटने में व्यस्त थी, जबकि वह चुपचाप भारत के चुनावी नतीजों का इंतजार कर रही थी, ताकि यह आकलन कर सके कि अगली सरकार पिछले पांच वर्षों की आतंकवाद के बीच बातचीत न करने की नीति में बदलाव लाएगी या नहीं।

एक लंबे बयान में कहा गया है, "हम भारतीय राजनेताओं से आग्रह करते हैं कि वे चुनावी लाभ के लिए पाकिस्तान को अपनी राजनीति में घसीटना बंद करें और संवेदनशील रणनीतिक मामलों को अत्यंत सावधानी से संभालें।"

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे इस बात पर ध्यान दें कि भारत "क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा" के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। बयान में अनुमान लगाया गया कि भारतीय अंधराष्ट्रवाद "लापरवाह और उग्रवादी मानसिकता" को दर्शाता है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जनता के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के कारण चर्चा में आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान की आलोचना में अपना योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निकट भविष्य में पीओके क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लेगी। उनके राजनीतिक घमंड और प्रधानमंत्री के चूड़ियों वाले ताने के बीच एक व्यापक रणनीतिक संबंध छिपा है।

एक ऐसा स्थान जिस पर बहस की जा सकती है, तथा जोखिम और लाभ का मूल्यांकन किया जा सकता है। चुनावों में अंधराष्ट्रीयता उपयोगी हो सकती है, जब जनता भाजपा के मानक विभाजनकारी कथानक से उतनी उत्साहित नहीं दिखती, लेकिन पड़ोस की स्थिति लोकप्रिय छवि से कहीं अधिक जटिल है।

पीओके और सम्पूर्ण कश्मीर मुद्दा आज भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है जैसा कि 1972 के शिमला समझौते में परिकल्पना की गई थी।

यह याद किया जा सकता है कि जब 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था, तो चीन ने एक विवादित क्षेत्र के संबंध में भारत द्वारा एकतरफा बदलाव करने पर आपत्ति जताई थी।

चुनावी बयानबाजी चाहे जो भी हो, अगली भारतीय सरकार के सामने क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है, जितना कि चूड़ियों के तानों से पता चलता है।

यह क्षेत्र चीन से भी संबद्ध था। मई 2020 में गलवान घाटी से शुरू होकर लद्दाख में उनकी सैन्य घुसपैठ उनकी आपत्तियों का ही परिणाम थी। चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में भारी निवेश किया है, जिसका परिव्यय 46 बिलियन डॉलर से बढ़कर 62 बिलियन डॉलर हो गया है। यह गलियारा दक्षिणी शिनजियांग को बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो POK के गिलगी-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इसलिए भारत द्वारा POK को सैन्य रूप से पुनः प्राप्त करने के किसी भी प्रयास में चीन के शामिल होने की प्रबल संभावना है।

संघर्ष।

दरअसल, विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा है और भाजपा उसे टाल रही है, वह यह है कि देपसांग मैदानों और डेमचोक में चीनी घुसपैठ को वापस क्यों नहीं लिया गया है। बेशक सरकार ने 2020 में सुस्ती के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारतीय सैन्य स्थिति को मजबूत किया है। सरकार ने LAC पर बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा दिया है। लेकिन सेना-से-सेना वार्ता ने देश के कुछ हिस्सों में शुरुआती सफलता के बाद प्रगति नहीं की है।

पूर्वी लद्दाख में। कुछ लोग कहेंगे कि सफलता का एक हिस्सा तब मिला जब भारत ने कैलाश पर्वतमाला पर प्रमुख स्थानों पर कब्जा करके चीन को चौंका दिया। स्पष्ट रूप से चीन क्षेत्रीय विवाद को अनसुलझा रखना चाहता है क्योंकि इससे वह समय-समय पर उकसावे के ज़रिए भारत को असंतुलित रखने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए, लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर चीन ने न केवल अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखाया बल्कि इसके बसे हुए इलाकों को भी चीनी नाम दिए।

भारत इस मामले में सतर्क रहा है।

चीन को पीछे छोड़ते हुए। इसने एशिया-प्रशांत में अमेरिका द्वारा प्रायोजित छोटे गठबंधनों में शामिल होने से परहेज किया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका से मिलकर बना क्वाड, चीन की आशंका के मुताबिक इंडो-पैसिफिक का नाटो बनने से चूक गया है। भारत की अनिच्छा को देखते हुए, अमेरिका ने AUKUS बनाया - मौजूदा सहयोगी ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ एक त्रिपक्षीय समूह। इसके बाद वे अन्य प्रशांत शक्तियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 12 जुलाई, 2023 को लिथुआनिया में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया के नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

इसलिए, चुनावी बयानबाजी चाहे जो भी हो, अगली भारतीय सरकार के सामने क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है, जितना कि चूड़ियों के तानों से पता चलता है।

तार्किक रूप से, जब दो शत्रुतापूर्ण विरोधियों का सामना हो तो उद्देश्य उनके गठबंधन को कमजोर करना होना चाहिए।

उन्हें और अधिक निकट लाने के लिए दबाव डालना दीर्घकाल में आत्मघाती होगा।

इजरायल पर हमास के हमले में भारत के लिए सबक है - ऐतिहासिक विवादों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्हें चीनी हथियारों की ओर धकेलना कूटनीतिक विफलता है।

के.सी. सिंह विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं

हिंदू राष्ट्रवाद की नैतिक घबराहट और चिंताएं

असहमत कोना

÷कॉनराड बार्वा

सबसे अधिक नियंत्रण में से एक दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल, 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में चुनाव अभियान के दौरान दिए गए भाषणों में। इसमें हिंदुत्व विचारकों द्वारा पसंद किए जाने वाले जुमलों को दोहराया गया, जैसे कि मुसलमानों में अधिक बच्चे पैदा करने की कथित प्रवृत्ति, जिससे मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मुसलमानों का वर्णन करने के लिए "घुसपैठिए" जैसे शब्दों का इस्तेमाल, पिछली गैर-भाजपा सरकारों पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को लाड़-प्यार दिया है, और यह इस दावे के साथ चरम पर पहुंच गया कि कांग्रेस के घोषणापत्र में धन के पुनर्वितरण के प्रस्ताव से व्यक्तिगत संपत्ति और बचत का जबरन अधिग्रहण होगा, जैसे कि "हमारी माताओं और बहनों" के गले से मंगलसूत्र छीनना।

इस भाषण की विषय-वस्तु के पीछे कई ऐसे तत्व छिपे हैं, जो प्रधानमंत्री और भाजपा दोनों की विचारधारा के बारे में जानकारी देते हैं।

सबसे पहले, जैसा कि नीलांजन मुखोपाध्याय जैसे कई टिप्पणीकारों ने कहा है, इस तरह की सांप्रदायिक भाषा और विषय-वस्तु का प्रयोग कोई अपवाद नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जो प्रधानमंत्री के भाषणों से दूर हो गया हो, बल्कि यह एक ऐसा तत्व है जो हमेशा से मौजूद रहा है।

उनके कार्यों और शब्दों में हमेशा "अचेतन सांप्रदायिक कोण" रहा है। जैसा कि मुखोपाध्याय तर्क देते हैं, "मोदी के हाथ में हमेशा दो कार्ड होते हैं - विकास और सांप्रदायिक विभाजन। यह स्थिति पर निर्भर करता है कि उनका प्राथमिक कार्ड कौन सा होगा।

सांप्रदायिकता का मुद्दा हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे लाया जाता है, ताकि मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत किया जा सके। जो पर्यवेक्षक इस तर्क से खुद को सहज महसूस करते हैं कि पद पर बने रहना एक नरमपंथी ताकत के रूप में काम करता है या जो मोदी की कल्याणकारी और विकासवादी बयानबाजी पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह किसी तरह उनकी सरकार का असली जोर है, वे इस पहलू को महत्वपूर्ण और अशुभ रूप से नजरअंदाज करते हैं।

यहाँ की अधिकांश शैली अब तक अच्छी तरह से अभ्यास की गई और अल्पविकसित है, जिसका इस्तेमाल पिछले दशक में प्रधानमंत्री द्वारा अपने विभिन्न अभियान अभियानों में अक्सर किया गया है। संवादात्मक शैली स्वर में वार्तालापपूर्ण है, जो लक्षित दर्शकों, मुख्य रूप से पुरुष, के साथ एक काल्पनिक वार्तालाप की नकल करती है, जिसमें किसी भी कठिन शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। यह रूपकात्मक भी है, जो लगातार हिंदुओं और उनके विरोधियों के लिए कथित खतरों की शक्तिशाली छवियों को उजागर करता है। ये रूपक बहादुरी, मर्दानगी और सदाचार के हैं, जो कायरता, स्त्रीत्व और बुराई के विपरीत हैं; या कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बात करें तो कमजोरी, घातक नीतियों और उपहास के रूपक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावधानीपूर्वक नपे-तुले "मानक अतिक्रमण" का प्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए, मुसलमानों को "घुसपैठिए" के रूप में वर्णित किया गया है, जो उनके डिप्टी और गृह मंत्री अमित शाह की बात को प्रतिध्वनित करता है, जिन्होंने मुसलमानों को कुख्यात रूप से "दीमक" के रूप में संदर्भित किया था, जो कथित रूप से बड़ी संख्या में मुसलमानों की ओर इशारा करता है, जो बांग्लादेश से सीमा पार कर भारत में बस गए थे।

मोदी का कौशल, कई दक्षिणपंथी लोकलुभावन प्रचारकों की तरह, अपने लक्षित दर्शकों के साथ घनिष्ठता बनाने की कोशिश करना है, इस तरह के बयानों को केवल लोकप्रिय मुहावरों, पूर्वाग्रहों और दुनिया की सामान्य समझ की स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत करना;

यह निहित है कि अन्य राजनेता या तो बहुत डरते हैं या उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, भले ही वे जानते हों कि वे सच हैं, जबकि मोदी के पास निश्चित रूप से ऐसी कोई बाधा नहीं है। यहाँ जो बात नहीं कही गई है, वह यह है कि इस तरह के रोज़मर्रा के "सामान्य ज्ञान" को अक्सर प्रतिक्रियावादी, स्त्री-द्वेषी, पितृसत्तात्मक और निश्चित रूप से सांप्रदायिक रूढ़िवादिता द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसी सीमाओं को पार करके ऐसा प्रतीत होना कि उनके श्रोता वैसे भी क्या सोच रहे हैं; लेकिन राजनीतिक भाषणों की परंपराओं के कारण सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी कहा जाता है, बहुत दूर तक जाए बिना ऐसा करना एक मुश्किल काम है, लेकिन मोदी ने अपने भाषण में इसे बड़ी चतुराई से प्रबंधित किया है।

परिवार और राष्ट्र दोनों को सुरक्षित रूप से बंधे रहना चाहिए, ताकि कमजोर महिलाओं की रक्षा हो सके, और जब यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है, तो नैतिक आतंक पैदा होता है

प्रोकैटालेप्टिक डायट्रीब्स.

जो बात विशेष रूप से चिंताजनक और भयावह है, वह है उन माताओं और बहनों के संदर्भ में, जिनके मंगलसूत्रों की रक्षा की जानी चाहिए, एक कामुक रूप से भयावह विषम राष्ट्रवादी कल्पना का निर्माण, जो एक स्वस्थ हिंदू पुरुषत्व और मुसलमानों, विशेष रूप से मुस्लिम पुरुषों को अन्यीकरण करने के लिए परेशान करने वाली भावनाएँ पैदा करती है, ताकि सांप्रदायिक रूप से नैतिक आतंक पैदा किया जा सके। हिंदू राष्ट्रवाद सभी सांस्कृतिक राष्ट्रवादों की तरह राष्ट्र, समाज और परिवार के चारों ओर सख्त सीमाओं के निर्माण पर आधारित है। इनके उल्लंघन या उल्लंघन के किसी भी संकेत को अस्तित्व के लिए खतरा माना जाता है, जिसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए।

राष्ट्र की सीमाएं, बहुसंख्यकों की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान तथा विषमलैंगिक परिवार इकाई के चारों ओर की सुरक्षात्मक सीमाएं पवित्र हैं तथा इन्हें हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए।

सभी सांस्कृतिक राष्ट्रवादों की तरह, हिंदुत्व आधुनिकता द्वारा लाए गए तनावों से निपटने की एक प्रतिक्रियात्मक रणनीति है।

पूंजीवादी परिवर्तन, लोकतंत्रीकरण और उदारीकरण के दबाव, ये सभी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों की सीमाओं पर दबाव डालते हैं।

आधुनिकीकरण के कारण होने वाले तनावों के पीछे के कारणों का सही निदान करने के बजाय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमेशा इसके लिए किसी काल्पनिक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश करता है, जो किसी तरह राष्ट्रीय विकास को अवरुद्ध कर रहा है, सामाजिक अव्यवस्था का कारण बन रहा है, और सामाजिक व्यवस्था के अंतिम तत्व: परिवार के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष के विद्वानों ने उल्लेख किया है कि यह महिलाओं के शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है

जो अक्सर युद्ध का मैदान बन जाता है जिस पर परस्पर विरोधी विचारधाराएं और समूह अपने युद्ध लड़ते हैं, जिससे यौन हिंसा के उच्च स्तर सामने आते हैं। इसी तरह से, यह महिला की छवि है, जिसे इस वैचारिक मानसिकता में संरक्षण की जरूरत वाले परिवार के एक कमजोर हिस्से के रूप में पेश किया गया है; मंगल सूत्र के साथ - एक हिंदू महिला की विवाहित स्थिति का प्रतीक और समाज के भीतर परिवार के पुनरुत्पादन को सक्षम करने में उसकी भूमिका का प्रतीक है। हिंदुत्व की कल्पना के उस दूसरे प्रमुख तत्व से सुरक्षा; अति-कामुक मुस्लिम अन्य: जिसकी बहुत सारी पत्नियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सरकार से बहुत ज्यादा लाड़-प्यार है, बस सब कुछ बहुत ज्यादा है। दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी कल्पनाओं में यौन दुराचार को हमेशा दूसरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है: डीप साउथ में श्वेत अमेरिकियों द्वारा अश्वेत अमेरिकियों को, नाज़ियों द्वारा यहूदियों को और अफ़्रीकनर्स द्वारा रंगभेद के तहत काले दक्षिण अफ़्रीकी को।

बोल- के खिलाफ लगाए गए सबसे लोकप्रिय और बेतुके आरोपों में से एक यह है कि

रूसी क्रांति के शुरुआती दिनों में शेविकों के बारे में एक आम धारणा यह थी कि वे यौन संकीर्णता की वकालत करते थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सभी मनगढ़ंत मिथक हैं; जंगली, अति-कामुक, लाड़-प्यार में पले-बढ़े मुसलमान की छवि पूरी तरह से एक अमूर्त निर्माण है, लेकिन फिर भी यह लोकप्रिय कल्पना में एक निरंतर कल्पना बनी हुई है, जो पहले उल्लेखित सांप्रदायिक "रोज़मर्रा की सामान्य समझ" का हिस्सा है, जिसे इस प्रवचन में इतनी आसानी से हथियार बनाया गया है।

परिवार की महिलाओं के लिए खतरे के इस चश्मे से देखा जाए तो यह समाज और राष्ट्र की ख़तरे में पड़ी स्थिति का प्रतीक है। परिवार और राष्ट्र दोनों को ही सुरक्षित रूप से बंधे रहना चाहिए, ताकि कमज़ोर महिलाओं की रक्षा की जा सके, और जब यह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो नैतिक आतंक पैदा होता है।

यह नैतिक आतंक समाज और राष्ट्र दोनों को सुरक्षा के मायावी आश्वासन की तलाश में और भी अधिक चरम, और भी अधिक बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान भी है और हिंदू मर्दानगी के लिए एक अंतर्निहित चुनौती भी है। पिछले दिल्ली राज्य चुनावों के दौरान भाजपा के सांसदों ने यह दावा करने की हद तक चले गए कि अगर विपक्ष जीतता है तो हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया जाएगा। गहरी चिंता यह है कि कार्रवाई के लिए इस तरह के बार-बार आह्वान और सांप्रदायिक रूप से आवेशित प्रवचन का उपयोग अंततः सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाएगा जैसा कि अतीत में अक्सर होता रहा है।

यदि सांप्रदायिक विद्वेष को बनाए रखना है, तथा सांप्रदायिक हिंसा के खतरे को हमेशा के लिए टालना है, तो इस तरह के विमर्श को रहस्यमयी बनाना तथा महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के वास्तविक खतरों का पता लगाना आवश्यक है, जैसा कि प्रज्वल रेवन्ना के चौंकाने वाले मामले से पता चलता है।

कॉनराड बरवा एक निजी थिंक टैंक में वरिष्ठ शोध विश्लेषक और एक वरिष्ठ शोध सहयोगी हैं।

बर्मिंघम बिजनेस स्कूल

मेटा बनाम तत्वमीमांसा

— श्रीनाथ श्रीधरन

सभी चीजों की वास्तविकता, बद्ध-विश्व, अस्तित्व की कम प्रकृति का प्रभाव, तथा स्थायी सत्य जो डिजिटल पहलू से परे हैं।

मैं आज के परस्पर जुड़े हुए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मेटा प्लेटफॉर्म हमारे दैनिक जीवन में गहराई से समा गए हैं और यह हमारे आसपास और हमारे अंदर, यहां तक कि हमारे भीतर की दुनिया को देखने के तरीके को नया रूप दे रहे हैं। यह डिजिटल युग में सामाजिक-आर्थिक, रचनात्मक प्रथाओं, माइंडफुलनेस स्तरों, भाषाओं और यहां तक कि खुदाई के अभ्यासों और आत्मनिरीक्षण विशेषज्ञता के माध्यम से व्याप्त है। इन चिंतन के दौरान, हम सूचना के खजाने और डिजिटल युग की जटिलताओं के बीच अनुग्रह और बातचीत के साथ प्रवेश कर सकते हैं, यह आवश्यक है कि मौन रहें। आध्यात्मिकता के सूक्ष्म स्वरों के महत्व को पहचानते हुए, हम अपने डिजिटल जुड़ाव के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने आध्यात्मिक कल्याण में सांत्वना पा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की सलाह की खोज में निहित: अस्तित्व, वास्तविकता और प्रकृति। "आसक्त मत होइए । " जिस तरह अस्तित्व का यह सिद्धांत, हमेशा के लिए हमारी भौतिक और नैतिक इच्छाओं पर लागू होता है, वैसे ही आध्यात्मिकता ने संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं से परे जाने का मार्ग पेश किया है, यह हमारी गरिमा के लिए भी सही है। हालाँकि , हमारे डिजिटल और सोशल मीडिया की आदतों में, आध्यात्मिकता की गहरी अंतर्दृष्टि हमारे आभासी अस्तित्व की जटिलताओं को जोखिम में डालती है। जिस तरह हम आध्यात्मिकता की अधिक गहन अंतर्दृष्टि को नेविगेट करते हैं , वैसे ही हम अपने भीतर की निरंतर संतुष्टि की यात्रा भी करें , डिजिटल दुनिया और लाइक, शेयर और सूचनाओं के बीच सामंजस्य पाएँ ।

मार्गदर्शक प्रकाश

फिर भी, हमारी डिजिटल व्यस्तता के बीच, हमारे आध्यात्मिक सार और आत्माओं की गहराई को समृद्ध करने और कालातीत ज्ञान की खोज करने का अवसर अभी भी बना हुआ है ।

तत्वमीमांसा का। शांत प्रतिबिंब के क्षणों में, हम परस्पर जुड़े हुए चिंतन कर सकते हैं-

डॉ. श्रीनाथ श्रीधरन एक नीति शोधकर्ता और कॉर्पोरेट सलाहकार हैं।

एक्स: @ssmumbai

पत्र संपादक को

हमारी जीवन रेखा बचाओ

एक किफायती, सुरक्षित क्यों है और आरामदायक सार्वजनिक क्या परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना किसी राजनीतिक पार्टी का चुनावी वादा नहीं है?

आमची मुंबई आमची बेस्ट - एक नागरिक मंच जो मुंबई की एक समय में प्रशंसित सार्वजनिक बस प्रणाली, बेस्ट, की लगातार गिरावट का अध्ययन कर रहा है, और मांग कर रहा है कि इसे निजीकरण के जबड़े से बचाया जाए - जानना चाहता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि इस चुनाव में जीतने पर बेस्ट को बचाने के लिए क्या करेंगे।

बेस्ट द्वारा संचालित सिटी बस सेवा भारत की वित्तीय राजधानी की दूसरी जीवन रेखा है, पहली जीवन रेखा शहर में फैली स्थानीय रेलवे लाइनें हैं। पूरी कामकाजी आबादी अपने कार्यस्थलों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य स्थानों पर जाने के लिए परिवहन के इन साधनों पर निर्भर करती है।

अन्य आवश्यक सेवाएँ। भारी घाटे के कारण इसे चलाने में सक्षम न होने के बहाने इस किफायती परिवहन प्रणाली को धीरे-धीरे खत्म करना, मुंबई के नागरिकों की भलाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और यह एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

हम स्पष्टीकरण की मांग करते हैं वर्तमान और भावी निर्वाचित प्रतिनिधियों से: • भारत के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक इस सिटी बस सेवा को सब्सिडी देने के लिए अपने बजट को BEST बजट के साथ विलय करने से क्यों इनकार कर रहा है?

• बेस्ट घाटे में चलने की शिकायत क्यों कर रहा है, जबकि सार्वजनिक परिवहन एक आवश्यक सेवा है, न कि केवल लाभ कमाने के लिए चलाया जाने वाला व्यवसाय? • बेस्ट के साथ यह भेदभाव क्यों, जबकि घाटे में चल रही मेट्रो रेल पर लगभग एक लाख करोड़ रुपए उधार लेकर खर्च किए जाने हैं? • यदि बेस्ट का नई बसें खरीदने का दावा सही है, तो बस यात्रियों को ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?

बसों के लिए एक घंटे से अधिक समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि पहले यह 15-20 मिनट तक चलता था? बसों की आवृत्ति में भारी गिरावट क्यों आई है? • बेस्ट के स्वामित्व वाली बसों को चरणबद्ध तरीके से क्यों हटाया जा रहा है और उनकी जगह कम बैठने और खड़े होने की जगह वाली छोटी बसें क्यों लाई जा रही हैं? • सुरक्षित, बड़ी बेस्ट बसों को छोटी, खराब रखरखाव वाली वेट-लीज्ड या ठेकेदार के स्वामित्व वाली निजी बसों से क्यों बदला जा रहा है, जो अक्सर खराब हो जाती हैं या कुछ मामलों में आग भी पकड़ लेती हैं? • लंबी रूट की कई बसें क्यों बंद कर दी गई हैं? • अगर बेस्ट घाटे में चल रहा है, तो डिपो को बेहद कम कीमतों पर निजी मालिकों को क्यों बेचा जा रहा है और कुछ मामलों में बिक्री का पैसा भी क्यों नहीं वसूला गया है? इस जमीन की बिक्री से किसे फायदा होगा – बेस्ट को, लोगों को या निजी निगम को? क्या यह जमीन मेट्रो के लिए संसाधन जुटाने के लिए बेची जा रही है?

• निजी बसों को निजी चालकों द्वारा क्यों चलाया जा रहा है, जबकि बेस्ट चालकों को नौकरी से निकालने की तैयारी में बेकार बैठा दिया गया है? • सरकार तटीय सड़क आदि जैसे कार-अनुकूल एक्सप्रेसवे पर प्राथमिकता के आधार पर क्यों खर्च कर रही है और उच्च आय वर्ग के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने वाली मेट्रो को घाटे में क्यों चला रही है, जबकि बहुसंख्यक कामकाजी आबादी, वरिष्ठ नागरिक, छात्र, महिलाएं और अन्य निम्न आय वर्ग के लोग शहर की बसों की संख्या में भारी कमी के कारण असहाय रह गए हैं?

हम, मुंबई के नागरिक, इन सभी सवालों का जवाब मांगते हैं और जानना चाहते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि इस बारे में क्या करने जा रहे हैं।

आमची मुंबई आमची बेस्ट

amchibest.wordpress.com/

मिका का मैट्रिक्स

बंदूकें और पोज़ - एक परिचित कहानी

शस्त्र लॉबी कोई भी अमेरिकी को कभी भी राष्ट्रपति शांतिवादी बनें। यदि कोई संघर्ष को भड़काता है, तो उसका उत्तराधिकारी उसे आगे बढ़ाएगा या फिर दूसरा संघर्ष शुरू कर देगा। यूक्रेन या गाजा युद्ध भी इसी तरह उनके नवीनतम मेनू में शामिल हैं।

इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का बिडेन का फैसला दिखावटी है, क्योंकि वह फिर से चुनाव जीतने की अपनी कोशिशों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। यूक्रेन भी इससे अलग नहीं है; और एक निष्क्रिय संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पारित करने से संतुष्ट है।

आर नारायणन

फार्मा की कड़वी गोली

फार्मा उद्योग में बेचैनी

उद्योग जगत में व्याप्त असंतोष स्पष्ट है, पिछले एक महीने में इसके कुछ प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक दलों को किए गए भुगतानों को लेकर यह गहन जांच के दायरे में आ गया है। चुनाव आयोग की सूची से पता चलता है कि अस्पतालों, वैक्सीन कंपनियों और दवा निर्माताओं ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। हेल्थकेयर कंपनियां दवाओं या उपचारों की लागत कम करने में कठिनाइयों की व्याख्या करने के लिए कई कारण गिनाती हैं। फार्मा की कड़वी गोली स्वास्थ्य सेवा को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है।

जयंती सुब्रमण्यम

प्रिय पाठक,

हम आपकी राय, टिप्पणियाँ और सुझाव जानने के लिए उत्सुक हैं। editor.indore@fpj.co.in पर लिखें। क्या आप स्नेल मेल का उपयोग कर रहे हैं? अपने पत्र फ्री प्रेस, फ्री प्रेस हाउस, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, इंदौर 452008 को भेजें